



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 87]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

फा.सं. 21-4/2016-बीएंडसीएस.—केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39, जो –

(ए) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) और 45(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

**दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)**

**अध्याय I**

**प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण.**—(1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, पूरे देश में एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच वाणिज्यिक और तकनीकी समझौते कवर करेंगे।

(3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ए) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;

(बी) "सक्रिय सब्सक्राइबर" से, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, आशय है कोई ऐसा सब्सक्राइबर, जिसे सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के अनुसार टेलीविजन चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जिसके सेट टॉप बॉक्स को सिगनल मना नहीं किया गया है;

- (सी) "एड्रैसेबल प्रणाली" से आशय है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिन्हे एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से कार्यक्रमों का संचारण, टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के पुनः संचारण समेत, कूट (एनक्रिप्टिड) किया जा सकता है और, जिन्हें सब्सक्राइबर को टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा सब्सक्राइबर की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, सब्सक्राइबर के परिसर में किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है;
- (डी) "अ-ला-कार्ट अथवा अ-ला-कार्ट चैनल" टीवी चैनल के प्रस्ताव के संदर्भ में से आशय एकल आधार वाले चैनल के अलग-अलग प्रस्ताव से है;
- (ई) "प्राधिकरण" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
- (एफ) "औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार" से आशय है, इन विनियमों की अनुसूची 7 में विनिर्धारित तरीके से सक्रिय सब्सक्राइबर के आधार संख्या का औसत लेकर निकाली गई संख्या;
- (जी) "बुके" या "चैनलों के बुके" से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा;
- (एच) "प्रसारक" से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केन्द्र सरकार से डॉउनलिकिंग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है;
- (आई) "अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी" पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के संदर्भ में इसका आशय किसी टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को उसके पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के लिए, जैसा भी मामला हो, देय शुल्क है जिसके लिए उस प्रसारक से वितरक द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृति प्राप्त की गई हो;
- (जे) "प्रसारण सेवाओं" का आशय है अंतरिक्ष के माध्यम से अथवा केबल के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिग्नलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार, जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना आशयित है, और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ माना जाएगा;
- (के) "केबल सेवा" अथवा "केबल टीवी सेवा" से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है ;
- (एल) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" अथवा "केबल टीवी नेटवर्क" से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;
- (एम) "कैरिज शुल्क" से आशय है, अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों का इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका में विशिष्ट स्थान का ब्योरा अथवा विशिष्ट चैनल संख्या का ब्योरा दिए बिना, टीवी चैनलों के वितरक के द्वारा संचालित प्लेटफार्म पर, उक्त प्रसारक के चैनल अथवा चैनलों के बुके (गुच्छों) के केवल कैरिज के लिए किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के वितरक को देय शुल्क;
- (एन) "अनुपालन अधिकारी" से आशय है, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नामजद कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के तहत अनुपालन के लिए आवश्यकताओं को समझने में सक्षम है;
- (ओ) "डॉयरेक्ट-टू-होम ऑपरेटर" अथवा "डीटीएच ऑपरेटर" से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;
- (पी) "डॉयरेक्ट-टू-होम सेवा" अथवा "डीटीएच सेवा" से आशय है उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके, बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबल आपरेटर अथवा टेलीविजन चैनलों के किसी अन्य वितरक, के सीधे सब्सक्राइबर के घर तक टेलीविजन के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण करना;
- (क्यू) "वितरण शुल्क" से आशय है, उपभोक्ताओं को, अपने पे टेलीविजन चैनल (चैनलों) या जनरल पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के वितरण के उद्देश्य के लिए टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक को किसी प्रसारक द्वारा भुगतानयोग्य कोई शुल्क और इसमें कैरिज शुल्क शामिल नहीं हैं;
- (आर) "डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म" से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर के वितरण नेटवर्क से है;
- (एस) "टेलीविजन चैनलों का वितरक" अथवा "वितरक" से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर से है;
- (टी) "इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका" अथवा "ईपीजी" से आशय टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा अनुरक्षित कार्यक्रम मार्गदर्शिका से है जिसमें टेलीविजन चैनलों तथा कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाता है और जिसमें कार्यक्रम और उनके समय निर्धारण संबंधी

जानकारी होती है तथा इसमें ऐसी और जानकारी वाली मार्गदर्शिका शामिल होती है जिसमें सब्सक्राइबर नेवीगेट कर ऐसे उपलब्ध चैनलों और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं;

- (यू) "फ्री-टु-एयर चैनल" अथवा "फ्री-टु-एयर टेलीविजन चैनल" से आशय ऐसे टेलीविजन चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है और जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा ऐसे चैनल के सिग्नल हेतु प्रसारक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है ;
- (वी) "हैड एंड इन द स्काई आपरेटर" अथवा "एचआईटीएस आपरेटर" से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा हैड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;
- (डब्ल्यू) "हैड एंड इन द स्काई सेवा" अथवा "एचआईटीएस सेवा" से आशय टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के पुनःप्रसारण सहित कार्यक्रमों के प्रसारण से है—
- (i) मध्यस्थों को जैसे केबल प्रचालक या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए और सब्सक्राइबरों को सीधे नहीं; और
  - (ii) उपग्रह प्रणाली तथा स्वयं का केबल नेटवर्क उपयोग कर सब्सक्राइबरों को ;
- (एक्स) "अंतःसंयोजन" से आशय है, ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी समझौते जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने उपस्कर और नेटवर्क संयोजित करते हैं;
- (वाई) "अंतःसंयोजन करार" इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और समझौतीय अभिव्यक्तियों के साथ इससे आशय है, ऐसे अंतःसंयोजन करार जिनमें टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के वितरण के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों का उपबंध किया गया है;
- (जेड) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आपरेटर" अथवा "आईपीटीवी आपरेटर" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा आईपीटीवी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;
- (एए) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा" अथवा "आईपीटीवी सेवा" से आशय है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोज्ड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके एड्रेसेबल पद्धति में मल्टी चैनल टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण करना;
- (बीबी) "स्थानीय केबल ऑपरेटर" अथवा "एलसीओ" से आशय, ऐसे व्यक्ति से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है;
- (सीसी) "अधिकतम खुदरा मूल्य" अथवा "एमआरपी" से इस विनियम के प्रयोजनार्थ आशय, कर के अलावा, ऐसे अधिकतम मूल्य से है जो किसी सब्सक्राइबर द्वारा अ-ला-कार्ट पे चैनल अथवा पे-चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए देय है;
- (डीडी) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर" अथवा "एमएसओ" से आशय किसी ऐसे ऑपरेटर से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और एक से अधिक सब्सक्राइबर को सीधे ही अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से, साथ-साथ प्राप्त करने के लिए, इन्हें पुनः संचारित करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को संचारित करता है;
- (ईई) "नेटवर्क क्षमता शुल्क" से आशय, कर के अलावा, उस राशि से है जो एक सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किए गए टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए वितरण नेटवर्क क्षमता हेतु टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय है तथा इसमें पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क शामिल नहीं है;
- (एफएफ) "पे प्रसारक" से आशय ऐसे प्रसारक से है, जिसने एक या एक से अधिक चैनलों को पे चैनल के रूप में, उपयुक्त विनियमों या टैरिफ आदेश के तहत, जैसा मामला हो, प्राधिकरण को घोषित किया है;
- (जीजी) "पे-चैनल" से आशय ऐसे चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है तथा जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को अधिकतम खुदरा मूल्य के हिस्से को भुगतान किया जाना होता है और जिसके लिए सब्सक्राइबरों तक ऐसे चैनलों के वितरण हेतु प्रसारक से विधिवत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है;
- (एचएच) "कार्यक्रम" से आशय किसी टेलीविजन प्रसारण से है तथा इसमें निम्नवत शामिल हैं:—
- (i) फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;
  - (ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण; और
- "कार्यक्रम सेवा" अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ समझा जाएगा;
- (आईआई) "क्यूओएस विनियम" से आशय है दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं – सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017;
- (जेजे) "संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव" अथवा "आरआईओ" का आशय एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज से है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिस पर अन्य सेवा प्रदाता ऐसे सेवा प्रदाता के साथ अंतःसंयोजन प्राप्त कर सकते हैं;

- (केके) “सेवा प्रदाता” से आशय सेवा प्रदाता के रूप में सरकार से है और जिसमें लाइसेंसधारी के साथ प्रसारक, टेलीविजन चैनलों के वितरक अथवा स्थानीय केबल ऑपरेटर भी शामिल हैं;
- (एलएल) “सेट टॉप बाक्स” अथवा “एस.टी.बी.” का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;
- (एमएम) “सब्सक्राइबर” से आशय इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइब की गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा;
- (एनएन) “सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली” से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके (गुच्छे), प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुक या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है;
- (ओओ) “टैरिफ आदेश” से आशय है दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रैसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017;
- (पीपी) “टेलीविजन चैनल” से आशय किसी चैनल से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत डाउनलिकिंग हेतु अनुमति प्रदान की जाती गई हो तथा “चैनल” शब्द का अभिप्राय “टेलीविजन चैनल” माना जाएगा।

(2) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया है।

## अध्याय II

### अंतःसंयोजन

**3. प्रसारकों के सामान्य दायित्व.**—(1) कोई भी प्रसारक, टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक के साथ अनन्य संविदाओं सहित किसी ऐसी पद्धति या क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा या कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, जो किसी अन्य टेलीविजन चैनलों के वितरक को ऐसे प्रसारक के टेलीविजन चैनल के वितरण हेतु सिग्नल प्राप्त करने से रोकते हों।

(2) प्रत्येक प्रसारक, टेलीविजन चैनल के सिग्नल प्राप्त करने के लिए टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक से प्राप्त लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर या वितरक के साथ अंतःसंयोजन करार करने के 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर वितरक को टेलीविजन चैनल के सिग्नल उपलब्ध कराएगा या अनुरोध अस्वीकार करने के कारण लिखित में संसूचित करेगा, यदि उस वितरक को टेलीविजन चैनल के सिग्नलों को देने से मना किया जाता है:

परंतु यह कि प्रसारक द्वारा कोई ऐसी शर्त या निबंधन, जो अतर्कसंगत है, लगाना अनुरोध से मना करना माना जाएगा:

पुनः परंतु यह कि यह उप-विनियम टेलीविजन चैनलों के किसी ऐसे वितरक के मामले में लागू नहीं होगा, जो किसी प्रसारक से किसी विशेष टेलीविजन चैनल के सिग्नल प्राप्त करने का इच्छुक हो साथ ही साथ, उस टेलीविजन चैनल के वितरण हेतु कैरिज शुल्क की मांग करता है या जो प्रसारक के प्रति भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है।

(3) यदि कोई प्रसारक सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु एक पूर्व-शर्त के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में किसी विशिष्ट स्थान पर चैनल (चैनलों) को स्थान देने हेतु या कोई विशेष चैनल नंबर देने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव देता है या शर्त रखता है तो इस प्रकार की पूर्व-शर्त भी अतर्कसंगत शर्त लगाने के रूप में मानी जाएगी।

*स्पष्टीकरण :* संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रसारक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में किसी विशिष्ट स्थान पर चैनल को स्थान देने के लिए या विशेष चैनल नंबर देने के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरकों को विनियम (7) के उप-विनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा के अंदर प्रस्ताव देता है तो छूट के इस प्रस्ताव को पूर्व-शर्त के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) कोई भी प्रसारक, उपभोक्ताओं को टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रस्तावित किसी विशेष गुच्छे में चैनल के पैकेजिंग हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं रखेगा या मांग नहीं करेगा।

(5) कोई भी प्रसारक टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक को टेलीविजन चैनल के सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु अपने चैनल या गुच्छे के लिए एक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत या एक न्यूनतम उपभोक्ता आधार की गारंटी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं रखेगा या मांग नहीं करेगा।

*स्पष्टीकरण :* संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी चैनल या गुच्छे का सब्सक्रिप्शन प्रतिशत किसी वितरक के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार में से किसी विशिष्ट चैनल या गुच्छे के प्रति सब्सक्रिप्शन करने वाले उपभोक्ताओं के प्रतिशत से संबंधित है।

4. **टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के सामान्य दायित्व** - (1) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक किसी ऐसी पद्धति या क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा या किसी प्रसारक के साथ अनन्य संविदाओं सहित कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, जो किसी अन्य प्रसारक को, चैनल के वितरण हेतु उस वितरक के नेटवर्क का एक्सेस प्राप्त करने से रोकता हो।

(2) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक किसी ऐसी पद्धति या क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा या किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ अनन्य संविदाओं सहित कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, जो आगे वितरण हेतु उस वितरक से टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने से किसी अन्य स्थानीय केबल ऑपरेटर को रोकता है।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक एक टारगेट मार्केट के रूप में प्रत्येक वितरण नेटवर्क का कवरेज एरिया घोषित करेगा,

परंतु यह कि किसी वितरक को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह एक टारगेट मार्केट के रूप में वितरण नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र के अंदर कोई क्षेत्र गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से घोषित कर सके।

*स्पष्टीकरण : इस विनियम के उद्देश्य के लिए प्रत्येक हेड-एंड या अर्थ स्टेशन, जैसा भी मामला हो, और टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया गया इसका संबद्ध नेटवर्क एक वितरण नेटवर्क माना जाएगा।*

(4) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक इन विनियमों के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर या अपने प्रचालनों के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रकाशित करेगा:

(ए) टारगेट मार्केट जैसा उप-विनियम (3) में घोषित किया गया है;

(बी) स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनलों की संख्या के हिसाब से अपने वितरण नेटवर्क की कुल चैनल ले जाने की क्षमता;

(सी) नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों की सूची;

(डी) उन चैनलों की संख्या, जिनके लिए प्रसारक से वितरक द्वारा टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों का अनुरोध किया गया है और अंतःसंयोजन करार किए गए हैं;

(ई) टेलीविज़न चैनल के सिगनलों को ले जाने के लिए नेटवर्क (नेटवर्कों) पर उपलब्ध अतिरिक्त चैनल क्षमता; और

(एफ) चैनलों की सूची जिसके लिए प्रसारक द्वारा नेटवर्क का एक्सेस उपलब्ध सिगनलों के वितरण हेतु अनुरोध किया गया है और अंतःसंयोजन करार किए गए हैं और जो अतिरिक्त चैनल क्षमता की अनुपलब्धता के कारण वितरण के लिए नेटवर्क का एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए लंबित हैं।

परंतु यह कि खंड (एफ) के अंतर्गत चैनलों की क्रमागत सूची प्रसारक से लिखित अनुरोध के दिनांक और समय की प्राप्ति के अनुसार बनाई जाएगी:

पुनः परंतु यह कि एक हाई डेफिनिशन चैनल, वितरण नेटवर्क की क्षमता परिकलित करने के उद्देश्य के लिए, दो स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनलों के बराबर होगी;

पुनः परंतु यह कि खंड (ई) के अंतर्गत नेटवर्क पर उपलब्ध हो रही अतिरिक्त चैनल क्षमता वितरण नेटवर्क की कुल चैनल ले जाने की क्षमता और नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों की सूची स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनलों की संख्या के हिसाब का अंतर होगी;

पुनः परंतु यह कि कोई भी परिवर्तन जो कि किसी चैनल ले जाने की क्षमता जुड़ने या घटने या चैनल के जुड़ने या किसी चैनल के हटने की वजह से हो वह उपलब्ध चैनल की क्षमता में दिखाई जाएगी;

पुनः परंतु यह कि इस उप-विनियम के अंतर्गत प्रकाशित सूचना में होने वाले किसी परिवर्तन को परिवर्तन होने की तारीख से 7 कैलेंडर दिवसों के अंदर वेबसाइट पर अद्यतनीकृत किया जाएगा।

(5) प्रत्येक वितरक नेटवर्क पर उपलब्ध अतिरिक्त चैनल क्षमता को क्रमानुसार बारी बारी से उपविनियम (4) के खंड (एफ) में बनी सूची में से टेलीविज़न चैनलों का प्रसारण करेगा।

(6) उप-विनियम (5) में संदर्भित लागू नहीं होगा यदि कोई लिखित अनुरोध चैनल के वितरण हेतु उप विनियम (4) के खंड (एफ) के अंतर्गत लंबित है,

(7) उप-विनियम (4) के अंतर्गत, वितरण नेटवर्क पर अतिरिक्त चैनल क्षमता की उपलब्धता होने पर टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण हेतु किसी प्रसारक से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर या प्रसारक के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार किए जाने के 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर उस टेलीविज़न चैनल के सिगनल चलाएगा या अनुरोध अस्वीकार करने की स्थिति में लिखित में कारण संसूचित करेगा, यदि टेलीविज़न चैनल के उन सिगनलों का वितरण के लिए, प्रसारक को मना कर दिया जाता है,

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा कोई ऐसी शर्त या निबंधन, जो अतर्कसंगत हैं, लगाने को अनुरोध से मना करना माना जाएगा;

पुनः परंतु यह भी कि इस उप-विनियम में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे प्रसारक पर लागू नहीं होगी, जो टेलीविज़न चैनलों के वितरक को कैरिज शुल्क का भुगतान करने से मना कर देता है या जो वितरक के प्रति भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है।

(8) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह किसी टेलीविज़न चैनल को चलाना बंद कर दे, यदि उस विशेष टेलीविज़न चैनल के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत एकदम पीछे के लगातार 6 महीनों में से प्रत्येक महीने में, अंतःसंयोजन करार में विनिर्दिष्ट टारगेट मार्केट में उस वितरक के मासिक सक्रिय उपभोक्ता आधार के 5 प्रतिशत से कम है,

परंतु यह कि हाई डेफिनिशन टेलीविज़न चैनल के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के परिकलन के उद्देश्य के लिए औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार, प्राप्तकर्ता हाई डेफिनिशन टेलीविज़न चैनलों के सक्षम उपभोक्ताओं का औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार होगा।

(9) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को ऐसा चैनल चलाने का, चैनल बंद किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, दायित्व नहीं होगा, जिसे उप-विनियम (8) के अनुसार बंद कर दिया गया है।

(10) यदि कोई टेलीविज़न चैनलों का वितरक, टेलीविज़न चैनल के वितरण हेतु नेटवर्क का एक्सेस उपलब्ध कराने से पहले न्यूनतम अवधि की गारंटी के लिए या न्यूनतम चैनल की संख्या की गारंटी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रस्ताव पूर्व शर्त के रूप में रखता है तो इस प्रकार की पूर्व-शर्त भी अतर्कसंगत शर्त लगाने के रूप में मानी जाएगी।

(11) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर या स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार करने से 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराएगा या अनुरोध अस्वीकार करने के लिए लिखित में कारण संसूचित करेगा, यदि उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को सिगनल देने से मना किया गया है,

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा कोई ऐसी शर्त या निबंधन, जो अतर्कसंगत है, को अनुरोध से मना करना माना जाएगा;

पुनः परंतु यह कि यदि किसी ऐसे स्थान पर, जहां स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा सिगनलों का अनुरोध किया गया है, टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है, तो टेलीविज़न चैनलों का वितरक अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर स्थानीय केबल ऑपरेटर को सूचित करेगा, जिसमें ये कारण दर्शाए जाएंगे कि उस स्थान पर टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराना क्यों व्यवहार्य नहीं है;

पुनः परंतु यह कि यह उप-विनियम किसी ऐसे स्थानीय केबल ऑपरेटर के मामले में लागू नहीं होगा, जो टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है;

पुनः परंतु यह भी कि किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर को किसी वितरक के प्रति भुगतान का चूककर्ता नहीं माना जाएगा, यदि उसने पिछले लगातार छः महीने की देय धनराशियों का भुगतान कर दिया है।

(12) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए किसी न्यूनतम उपभोक्ता आधार की गारंटी या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की गारंटी के लिए प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं लगाएगा या मांग नहीं करेगा।

(13) इस विनियम के उप-विनियम (11) और उप-विनियम (12) में दी गई कोई भी बात किसी डीटीएच ऑपरेटर पर लागू नहीं होगी।

**5. सेवा प्रदाताओं के सामान्य दायित्व.—**(1) कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता को या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसा भी मामला हो, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने से अन्य सेवा प्रदाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं रोकेगा।

(2) कोई भी सेवा प्रदाता टेलीविज़न चैनलों के सिगनल या नेटवर्क, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवा प्रदाता द्वारा किसी न्यूनतम गारंटी धनराशि के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं रखेगा या मांग नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता दूसरे सेवा प्रदाता को, जिससे उसने अंतःसंयोजन करार किया है, भुगतान सग्रह के लिए, मासिक इनवॉयस जारी करेगा और उस इनवॉयस में, भुगतान की नियत तारीख के साथ-साथ वर्तमान भुगतान की देय धनराशियां और बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(4) इस विनियम के अंतर्गत, सेवा प्रदाता द्वारा किए गए बकाया धनराशियों के किसी दावे के साथ, उस अवधि, जिनसे बकाया धनराशियां संबंधित हैं, के इनवॉयस की सेवा का प्रमाण भेजा जाएगा।

### अध्याय III

#### संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव

**6. अ-ला-कार्टे आधार पर चैनलों का अनिवार्य रूप से प्रस्ताव देना.—**(1) प्रत्येक प्रसारक, टेलीविज़न चैनलों के सभी वितरकों को अ-ला-कार्टे आधार पर अपने सभी टेलीविज़न चैनलों का प्रस्ताव देगा।

परंतु यह भी कि प्रसारक पे चैनलों को गुच्छे के रूप में भी, अ-ला-कार्टे आधार पर पे चैनलों का प्रस्ताव देने के अतिरिक्त, भी दे सकता है।

परंतु यह कि इस गुच्छे में निम्नलिखित नहीं होंगे:

(क) कोई "फ्री टू एयर चैनल"; और

(ख) उसी चैनल के हाई डेफिनिशन (एचडी) तथा स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) प्रारूप रूप।

7. **पे टेलीविज़न चैनलों के लिए प्रसारक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन** — (1) प्रत्येक प्रसारक अपनी वेबसाइट पर, टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को अपने सभी पे टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का मसौदा,

(क) इन विनियमों के प्रारंभ के 60 दिन के अंदर; और

(ख) पे टेलीविज़न चैनल आरंभ किए जाने से पहले,

प्रकाशित करेगा और साथ ही साथ, प्राधिकरण को इसकी एक प्रति रिकार्ड के उद्देश्य के लिए जमा कराएगा।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को पे टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए इस संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के मसौदे में पे टेलीविज़न चैनलों के प्रति मास अधिकतम खुदरा मूल्य, पे चैनलों के गुच्छे का प्रति मास अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रस्तावित छूटों, यदि कोई हो, वितरण शुल्क, अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक के हिस्से के परिकलन के तरीके, जेनरे और अन्य आवश्यक शर्तें देगा, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:

परंतु यह कि कोई प्रसारक अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में अपनी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसने अपने नाम में उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किए जाने के पश्चात वेंद्र सरकार से अपने टेलीविज़न चैनलों के लिए डाउनलिकिंग अनुमति प्राप्त कर ली है, के भुगतान टेलीविज़न चैनलों के गुच्छा या टेलीविज़न चैनल शामिल कर सकता है।

*स्पष्टीकरण :* इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए "सहायक कंपनी" और ("होल्डिंग कंपनी") की परिभाषा वही होगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में इन्हें दी गई है।

(3) प्रत्येक प्रसारक पे टेलीविज़न चैनल या पे चैनलों के गुच्छे के अधिकतम खुदरा मूल्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत वितरण शुल्क के रूप में घोषित करेगा,

परंतु यह कि प्रसारक द्वारा घोषित वितरण शुल्क सभी वितरण प्लेटफार्म के लिए एकसमान होगा।

(4) किसी प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह टेलीविज़न चैनलों के वितरकों को पे टेलीविज़न चैनल या पे चैनलों के गुच्छे के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट का प्रस्ताव दे सके, जो संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,

परंतु यह कि उप-विनियम (3) के अंतर्गत और इस उप-विनियम के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा प्रस्तावित छूट और घोषित वितरण शुल्क की रकम किसी भी स्थिति में पे टेलीविज़न चैनल या पे चैनलों के गुच्छे, जैसा भी मामला हो, के अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के वितरकों को छूट, यदि कोई है, का प्रस्ताव उचित, पारदर्शी और गैर-पक्षपातपूर्ण शर्तों के आधार पर होगा;

पुनः परंतु यह कि छूटों के मापदंड मापनयोग्य और परिकलनयोग्य होंगे।

(5) पे चैनलों का प्रत्येक प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरकों से अंतःसंयोजन अनुरोध और उनकी शिकायतों का निवारण करने, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में नामजद किए गए व्यक्तियों के नाम, टेलीफोन नंबर और ई-मेल का पत्तों का उल्लेख करेगा।

(6) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों में ऐसे सभी आवश्यक और पर्याप्त उपबंध शामिल होंगे, जो इसे टेलीविज़न चैनल के वितरण हेतु अन्य पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक पूरा अंतःसंयोजन करार बनाता है।

(7) प्राधिकरण स्व-प्रेरणा से या अन्य कारणों से किसी प्रसारक द्वारा प्रस्तुत किए गए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की जांच कर सकता है और जांच किए जाने पर यदि प्राधिकरण की यह राय है कि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है तो वह उस प्रसारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस प्रसारक को निर्देश दे सकता है कि वह उक्त संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करे और वह प्रसारक तदनुसार संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करेगा और निर्देश की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर इसे प्रकाशित करेगा,

(8) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में किया जाने वाला कोई संशोधन उसी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, जो तरीका इस विनियम के उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6) के अंतर्गत उपबंधित है।

(9) उप-विनियम (8) के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कोई संशोधन किए जाने की स्थिति में प्रसारक उन सभी वितरकों, जिनके साथ मौजूदा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर लिखित अंतःसंयोजन करार मौजूद हैं, को उस संशोधन की तारीख से 30 दिन के अंदर एक विकल्प देगा और वितरकों के पास यह विकल्प होगा कि वे उस विकल्प की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर, संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार नया अंतःसंयोजन करार कर सकें या मौजूदा अंतःसंयोजन करार को बनाए रखें।

8. **टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन**—(1) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का मसौदा अपनी वेबसाइट पर,

(क) इन विनियमों के प्रारंभ के 60 दिन के अंदर; और

(ख) नया वितरण नेटवर्क आरंभ करने से पहले,

प्रकाशित करेगा और साथ ही साथ, प्राधिकरण को इसकी एक प्रति रिकार्ड के उद्देश्य के लिए जमा कराएगा।

परंतु यह कि यह संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा, जहां कोई प्रसारक, वितरण नेटवर्क पर प्रसारक के चैनल चलाने हेतु टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक से अनुरोध करता है।

(2) टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए इस संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के मसौदे में टारगेट मार्केट, प्रति मास कैरिज की दर, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के मसौदे के प्रकाशन के समय स्टैंडर्ड डेफिनिशन सेट ऑप बॉक्स और हाई डेफिनिशन सेट टॉप बॉक्सेज का औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार, कैरिज शुल्क की दर पर प्रस्तावित छूट, यदि कोई हो, कैरिज शुल्क की धनराशि के परिकलन का तरीका, और अन्य आवश्यक शर्तें दिए जाएंगे, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है,

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा घोषित किया जाने वाला प्रति उपभोक्ता प्रति मास, प्रति स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनल कैरिज शुल्क की दर 20 पैसे से अधिक नहीं होगी;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा घोषित किया जाने वाले प्रति उपभोक्ता प्रति मास प्रति हाई डेफिनिशन चैनल कैरिज शुल्क की दर 40 पैसे से अधिक नहीं होगी;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का कोई वितरक, टेलीविज़न चैनलों के लिए कैरिज शुल्क की धनराशि का परिकलन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार करेगा, जिसमें उन टेलीविज़न चैनल के मासिक सब्सक्राइबर संख्या में परिवर्तनों के साथ परिवर्तन होगा।

(3) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह कैरिज शुल्क की दर पर प्रसारकों को छूट का प्रस्ताव दे सके, जो उप-विनियम (2) के अंतर्गत घोषित कैरिज शुल्क की दर के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

परंतु यह कि कैरिज शुल्क पर प्रसारक को छूटों, यदि कोई हैं, का प्रस्ताव उचित, पारदर्शी और गैर-पक्षपातपूर्ण शर्तों के आधार पर होगा;

पुनः परंतु यह कि छूटों के मापदंड मापनयोग्य और परिकलनयोग्य होंगे;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह लोक हित में एक निर्देश के जरिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट चैनल (चैनलों) के लिए उप-विनियम (2) के अंतर्गत घोषित कैरिज शुल्क की दर के 35 प्रतिशत से अधिक छूट का प्रस्ताव दे सके।

(4) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक प्रसारकों से अंतःसंयोजन अनुरोध और उनकी शिकायतों का निवारण करने, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में नामजद किए गए व्यक्तियों के नाम, टेलीफोन नंबर और ई-मेल का पता का उल्लेख करेगा।

(5) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों में ऐसे सभी आवश्यक और पर्याप्त उपबंध शामिल होंगे, जो इसे टेलीविज़न चैनल को चलाने हेतु अन्य पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक पूरा अंतःसंयोजन करार बनाता है।

(6) प्राधिकरण स्व-प्रेरणा से या अन्य कारणों से किसी वितरक द्वारा प्रस्तुत किए गए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की जांच कर सकता है और जांच किए जाने पर यदि प्राधिकरण की यह राय है कि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है तो वह उस वितरक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस वितरक को निर्देश दे सकता है कि वह उक्त संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करे और वह वितरक तदनुसार संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करेगा और निर्देश की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर इसे प्रकाशित करेगा।

(7) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में किया जाने वाला कोई संशोधन उसी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, जो तरीका इस विनियम के उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) के अंतर्गत उपबंधित है।

(8) उप-विनियम (7) के अंतर्गत टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कोई संशोधन किए जाने की स्थिति में वितरक उन सभी प्रसारकों, जिनके साथ मौजूदा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर लिखित अंतःसंयोजन करार मौजूद हैं, को उस संशोधन की तारीख से 30 दिन के अंदर एक विकल्प देगा और उन प्रसारकों के पास यह विकल्प होगा कि वे उस विकल्प की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर, संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार नया अंतःसंयोजन करार कर सकें या मौजूदा अंतःसंयोजन करार को बनाए रखें।

#### अध्याय IV

##### अंतः संयोजन करार

9. अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सामान्य उपबंध.—(1) सभी सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने सभी अंतःसंयोजन करारों की शर्तों और निबंधनों को लिखित में लाएं।

(2) कोई भी सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता के साथ किसी अंतःसंयोजन करार में किसी ऐसे प्रावधान सम्मिलित नहीं करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य सेवा प्रदाता के लिए न्यूनतम गारंटीकृत धनराशि का भुगतान करने को आवश्यक बनाए।

(3) सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इन विनियमों के प्रारंभ के 150 दिनों के भीतर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप अपने सभी मौजूदा अंतःसंयोजन करारों का या तो नवीकरण करें या उन्हें संशोधित करें।

10. प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों के वितरक के बीच अंतःसंयोजन करार.—(1) कोई भी प्रसारक, टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को, टेलीविज़न चैनलों के उस वितरक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना पे टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा।

(2) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक किसी प्रसारक के साथ कोई लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना किसी प्रसारक के पे टेलीविज़न चैनलों के सिगनल पुनः प्रसारित नहीं करेगा।



(3) टेलीविज़न चैनलों के किसी प्रसारक और किसी वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पे चैनलों के वितरण के लिए अ-ला-कार्टे आधार पर लिखित अंतःसंयोजन करार करे।

(4) प्रत्येक प्रसारक अनुसूची 2 के अनुसार टेलीविज़न चैनलों के वितरकों द्वारा टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के अनुरोध के लिए एक आवेदनपत्र तैयार करेगा।

(5) टेलीविज़न चैनल के सिगनल प्राप्त करने का इच्छुक टेलीविज़न चैनलों का कोई वितरक उस टेलीविज़न चैनल के प्रसारक द्वारा तैयार आवेदन फार्म पर एक लिखित अनुरोध करेगा।

(6) किसी प्रसारक से टेलीविज़न चैनल के सिगनलों का अनुरोध करने से पहले टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि टेलीविज़न चैनलों के वितरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एड्रेसेबल प्रणालियां अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करती हैं।

(7) टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने से पहले यदि किसी प्रसारक की यह राय है कि टेलीविज़न चैनलों के वितरण के लिए वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणालियां अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती, तो विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निर्धारित समय-सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रसारक मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड या ऐसा अंकेक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा चैनल में रखे गए किसी अन्य अंकेक्षक द्वारा वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों का अंकेक्षण कराएगा और वितरक को, अंकेक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा।

परंतु यह कि जब तक वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों की आकृति या रूपांतर में अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट के जारी किए जाने के पश्चात परिवर्तन न कर दिया गया हो, टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराने से पहले प्रसारक वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों का अंकेक्षण नहीं कराएगा, यदि उस वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों का अंकेक्षण पिछले एक वर्ष के दौरान मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड या प्राधिकरण द्वारा चैनल में रखे गए किसी अन्य अंकेक्षक द्वारा किया गया है और वितरक अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों की अनुरूपता के प्रमाण के रूप में अंकेक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(8) पे टेलीविज़न चैनल का प्रत्येक प्रसारक, टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपने पे टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा:

परंतु यह कि अंतःसंयोजन करार के अंतर्गत "अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी" का परिकलन अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरण शुल्क और अंतःसंयोजन करार में सहमति वाली छूटों के आधार पर किया जाएगा;

पुनः परंतु यह कि अंतःसंयोजन करार की अवधि किसी भी मामले में, करार के प्रारंभण की तारीख से एक वर्ष से कम नहीं होगी;

पुनः परंतु यह भी कि यदि पे चैनलों के टेलीविज़न चैनल या गुच्छे के संबंध में टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ एक से अधिक अंतःसंयोजन करार किए गए हैं, तो प्रत्येक उत्तरवर्ती अंतःसंयोजन करार में उस चैनल या गुच्छे के लिए उस वितरक के साथ लागू पिछले करारों के ब्यारे दिए जाएंगे।

*स्पष्टीकरण :* कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए किसी प्रसारक द्वारा किसी वितरक से कोई लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर प्रसारक और वितरक के बीच लिखित अंतःसंयोजन करार उस अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। इसके पश्चात, प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरक को, लिखित अंतःसंयोजन करार किए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने पे टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराएगा।

(9) कोई प्रसारक अपनी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसने अपने नाम में, उन कंपनियों से लिखित प्राधिकार के पश्चात वेंद सरकार से अपने टेलीविज़न चैनलों की डाउनलिकिंग अनुमति प्राप्त कर ली है, के पे चैनलों के अ-ला-कार्टे पे टेलीविज़न चैनल या गुच्छे के लिए टेलीविज़न चैनल के वितरकों के साथ अंतःसंयोजन करार कर सकता है।

(10) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए एक अंतःसंयोजन करार के रूप में, विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा प्रकाशित अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकता है और सिगनल उपलब्ध कराने के लिए उस प्रसारक को उक्त करार भेज सकता है।

(11) कोई भी प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ किए गए अंतःसंयोजन करार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे प्रावधान का समायोजन नहीं करेगा, जो उपभोक्ताओं को उस वितरक द्वारा प्रदान किए गए चैनलों के किसी विशेष गुच्छे में प्रसारक द्वारा प्रदान किए गए चैनल या पे चैनलों के गुच्छे शामिल करने को टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए आवश्यक बना दें और ऐसा प्रतिकूल अनुबंध निरस्त होगा।

(12) कोई भी प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ किए जाने वाले किसी अंतःसंयोजन करार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे प्रावधान का समायोजन नहीं करेगा, जो उस प्रसारक के चैनल के लिए कोई न्यूनतम उपभोक्ता आधार या किसी न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के लिए गारंटी देना टेलीविज़न चैनलों के लिए उस वितरक के लिए आवश्यक बना दे ऐसा प्रतिकूल अनुबंध निरस्त होगा।

*स्पष्टीकरण :* कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी महीने में दर्ज की गई उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या या वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत पर आधारित पे चैनल या पे चैनलों के गुच्छे के अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसी प्रसारक द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई किसी छूट को अपने चैनल के लिए कोई न्यूनतम उपभोक्ता आधार या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के लिए गारंटी नहीं माना जाएगा।

(13) ऐसे प्रत्येक प्रसारक, जो टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ कोई अंतःसंयोजन करार करते हैं, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अंतःसंयोजन करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर टेलीविज़न चैनलों के उस वितरक को उस अंतःसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और वितरक से प्राप्त की गई अभिस्वीकृति की एक प्रति रखे।

(14) प्रत्येक प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि बीत जाने से पहले टेलीविज़न चैनलों के वितरक के साथ एक नया लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरक को नोटिस देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि समाप्त होने से पहले नया अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं, तो प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर टेलीविज़न चैनलों के वितरक को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा;

परंतु यह यह भी कि टेलीविज़न चैनलों का वितरक, अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिन पहले, उन चैनलों पर जो अंतःसंयोजन करार में शामिल हैं, स्करोल के जरिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचित करेगा:

(क) उसके अपने मौजूदा अंतःसंयोजन की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में अपनी विफलता की स्थिति में चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख की सूचना।

(15) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक प्रसारक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना कोई ऐसा टेलीविज़न चैनल नहीं चलाएगा, जिसके लिए टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण हेतु किसी प्रसारक से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(16) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, अनुसूची 4 के अनुसार प्रसारकों द्वारा टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के पुनः प्रसारण हेतु वितरण नेटवर्क पर एक्सेस का अनुरोध करने के लिए एक आवेदन फार्म तैयार करेगा।

(17) अपने टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण का इच्छुक कोई प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा तैयार किए गए आवेदन फार्म पर एक लिखित अनुरोध करेगा।

(18) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, टेलीविज़न चैनलों के वितरण हेतु किसी प्रसारक से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर वितरक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतः संयोजन प्रस्ताव की शर्तों और निबंधनों के अनुसार टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए प्रसारक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि अंतःसंयोजन करार के अंतर्गत टेलीविज़न चैनलों के वितरक को किसी प्रसारक द्वारा भुगतान योग्य कैरिज शुल्क का परिकलन कैरिज शुल्क की दर और अंतःसंयोजन करार में सहमति वाली छूटों के आधार पर किया जाएगा;

पुनः परंतु यह कि किसी भी मामले में अंतःसंयोजन करार की अवधि, करार के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष से कम नहीं होगी;

परंतु यह यह भी कि यदि किसी टेलीविज़न चैनल के संबंध में किसी प्रसारक के साथ एक से अधिक अंतःसंयोजन करार किए गए हैं तो उत्तरवर्ती प्रत्येक अंतःसंयोजन करार में उस चैनल के लिए उस प्रसारक के साथ लागू पिछले करारों के ब्योरे दिए जाएंगे।

*स्पष्टीकरण :* कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए किसी वितरक द्वारा किसी प्रसारक से एक लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर वितरक और प्रसारक के बीच लिखित अंतःसंयोजन करार, अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर किया जाएगा। इसलिए, वितरक लिखित अंतःसंयोजन करार किए जाने की तारीख या वितरण नेटवर्क पर अतिरिक्त चैनल क्षमता की उपलब्धता की तारीख, इनमें जो भी बाद में, से वितरण नेटवर्क के जरिए 30 दिन के अंदर उस प्रसारक के टेलीविज़न चैनल (चैनलों) के सिगनल वितरित प्रसारित करेगा।

(19) किसी प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए एक अंतःसंयोजन करार के रूप में विनियम 8 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा प्रकाशित अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे और वितरण नेटवर्क में एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए उस वितरक को उक्त करार भेजे।

(20) टेलीविज़न चैनल के प्रत्येक ऐसे वितरक, जो किसी प्रसारक के साथ अंतःसंयोजन करार करता है, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अंतःसंयोजन करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर उस प्रसारक को लिखित अंतःसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और प्रसारक से इस प्रकार प्राप्त की गई अभिस्वीकृति की एक प्रति रखे।

(21) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले किसी प्रसारक द्वारा अनुरोध किए गए टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए एक नया लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का वितरक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले, नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए प्रसारक को नोटिस देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले नया अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं तो मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर टेलीविज़न चैनलों का वितरक संभवतः उन टेलीविज़न चैनलों को न चलाए;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का कोई वितरक किसी टेलीविज़न चैनल को चलाना बंद नहीं करेगा, यदि उस टेलीविज़न चैनल के सिगनल वितरण हेतु उपलब्ध रहते हैं और उस विशेष टेलीविज़न चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन, टारगेट मार्केट में औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के 20 प्रतिशत से अधिक है;

परंतु यह यह भी कि यदि टेलीविज़न चैनलों का वितरक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति के कारण कोई टेलीविज़न चैनल चलाना बंद करने का निर्णय लेता है तो वह अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से 15 दिन पहले, उन चैनलों पर जो अंतःसंयोजन करार में शामिल हैं, स्करोल के जरिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचित करेगा:

(क) अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में अपनी विफलता की स्थिति में चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख की सूचना।

**11. अंतःसंयोजन करार का क्षेत्र** — (1) किसी प्रसारक और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के बीच किए गए अंतःसंयोजन करार में, टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण के उद्देश्य के लिए क्षेत्र विनिर्धारित करने हेतु निम्नलिखित ब्योरे शामिल होंगे:

(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण में यथा उल्लिखित मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के प्रचालन का पंजीकृत क्षेत्र;

(ख) उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम, जिनके लिए टेलीविज़न चैनल (चैनलों) के सिगनलों के वितरण पर अंतःसंयोजन करार करने के समय मूलतः सहमति की गई थी; और

(ग) तदनुसूची राज्य (राज्यों)/ संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम, जिनमें इस उप-विनियम के खंड (ख) में यथाउल्लिखित इस प्रकार सहमति वाले क्षेत्र स्थित हैं।

(2) किसी मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को यह विकल्प होगा कि वह उस/उन चैनल (चैनलों) के प्रसारक को पूर्व-लिखित नोटिस देकर उप-विनियम (1) के अंतर्गत सहमति वाले क्षेत्रों के पार, प्रसारक द्वारा ऐसी नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के बाद, चैनल वितरित कर सके, और ऐसी नोटिस को मौजूदा अंतःसंयोजन करार का भाग माना जाएगा:

परंतु यह कि विस्तारण के ये क्षेत्र निम्नलिखित के अंदर पड़ते हों:

(क) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के प्रचालन के पंजीकृत क्षेत्र के अंदर; और

(ख) राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों जिसमें मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को अंतःसंयोजन करार के अंतर्गत सिग्नल को वितरित करने की अनुमति प्राप्त है।

(3) **उपविनियम (2)** में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि प्रसारक ने लिखित आपत्ति, कारणों सहित उन 30 दिनों के भीतर मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को दिया है:

परंतु यह कि प्रसारक की कोई ऐसी आपत्ति जो कि अनुचित हो वह सिग्नल का प्रावधान, क्षेत्रों के पार, उपविनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत, करने को मना किया जाना माना जाएगा

**12. टेलीविज़न चैनलों के वितरक और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच अंतःसंयोजन करार**—(1) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनल के सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएगा।

(2) कोई भी स्थानीय केबल ऑपरेटर टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना किसी उपभोक्ता को किसी प्रसारक के टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल वितरित नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उक्त करार के खंड 10, 11 और 12 पर परस्पर सहमति करके अनुसूची 5 में उल्लिखित मॉडल अंतःसंयोजन करार के अनुरूप टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर, मॉडल अंतःसंयोजन करार के किसी खंड में परिवर्तन किए बिना और उनका विलोप किए बिना परस्पर करार के जरिए मॉडल अंतःसंयोजन करार में अभिवर्धन कर सकते हैं। तथापि, इस प्रकार के अभिवर्धन का मॉडल अंतःसंयोजन करार में यथा विनिर्धारित खंडों में से किसी खंड पर अल्पीकरण प्रभाव नहीं होगा;

पुनः परंतु यह कि यदि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर इस उप-विनियम में ऊपर यथा उपबध्दित अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं तो मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर अनुसूची 6 में यथाविनिर्दिष्ट मानक अंतःसंयोजन करार करेंगे।

**स्पष्टीकरण :** संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विनिर्धारित मॉडल अंतःसंयोजन करार की शर्तों और निबंधनों तथा पक्षकारों द्वारा परस्पर करार के जरिए जोड़ी गई शर्तों और निबंधनों के बीच किसी विरोध की स्थिति में विनिर्धारित मॉडल अंतःसंयोजन करार की शर्तों और निबंधन अभिभावी होंगे।

(4) किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार कर लेने पर प्रत्येक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को लिखित अंतःसंयोजन करार करने के 30 दिन के अंदर टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा।

(5) प्रत्येक ऐसे मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर, जो किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ कोई अंतःसंयोजन करार करता है, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को उस करार की एक प्रति सौंपे और स्थानीय केबल ऑपरेटर से प्राप्त अभिसवीकृति की प्रति रखे।

(6) प्रत्येक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर, मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ एक नया लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर को नोटिस देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं, तो वितरक, मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा;

परंतु यह यह भी कि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से 15 दिन पहले, उन चैनलों पर जो अंतःसंयोजन करार में शामिल हैं, स्करोल के जरिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचित करेगा:

(क) अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में अपनी विफलता की स्थिति में चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख की सूचना

(7) स्थानीय केबल ऑपरेटर और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के बीच सेवा प्रभारों का निर्धारण, परस्पर करार द्वारा किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर सहमति पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो अभिदत्त विवरण क्षमता के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क तथा वितरण शुल्क की धनराशि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में बांटी जाएगी।

(8) इस विनियम के उप-विनियमों (3), (4), (5), (6) और (7) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ एचआईटीएस ऑपरेटर और आईपीटीवी ऑपरेटर पर लागू होंगे।

13. **डीटीएच ऑपरेटर पर अननुप्रयोज्यता.**—विनियम 11 और 12 में दी गई कोई भी बात किसी डीटीएच ऑपरेटर पर लागू नहीं होगी।

## अध्याय V

### सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट और अंकेक्षण

14. **सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट और मासिक शुल्क.**—(1) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, उन प्रसारकों, जिनके साथ चैनलों के वितरण के लिए लिखित अंतःसंयोजन करार किए गए हैं, को प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति से सात दिन के अंदर अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट पर चैनल और पे चैनलों के गुच्छे की पूर्ण और सही मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

परंतु यह कि किसी प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह, वितरक को तीन सप्ताह का पूर्व-लिखित नोटिस देने के पश्चात टेलीविज़न चैनल के सिगनल विसंयोजित कर सके, यदि वितरक इस विनियम के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विफल रहता है;

(2) मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के आधार पर, प्रसारक, ऐसे वितरक द्वारा भुगतानयोग्य अधिकतम खुदरा मूल्य के प्रसारक के हिस्से के लिए वितरक को मासिक इनवॉयस जारी करेगा और उस इनवॉयस में, भुगतान की नियत तारीख के साथ-साथ वर्तमान भुगतान की देय धनराशियां और बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा,

परंतु यह कि प्रसारक, वितरक द्वारा इनवॉयस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान करने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरक को कम से कम 15 दिन की समय अवधि की अनुमति देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि वितरक, कैलेंडर मास की समाप्ति से सात दिन की अवधि के अंदर मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो प्रसारक को यह अधिकार होगा कि वह तुरंत पिछले महीने के लिए वितरक द्वारा भुगतानयोग्य सब्सक्रिप्शन शुल्क के प्रसारक के सब्सक्रिप्शन के दस प्रतिशत तक बढ़ाई गई धनराशि के लिए कोई अनंतिम इनवॉयस जारी कर सके एवं वितरक का यह दायित्व होगा कि वह इस अनंतिम इनवॉयस के आधार पर भुगतान करे;

परंतु यह यह भी कि प्रसारक और वितरक के लिए अनिवार्य होगा कि वे ऐसे अनंतिम इनवॉयस के जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के अंदर, वितरक द्वारा भेजी गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के आधार पर प्रसारक द्वारा किए गए अनंतिम इनवॉयस और अंतिम इनवॉयस के बीच मेल-मिलाप करें।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, उन प्रसारकों, जिनके साथ टारगेट मार्केट में औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के साथ-साथ प्रसारक द्वारा भुगतान योग्य कैरिज शुल्क धनराशि के भुगतान के लिए, चैनल चलाने हेतु किए गए लिखित अंतःसंयोजन करार किए गए हैं, को मासिक इनवॉयस और टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा चलाए गए चैनल के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट पर जारी करेगा और ऐसे इनवॉयस में, भुगतान की नियत तारीख के साथ-साथ वर्तमान भुगतान की देय धनराशियों और बकाया धनराशियों, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा,

परंतु यह कि वितरक, प्रसारक द्वारा इनवॉयस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान करने के लिए प्रसारक को कम से कम 15 दिन की समय अवधि की अनुमति देगा;

15. **अंकेक्षण.**—(1) प्रत्येक टेलीविज़न चैनलों का वितरक, यह सत्यापित करने के लिए कि वितरक द्वारा प्रसारक को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं, एक कैलेंडर वर्ष में एक बार किसी अंकेक्षक से अपनी उपभोक्ता प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण कराएगा और इस संबंध में उस प्रत्येक प्रसारक को एक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करेगा, जिनके साथ उसने अंतःसंयोजन करार किया है,

परंतु यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविज़न चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप-विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण के कारण कोई भिन्नता, जिसके परिणामस्वरूप, बिल में दी गई धनराशि के 0.5 प्रतिशत से कम हो, में, पहले ही जारी कर दिए गए भुगतान कर दिए गए इनवॉयसों का कोई संशोधन आवश्यक नहीं होगा।

(2) ऐसे मामलों में, जहां कोई प्रसारक उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है या किसी प्रसारक की राय में, वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं कर करती तो वितरक को लिखित में असंतुष्टि के कारण संसूचित करने के पश्चात वह प्रसारक, अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में एक बार टेलीविज़न चैनलों के वितरक की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण करेगा,

परंतु यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविज़न चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप-विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि प्रसारक को अतिरिक्त धनराशि भुगतान योग्य है तो वितरक 10 दिन के अंदर, अंतःसंयोजन करार से प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर विलंबित भुगतान संबंधी ब्याज के साथ-साथ उन धनराशियों का भुगतान करेगा और यदि किसी अवधि के लिए देय ब्याज सहित वह धनराशि, उस अवधि के लिए देय होने के लिए, वितरक द्वारा सूचित धनराशि से 2 प्रतिशत अधिक या इससे अधिक हो जाती है तो वितरक अंकेक्षण व्यय वहन करेगा और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

पुनः परंतु यह कि प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह वितरक को तीन सप्ताह का पूर्व-नोटिस देने के पश्चात टेलीविज़न चैनल के सिगनल विसंयोजित कर सके, यदि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, अंकेक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि अंकेक्षण कार्य एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

## अध्याय VI

### विविध

**16. अधिकतम खुदरा मूल्य और किसी चैनल के स्वरूप में परिवर्तन** — पे चैनल या पे चैनलों के गुच्छे, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेश के अंतर्गत घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य में या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करने से पहले प्रत्येक प्रसारक, इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा, जिनमें पे चैनलों के प्रसारकों द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन से संबंधित उपबंध शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

**17. टेलीविज़न चैनल के सिगनलों का विसंयोजन** — कोई भी सेवा प्रदाता, अन्य सेवा प्रदाता को लिखित में कम से कम तीन सप्ताह का ऐसा नोटिस दिए बिना, टेलीविज़न चैनल के सिगनल विसंयोजित नहीं करेगा, जिसमें प्रस्तावित विसंयोजन के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो:

परंतु यह कि तीन सप्ताह के नोटिस की अवधि, अन्य सेवा प्रदाता द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से आरंभ होगी:

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का वितरक, विसंयोजन की तारीख से 15 दिन पहले, उन टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख के संबंध में उन चैनलों पर जिनका विसंयोजन प्रस्तावित है, स्कॉल के जरिए उपभोक्ता को सूचित करेगा:

परंतु यह भी कि कोई भी सेवा प्रदाता, टेलीविज़न स्क्रीन पर लगाए जाने वाले स्थिर चित्र के रूप में, टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन के लिए ऐसा नोटिस प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से देखने में बाधा उत्पन्न हो।

**18. इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों का सूचीकरण** — (1) प्रत्येक प्रसारक अपने चैनलों का जेनरे निर्धारित करेगा जो कि या तो भक्ति या सामान्य मनोरंजन या सूचना मनोरंजन या किड्स या मूविज या संगीत या न्यूज एवं समसामयिक या खेल या विविध में से एक होगा।

(2) वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों को ऐसे तरीके से स्थान दे कि प्रसारक द्वारा घोषित उसी प्रकार के जेनरे के टेलीविज़न चैनल लगातार एक साथ रखे जाएं और एक चैनल केवल एक स्थान पर दिखाई दे,

परंतु यह कि उसी प्रकार के अंदर उसी भाषा के सभी टेलीविज़न चैनल इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में एकसाथ लगातार दिखाई देंगे।

परंतु वितरक प्रसारक के द्वारा निर्धारित किये गए जेनरे के अंतर्गत उप-जेनरे के अंतर्गत रख सकता है।

(3) प्रत्येक वितरक के लिए यह आवश्यक होगा कि टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के लिए एक अनन्य चैनल नंबर देगा।

(4) किसी विशेष टेलीविज़न चैनल को एक बार दिया गया चैनल नंबर, नंबर दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक वितरक द्वारा नहीं बदला जाएगा।

परंतु यह कि यह उप-विनियम, वितरण नेटवर्क पर अनुपलब्ध हो गए चैनल के मामले में लागू नहीं होगा;

पुनः परंतु यह कि यदि कोई प्रसारक, किसी चैनल के प्रकार में परिवर्तन करता है तो विशेष टेलीविज़न चैनल को दिया गया चैनल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका को स्थान देने के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

**19. सेवा प्रदाता के ब्योरे** — (1) उपभोक्ता या सेवा प्रदाता के हित की रक्षा करने या प्रसारण एवं केबल सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने की दृष्टि से या आदेश अथवा निर्देश द्वारा इन विनियमों को मॉनीटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्योरों की रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए वेबसाइट विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता, इन विनियमों के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर या इस उद्देश्य के लिए वेबसाइट की पहचान से 30 दिन के अंदर, इनमें से जो भी बाद में, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल का पता और वेंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस/ अनुमति/ पंजीकरण के ब्योरे सूचित करेगा।

(3) कोई ऐसा सेवा प्रदाता, जो इन विनियमों को लागू किए जाने के पश्चात अपने प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन के अंदर या इस उद्देश्य के लिए वेबसाइट की पहचान से 30 दिन के अंदर, इनमें से जो भी बाद में हो, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल का पता और वेंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस/ अनुमति पंजीकरण के ब्योरे सूचित करेगा।

(4) किसी सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट से यह सत्यापन करे कि टेलीविज़न चैनलों के सिगनल या नेटवर्क के एक्सेस, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराने के लिए अंतः संयोजन प्राप्त करने के इच्छुक सेवा प्रदाता ने उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के अंतर्गत अपने ब्योरे सूचित कर दिए हैं;

परंतु यह कि यह उप-विनियम, प्राधिकरण द्वारा ऐसी वेबसाइट विनिर्दिष्ट करने की स्थिति में ही लागू होगा।

**20. अनुपालन अधिकारी की नामजदगी और उसके दायित्व** — (1) प्रत्येक प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन के अंदर एक अनुपालन अधिकारी को नामजद करेगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, जो इन विनियमों के लागू किए जाने के पश्चात अपने प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन के अंदर एक अनुपालन अधिकारी नामजद करेगा।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक ऐसा प्रसारक या वितरक, जैसा भी मामला हो, इन विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी नामजदगी की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को, बोर्ड के संकल्प, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी की नामजदगी प्राधिकृत की गई हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ-साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और ई-मेल का पता प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, जो एक कंपनी नहीं है, इन विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी की नामजदगी की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को प्राधिकार-पत्र, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी की नामजदगी प्राधिकृत की गई हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ-साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और ई-मेल का पता प्रस्तुत करेगा।

(4) इस विनियम के उपबंधों के अंतर्गत नामजद किए गए अनुपालन अधिकारी के नाम में किसी परिवर्तन की स्थिति में, इसे बोर्ड के संकल्प या प्राधिकार पत्र, जैसा भी मामला हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ-साथ, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से 30 दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(5) अनुपालन अधिकारी के पते या संपर्क नंबर या ई-मेल के पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से 10 दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(6) अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

(क) इन विनियमों के उपबंधों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करना;

(ख) इन विनियमों और इन विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए प्राधिकरण के अन्य निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उचित प्रक्रियाएं स्थापित कर दी गई हैं और उनका पालन किया जा रहा है।

(7) उप-विनियम (6) में निहित प्रावधान सेवा प्रदाता द्वारा इन विनियमों के पालन के दायित्व के अतिरिक्त होगा।

**21. प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप** — उपभोक्ता या सेवा प्रदाता के हित की रक्षा करने या प्रसारण एवं केबल सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने की दृष्टि से या इन विनियमों को मॉनीटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण आदेश या निर्देश के माध्यम से समय-समय पर हस्तक्षेप कर सकता है।

**22. निरसन** — (1) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविज़न प्रणालियां) विनियम 2012, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन, विनियम 2004 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस विनियम के उप-विनियम (2) तथा उप-विनियम(1) में वर्णित विनियमों के निरसन के होते हुए भी, उक्त विनियम में की गई कोई बात अथवा की गई किसी कार्यवाही को इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत किया गया अथवा लिया गया समझा जाएगा।

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./456/16]

**टिप्पणी :** इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

## अनुसूची 1

(विनियम 8 का उप-विनियम (2) देखें)

## कैरिज शुल्क राशि की गणना

इंटरकनेक्शन अनुबंध की अवधि के दौरान, प्रत्येक माह या तत्संबंधी भाग के लिए कैरिज शुल्क राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

क्र. सं.	कैरिज शुल्क राशि की गणना
1	यदि टारगेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टारगेट मार्केट में उस माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के पांच प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के बराबर होगी।
2	यदि टारगेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के पांच प्रतिशत के बराबर या अधिक है मगर दस प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के 0.75 के बराबर होगी।
3	यदि टारगेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के दस प्रतिशत के बराबर या अधिक है मगर पन्द्रह प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के 0.5 के बराबर होगी।
4	यदि टारगेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर या अधिक है मगर बीस प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के 0.25 के बराबर होगी।
5	यदि टारगेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के बीस प्रतिशत के बराबर या अधिक है तो कैरिज शुल्क राशि 'शून्य' होगी।

**टिप्पणी:-** (1) हाई डेफिनेशन चैनल के लिए कैरिज शुल्क की गणना करने के लिए टारगेट मार्केट में उक्त माह में वितरकों के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या हाई डेफिनेशन टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने में समर्थ उपभोक्ताओं की संख्या के बराबर होगा।

(2) एक माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या की गणना इन विनियमों की अनुसूची 7 में दी गई विधि से की जाएगी।

(3) चैनल के लिए मासिक उपभोक्ता की गणना इन विनियमों की अनुसूची 7 में दी गई विधि से की जाएगी।

(4) नीचे दिए उदाहरण-1 (स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल हेतु) और उदाहरण-2 हाई डेफिनेशन चैनल हेतु) में कैरिज शुल्क राशि की गणना के बारे में बताया गया है।

**उदाहरण-1**

मान लीजिये टेलीविजन चैनलों का एक वितरक का प्रसारक के साथ 'एक्स' नाम के स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल को 0.20 रु. प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर पर कैरिज करने का अनुबंध हो रखा है। प्रसारक द्वारा वितरक को देय कैरिज शुल्क राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगी:-

माह	माह के दौरान उपभोक्ताओं की औसत संख्या	स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल 'एक्स' की मासिक उपभोक्ता संख्या का प्रतिशत	कैरिज शुल्क की दर (पैसे में)	गुणक	कैरिज शुल्क राशि (रु. में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)=(ख)x(घ)x(ङ)
जनवरी	1000	4%	20	1	200.00
फरवरी	800	8%	20	0.75	120.00
मार्च	1500	12%	20	0.50	150.00
अप्रैल	2000	19%	20	0.25	100.00
मई	3000	20%	20	0	0.00

जून	4000	22%	20	0	0.00
जुलाई	10000	17%	20	0.25	500.00
अगस्त	20000	25%	20	0	0.00

**उदाहरण-2**

मान लीजिये टेलीविजन चैनलों का एक वितरक का प्रसारक के साथ 'वाई' नाम के हाई डेफिनेशन चैनल को 0.40 रु. प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर पर कैंरिज करने का अनुबंध हो रखा है। प्रसारक द्वारा वितरक को देय कैंरिज शुल्क राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगी:-

**अनुसूची 2**

माह	माह के दौरान हाई डेफिनेशन एसटीबी की औसत संख्या	हाई डेफिनेशन चैनल 'वाई' की मासिक उपभोक्ता संख्या का प्रतिशत	कैंरिज शुल्क की दर (पैसे में)	गुणक	कैंरिज शुल्क राशि (रु. में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)=(ख)x(घ)x(ङ)
जनवरी	100	2%	40	1	40.00
फरवरी	80	5%	40	0.75	24.00
मार्च	150	11%	40	0.50	30.00
अप्रैल	160	16%	40	0.25	16.00
मई	180	20%	40	0	0.00
जून	200	22%	40	0	0.00
जुलाई	190	17%	40	0.25	19.00
अगस्त	170	25%	40	0	0.00

( विनियम 10 का उप-विनियम (4) देखें )

**टेलीविजन चैनल (चैनलों) के सिगनल के अनुरोध का आवेदन फार्म**

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक का नाम:
2. वितरक के मालिकों/निदेशकों/साझेदारों के नाम:
3. पंजीकृत कार्यालय का पता:
4. पत्राचार का पता
5. संपर्क व्यक्ति/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:
6. टेलीफोन:
7. ईमेल एड्रेस:
8. पंजीकरण प्रमाणपत्र/अनुमति/लाइसेंस की प्रति (प्रति संलग्न करें) :
9. वितरक द्वारा कार्यान्वित हेड-एंड, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) का विवरण:
10. क्षेत्रों, संबंधित राज्य (राज्यों)/केन्द्र शासित प्रदेश (प्रदेशों) का विवरण और हेड-एंड का विवरण, जिससे इन क्षेत्रों में टेलीविजन चैनलों के सिगनलों का वितरण किया जाएगा:
11. वितरक के क्षेत्रवार वर्तमान उपभोक्ताओं की संख्या:
12. चैनल (चैनलों) और बुके (बुकों) की सूची, जिनके लिए टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के लिए अनुरोध किए गए हैं:
13. सेवा कर पंजीकरण संख्या:
14. मनोरंजन कर संख्या :
15. पैन संख्या (प्रति संलग्न करें):
16. क्या सीएस/एसएमएस विनियमों का अनुपालन करते हैं: हां/नहीं



17. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) विनियम 2017, की अनुसूची III के अनुपालन में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हों,

(हस्ताक्षर)

स्थान व तारीख

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (टेलीविजन चैनलों के वितरक का नाम) के \_\_\_\_\_ (मालिक/स्वामी/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य और सही है। मैं उल्लेख करता/करती हूँ कि टेलीविजन चैनलों के वितरण हेतु संस्थापित एड्रसेबल सिस्टम दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) विनियम 2017 की अनुसूची III में निर्दिष्ट तकनीकी और अन्य अपेक्षा (अपेक्षाओं) को पूरा करता है। एड्रसेबल सिस्टम का कॉन्फिगरेशन एवं वर्जन में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी होने के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(हस्ताक्षर)

तारीख व स्थान

### अनुसूची 3

(विनियम 10 का उप-विनियम (6) देखें)

#### एड्रसेबल सिस्टम की अपेक्षाएं

#### क) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस):

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएएस का मौजूदा संस्करण का हैकिंग का कोई इतिहास नहीं है।

**स्पष्टीकरण:** इस संबंध में सीएएस वैडर से वितरक के पास उपलब्ध लिखित घोषणा का अर्थ इस अपेक्षा का अनुपालन माना जायेगा।

2. एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए एसएमएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।
3. सीएएस और एसएमएस में दर्ज डाटा और लॉग्स में बदलाव करना संभव नहीं होगा।
4. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएएस में सीधे सीएएस टर्मिनल से सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को एक्टीवेट और डिएक्टीवेट करने की सुविधा नहीं है। एसटीबी के सभी एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस की कमांड से किया जाएंगे।
5. एसएमएस और सीएएस को इस तरह से एकीकृत किया जाएगा कि दोनों सिस्टम में एसटीबी का एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एक साथ हों।

**स्पष्टीकरण:** आवश्यक और पर्याप्त विधियां उपलब्ध होंगी ताकि एसटीबी का प्रत्येक एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस और सीएएस टर्मिनलों में जनरेट होने वाली रिपोर्टों में प्रदर्शित हों।

6. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि सीएएस में एसटीबी ओवर-द-एयर (ओटीए) अपग्रेड करने की क्षमता है ताकि जुड़े एसटीबी को हैकिंग की स्थिति में अपग्रेड किया जा सकें।
7. किसी उपकरण या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फिंगरप्रिंटिंग अमान्य नहीं होने चाहिए।
8. सीएएस और एसएमएस 24 घंटे के भीतर वितरकों के उपभोक्ताओं की संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत एसटीबी या सेवाओं को एक्टीवेट या डिएक्टीवेट करने में समर्थ होने चाहिए।
9. कंटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और व्यूविंग कार्ड (वीसी) को एसएमएस से युग्मित किया जाएगा।
10. सीएएस और एसएमएस चैनल बाई चैनल और एसटीबी बाई एसटीबी के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करने के उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं को एकल रूप से एड्रेस करने में समर्थ होने चाहिए।
11. एसएमएस कंप्यूटीकृत होना चाहिए और उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और डाटा को रिकार्ड करने में समर्थ होना चाहिए जैसे:

क. विशिष्ट ग्राहक पहचान (आईडी)

- ख. सब्सक्रिप्शन कान्ट्रेक्ट नंबर
- ग. उपभोक्ता का नाम
- घ. बिलिंग का पता
- ड. इंस्टॉलेशन का पता
- च. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर
- छ. मोबाइल टेलीफोन नंबर
- ज. ईमेल एड्रेस
- झ. सब्सक्राइब किए गए चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) और सेवाएं
- ञ. विशिष्ट एसटीबी नंबर
- ट. विशिष्ट वीसी नंबर

12. एसएमएस निम्नलिखित में समर्थ होना चाहिए:

- क. एसटीबी के एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन के संबंध में ऐतिहासिक डाटा को देखना और मुद्रित करना।
- ख. संस्थापित प्रत्येक एसटीबी और वीसी का पता लगाना।
- ग. प्रत्येक उपभोक्ता के लिए शुल्क में बदलाव और उपभोक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के तदनुरूपी स्रोत के ऐतिहासिक डाटा को जनरेट करना।

13. एसएमएस को निम्नलिखित के संबंध में वांछित समय पर रिपोर्ट जनरेट करने में समर्थ होना चाहिए:

- i. पंजीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या
- ii. सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या
- iii. अस्थायी रूप से निलंबित उपभोक्ताओं की कुल संख्या
- iv. डिएक्टीवेट किए गए उपभोक्ताओं की कुल संख्या
- v. सिस्टम में काली सूची में डाले गए एसटीबी की सूची।
- vi. विनिर्धारित फार्मेट में चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) वार मासिक उपभोक्ता रिपोर्ट।
- vii. प्रत्येक बुके के भाग के रूप में शामिल चैनलों के नाम।
- viii. निर्धारित समय पर चैनल या बुके विशेष के सब्सक्राइब करने वाले सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या।
- ix. उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइब किए गए अला-कार्टे चैनल (चैनलों) और बुके (बुकों) के नाम।
- x. चैनल या बुके विशेष के शुल्क के लिए एजिंग रिपोर्ट।

14. सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मॉटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।

15. सीएस ऐसे वीसी नंबरों और एसटीबी नंबरों को टैग करने और काली सूची में डालने में समर्थ होगा जो विगत में पाइरेसी में शामिल रहे हैं ताकि ऐसे वीसी या एसटीबी दुबारा कार्यान्वित न किए जा सकें।

16. यह सीएस के लॉग्स से निम्नलिखित रिपोर्टें जनरेट करने में समर्थ होगा:

- क. एसटीबी-वीसी पेयरिंग/डिपेयरिंग
- ख. एसटीबी एक्टीवेशन/डिएक्टीवेशन
- ग. एसटीबी के लिए नियत चैनल
- घ. निर्धारित अवधि के लिए चैनल विशेष के एक्टीवेशन या डिएक्टीवेशन की रिपोर्ट।

17. एसएमएस मदवार विवरण जैसे सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या, सब्सक्राइब किए गए चैनलों की रेंटल राशि, ग्राहक परिसर उपस्कर हेतु रेंटल राशि, तननुरूपी पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) की सूची और खुदरा मूल्य और कर सहित पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) के लिए प्रभार के साथ प्रत्येक उपभोक्ता के लिए बिल जनरेट करने में समर्थ होगा।

18. वितरक सुनिश्चित करेगा कि सीएस और एसएमएस वैडर (वैडरों) के पास वर्षभर 24x7 आधार पर सिस्टम को मॉटेन करने की क्षमता है।
19. टेलीविजन चैनलों का वितरक चैनलों के वितरण के लिए कार्यान्वित सीएस और एसएमएस के विवरण की घोषणा करेगा। किसी अतिरिक्त सीएस/एसएमएस को कार्यान्वित करने के मामले में, वितरक द्वारा इसकी सूचना प्रसारकों को दी जाएगी।
20. किसी उपभोक्ता को एसएमएस से डिएक्टिवेट करने के मामले में सभी कार्यक्रम/सेवाएं उस उपभोक्ता के लिए बंद कर दी जाएंगी।
21. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सीएस और एसएमएस के असंपादित डाटा को कम से कम दो वर्ष के लिए संभाल कर रखना होगा।

**(ख) फिंगरप्रिंटिंग:**

1. टेलीविजन चैनलों का वितरक सुनिश्चित करेगा कि इसके पास नियमित अंतराल पर फिंगर प्रिंटिंग चलाने के लिए सिस्टम, प्रोसेस और कंट्रोलर्स हैं।
2. एसटीबी फिंगर प्रिंटिंग के विजिबल और कवर्ट टाइप को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।
3. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी के रिमोट पर किसी बटन (की) को दबाने पर विलुप्त होने वाली नहीं होनी चाहिए।
4. फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी सतह पर होनी चाहिए।
5. फिंगर प्रिंटिंग इस तरह होनी चाहिए कि यह विशिष्ट एसटीबी नंबर या विशिष्ट वीसी नंबर को पहचान सकें।
6. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी की सभी स्क्रीनों जैसे मेन्यू, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, नो कंटेंट स्क्रीन और गेम्स आदि पर प्रदर्शित होनी चाहिए।
7. फिंगरप्रिंट की लोकेशन, फॉट कलर और बैकग्राउंड कलर हेड एंड से परिवर्तनीय होना चाहिए और व्यूविंग डिवाइस पर रैंडम होना चाहिए।
8. फिंगर प्रिंटिंग विशिष्ट एसटीबी और/या वीसी की पहचान करने के लिए करेक्टरों की संख्या को बताने में समर्थ होनी चाहिए।
9. फिंगर प्रिंटिंग ग्लोबल के साथ-साथ एकल एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।
10. ओवर्ट फिंगर प्रिंटिंग टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा समय, लोकेशन, अवधि, फ्रिक्वेंसी के संबंध में किसी बदलाव में प्रदर्शित की जानी चाहिए।
11. स्कॉल मैसेजिंग केवल स्क्रीन के निचले भाग में उपलब्ध होनी चाहिए।
12. एसटीबी में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि फिंगर प्रिंटिंग कभी भी डिसेबल न हों।
13. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल इन्कोडर एंड में इन्सर्ट किया जाएगा।

**(ग) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी):**

1. सभी एसटीबी में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होना चाहिए।
2. एसटीबी हेड-एंड द्वारा इन्सर्ट किए गए कंडीशनल एक्सेस मैसेजों को डिफ्रिक्ट करने में समर्थ होने चाहिए।
3. एसटीबी को फिंगर प्रिंटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी इन्टाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) और इन्टाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम) आधारित फिंगरप्रिंटिंग को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।
4. एसटीबी एकल रूप में हेड-एंड से एड्रेसेबल होना चाहिए।
5. एसटीबी हेड-एंड से मैसेज प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।
6. मैसेज करेक्टर लंबाई कम से कम 120 करेक्टर की होगी।
7. इसमें ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग और एकल एसटीबी मैसेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. एसटीबी में फोर्सड फिंगर प्रिंटिंग डिस्प्ले सहित फोर्सड मैसेजिंग की क्षमता होनी चाहिए।
9. एसटीबी को लागू भारतीय मानक ब्यूरो का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।
10. एसटीबी ओटीए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ओवर द एयर के लिए एड्रेसेबल होना चाहिए।
11. कार्यक्रमों को रिकार्ड करने की सुविधा वाले एसटीबी में कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए।

**अनुसूची 4**

( विनियम 10 का उप-विनियम (16) देखें)

**टेलीविजन चैनल के पुनः प्रसारण के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए आवेदन फार्म**

1. प्रसारक का नाम:
2. प्रसारक के सीईओ/एमडी के नाम:
3. पंजीकृत कार्यालय का पता:
4. पत्राचार का पता
5. संपर्क व्यक्ति/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:
6. टेलीफोन:
7. ईमेल एड्रेस:
8. चैनल (चैनलों) के नाम, जिनके पुनःप्रसारण के लिए आवेदन किया गया है:
9. भारत में ऊपर वर्णित चैनल (चैनलों) की डाउन-लिकिंग के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति:
10. चैनल (चैनलों) की प्रकृति (पे या फ्री टू एयर):
11. चैनल (चैनलों) का प्रकार:
12. चैनल (चैनलों) की भाषा (भाषाएं):
13. चैनल (चैनलों) के डाउन-लिकिंग पैरामीटर:  
 क. सेटेलाइट का नाम:  
 ख. कक्षीय स्थान:  
 ग. ध्रुवीकरण:  
 घ. डाउनलिकिंग आवृत्ति:
14. चैनल (चैनलों) का मॉड्युलेशन/कोडिंग कम्प्रेषन स्टैंडर्ड:
15. चैनल (चैनलों) का इन्क्रिप्शन: इन्क्रिप्टिड/अनइन्क्रिप्टिड

(हस्ताक्षर)

स्थान व तारीख

**घोषणा**

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (प्रसारक का नाम) का \_\_\_\_\_ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही और सत्य है।

(हस्ताक्षर)

तारीख व स्थान

**अनुसूची-5**

[ विनियम 12 के उप-विनियम (3) को संदर्भित]

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रसेबल प्रणालियों (डीएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए आदर्श अंतःसंयोजन करार

[1. इस करार के प्रत्येक पृष्ठ पर एमएसओ तथा एलसीओ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।]

2. इस प्रारूप के खंडों में आबंटित संख्या में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्धन एवं परिवर्तन (यदि कोई हो) संबंधित खंड के अंत में या इस प्रारूप के अंत में किया जाएगा]

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहित:

**प्रथम पक्ष,** ----- जिनका पंजीकृत कार्यालय -----  
में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **“एमएसओ”** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशि, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

**और**

**द्वितीय पक्ष,** ----- जिनका पंजीकृत कार्यालय -----  
में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **“एलसीओ”** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशि, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच दिन ----- माह ----- 201----- को निष्पादित किया गया।

**एमएसओ तथा एलसीओ** को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से ‘पक्ष’ कहा जाएगा तथा समग्र रूप से **“पक्ष(क्षों)”** कहा जाएगा।

**जबकि,**

- (क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित ----- क्षेत्र में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए ----- दिनांक -----का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।
- (ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत ----- (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए ----- मुख्य डाकघर (मुख्य डाकघर का नाम) में दिनांक ----- को पंजीकरण संख्या ----- प्रदान किया गया है।
- (ग) एलसीओ ने दिनांक ----- के पत्र संख्या ----- के माध्यम से टेलीविजन चैनलों हेतु सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है तथा एमएसओ दिनांक ----- के पत्र संख्या ----- के माध्यम से ऐसे एलसीओ को टेलीविजन चैनलों के लिए सिग्नल उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है।
- (घ) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र ----- है [उस क्षेत्र(त्रों)/शहरों (रों)/जिला(लों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
- (ङ) दोनों पक्ष, प्रधान से प्रधान आधार पर तथा गैर-अनन्य आधार पर क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इस करार को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।
- (च) दोनों पक्ष इस बात पर भी आपस में सहमत हैं कि दोनों पक्षों के बीच किसी सम्पत्ति/ परिसम्पत्तियों के लेन-देन सहित प्रत्येक लेन-देन को लिखित में तथा अन्य सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।

**अब इसलिए,** उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:-

### 1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

### 2. करार की शर्तें

- 2.1 करार, ----- (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा ----- (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

- 2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि विस्तारित अवधि एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की अवधि की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, से अधिक न हो।

### 3. करार को समाप्त करना

- 3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगा:—
- (i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्त्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पंद्रह (15) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय—सीमा के भीतर सशोधित नहीं किया गया हो; अथवा
  - (ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा
  - (iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय—समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।
- 3.2 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 3.3 एलसीओ द्वारा क्षेत्र में अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 3.4 यदि किसी कारणवश, एमएसओ क्षेत्र में टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।
- 3.5 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो, वह एमएसओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

### 4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभाव :

- 4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।
- 4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एलसीओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एलसीओ, एमएसओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।
- 4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एमएसओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एमसीओ, एलसीओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।
- स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपस्करों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।
- 4.4 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त विनिर्धारित अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो चूककर्ता पक्ष इसके मूल्यह्रासित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के दो प्रतिशत के ऊपर की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

### 5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

- 5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप गैर-अनन्य आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा ताकि इसे क्षेत्र के सब्सक्राइबरों को पुनः प्रसारित किया जा सके।
- 5.2 एलसीओ, एमएसओ को अपने नेटवर्क तक गैर-अनन्य आधार पर पहुंच उपलब्ध कराएगा ताकि एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीविजन सिग्नलों को क्षेत्र में सब्सक्राइबरों तक पहुंचाया जा सके।
- 5.3 दोनों पक्ष लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप कड़ाई से केवल डिजिटल एड्रैसेबल प्रणाली के माध्यम से ही कूटबद्ध पद्धति द्वारा ही किसी चैनल, विषयवस्तु अथवा कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रसारण, पुनःप्रसारण करेंगे अथवा उसे प्रणाली के माध्यम से संवाहित करेंगे।
- 5.4 सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस करार के पक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के खण्ड 10 में अंतर्विष्ट हैं।
- 5.5 इस करार के खण्ड-10 में उल्लिखित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित खण्ड-12 में उल्लेख किया गया है।

**6. एमएसओ के अधिकार**

- 6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।
- 6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- 6.3 एमएसओ को लागू कानूनों तथा विनियमों के अधीन सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिमरूप से विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।
- 6.5 एमएसओ को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

**7. एलसीओ के अधिकार**

- 7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।
- 7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

**8. एमएसओ के दायित्व**

- 8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्रम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड-एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।
- 8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।
- 8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।
- 8.4 एमएसओ, पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्रारूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।
- 8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।
- 8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।
- 8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।
- 8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्ही नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।
- 8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउल्लंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।
- 8.10 एमएसओ संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- 8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा तथा अंतःसंयोजन विनियमों में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।
- 8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।
- 8.13 एमएसओ, एलसीओ को अनुरक्षण हेतु पहले से सक्रिय नहीं किए गए अतिरिक्त एसटीबी के रूप में अधिकतम 30 एसटीबी की अधिकतम सीमा के साथ उसके नेटवर्क पर सक्रिय कुल एसटीबी के कम से कम 2 प्रतिशत एसटीबी उपलब्ध कराएगा ताकि एसटीबी में किसी खराबी के कारण प्रभावित सेवाओं को त्वरित रूप बहाल किया जा सके। करार की अवधि के दौरान, अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त एसटीबी की संख्या को बनाए रखा जाएगा।
- 8.14 एमएसओ, एलसीओ को पैकेज की संरचना अथवा सब्सक्राइबरों को पेशकश किए जा रहे खुदरा टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में कम से कम 15 दिन पहले जानकारी देगा।
- 8.15 एलसीओ की पूर्व सहमति के बिना एमएसओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

### 9. एलसीओ के दायित्व

- 9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) की प्रति को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।
- 9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्योरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।
- 9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 9.5 एलसीओ सब्सक्राइबर से मौजूदा कनेक्शनों हेतु कनेक्शन काटने के आवेदन के माध्यम से तथा नए कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता आवेदन प्ररूप के माध्यम से अनुरोध प्राप्त किए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नए सेट-टॉप बॉक्स को नए उपभोक्ता आवेदन प्ररूप में दिए गए ब्योरे की नए एमएसओ के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि के पश्चात् ही सक्रिय किया जाएगा।
- 9.6 एलसीओ :-
- (i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;
  - (ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।
  - (iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिफोल्डिंग, सिग्नल प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने के उपस्कर(रों), नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।
  - (iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेर-बदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुनर्स्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिपट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।
  - (v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिफोल्डिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।
  - (iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुनर्स्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिफोल्डिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपस्कर(रों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।
- 9.7 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।



- 9.8 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुनर्स्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।
- 9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अति-उलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।
- 9.10 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा।
- 9.11 एलसीओ, एमसीओ को तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह अंतःसंयोजन विनियम में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

**10. एमएसओ और एलसीओ के कार्य और दायित्व:**

क्र. सं.	कार्य	पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर एमएसओ या एलसीओ के दायित्व – तदनुसार खाने को भरें	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट अथवा दोनों फारमेट में सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची-1 में यथा निर्दिष्ट आवेदन के फारमेट तैयार करना।		
2	क. मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर योजना और इस पर लागू वारंटी/मरम्मत नीति के विवरण की सूचना उपभोक्ता को मुहैया कराना। ख. सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, प्रत्येक नए कनेक्शन के समय सेवाओं के विवरण की सूचना उपभोक्ताओं को मुहैया कराना।		
3	विधिवत रूप से भरे उपभोक्ता आवेदन फार्म प्राप्त होने पर उपभोक्ता को टेलीविजन सेवाएं मुहैया कराना और इसकी एक प्रति उपभोक्ता को देना।		जिस पक्ष को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह प्रत्येक मामले में आवेदन प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।
4	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) देना और इसकी सूचना देना।		एसएमएस से यूआईएन जनरेट किया जाएगा। अगर यह जिम्मेदारी एलसीओ को दी जाती है तो एसएमएस की संगत एक्सेस एमएसओ द्वारा एलसीओ को मुहैया कराई जाएगी।

5	उपभोक्ताओं के लिए टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को एकटीवेट करना।		<p>➤ एकटीवेशन एसएमएस में उपभोक्ता आवेदन फार्म की जानकारी डालने के बाद ही किया जाएगा।</p> <p>➤ यदि एलसीओ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो एमएसओ को एसटीबी को सक्रिय करने के लिए एसएमएस के संगत भाग तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए।</p>
6	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को एकटीवेट करना।		
7	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को डीएकटीवेट करना।		
8	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित रखना।		
9	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को पुनः स्थापित रखना।		
10	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसके कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना।		
11	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में यथा निर्दिष्ट निरोधक रखरखाव के लिए सिगनलों की रूकावट के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना देना।		
12	सेवा की गुणवत्ता में यथा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के कनेक्शन को काटना।		
13	उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड या दोनों के आधार पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं की पेशकश करना।		
14	उपभोक्ता के अनुरोध पर भुगतान प्रणाली को प्रीपेड से पोस्टपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड, जैसा भी मामला हों, में बदलना।		
15	सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड बिल जनरेट करना।		
16	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को पोस्टपेड बिल भेजना।		
17	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के लिए रसीदें जारी करना और देना तथा रसीदों का विवरण सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) में दर्ज करना।		
18	उपभोक्ताओं को प्रीपेड भुगतान की पावती देना और तदनुसार सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करना।		
19	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स मुहैया कराना।		
20	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, सीपीई के लिए विभिन्न योजनाओं की पेशकश करना।		
21	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, गारंटी/वारंटी अवधियों की समाप्ति के बाद एकमुश्त खरीद योजना के तहत मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर के लिए वार्षिक रखरखाव योजना की पेशकश करना।		

22	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, खराब सेट टॉप बॉक्स की मरम्मत करना।		
23	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में दिए गए ग्राहक सेवा चैनलों और वेबसाइटों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टॉल फ्री ग्राहक सेवा नंबर और वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली का पता प्रकाशित/प्रचारित करना।		
24	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए कार्यविधि पुस्तिका (एमओपी) मुहैया कराना।		एमएसओ एमओपी की विषय-वस्तु को अंतिम रूप देगा। ऐसी एमओपी की प्रतियां एलसीओ को दी जाएगी।
25	सरकार को करें का भुगतान करना।	एमएसओ और/या एलसीओ	संबंधित कर प्राधिकारियों के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय कर भुगतान दायित्वों का विशिष्ट विवरण साथ वाले खाने में भरा जाएगा।

टिप्पणी:- ऊपर कॉलम (2) में उल्लिखित विभिन्न कार्यों के लिए दायित्व पक्षों की परस्पर सहमति पर आधारित हैं और तदनुसार कॉलम (3) के खाने भरे जाएंगे।

## 11. बिलिंग

11.1 उपभोक्ता के लिए बिलिंग \_\_\_\_\_ के नाम में की जाएगी। बहरहाल, प्रत्येक पक्ष सुनिश्चित करेगा कि करें से संबंधित लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाए।

11.2 पक्ष, ऊपर खंड 11.1 में उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग के लिए जिसके नाम पर सहमति हुई है, उपभोक्ता द्वारा अदा किए गए शुल्क का भुगतान प्राप्त करेगा। इस अनुबंध के खंड 12.1 के अनुसार, दूसरे पक्ष से बिल प्राप्त होने पर राजस्व शेयर का भुगतान पहले पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया जाएगा।

## 12. एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व सेटलमेंट और संबंधित अधिकार एवं दायित्व

12.1 एलसीओ और वितरक के बीच प्रभारों का सेटलमेंट निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

(क) सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः \_\_\_\_ : \_\_\_\_ के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

(ख) वितरण शुल्क मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः \_\_\_\_ : \_\_\_\_ के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

टिप्पणी:-

(1) परस्पर अनुबंध के मामलों में, जिनमें एमएसओ और एलसीओ के कार्य और दायित्व खंड (10) के कॉलम (3) के अनुसार तय किए गए हैं, इस खंड में परस्पर सहमति के आधार पर यथोचित ढंग से संशोधन किया जा सकता है।

(2) सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क और वितरण शुल्क की परिभाषा वही है जो अंतः संयोजन विनियम और टैरिफ आदेश में निहित है।

12.2\*

(जब उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग एलसीओ के नाम में है और एलसीओ उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए शुल्क का भुगतान प्राप्त करता है)

एमएसओ राजस्व सेटलमेंट के लिए एलसीओ द्वारा देय बकायों के लिए एलसीओ को मासिक बिल जारी करेगा और ऐसे बिलों में भुगतान की देय तारीख, जो सात दिन से कम नहीं होगी, के साथ वर्तमान भुगतान देय राशियों और बकायों, यदि कोई हों, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। बकायों की मांग को अवधि, जिससे बकाया संबंधित है, की सेवा के बिल के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बिल में उल्लिखित राशि का भुगतान उसमें उल्लिखित देय तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

या

12.2\*

(जब उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग एमएसओ के नाम में है और एमएसओ उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए शुल्क का भुगतान प्राप्त करता है)

एमएसओ उपभोक्ता बिलिंग और भुगतान की रसीद से संबंधित पूरी सूचना को एलसीओ के साथ साझा करेगा। एलसीओ राजस्व सेटलमेंट के लिए एमएसओ द्वारा देय बकायों के लिए एमएसओ को मासिक बिल जारी करेगा और ऐसे बिलों में भुगतान की देय तारीख, जो सात दिन से कम नहीं होगी, के साथ वर्तमान भुगतान देय राशियों और बकायों, यदि कोई हों, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। बकायों की मांग को अवधि, जिससे बकाया संबंधित है, की सेवा के बिल के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बिल में उल्लिखित राशि का भुगतान उसमें उल्लिखित देय तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

(\* एकल अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय जो लागू न हों, उसे काट दें)

12.3 संबंधित पक्ष सब्सक्राइबर से वसूली गई सब्सक्रिप्शन राशि के ब्यौरे को देय तिथि से 7 दिन के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में अद्यतन करेंगे।

### 13. भुगतान में चूक

13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, को अधिकार होगा कि वह:-

- (i) सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;
- (ii) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।
- (iii) जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।

13.2 उस स्थिति में जब कोई पक्ष ने विगत में लगातार तीन माह तक भुगतान करने में चूक की हो तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा जो कि बीते 6 माह की बिलिंग राशि कुल औसत राशि से अधिक नहीं होगा जिसे करार की शेष अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

13.3 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, चूककर्ता पक्ष को भविष्य में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि को जमा करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के ऊपर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

### 14. वचन

14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पत्ति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेंट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, प्रधान से प्रधान आधार पर होगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि “-----” लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि “-----” लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।

बशर्ते कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।

- 14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।
- 14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय-समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।
- 14.9 दोनों पक्ष केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, समय-समय पर यथा संशोधित, में विहित कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे।
- 14.10 दोनों पक्ष, देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

#### 15. पायरेसी की रोकथाम

- 15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड-एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।
- 15.2 किसी भी सबक्राइबर को किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

#### 16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

- 16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुपंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- 16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुपंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- 16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सबक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।
- 16.4 एमसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सबक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

#### 17. शासी विधि तथा विवाद निपटान

- 17.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली ("टीडीसेट") के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीसेट के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

#### 18. अपरिहार्य घटना

- 18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़-फोड़, संगरोध, महामारी, लूट-पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के पंजीकरण का रद्दीकरण अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन-देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।
- 18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

**19. नोटिस**

- 19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

**20. अंतरण हेतु निर्बंधन**

- 20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विलंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

**21. गोपनीयता**

- 21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक-दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।
- 21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेंटों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।
- 21.3 दोनों पक्ष, एतद्वारा सहमत हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मांगे जाने गोपनीय जानकारी का उद्घटन किया जा सकता है।

**22. आशोधन**

- 22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, फेरफार अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार, अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

**23. बाध्यकारी प्रभाव**

- 23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

**इसके साक्षी स्वरूप** पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(-----)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. -----

2. -----

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(-----)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. -----

2. -----

**नोट** मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिनके माध्यम से इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षों की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को इस करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

## अनुसूची

## परिभाषाएं तथा निर्वचन

## क. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है:-

- (a) **“अधिनियम”** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है;
- (b) **“एड्रसेबल प्रणाली”** का अभिप्राय वही होगा जोकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में दिया गया है;
- (c) **“प्राधिकरण”** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
- (d) **“बुनियादी सेवा टीयर”** का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है;
- (e) **“बुके”** अथवा **“चैनलों के बुके”** से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबंध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा ;
- (f) **“प्रसारक”** से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केंद्र सरकार से डॉउनलिकिंग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है ;
- (g) **“केबल सेवाएं अथवा केबल टेलीविजन सेवाएं”** से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है ;
- (h) **“केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क”** से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबंधित सिग्नल जनरेशन नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबर्स द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है ;
- (i) **“उपभोक्ता सेवा केन्द्र”** का आशय किसी सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित विभाग अथवा एक सुविधा से है।
- (j) **“सीटीएन अधिनियम”** का अभिप्राय समय-समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।
- (k) **“कूटबद्ध करना”** किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके और वाक्यांश **“अकूटबद्ध”** का तदनुसार अर्थ होगा;
- (l) **“फ्री-टु-एयर-चैनल”** का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।
- (m) **“हार्डवेयर”** का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबंध पुर्जों तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारंपरिक चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।
- (n) **“हेड-एंड”** का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलैटर, कम्प्रेसन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारंपरिक उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियो अथवा संबंध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।
- (o) **“अंतःसंयोजन विनियम”** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है।
- (p) **“पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)”** का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।
- (q) **“पे-चैनल”** का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।
- (r) **“पायरेसी”** का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना उसका पुनर्प्रसारण तथा पुनर्वितरण करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़-छाड़, उसकी सील के साथ छेड़-छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट-टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिक्कोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिकॉडिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है;
- (s) **“कार्यक्रम”** का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :-  
  - (i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

- (ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और
- “प्रोग्रामिंग सेवा” वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए;
- (t) “सेवा की गुणवत्ता विनियम” का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है;
- (u) “सेट टॉप बॉक्स अथवा एसटीबी” का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;
- (v) “स्मार्ट कार्ड” का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है;
- (w) “सब्सक्राइबर” “सब्सक्राइबर” से आशय इस विनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे अन्य किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइबर की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा।
- (x) “सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली” अथवा एसएमएससे आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके (गुच्छे), प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुक या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है।
- (y) “टैरिफ आदेश” का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 से है।
- (z) “ट्रंक लाइन” का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबंधित उपकरण जैसे रीसिवर नोड्स, एम्पलीफायर, स्प्लिटर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबंधित कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारेषण किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबंध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

## ख. निर्वचन

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (ख) “व्यक्ति” शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं;
- (ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप-खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप-खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो;
- (घ) “माह” के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा;
- (ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो;
- (च) विधि, विनियम, साविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय-समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।



## अनुसूची-6

(विनियम 12 के उप-विनियम (3) को संदर्भित)

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रसेबल प्रणालियों (डीएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए मानक अंतःसंयोजन करार

{ 1. इस करार के प्रत्येक पृष्ठ पर एमएसओ तथा एलसीओ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। }

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहित:

**प्रथम पक्ष,** \_\_\_\_\_ जिनका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_ में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **“एमएसओ”** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशित, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

और

**द्वितीय पक्ष,** \_\_\_\_\_ जिनका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_ में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **“एलसीओ”** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशित, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच दिन \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_\_ को निष्पादित किया गया।

**एमएसओ तथा एलसीओ** को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा तथा समग्र रूप से **“पक्ष(क्षों)”** कहा जाएगा।

**जबकि,**

- (क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित \_\_\_\_\_ क्षेत्र में एड्रसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।
- (ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत \_\_\_\_\_ (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए \_\_\_\_\_ मुख्य डाकघर (मुख्य डाकघर का नाम) में दिनांक \_\_\_\_\_ को पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ प्रदान किया गया है।
- (ग) एलसीओ ने दिनांक \_\_\_\_\_ के पत्र संख्या \_\_\_\_\_ के माध्यम से टेलीविजन चैनलों हेतु सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है तथा एमएसओ दिनांक \_\_\_\_\_ के पत्र संख्या \_\_\_\_\_ के माध्यम से ऐसे एलसीओ को टेलीविजन चैनलों के लिए सिग्नल उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है।
- (घ) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र \_\_\_\_\_ है [उस क्षेत्र(त्रों)/शहरों (रों)/जिला(लों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।]
- (ङ) दोनों पक्ष, प्रधान से प्रधान आधार पर तथा गैर-अनन्य आधार पर क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इस करार निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।
- (च) दोनों पक्ष इस बात पर भी आपस में सहमत हैं कि दोनों पक्षों के बीच किसी सम्पत्ति/ परिसम्पत्तियों के लेन-देन सहित प्रत्येक लेन-देन को लिखित में तथा अन्य सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।

**अब इसलिए,** उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:-

### 1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

## 2. करार की शर्तें

- 2.1 करार, \_\_\_\_\_ (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा \_\_\_\_\_ (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।
- 2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि विस्तारित अवधि एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की अवधि की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, से अधिक न हो।

## 3. करार को समाप्त करना

- 3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगा:—
  - (i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्त्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पंद्रह (15) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय-सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया गया हो; अथवा
  - (ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा
  - (iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय-समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।
- 3.6 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 3.7 एलसीओ द्वारा क्षेत्र में अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 3.8 यदि किसी कारणवश, एमएसओ क्षेत्र में टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।
- 3.9 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो, वह एमएसओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

## 4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभाव :

- 4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।
  - 4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एलसीओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एलसीओ, एमएसओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यहासित मूल्य का भुगतान करेगा।
  - 4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एमएसओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एमएसओ, एलसीओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यहासित मूल्य का भुगतान करेगा।
- स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपकरणों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।
- 4.5 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त विनिर्धारित अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो चूककर्ता पक्ष इसके मूल्यहासित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के दो प्रतिशत के ऊपर की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

## 5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

- 5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप गैर-अनन्य आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा ताकि इसे क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को पुनः प्रसारित किया जा सके।
- 5.2 एलसीओ, एमएसओ को अपने नेटवर्क तक गैर-अनन्य आधार पर पहुंच उपलब्ध कराएगा ताकि एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीविजन सिग्नलों को क्षेत्र में सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया जा सके।

- 5.3 दोनों पक्ष लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप कड़ाई से केवल डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से ही कूटबद्ध पद्धति द्वारा ही किसी चैनल, विषयवस्तु अथवा कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रसारण, पुनःप्रसारण करेंगे अथवा उसे प्रणाली के माध्यम से संवाहित करेंगे।
- 5.4 सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस करार के पक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के **खण्ड 10** में अंतर्विष्ट हैं।
- 5.5 इस करार के **खण्ड-10** में उल्लिखित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित **खण्ड-12** में उल्लेख किया गया है।

#### 6. एमएसओ के अधिकार

- 6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।
- 6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनःप्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- 6.3 एमएसओ को लागू कानूनों तथा विनियमों के अधीन सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिमरूप से विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।
- 6.5 एमएसओ को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

#### 7. एलसीओ के अधिकार

- 7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।
- 7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

#### 8. एमएसओ के दायित्व

- 8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्रम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड-एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।
- 8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।
- 8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।
- 8.4 एमएसओ, पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।
- 8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।
- 8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।
- 8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

- 8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्हीं नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।
- 8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउल्लंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।
- 8.10 एमएसओ संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा तथा अंतःसंयोजन विनियमों में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।
- 8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।
- 8.13 एमएसओ, एलसीओ को अनुरक्षण हेतु पहले से सक्रिय नहीं किए गए अतिरिक्त एसटीबी के रूप में अधिकतम 30 एसटीबी की अधिकतम सीमा के साथ उसके नेटवर्क पर सक्रिय कुल एसटीबी के कम से कम 2 प्रतिशत एसटीबी उपलब्ध कराएगा ताकि एसटीबी में किसी खराबी के कारण प्रभावित सेवाओं को त्वरित रूप बहाल किया जा सके। करार की अवधि के दौरान, अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त एसटीबी की संख्या को बनाए रखा जाएगा।
- 8.14 एमएसओ, एलसीओ को पैकेज की संरचना अथवा सब्सक्राइबरों को पेशकश किए जा रहे खुदरा टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में कम से कम 15 दिन पहले जानकारी देगा।
- 8.15 एलसीओ की पूर्व सहमति के बिना एमएसओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

#### 9. एलसीओ के दायित्व

- 9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) की प्रति को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।
- 9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्यौरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।
- 9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 9.5 एलसीओ सब्सक्राइबर से मौजूदा कनेक्शनों हेतु कनेक्शन काटने के आवेदन के माध्यम से तथा नए कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता आवेदन प्ररूप के माध्यम से अनुरोध प्राप्त किए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नए सेट-टॉप बॉक्स को नए उपभोक्ता आवेदन प्ररूप में दिए गए ब्यौरे की नए एमएसओ के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि के पश्चात् ही सक्रिय किया जाएगा।
- 9.6 एलसीओ :-
  - (i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;
  - (ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।
  - (iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिक्लॉडिंग, सिग्नल प्राप्त करन और रिकॉर्ड करने के उपस्कर(रों), नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।
  - (iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेर-बदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुनर्स्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।
  - (v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिक्लॉडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकार्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।
  - (vi) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुनर्स्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा

सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपस्कर(रों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

- 9.7 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।
- 9.8 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुनर्स्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।
- 9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अति-उल्लंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।
- 9.10 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा।
- 9.11 एलसीओ, एमसीओ को तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह अंतःसंयोजन विनियम में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

#### 10. एमएसओ और एलसीओ के कार्य और दायित्व:

क्र. सं.	कार्य	एमएसओ या एलसीओ के दायित्व	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट अथवा दोनों फॉरमेट में सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची-1 में यथा निर्दिष्ट आवेदन के फॉर्मेट तैयार करना।	एमएसओ	
2	क. मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर योजना और इस पर लागू वारंटी/मरम्मत नीति के विवरण की सूचना उपभोक्ता को मुहैया कराना। ख. सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, प्रत्येक नए कनेक्शन के समय सेवाओं के विवरण की सूचना उपभोक्ताओं को मुहैया कराना।	एलसीओ	एमएसओ एसटीबी को उपलब्ध कराने/एसटीबी को वापस करने, तत्संबंध पर लागू वारंटी/मरम्मत संबंधी नीतिको अंतिम रूप देगा। तथापि, एमएसओ ऐसे ब्योरे को एलसीओ के साथ साझा करेगा।
3	विधिवत रूप से भरे उपभोक्ता आवेदन फार्म प्राप्त होने पर उपभोक्ता को टेलीविजन सेवाएं मुहैया कराना और इसकी एक प्रति उपभोक्ता को देना।	एलसीओ	जिस पक्ष को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह प्रत्येक मामले में आवेदन प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।
4	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) देना और इसकी सूचना देना।	एलसीओ	एसएमएस से यूआईएन जनरेट किया जाएगा। एसएमएस की संगत एक्सेस एमएसओ द्वारा एलसीओ को मुहैया कराई जाएगी।

5	उपभोक्ताओं के लिए टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को एक्टीवेट करना।	एमएसओ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एक्टीवेशन एसएमएस में उपभोक्ता आवेदन फार्म की जानकारी डालने के बाद ही किया जाएगा।</li> <li>➤ यदि एलसीओ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो एमएसओ को एसटीबी को सक्रिय करने के लिए एसएमएस के संगत भाग तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए।</li> </ul>
6	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को एक्टीवेट करना।	एलसीओ	एक्टीवेशन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा।
7	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को डीएक्टीवेट करना।	एलसीओ	डीएक्टीवेशन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा।
8	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित रखना।	एलसीओ	निलंबन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा।
9	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को पुनः स्थापित रखना।	एलसीओ	पुनः स्थापन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा।
10	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसके कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना।	एलसीओ	एलसीओ द्वारा प्राप्त भुगतान के ब्योरे को तुरंत एसएमएस में अद्यतन किया जाएगा
11	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में यथा निर्दिष्ट निरोधक रखरखाव के लिए सिगनलों की रूकावट के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना देना।	एमएसओ	यदि एलसीओ द्वारा निरोधात्मक रखरखाव किया जाना हो तो वह एमएसओ को सूचित करेगा ताकि वह सब्सक्राइबर्स को जानकारी दे सके।
12	सेवा की गुणवत्ता में यथा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के कनेक्शन को काटना।	एमएसओ	
13	उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड या दोनों के आधार पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं की पेशकश करना।	एमएसओ	
14	उपभोक्ता के अनुरोध पर भुगतान प्रणाली को प्रीपेड से पोस्टपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड, जैसा भी मामला हो, में बदलना।	एमएसओ	
15	सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड बिल जनरेट करना।	एमएसओ	
16	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को पोस्टपेड बिल भेजना।	एमएसओ	
17	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के लिए रसीदें जारी करना और देना तथा रसीदों का विवरण सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) में दर्ज करना।	एमएसओ	
18	उपभोक्ताओं को प्रीपेड भुगतान की पावती देना और तदनुसार सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करना।	एमएसओ	
19	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स मुहैया कराना।	एमएसओ	
20	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, सीपीई के लिए विभिन्न योजनाओं की पेशकश करना।	एमएसओ	

21	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, गारंटी/वारंटी अवधियों की समाप्ति के बाद एकमुश्त खरीद योजना के तहत मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर के लिए वार्षिक रखरखाव योजना की पेशकश करना।	एमएसओ	
22	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, खराब सेट टॉप बॉक्स की मरम्मत करना।	एमएसओ	
23	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में दिए गए ग्राहक सेवा चैनलों और वेबसाइटों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टॉल फ्री ग्राहक सेवा नंबर और वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली का पता प्रकाशित/प्रचारित करना।	एमएसओ	
24	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए कार्यविधि पुस्तिका (एमओपी) मुहैया कराना।	एलसीओ	एमएसओ एमओपी की विषय-वस्तु को अंतिम रूप देगा। ऐसी एमओपी की प्रतियां एलसीओ को दी जाएगी।
25	सरकार को करों का भुगतान करना।	एमएसओ और/या एलसीओ	संबंधित कर प्राधिकारियों के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय कर भुगतान दायित्वों का विशिष्ट विवरण साथ वाले खाने में भरा जाएगा।

### 11. बिलिंग

- 11.1 सब्सक्राइबर हेतु बिलिंग एमएसओ के नाम पर की जाएगी। तथापि, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू कानून, नियम तथा विनियमों का अनुपालन किया जाए।
- 11.2 एमएसओ सब्सक्राइबरों द्वारा दिया गया सब्सक्रिप्शन फीस को ग्रहण करेगा। राजस्व हिस्सा, इस समझौते के खंड 12.1 के अनुसार, एमएसओ, एलसीओ से बीजक मिलने पर, एलसीओ को देगा।

### 12. एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व सेटलमेंट और संबंधित अधिकार एवं दायित्व

- 12.1 सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क और वितरण शुल्क मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

नोट: सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क और वितरण शुल्क की परिभाषा वही है जो अंतः संयोजन विनियम और टैरिफ आदेश में निहित है।

- 12.2 एमएसओ सब्सक्राइबर बिलिंग और भुगतान प्राप्ति से संबंधित पूरी सूचना एलसीओ के साथ साझा करेगा। एलसीओ, एमएसओ को भुगतान की जाने वाली देय राशि के लिए एमएसओ को मासिक बीजक(कों) जारी करेगा तथा ऐसे बीजक(कों) में स्पष्ट रूप से वर्तमान भुगतान देय राशि तथा बकाया राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान की अंतिम तिथि के साथ उल्लेख किया जाएगा, जो कि सात दिनों से कम नहीं होगी। बकाया राशि हेतु किसी भी मांग के साथ उस अवधि हेतु बीजकों को भेजे जाने का प्रमाण भी संलग्न किया जाए। बीजकों के अनुसार बिल की गई सभी राशियों का भुगतान उसमें उल्लिखित देय राशि हेतु अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

- 12.3 संबंधित पक्ष सब्सक्राइबर से वसूली गई सब्सक्रिप्शन राशि के ब्यौरे को देय तिथि से 7 दिन के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में अद्यतन करेंगे।

### 13. भुगतान में चूक

- 13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, को अधिकार होगा कि वह:-
- सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;
  - लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।
  - जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।
- 13.2 उस स्थिति में जब कोई पक्ष ने विगत में लगातार तीन माह तक भुगतान करने में चूक की हो तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा जो कि बीते 6 माह की बिलिंग राशि कुल औसत राशि से अधिक नहीं होगा जिसे करार की शेष अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।
- 13.3 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, चूककर्ता पक्ष को भविष्य में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि को जमा करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर

तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के ऊपर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

#### 14. वचन

- 14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पत्ति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।
- 14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेन्ट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, प्रधान से प्रधान आधार पर होगा।
- 14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि “\_\_\_\_\_” लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि “\_\_\_\_\_” लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।  
बशर्त कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।
- 14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।
- 14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय-समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।
- 14.9 दोनों पक्ष केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, समय-समय पर यथा संशोधित, में विहित कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे।
- 14.10 दोनों पक्ष, देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

#### 15. पायरेसी की रोकथाम

- 15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड-एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।
- 15.2 किसी भी सब्सक्राइबर को किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

#### 16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

- 16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- 16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।



- 16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।
- 16.4 एमएसओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

## 17. शासी विधि तथा विवाद निपटान

- 17.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली ("टीडीसेट") के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीसेट के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

## 18. अपरिहार्य घटना

- 18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़-फोड़, संगरोध, महामारी, लूट-पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के पंजीकरण का रद्दीकरण अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन-देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।
- 18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

## 19. नोटिस

- 19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

## 20. अंतरण हेतु निर्बंधन

- 20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विलंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

## 21. गोपनीयता

- 21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक-दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घाटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।
- 21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेंटों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।
- 21.3 दोनों पक्ष, एतद्वारा सहमत हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मांगे जाने गोपनीय जानकारी का उद्घाटन किया जा सकता है।

## 22. आशोधन

- 22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, फेरफार अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार, अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

**23. बाध्यकारी प्रभाव**

- 23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

**इसके साक्षी स्वरूप** पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(\_\_\_\_\_)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(\_\_\_\_\_)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**नोट:** *मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिनके माध्यम से इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षों की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को इस करार के साथ संलग्न किया जाएगा।*

**अनुसूची**

**परिभाषाएं तथा निर्वचन**

**क. परिभाषाएं**

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है:-

- (a) **“अधिनियम”** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है;
- (b) **“एड्रेसेबल प्रणाली”** का अभिप्राय वही होगा जोकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में दिया गया है;
- (c) **“प्राधिकरण”** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
- (d) **“बुनियादी सेवा टीयर”** का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है;
- (e) **“बुके”** अथवा **“चैनलों के बुके”** से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा ;
- (f) **“प्रसारक”** से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केंद्र सरकार से डॉउनलिकिंग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है” ;
- (g) **“केबल सेवाएं”** अथवा **“केबल टेलीविजन सेवाएं”** से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनःप्रसारण शामिल है ;
- (h) **“केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क”** से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पथ और संबंधित सिग्नल जनरेशन नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबर्स द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है ;
- (i) **“उपभोक्ता सेवा केन्द्र”** का आशय किसी सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित विभाग अथवा एक सुविधा से है।
- (j) **“सीटीएन अधिनियम”** का अभिप्राय समय-समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।
- (k) **“कूटबद्ध करना”** किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके और वाक्यांश “अकूटबद्ध” का तदनुसार अर्थ होगा;

- (l) “फ्री-टु-एयर-चैनल” का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।
- (m) “हार्डवेयर” का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबद्ध पुर्जों तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारंपरिक चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।
- (n) “हेड-एंड” का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलैटर, कम्प्रेसन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारंपरिक उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियो अथवा संबद्ध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।
- (o) “अंतःसंयोजन विनियम” का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रिसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है।
- (p) “पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)” का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।
- (q) “पे-चैनल” का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।
- (r) “पायरेसी” का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना उसका पुनर्प्रसारण तथा पुनर्वितरण करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़-छाड़, उसकी सील के साथ छेड़-छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट-टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिक्लॉकिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिकॉर्डिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है;
- (s) “कार्यक्रम” का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :-
- (i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;
  - (ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और
- “प्रोग्रामिंग सेवा” वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए;
- (t) “सेवा की गुणवत्ता विनियम” का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रिसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है;
- (u) “सेट टॉप बॉक्स अथवा एसटीबी” का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रीसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;
- (v) “स्मार्ट कार्ड” का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है;
- (w) “सब्सक्राइबर” “सब्सक्राइबर” से आशय इस विनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे अन्य किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइबर की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा।
- (x) “सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली अथवा एसएमएस से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके (गुच्छे), प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुक या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है।
- (y) “टैरिफ आदेश” का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रिसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 से है।
- (z) “ट्रंक लाइन” का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबद्ध उपकरण जैसे रीसीवर नोड्स, एम्प्लीफायर, स्प्लिटर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबद्ध कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारंपरिक किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबंध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

**ख. निर्वचन**

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (ख) "व्यक्ति" शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं;
- (ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप-खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप-खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो;
- (घ) "माह" के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा;
- (ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो;
- (च) विधि, विनियम, सांविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय-समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।

**अनुसूची 7**

[ विनियम 14 के उप-विनियम (1) और (3) देखें ]

**मासिक उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट****A: टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को मुहैया कराई जाने वाली चैनलों और बुकों की मासिक उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट**

रिपोर्ट का महीना: \_\_\_\_\_

वर्ष: \_\_\_\_\_

**A.1** चैनल या बुके के मासिक उपभोक्ताओं की गणना सारणी-1 और सारणी-2 के अनुसार, प्रत्येक माह में चार बार दर्ज उक्त चैनल या बुके, जैसा भी मामला हो, के उपभोक्ता की गणना का औसत निकाल कर की जाएगी। उपभोक्ताओं की गणना को किसी मामले के लिए दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच दर्ज किया जाएगा।

सारणी 1— अला-कार्टे चैनलों के लिए मासिक उपभोक्ता गणना

क्र. सं.	चैनल का नाम	माह के 7वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 14वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 21वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 28वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	चैनल की मासिक उपभोक्ता गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=[(3)+(4)+(5)+(6)]/4
1.						
2.						

सारणी 2— पे चैनलों के बुके के लिए मासिक उपभोक्ता गणना

क्र. सं.	पे चैनलों के बुके का नाम	प्रसारक के बुके के घटक चैनलों का नाम	माह के 7वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 14वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 21वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 28वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	चैनल की मासिक उपभोक्ता गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=[(4)+(5)+(6)+(7)]/4
1.							
2.							

**B: उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट उन मामलों में, जिनमें कैरिज शुल्क का लेनदेन शामिल है ।**

रिपोर्ट का महीना: \_\_\_\_\_

वर्ष: \_\_\_\_\_

टारगेट मार्केट: \_\_\_\_\_

B1: चैनल वितरक के द्वारा कैरी किए जाने वाले चैनल के लिए मासिक उपभोक्ता संख्या की गणना इस अनुसूची के सारणी 1 के तरीके से की जाएगी।

B2: टारगेट मार्केट में सक्रिय उपभोक्ता आधार की औसत संख्या को सारणी-3 के विधि से प्रत्येक माह में चार बार दर्ज सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या का औसत निकाल कर ज्ञात किया जाएगा। नेटवर्क के सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या किसी मामले के लिए दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच दर्ज की जाएगी।

सारणी 3 – टारगेट मार्केट में सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या

एसटीबी का प्रकार	माह के 7वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह के 14वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह के 21वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह के 28वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह की सक्रिय उपभोक्ता आधार की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(2)+(3)+(4)+(5)]/4
स्टैंडर्ड डेफिनेशन					
हाई डेफिनेशन					

B3: स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल के कैरिज शुल्क की गणना के लिए टारगेट मार्केट में स्थापित स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स और हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार को लिया जाएगा।

B4: हाई डेफिनेशन चैनल के कैरिज शुल्क की गणना के लिए टारगेट मार्केट में स्थापित हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार को लिया जाएगा।

नोट:

- 1 टेलीविजन चैनलों के वितरक से सब्सक्राइब की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा इंगित स्थान पर लगे प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स में एक उपभोक्ता शामिल होगा।
- 2 रिपोर्ट केवल पढ़ने की अनुमति के साथ गैर-संशोधनीय पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट की जाएगी।

**दूरसंचार (प्रसारण एवं केवल) अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1) का व्याख्यात्मक ज्ञापन****पृष्ठभूमि**

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में, भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण को, अन्य कार्यों के साथ-साथ, भिन्न-भिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजनीयता की शर्तें और निबंधन निर्धारित करने और दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से प्राप्त अपने राजस्व सहभाजित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था विनियमित करने के कार्य सौंपे गए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2(k) के अनुसार, वर्ष 2004 में केंद्रीय सरकारी अधिसूचना के जरिए प्रसारण एवं केवल सेवाओं को प्राधिकरण के दायरे में लाया गया था। सेवा प्रदाताओं के बीच, अंतःसंयोजन एक तकनीकी-वाणिज्यिक समझौता है, जिसके जरिए सेवा प्रदाता, उपभोक्ताओं को प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने उपस्कर और जालक्रम (नेटवर्क) संयोजित करते हैं।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकरण समय-समय पर, प्रसारण एवं केवल सेवाओं के सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन हेतु विनियामक ढांचा अधिसूचित करता है। इस ढांचे के अंतर्गत सेवा प्रदाता, समझौता करने और प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने से प्राप्त राजस्व सहभाजित करने के लिए अपनी वाणिज्यिक और तकनीकी शर्तों को अंतिम रूप देते हैं।
3. प्रसारण एवं केवल सेवाओं के लिए प्रथम अंतःसंयोजन विनियम नामतः दूरसंचार (प्रसारण एवं केवल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 (2004 की 13) (जिसे इसमें आगे अंतःसंयोजन विनियम, 2004 कहा गया है) प्राधिकरण द्वारा 10/12/2004 को अधिसूचित की गई थी। ये मूलतः, उस समय प्रचलित एनॉलॉग मोड में टेलीविजन चैनल संकेतों के पुनः प्रेषण हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन समझौते विनियमित करने के लिए अधिसूचित किए गए थे। समय-समय पर, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), हेड एण्ड इन दि स्काई (एचआईटीएस) और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) आदि जैसे एड्रेसेबल प्रणाली शामिल करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 का दायरा स्पष्ट करने और उसका विस्तार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 की मूलभूत विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ टीवी चैनलों के

वितरकों को गैर-पक्षपातपूर्ण शर्तों पर किसी टीवी चैनल के संकेत उपलब्ध कराने, अंतःसंयोजन के लिए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्रकाशित करने, लिखित अंतःसंयोजन करार करने, टीवी चैनल के संकेतों के विसंयोजन और उपभोक्ता आधार का पता लगाने के लिए उपबन्ध सम्मिलित हैं।

4. प्रौद्योगिकी के विकास ने, केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण और एड्रसेबिलिटी का मार्ग प्रशस्त किया। केबल टीवी सेवाओं में एड्रसेबिलिटी वाला डिजिटलीकरण कार्यान्वित करने के लिए संसद ने 30 दिसंबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 संशोधित किया। बाद में, 28 अप्रैल, 2012 को भारत सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमावली, 2012 अधिसूचित की गई थी। केबल टीवी नियमावली, 2012 की अधिसूचना के तुरंत बाद, प्राधिकरण ने 30 अप्रैल, 2012 की दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियमावली, 2012 (2012 की 9) (जिसे इसमें आगे दूरसंचार विनियमावली, 2012 कहा गया है) अधिसूचित की। ये विनियम विशेष रूप से डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएस) के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली केबल टीवी सेवाओं के लिए लागू थे। जबकि दूरसंचार विनियमावली, 2004, गैर-एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए और डीटीएच, एचआईटीएस तथा आईपीटीवी जैसी अन्य एड्रसेबल प्रणालियों के लिए भी जारी रहीं। दूरसंचार विनियमावली, 2012 की मूलभूत विशेषताएं, ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अंतःसंयोजन नियमावली, 2004 की मूलभूत विशेषताओं के समान थीं।
5. 31 मार्च, 2017 के पश्चात भारत सरकार द्वारा अधिसूचित रूपरेखा के अनुसार, केबल टीवी सेवाओं की व्यवस्था करने की अनुमति, केबल डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली के जरिए ही प्रदान की जाएगी। अब तक अधिकांश डीएस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। डीएस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण और एड्रसेबिलिटी के कार्यान्वयन के साथ प्रसारण एवं केबल सेवाओं के अधिकांश उपभोक्ता, एड्रसेबल प्रणाली के जरिए ये सेवाएं प्राप्त करते हैं।
6. एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए उपलब्ध कराई गई प्रसारण एवं केबल सेवाओं को, 'एनालॉग नॉन-एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसारण एवं केबल सेवाओं की तुलना में अनेक लाभ प्राप्त हैं। एड्रसेबल प्रणालियां, उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने में दक्ष हैं और उपभोक्ताओं को सेवाएं चुनने में समर्थ करते हैं। उपभोक्ता, सिग्नल बेहतर गुणवत्ता, देखने की वृद्धित अनुभूति, चैनलों के अधिक विकल्प प्राप्त करते हैं और वे केवल उन्हीं चैनलों/सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, जिनके लिए वे अंशदान करते हैं। सेवा प्रदाताओं के लिए एड्रसेबल प्रणालियां, सत्यापनयोग्य मापदंडों पर आधारित पारदर्शी व्यवसाय लेन-देनों को समर्थ बनाती हैं, विषय-वस्तु की सुरक्षा को समर्थ बनाती हैं। सरकार द्वारा कर संग्रहण, बाजार के वास्तविक आकार के अनुरूप होता है।
7. डिजिटलीकरण का पूरा लाभ, पणधारियों को केवल तभी प्राप्त हो सकता है, यदि व्यवसाय संबंधी लेन-देन, उद्देश्य, मापनयोग्य और परिकलनयोग्य मापदंडों पर आधारित हो। प्रभावी प्रतियोगिता तभी संभव है, जब अंतःसंयोजन, पारदर्शी और गैर-पक्षपातपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित हो। प्राधिकरण को संज्ञान है कि अंतःसंयोजन विनियम ढांचा पारदर्शी और गैर पक्षपात पूर्ण नियमों को सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर में आवश्यक अनुशासन लाने में सहायक होना चाहिए। साथ ही साथ ढांचे में व्यवसाय करने और अभिनवीकरण के लिए मूल्य श्रृंखला में सेवा प्रदाताओं को आवश्यक स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसे सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और उपभोक्ताओं को प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराने में समर्थ होना चाहिए।
8. विनियामक ढांचे को, इस सेक्टर में होने वाली प्रमुख प्रगतियों के साथ गति बनाए रखने के लिए विकसित होना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण ने, एड्रसेबल प्रणालियों, जिनमें प्रशुल्क संबंधी आदेश और अंतःसंयोजन तथा सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओएस) विनियमावली शामिल हैं, के जरिए प्रदान की गई प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की संपूर्ण और हॉलिस्टिक तरीके से समीक्षा करने का निर्णय लिया।
9. स्थापित पद्धति के अनुरूप, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए, प्राधिकरण ने प्रशुल्क, अंतःसंयोजन और क्यूओएस मुद्दों पर परामर्श पत्रों की श्रृंखलाएं जारी कीं। "टीवी सेवाओं से संबंधित प्रशुल्क मुद्दे" विषय पर परामर्श पत्र 29 जनवरी, 2016 को जारी किया गया था, "एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए वितरित प्रसारण टीवी सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन ढांचा" 4 मई, 2016 को जारी किया गया था और "डिजिटल एड्रसेबल प्रणालियों और उपभोक्ता संरक्षण में सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे" 18 मई, 2016 को जारी किया गया था।
10. "एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए वितरित प्रसारण टीवी सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन ढांचा" (सीपी) विषय पर परामर्श के लिए, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पणधारियों को मूलतः एक महीने का समय दिया गया था। पणधारियों के अनुरोधों पर, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, एक सप्ताह के समय अर्थात् 10 जून, 2016 तक बढ़ा दी गई थी। प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 17 जून, 2016 थी। इस परामर्श सत्र के प्रत्युत्तर में पणधारियों से कुल 28 टिप्पणियां और 1 प्रति-टिप्पणी प्राप्त हुई थी। बाद में, पणधारियों के साथ अंतःसंयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में 13 जुलाई, 2016 को 'ओपन हाउस चर्चा' (ओएचडी) कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पणधारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था।
11. पणधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के विस्तृत विश्लेषण और उपलब्ध सूचना के आधार पर अंतःसंयोजन से संबंधित मुद्दों की आंतरिक जांच के पश्चात प्राधिकरण ने अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 नामतः दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवा) अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016 का मसौदा तैयार किया और व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें पणधारियों के साथ परामर्श हेतु अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के उद्देश्य और कारण विस्तार से दिए गए थे, के साथ यह मसौदा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। पणधारियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/विचार, विशेष रूप से मसौदे में सुझाए गए विशिष्ट मूल्यों पर, उपलब्ध कराएं। टिप्पणियों के लिए पणधारियों को 28 अक्टूबर, 2016 तक का समय दिया गया था, जिसे पणधारियों के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा 15 नवंबर, 2016 तक बढ़ा दिया गया था। पणधारियों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे अन्य विनियमावली के मसौदे/प्रशुल्क आदेशों के साथ और के अंदर विनियमावली की पूर्णता और सुसंगतता पर अपने इनपुट उपलब्ध कराएं। विचारों/टिप्पणियों को बेहतर समझने के लिए पणधारियों से अनुरोध किया गया था कि वे पर्याप्त औचित्य के साथ अपने इनपुट उपलब्ध कराएं। इसके प्रत्युत्तर में कुल 45 टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और ये लिखित टिप्पणियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई थीं। पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण के पश्चात, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा

अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियाँ) विनियमावली, 2016 को अंतिम रूप दिया। उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियाँ) विनियमावली, 2016 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

### **कॉपीराइट मामले**

- 12- मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियमावली, 2016 की प्रतिक्रिया में कुछ प्रसारकों द्वारा यह कहा गया है कि "गैर-अनन्य" तथा "अवश्य उपलब्धि" के संबंध में किए गए प्रावधान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के कुछ प्रावधानों के परस्पर विरोधी हैं। उनका यह दावा है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में विषय स्वामियों तथा प्रसारण संगठनों को अपने कार्य के लिए विशिष्ट लाइसेंस अथवा निर्धारण करने तथा प्रसारण पुनर्निर्माण अधिकार प्रदान करने की अनुमति प्राप्त है जबकि मसौदा विनियमों के अंतर्गत प्रसारकों से अनिवार्य तौर पर अपने चैनल टेलीविजन चैनलों के वितरकों को गैर अनन्य आधार पर उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गई है। उनका यह भी कहना है कि मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2016 में प्रसारकों को वितरकों के साथ मोलभाव करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।
- 13- प्राधिकरण का यह मानना है कि टेलीविजन चैनल एक पृथक् एवं अलग प्रकार का 'उत्पाद' है तथा इसमें फिल्में, खेल, नाटक, धारावाहिक, संगीत इत्यादि जैसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम प्रसारकों द्वारा स्वयं निर्मित किए जाते हैं अथवा वे अन्य विषय उत्पादकों अथवा उत्पादन गृहों से इनकी प्राप्ति लाइसेंस / निर्धारण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तदनुसार, टेलीविजन चैनल विभिन्न प्रकार के कॉपीराइट योग्य कार्य होते हैं जिनका स्वामित्व या तो उनके पास होता है या फिर प्रसारक द्वारा अन्य कॉपीराइट स्वामियों / लेखकों से इनकी प्राप्ति लाइसेंस / निर्धारण के माध्यम से की जाती है। इंटरक्नेक्शन विनियम, 2017 के प्रावधानों से किसी भी स्वरूप में यह नियंत्रण नहीं किया जा सकता कि प्रसारकों द्वारा किस मूल्य/रॉयल्टी पर अथवा किस प्रकार विषय स्वामियों से इनकी प्राप्ति की जा सकती है। इन विनियमों में किसी भी प्रकार से प्रसारकों द्वारा अपने टेलीविजन चैनलों के लिए विषय स्वामियों से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का नियमन नहीं किया गया है तथा न ही इसमें टेलीविजन चैनलों के लिए विशेष रूप से कॉपीराइट युक्त कार्यों के विनियमन की व्यवस्था की गई है। इन विनियमों के अंतर्गत तथापि डीपीओ को अंशदाताओं के सम्मुख प्रस्तुति के लिए टेलीविजन चैनलों की प्राप्ति बिना किसी पक्षपात के आधार पर होती है। तदनुसार प्रसारक द्वारा दिया गया यह दावा सही नहीं है कि विनियमों में किए गए प्रावधान कॉपीराइट अधिनियम के परस्पर विरोधी हैं।
- 14- प्रसारक द्वारा डीपीओ को गैर अनन्य आधार पर टेलीविजन सिग्नलों की अनिवार्य उपलब्धि तथा आरआईओ के आधार पर अनुबंध की अनिवार्यता प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परस्पर विरोधी होने के संबंध में किया गया दावा सुव्यवस्थित विधिक स्थिति के अनुसार नहीं है। इस मामले का निपटान माननीय टीडीएसएटी द्वारा मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लिमिटेड बनाम मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्यो के मामले की वर्ष 2014 की याचिका संख्या 295(सी) पर दिनांक 7.12.2015 को दिए गए निर्णय से हो गया था। मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लिमिटेड बनाम मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले के संबंध में माननीय टीडीएसएटी के निर्णय पर अपील दायर की गई थी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2016 की सिविल अपील संख्या 1446 को दिनांक 26.2.2016 को जारी आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।
- 15- प्रसारकों द्वारा आरआईओ के आधार पर इंटरक्नेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के तहत उन्हें अपने बीआरआर की लाइसेंसिंग के पारस्परिक मोलभाव के लिए प्राप्त अधिकार समाप्त होने के संबंध में दिया गया तर्क भी मान्य नहीं है। इस विषय पर इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 10 के साथ पठनीय नियम 9 के अंतर्गत भादूविप्रा के लिए प्रसारक तथा एमएसओ के मध्य इंटरक्नेक्शन के लिए किए जाने वाले मानक इंटरक्नेक्शन अनुबंध (एसआईए) का उल्लेख किए जाने की अनिवार्यता की गई है। तथापि, इन विनियमों के संबंध में भादूविप्रा द्वारा वस्तुतः प्रसारकों के लिए आरआईओ अथवा एसआई के संबंध में किसी प्रकार का ऐसा विनिर्देशन नहीं किया गया है जिससे नवोपाय एवं अपनी प्रस्तुतियों के प्रति उन्हें पूर्ण बाजार स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो। इन विनियमों से प्रसारकों को विनियमों / मूल्य सूची आदेश के अनुपालन की शर्त पर अपनी पसंद के अनुसार आरआईओ के निर्माण तथा डिजाइन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। माननीय टीडीएसएटी ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड के मामले में 2014 की याचिका संख्या 47(सी) पर अपने दिनांक 25.9.2014 के निर्णय में समान अवसरों की उपलब्धि के उपाय के सुनिश्चय के लिए आरआईओ की अवधारणा के लिए अनुमोदन दिया गया है। इन विनियमों में यदि कुछ किया जा सकता था तो वह यह है कि इनके संबंध में भादूविप्रा ने विनियामक द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप का दायरा कम कर दिया है।
- 16- ऊपर संदर्भित निर्णयों में माननीय टीडीएसएटी द्वारा कॉपीराइट तथा इंटरक्नेक्शन विनियमों के मामलों पर गहनता से विचार किया गया है तथा निश्चयात्मक रूप से यह निर्धारण किया गया है कि गैर-अन्ययता, पक्षपात रहित, इंटरक्नेक्शन प्रस्ताव के संदर्भ इत्यादि से संबंधित प्रावधान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रावधानों से परस्पर विरोधी नहीं हैं।

### **गैर-अपवर्जकता का सिद्धांत**

17. अंतः संयोजन विनियमावली, 2004 और अंतः संयोजन विनियमावली, 2012 में उन अपवर्जक समझौतों का निषेध किया गया है जो सेवा प्रदाताओं के बीच वितरण नेटवर्क तक पहुंच या टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त करने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं को रोकते हैं। गैर-अपवर्जकता के सिद्धांत की जांच प्राथमिकतः उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से की जानी होगी। जबकि इस परिस्थिति में, हालांकि बड़ी संख्या में प्रसारणकर्ता पूरे लोकप्रिय प्रकार से उपस्थित हैं, परंतु प्रतियोगिता टीवी चैनलों के एकाधिकार वाले स्वरूप के कारण अपूर्ण है। उसी प्रकार के अंदर टीवी चैनलों को उनके ब्रांडिंग और कार्यक्रमों की बनावट द्वारा एक-दूसरे से भिन्न कर दिया जाता है। वे उपभोक्ताओं की अवधारणा में पूर्ण विकल्प नहीं हैं

जैसाकि किसी एकाधिकार में एकाधिकार वाली प्रतियोगिता में फर्म मूल्य प्राप्तकर्ताओं के बजाय मूल्य निर्धारितकर्ता हैं। यदि किसी बाजार विशेष में मांग वाला कोई टीवी चैनल किसी एक टीवी वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं है और दूसरा लोकप्रिय चैनल उस बाजार में किसी प्रतियोगी वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं है तो उस बाजार में उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा चैनलों को देखने के लिए एक से अधिक ऑपरेटरों की सेवाओं हेतु अंशदान करना पड़ सकता है। प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर में, कुछ सीमा तक, प्रसारणकर्ताओं और डीपीओ के बीच वर्टिकल इंटीग्रेशन अभी भी मौजूद है। किसी भी प्रकार के ऐसे अपवर्जक समझौते, जिनके द्वारा लोकप्रिय टीवी चैनलों के सिग्नल किसी प्रतियोगी को मना किए जा सकते हैं ताकि प्रसारणकर्ता के एकीकृत वितरण नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा सके, उचित प्रतियोगिता और उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार, किसी डीपीओ द्वारा किसी प्रसारणकर्ता या एलसीओ के साथ कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था करना, डीपीओ के नेटवर्क तक अन्य प्रसारणकर्ता या अन्य एलसीओ की पुनः प्रेषण या टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त करने के लिए डीपीओ के नेटवर्क तक पहुंच को रोकता है, प्रतियोगिता के प्रतिकूल हो सकता है।

18. प्रसारण सेवाओं तथा केबल सेवाओं के क्षेत्र के विनियामक के तौर पर भादूविप्रा द्वारा इस क्षेत्र के लिए समान अवसर प्रदान करने एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के निर्माण का सुनिश्चय करने तथा उपभोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के हितों के संरक्षण का सुनिश्चय करने से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। तदनुसार, भादूविप्रा को बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकर सभी मामलों की देख रेख तथा प्रत्याशित आधार पर उपाय करने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्राधिकरण का ऐसा मानना है कि टेलीविजन चैनलों के वितरण के लिए किसी प्रकार की अन्ययता प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकर है तथा इसलिए इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए एवं सिग्नल के लिए प्रावधानों की अनिवार्यता स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता हित के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अर्थपूर्ण उपाय है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत था कि टीवी चैनल के वितरण में किसी भी प्रकार की अपवर्जकता प्रतियोगिता के लिए प्रतिकूल है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तदनुसार, अंतः संयोजन विनियमावली, 2016 में गैर-अपवर्जकता के आवश्यक उपबंध किए गए थे। अंतः संयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और इसलिए गैर-अपवर्जकता का सिद्धांत इन विनियमों में रखा गया है।

### **‘मस्ट कैरी’**

19. इसी प्रकार, ‘मस्ट कैरी’ संबंधी उपबंध, अविभेदकारी आधार पर और इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर डीपीओ के लिए प्रसारकों के टीवी चैनलों के सिग्नलों को कैरी करने को अनिवार्य बनाते हैं। ‘मस्ट कैरी’ संबंधी उपबंध इंटरकनेक्शन विनियम, 2012 में विद्यमान हैं जो डीएएस के जरिये मुहैया कराई जा रही केबल टीवी सेवाओं पर लागू थे। इंटरकनेक्शन विनियम, 2012 के ‘मस्ट कैरी’ उपबंध हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय चैनलों के प्रसारकों को उपभोक्ताओं को पुनःप्रसारित करने के लिए एमएसओ के नेटवर्क को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। हालांकि, इंटरकनेक्शन विनियम, 2004, जो गैर-एड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम और अन्य एड्रसेबल सिस्टम जैसे डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी को नियंत्रित करते हैं, में कोई ‘मस्ट कैरी’ उपबंध नहीं था। परामर्श पत्र में सभी एड्रसेबल सिस्टम के लिए एकसमान ‘मस्ट कैरी’ उपबंध बनाने का प्रस्ताव किया गया था।
20. वैल्यू चेन में सेवा प्रदाता याचक या प्रदाता के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब वितरक प्रसारक से टीवी चैनलों के सिग्नलों की मांग करता है तो वह एक याचक के रूप में काम करता है और ऐसे मामले में प्रसारक टीवी चैनल के सिग्नलों का प्रदाता बन जाता है। और जब प्रसारक इसके चैनल (चैनलों) के पुनःप्रसारण के लिए वितरक के नेटवर्क के लिए वितरक से संपर्क करता है, यह एक याचक का काम करता है और वितरक प्रदाता बन जाता है। ‘मस्ट प्रोवाइड’ उपबंध बाजार में मांग के आधार पर उपभोक्ताओं को टीवी चैनल उपलब्ध कराने में डीपीओ की सहायता करता है। इसी प्रकार, ‘मस्ट कैरी’ उपबंध लक्षित बाजार में प्रवेश करने के लिए टेलीविजन चैनल के मार्ग की बाधाओं को दूर करता है ताकि प्रसारक उक्त लक्षित बाजार में उपलब्ध डीपीओ के माध्यम से अपने चैनलों का वितरण कर सकें।
21. परामर्श पत्र के जवाब में अधिकांश प्रसारकों ने उल्लेख किया है कि ‘मस्ट कैरी’ उपबंध को सभी प्रकार के नेटवर्क पर लागू किया जाना चाहिए। जबकि, एक प्रसारक ने कहा है कि ‘मस्ट कैरी’ उपबंध डीटीएच और एचआईटीएस नेटवर्कों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस में ट्रांसपोजर क्षमता संबंधी बाधाएं हैं। कुछ डीपीओ ने कहा कि ‘मस्ट कैरी’ उपबंध को सीमित ट्रांसपोजर क्षमता के चलते डीटीएच और एचआईटीएस नेटवर्क के लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। परामर्श पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद, सभी प्रकार के एड्रसेबल सिस्टमों के लिए मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में ‘मस्ट कैरी’ उपबंध, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डीपीओ की अतिरिक्त क्षमता का आवंटन किया जाएगा, का प्रस्ताव किया गया था।
22. मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 के प्रत्युत्तर में एक प्रसारक ने सुझाव दिया कि इस खंड का पर्याप्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध-पत्रों की सही समय पर निगरानी अपेक्षित है। यह सुझाव दिया गया था कि प्रसारकों के चैनलों के पुनःप्रसारण के लिए उनके अनुरोधों को डीपीओ द्वारा केवल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किए जाएं। एक अन्य डीपीओ का यह मत था कि डीपीओ को किसी परिवर्तन के बारे में 30 दिन के बजाय 7 दिन के भीतर क्रम में लंबित चैनलों की सूची और अपने नेटवर्क की चैनल की कैरी करने क्षमता का पूरा विवरण प्रकाशित और अद्यतन करना चाहिए। कुछ प्रसारकों और एक एसोसिएशन ने कहा कि डीपीओ के लिए चैनल कैरी करने की न्यूनतम क्षमता निर्धारित नहीं करने से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रस्ताव मस्ट कैरी उपबंध मस्ट कैरी के सिद्धांत के महत्व को समाप्त कर देगा क्योंकि पात्र चैनल अनुरोध की टाइमिंग के कारण एक्सेस से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय चैनलों को क्षेत्रीय एमएसओ द्वारा कैरी किया जाना चाहिए। कई प्रसारकों ने यह सुझाव दिया कि डीपीओ सभी चैनलों/बुके, जो पिछले कैलेंडर तिमाही के दौरान उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, को प्रस्तावित विनियम के प्रभावी होने की तारीख से कम से कम अगले 60 दिनों तक कैरी करना जारी रखना चाहिए ताकि सभी प्रसारकों को समान अवसर उपलब्ध हो सकें।
23. डीटीएच ऑपरेटरों ने टिप्पणी की है कि सेटलाइट बैंडविड्थ कम मात्रा में उपलब्ध संसाधन है, जो अपेक्षित ट्रांसपोजर शामिल करने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों के लिए न केवल इसे अत्यधिक लागत वाला बनाता है बल्कि विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लंबे प्रतीक्षा समय (सामान्यतः 1-2 वर्ष) के कारण इसे प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए उनका मत है कि मांग को पूरा करने और अपने रिटेल ग्राहकों को प्राथमिकता देने के लिए इस बैंडविड्थ का किफायती और कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने की छूट उन्हें दी जाए।



24. डीटीएच ऑपरेटरों ने यह भी कहा है कि 'पहले आओ पहले पाओ' को उन मामलों में लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है और/या उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं। 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के कारण प्रसारकों और डीपीओ के बीच विवाद हो सकता है क्योंकि चैनल को कैरी करने के लिए प्रसारकों के अनुरोधों का प्राथमिकता स्तर का निर्धारण करना मुश्किल होगा। इसके कारण प्रशासनिक समस्या (डॉक्यूमेंटेशन, आदि) भी होगी, जिसे संभालना निजी कंपनी के लिए मुश्किल होगा। डीटीएच ऑपरेटरों ने यह भी कहा है कि इन चुनौतियों के कारण यह मीडिया कभी भी केबल ऑपरेटरों की बराबरी नहीं कर सकता इसलिए एक बिजनेस कंपनी होने के नाते यह उनका अधिकार है कि वे सेटलाइट स्पेस को सर्वाधिक संभावित बिजनेस अनुपात में बेचने में समर्थ बनें।
25. कुछ डीटीएच ऑपरेटरों ने कहा है कि मस्ट कैरी का उपबंध डीटीएच को उन चैनलों को भी कैरी करने के लिए बाध्य करेगा जिनकी मांग बेहद कम है या बिल्कुल भी नहीं है और यह डीटीएच ऑपरेटरों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी बेहद हानिकारक होगा। इसका प्रभाव डीटीएच ऑपरेटरों के ग्राहकों पर पड़ेगा जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। डीएच ऑपरेटर, जिनके पास क्षेत्र आधारित ऑफर हो सकते हैं, से भिन्न डीटीएच प्रचालन एक अखिल भारतीय प्रचालन है जिसमें डीटीएच ऑपरेटर को चैनलों को चुनकर अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करना होता है।
26. एक एमएसओ ने यह सुझाव दिया है कि 'मस्ट कैरी मुद्दे' से संबंधित विनियम में यह परंतुक शामिल किया जाए कि यदि शैली (श्रॉर) में शामिल चैनलों की संख्या उपलब्ध क्षमता के 10 प्रतिशत के बराबर हो जाती है तो वितरक को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर चैनल को कैरी करने से मना करने की आजादी होनी चाहिए।
27. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रसारक अपने टीवी चैनल केवल टीवी चैनलों के वितरकों के जरिये वितरित कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बाजार विशेष को सेवित करने के इच्छुक प्रसारक को उक्त बाजार में मौजूद टीवी चैनलों के वितरकों के जरिये उक्त बाजार विशेष को एक्सेस करने में समर्थ होना चाहिए। 'मस्ट कैरी' सिद्धांत चैनलों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क चैनल के वितरण के लिए एक्सेस करने योग्य है। डीपीओ द्वारा उक्त बाजार विशेष के लिए एक्सेस की मनाही के कारण उक्त प्रसारक के लिए जोखिम बढ़ सकता है क्योंकि वह किसी अन्य वैकल्पिक माध्यम के जरिये उक्त बाजार विशेष में अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए, व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता है ताकि प्रसारक की लक्षित बाजार में वितरण नेटवर्क तक पहुंचें।
28. दूसरी ओर एक डीपीओ बाजार में मांग और नेटवर्क संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अपने वितरण नेटवर्कों के लिए योजना तैयार करता है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि किसी दिए गए समय पर, जब कोई प्रसारक अपने चैनलों के पुनःप्रसारण के लिए वितरक से संपर्क करता है तो वितरण नेटवर्क में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्षमता संबंधी और वितरण नेटवर्क के लिए अविभेदकारी एक्सेस संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, इन विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
  - i. डीपीओ के लिए उनके लक्षित बाजार की घोषणा करने और कुल चैनल कैरी करने की क्षमता और विनियम में विनिर्धारित अन्य विवरण के साथ अतिरिक्त चैनल क्षमता को वेबसाइट पर प्रकाशित करने को अनिवार्य बनाया गया है क्योंकि नेटवर्क-नेटवर्क की क्षमता में अंतर हो सकता है,
  - ii. डीपीओ द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना में होने वाले बदलाव को इसे किए जाने की जारीख से सात दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना जरूरी होगा ताकि प्रसारक चैनलों को कैरी करने के लिए अनुरोध करने से पहले सही निर्णय ले सकें।
  - iii. नेटवर्क के लिए एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक इंटरकनेक्शन अनुबंध होना चाहिए।
  - iv. डीपीओ को क्रम में चैनलों की एक सूची बनानी होगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा, जिनके लिए उनके चैनलों के पुनःप्रसारण हेतु प्रसारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, हस्ताक्षरित अनुबंधों एवं अतिरिक्त चैनल क्षमता की अनुपलब्धता के कारण लंबित अनुबंधों की सूची भी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि यह एक्सेस मांगने वाले गैर-गंभीर कंपनियों के लिए अवरोधक का काम करेगा।
  - v. डीपीओ को टेलीविजन चैनलों के पुनःप्रसारण हेतु सूची में से सुसंगत तरीके से इसके नेटवर्क पर प्रत्येक वैकल्पिक अतिरिक्त चैनल क्षमता को आवंटित करना होगा। इससे अविभेदकारी मसले का समाधान होगा।
29. अतः प्राधिकरण ने फैसला किया है कि 'मस्ट कैरी' उपबंध को अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के अधीन सभी प्रकार के डीपीओ पर एकसमान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस तरह से डीपीओ को उनके नेटवर्क के लिए योजना बनाने की आजादी होगी तो प्रसारक अविभेदकारी आधार पर वितरण नेटवर्कों को एक्सेस करने में समर्थ होंगे।
30. प्रसारकों के लिए की गई "अवश्य उपलब्ध करवाने" की अनिवार्यता की व्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप प्रसारकों द्वारा डीपीओ को "अवश्य धारण करें" के दायित्व सौंपे जाने की काफी समय से की जा रही मांग का सम्मान करते हुए भादूविप्रा द्वारा इन विनियमों में सभी श्रेणियों के डीपीओ के लिए ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं। "अवश्य धारण करें" से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत डीपीओ द्वारा प्रसारकों के टेलीविजन चैनलों का वहन लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर बिना किसी पक्षपात के किया जाना अनिवार्य किया गया है।
31. डीपीओ द्वारा चैनल कैरी करने की न्यूनतम क्षमता की स्थापना के संबंध में कुछ हितधारकों के सुझाव पर प्राधिकरण ने टिप्पणी की है कि भारत विविध अपेक्षाओं वाला एक बहुवादी देश है इसलिए विभिन्न जनसंख्या की आधार पर ग्राहकों की पसंद में भिन्नता हो सकती है। डीपीओ जिस बाजार में काम कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क क्षमता का निर्माण करते हैं। इसलिए नेटवर्कों के लिए न्यूनतम

क्षमता को अनिवार्य करने से एक क्षेत्र का उद्देश्य पूरा हो सकता है मगर ये दूसरे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत, वितरण नेटवर्क के लिए चैनल कैंरी करने की न्यूनतम क्षमता को अनिवार्य बनाने से उपभोक्ताओं की लागत में वृद्धि हो सकती है। डीपीओ की कैंरी करने की क्षमता के मामले में बाजार शक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि डीपीओ की चैनल वहन क्षमता को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाए और इसीलिए इसे विनियामित नहीं किया गया है।

32. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आमतौर पर वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध चैनल बाजार में मांग के अनुसार डीपीओ द्वारा वितरित 'मस्ट कैंरी', 'मस्ट प्रोवाइड' और फ्री टू एयर चैनलों का मिश्रण हैं। इसलिये यह जरूरी है कि वितरण नेटवर्क की उपलब्ध क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए ताकि बाजार विशेष में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके। अतः ये विनियम इसके नेटवर्क की क्षमता पर पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। बहरहाल, अतिरिक्त चैनल क्षमता के संबंध में लंबित सूची से सुसंगत तरीके से प्रत्येक वैकल्पिक क्षमता का आवंटन करने को अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे चैनलों के लिए डीपीओ चैनल उपभोक्ताओं की औसत संख्या 20 प्रतिशत तक पहुंचने तक कैरिज शुल्क लेगा। अतः उपरोक्त व्यवस्था किसी भी तरीके से डीपीओ के बिजनेस योजना पर रोक नहीं लगाती है और प्रसारकों की चिंता का निवारण करने के साथ चैनल कैंरी करने की इसकी क्षमता पर इसके अधिकार की भी रक्षा करती है।
33. एमएसओ का यह सुझाव कि 'मस्ट कैंरी मुद्दे' से संबंधित विनियम में यह परंतुक शामिल किया जाए कि यदि शैली (श्रॉर) में शामिल चैनलों की संख्या उपलब्ध क्षमता के 10 प्रतिशत के बराबर हो जाती है तो वितरक को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर चैनल को कैंरी करने से मना करने की आजादी होनी चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि डीपीओ केवल वैकल्पिक अतिरिक्त क्षमता को आवंटित कर रहे हैं जो कैरिज शुल्क के साथ है। इसके अलावा, ऐसे चैनल को जारी रखने में उपभोक्ता की मांग की भी भूमिका होगी और यदि यह उपभोक्ताओं की संख्या के न्यूनतम प्रतिशत को प्राप्त करने में विफल रहता है तो चैनल को बंद करने के लिए पहले से प्रावधान किए गए हैं। इस मुद्दे पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।
34. 'मस्ट कैंरी' के अंतर्गत अलोकप्रिय चैनलों को कैंरी करने से डीपीओ को बचाने के लिए प्रारूप इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में प्रस्ताव किया गया था कि यदि उक्त टेलीविजन चैनल विशेष के मासिक शुल्क प्रत्येक पिछले क्रमागत 6 माह में इंटरकनेक्शन अनुबंध में विनिर्धारित लक्षित बाजार में उक्त वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत मासिक संख्या के 5 प्रतिशत से कम है तो डीपीओ टेलीविजन चैनल को कैंरी करने को बंद कर सकता है। इस मुद्दे पर, अधिकांश प्रसारकों का यह मत है कि इस तरह के प्रावधान डीपीओ को भेदभाव करने के लिए एकपक्षीय शक्ति दे सकते हैं और यह नेटवर्क तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ होगा और यह ऑपरेटर को चैनलों के लिए गेट कीपर के रूप में काम करने में समर्थ बनाएगा। एक प्रसारक ने यह सुझाव दिया कि यदि पिछले 6 माह में शुल्क उक्त अवधि के दौरान उक्त ऑपरेटर के औसत के कुल सक्रिय उपभोक्ता संख्या के न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर या उससे कम है तो चैनल को बंद करने के लिए डीटीएच और एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए प्रावधान किया जाए। कई प्रसारकों ने कहा है कि चूंकि एचडी की पैठ बहुत कम है इसलिए यह संभावना है कि कई मामलों में एचडी चैनल 5 प्रतिशत के मानक पर खरे नहीं उतरेंगे और उन्हें डीपीओ द्वारा बंद किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने इस संबंध में एचडी चैनलों के लिए संरक्षण की मांग की है। कुछ अन्य प्रसारकों ने कहा है कि इसी तरह अंग्रेजी शैली के चैनलों का मामला है, क्योंकि बहुत कम लोग अंग्रेजी भाषा के चैनलों की मांग कर रहे हैं। इसके विपरीत, कुछ डीपीओ ने उल्लेख किया है कि 6 माह के स्थान पर पिछले 3 माह के उपभोक्ताओं की औसत संख्या पर शुल्क प्रतिशत 5 प्रतिशत से कम बना रहता है तो डीपीओ को चैनल बंद करने की अनुमति दी जाए और ऐसे डिस्कनेक्शन के बाद उसी चैनल को दुबारा कैंरी करने से मना करने की अनुमति अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाए।
35. प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि ऐसे प्रावधान इंटरकनेक्शन, 2012 में विद्यमान हैं जो डीएस पर लागू थे। प्राधिकरण का यह मानना है कि ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करेंगे कि अलोकप्रिय चैनल वितरण नेटवर्क पर जगह को न घेरें और यह बाजार के अनुसार बेहतर गुणवत्ता वाले कंटेंट का सृजन करने के लिए प्रेरित करेगा। अतः मामूली आशोधन के साथ प्रावधान को बरकरार रखा गया है। अपेक्षित शुल्क स्तर बनाए रखने में विफल रहने पर डीपीओ अपने स्वविवेक से एक और वर्ष के लिए नेटवर्क हेतु एक्सेस प्रदान करने में मना कर सकता है।
36. डिजिटल नेटवर्कों की अनूठी खूबियों में से एक खूबी यह है कि यह हाई डेफिनेशन (एचडी) चैनलों के पुनः प्रसारण को सपोर्ट करता है। एचडी चैनलों में पिक्चर क्वालिटी और देखने का अनुभव बाजार में प्रचलित एसडी चैनलों के मुकाबले काफी बेहतर होता है। आमतौर पर, एचडी चैनलों का बिट-रेट तदनुगुणी एसडी चैनलों के बिट रेट से लगभग दो गुना होता है। अतः प्राधिकरण ने यह अनिवार्य किया है कि यदि डीपीओ द्वारा एक एचडी चैनल बंद या शामिल किया जाता है तो अतिरिक्त क्षमता की गणना करने के उद्देश्य से एक एचडी चैनल को दो एसडी चैनल के बराबर गिना जाएगा।
37. प्राधिकरण ने यह उल्लेख किया है कि केवल 17 प्रतिशत डीटीएच उपभोक्ताओं के पास एचडी सेट टॉप बॉक्स हैं और एमएसओ के उपभोक्ताओं के मामले में यह संख्या बहुत कम है। अतः ऐसी स्थिति में, डीपीओ के कुल उपभोक्ता आधार के 5 प्रतिशत से नीचे रहने वाला एचडी चैनलों का शुल्क अत्यधिक है। इसलिए प्राधिकरण का यह मानना है कि ऐसे चैनलों को संरक्षण की आवश्यकता है और यह निर्णय लिया गया है कि इस उप-विनियम के अंतर्गत एचडी चैनलों के मासिक शुल्क की गणना करने के लिए एचडी चैनल प्राप्त करने में समर्थ सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या पर विचार किया जाएगा।
38. बहरहाल, प्राधिकरण ने अंग्रेजी भाषा के चैनलों को संरक्षण के संबंध में कुछ हितधारकों के सुझाव पर असहमति जताई है क्योंकि भाषा या शैली (श्रॉर) के आधार पर चैनलों को संरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और चैनलों की भाषा के लिए उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर उपभोक्ताओं को अलग-अलग करना भी असंभव होगा।
39. वेब आधारित इंटरकनेक्शन अनुरोध प्रबंधन सिस्टम की स्थापना के संबंध में परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में हितधारकों के सुझाव पर प्राधिकरण ने ऐसे सिस्टम के विकास के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है।

**सिग्नल उपलब्ध कराने/नेटवर्क तक पहुंच के लिए समय-सीमा**

40. अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 में एक समयबद्ध तरीके से इच्छुक व्यक्ति को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यह उपबंध किया गया था कि सेवा प्रदाता को या तो अनुरोध की तारीख से 60 दिन के निश्चित समय में सिग्नल उपलब्ध कराने चाहिए और यदि सेवा प्रदाता अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो इस प्रकार मना करने के कारण लिखित में दर्ज किए जाने चाहिए और अनुरोध की तारीख से 60 दिन के अंदर इच्छुक व्यक्ति को संसूचित किए जाने चाहिए ताकि प्रभावित पक्षकार सुधारात्मक कार्यवाहियां कर सके या समुचित मंच के समक्ष कार्यवाई कर सके, जैसा भी मामला हो। समय से उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच समयबद्ध अंतःसंयोजन आवश्यक है। तथापि, पिछले समय में अनेक अवसरों पर प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि हालांकि सेवा प्रदाता (प्रसारणकर्ता या डीपीओज) ने निर्धारित समय के अंदर अनुरोधों का उत्तर नहीं दिया, परंतु परस्पर सहमति वाले लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए की गई वार्ताओं को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा गया जिससे विनियमों का उद्देश्य ही विफल हो गया। अनेक मामलों में लंबी खींची गई वार्ताओं के कारण 60 दिन की समयावधि का पालन किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया गया। परामर्श पत्र में समय से सिग्नल उपलब्ध कराने/ वितरण नेटवर्क तक पहुंच से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
41. परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारणकर्ताओं और कुछ डीपीओज ने किसी उप-विभाजन के बिना टीवी चैनल के सिग्नल उपलब्ध कराने/नेटवर्क तक पहुंच के लिए 60 दिन की मौजूदा समय-सीमा का समर्थन किया और सुझाव दिया कि किसी चूक के मामले में सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय प्रोत्साहन और निरुत्साहन लगाए जाएं। अन्य प्रसारणकर्ताओं ने टिप्पणी की कि टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी करने हेतु किसी प्रसारणकर्ता के लिए 60 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है और इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ डीपीओज ने बताया कि 60 दिनों को दो अवधियों अर्थात् 30-30 दिन की अवधि में उप-विभाजित किया जाए, पहली आपत्तियां उठाने के लिए, तकनीकी लेखा-परीक्षा आदि के लिए और दूसरी दोषों को दूर करने के लिए। एक केबल प्रचालक ने टिप्पणी की कि टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए 30 दिन पर्याप्त हैं।
42. प्राधिकरण ने नोट किया कि सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे टीवी चैनलों के सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले कुछ क्रियाकलाप करें, जैसे लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए वाणिज्यिक चर्चाएं, वितरण नेटवर्क का मूल्यांकन, एकीकृत रिसीवर डिकोडर्स (आईआरडी) की व्यवस्था और अन्य तकनीकी अवसंरचना। सिग्नलों को समय से नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चाओं को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने में होने वाले विलंब के परिणामस्वरूप टीवी चैनलों के सिग्नल/नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने में विलंब होता है। अनेक बार यह अवलोकन किया गया है कि या तो कुछ अतिरिक्त सूचना के अभाव के कारण या तकनीकी अथवा वाणिज्यिक आधारों पर करार करने से मनाही अनुमत अवधि के बिल्कुल अंत में प्रदाता द्वारा इच्छुक व्यक्ति को संसूचित की गई थी। इसलिए, 60 दिन के अनुमत समय का इस्तेमाल केवल अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने या मना करने के लिए नहीं किया जा सकता। करार पर हस्ताक्षर करने की समयावधि और टीवी चैनल के सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले किए जाने वाले बाकी अन्य क्रियाकलापों को इस प्रकार विभाजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विलंब को समाप्त किया जा सके। इसलिए, प्राधिकरण का मत था कि इसमें शामिल पक्षकारों को किसी सेवा प्रदाता से अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखित अंतःसंयोजन करार करके सभी वाणिज्यिक चर्चाओं को पूरा करना चाहिए और अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 30 दिन के अंदर टीवी चैनलों के सिग्नल/नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। तदनुसार, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में करार पर हस्ताक्षर करने और सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 60 दिन की अवधि को 30-30 दिन की अलग-अलग दो अवधियों में विभाजित करने के लिए आवश्यक उपबंध किए गए थे। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पणधारियों के पास, परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में पहले से ही शामिल कर ली गई टिप्पणियों के अलावा, कोई अन्य विशिष्ट टिप्पणी नहीं है और इसलिए, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यथाप्रस्तावित सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए समय-सीमा से संबंधित उपबंधों को इन विनियमों में रखा गया है।
43. विलंब के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन लगाने के पहलू पर प्राधिकरण ने नोट किया कि आमतौर पर सिग्नल/ वितरण नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने में होने वाले विलंब या तो करारों पर हस्ताक्षर करने में विलंब के कारण हुए थे या सेवा प्रदाताओं के बीच विभिन्न स्वरूप के विवादों के कारण। अब अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने और बाकी तकनीकी क्रियाकलापों के लिए समयावधियों का अलग-अलग किया जाना और संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर करारों पर हस्ताक्षर करने की शर्त से काफी हद तक अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने में होने वाले विलंबों से संबंधित मुद्दा हल करने में समर्थ होना चाहिए। सेवा प्रदाताओं द्वारा विवादों का हल समुचित रूप से या तो परस्पर चर्चाओं के जरिए किया जा सकता है या इस पर विवाद निवारण मंचों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए प्राधिकरण का यह मत है कि इस चरण में वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित करना आवश्यक नहीं।

**सिग्नलों/नेटवर्क तक पहुंच से मना करने के कारण**

44. अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच से मना करने के लिए अनुमत मापदंडों में से एक मापदंड भुगतान में चूक थी। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में भी परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात प्राधिकरण ने प्रस्ताव दिया कि उस उपबंध को जारी रखा जाए, जो "अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए" और "आवश्यक रूप से करना चाहिए" के सिद्धांत को ऐसे मामलों में गैर-लागू बनाता है, जहां इच्छुक व्यक्ति भुगतान में चूक करने वाला है और निरंतर चूक करता रहता है।
45. अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि किसी डीपीओ (इच्छुक व्यक्ति) द्वारा की जाने वाली चूक पर विचार करते हुए अंतःसंयोजन अनुरोध की मनाही के लिए एक तर्कसंगत मापदंड के रूप में इस सेक्टर में प्रचालनरत अन्य सभी प्रसारणकर्ताओं के साथ-साथ उस प्रसारणकर्ता के साथ डीपीओ द्वारा की गई चूक पर विचार किया जाना चाहिए। अन्य प्रसारणकर्ता ने टिप्पणी की कि मना करने के कारणों में तकनीकी विनिर्देशनों का पालन न करने वाले डीपीओज के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही/ डीपीओ के आपराधिक रिकार्ड, भुगतान न करने का प्रमाणिक ट्रैक रिकार्ड/ किसी प्रसारणकर्ता के साथ पिछली बकाया धनराशि शामिल होनी चाहिए।

46. किसी उद्योग के लिए पूरी मूल्य शृंखला में राजस्व प्रवाह, उस उद्योग के विकास हेतु सबसे आवश्यक होता है। यह बात सही है कि किसी आदी चूककर्ता सेवा प्रदाता को सिग्नल/ वितरण नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले कुछ अतिरिक्त शर्तों का सामना करना चाहिए। तथापि, गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से ऐसा करने के लिए उद्योग को किसी सेवा प्रदाता की चूक के स्तर को मापने के लिए एक इंडेक्स तैयार करने की आवश्यकता है, जो आज मौजूद नहीं है। जब कभी उद्योग द्वारा ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जाता है, तो यह कुछ अतिरिक्त शर्तें लगाने के लिए अन्य कारण हो सकता है। चूक से संबंधित मौजूदा उपबंध में यह शामिल है और पूर्ण नहीं। सेवा प्रदाता गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कोई तर्कसंगत शर्त लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने उस उपबंध को रखा है, जो "अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए" और "अवश्य करना चाहिए" के सिद्धांत को ऐसे मामलों में गैर-लागू बनाता है, जहां इच्छुक व्यक्ति भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है।

### डीपीओज के गुच्छे में किसी चैनल का पैकेजिंग

47. अंशदान की आसानी के लिए वितरक अंशदाताओं की मांग के अनुसार, चैनलों के गुच्छे का प्रस्ताव देते हैं। तथापि, पिछले समय में यह बात नोट की गई थी कि वितरकों द्वारा प्रस्तावित गुच्छों में उनके चैनलों की पैकेजिंग के लिए वितरकों पर प्रसारणकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। इस प्रकार की पद्धतियों के परिणामस्वरूप गुच्छे के एक भाग के रूप में कुछ लोकप्रिय चैनलों के साथ-साथ कुछ गैर-लोकप्रिय चैनलों के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। इस पद्धति के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की पसंद के साथ समझौता किया गया है क्योंकि अंशदाता घटक चैनलों के ए-ला-कार्ट मूल्यों की रकम और गुच्छे के मूल्य के बीच व्यापक अंतर के कारण ए-ला-कार्ट चैनलों के स्थान पर उस गुच्छे के प्रति अंशदान करने के लिए मजबूर थे। इस मुद्दे का हल निकालने की दृष्टि से अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि कोई प्रसारणकर्ता अंतःसंयोजन करार में कोई ऐसा खंड शामिल नहीं करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अंशदाताओं को प्रस्तावित किसी गुच्छे में चैनलों का पैकेज करने के लिए किसी डीपीओ के निर्णय को प्रभावित करता हो।
48. अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारणकर्ताओं ने यह राय व्यक्त की कि विशिष्ट पैकेजिंग की बात कहने के लिए प्रसारणकर्ताओं पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह किसी प्रसारणकर्ता के राजस्व प्रवाह को प्रभावित करता है। प्रसारणकर्ताओं ने यह भी कहा कि ताक वाले चैनलों को इसके कारण हानि होगी और यह भौगोलिक वितरण के हिसाब से चैनलों की पहुंच को प्रभावित करेगा और इसलिए यह इस उद्योग में अच्छी गुणवत्ता वाली विषय वस्तु प्रस्तुत करने को सीमित कर सकता है। एक समाचारपत्र प्रसारणकर्ता ने टिप्पणी दी कि डीपीओज को किसी मिश्रित/ चैनलों के मिश्रण के बजाय "प्रकार वाइस पैक्स" सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, व्यापक प्रकार को कवर करने वाले पैकेजों के लिए डीपीओज को प्रतियोगी प्रकार में अन्य चैनलों के साथ किसी चैनल को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
49. कुछ वितरकों ने सुझाया कि विनियमों में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए जो प्रसारकों को ऐसी शर्त लगाने से रोके जिसमें वितरकों को प्रसारकों द्वारा निर्मित बुकों को ले जाने आवश्यक हों। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा प्रावधान नहीं जुड़ता है तो प्रसारक अपने बुके को आगे देने की कोशिश करेगा कि सब्सक्राइबर द्वारा चुने बुके को।
50. इस मुद्दे का हल निकालने की दृष्टि से अंतःसंयोजन (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एडजस्टेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 में प्राधिकरण एक नया ढांचा लाया है, जिसमें प्रसारणकर्ता भुगतान चैनल या अनन्य ए-ला-कार्ट चैनल के रूप में अपना भुगतान चैनल घोषित करेगा। इस ढांचे के अनुसार, प्रसारणकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने भुगतान चैनलों का प्रस्ताव गुच्छे (गुच्छों) के रूप में दे। इसी प्रकार, किसी वितरक को भी यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह भिन्न-भिन्न प्रसारणकर्ताओं के भुगतान चैनलों का गुच्छा (गुच्छों) या ए-ला-कार्ट भुगतान चैनलों को शामिल करके अपना स्वयं का गुच्छा (गुच्छे) तैयार कर सके।
51. पणधारियों की ये दलीलें अधार्य हैं कि पैकेजिंग पर प्रस्तावित प्रतिबंध अच्छी गुणवत्ता की विषय-वस्तु के उत्पादन को सीमित कर सकते हैं और किसी प्रसारणकर्ता के राजस्व प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि उनकी पसंद के अनुसार, उपभोक्ताओं द्वारा चैनलों/गुच्छों के प्रति अंशदान द्वारा इसके मौद्रिकीकरण और उनकी मांगें पूरी करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली विषय-वस्तु का प्रस्ताव देने हेतु प्रसारणकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भौगोलिक वितरण के हिसाब से चैनलों की पहुंच में सुधार करने के लिए प्राधिकरण ने इन विनियमों में "अवश्य करना चाहिए" के उपबंधों का दायरा पहले ही बढ़ा दिया है। तथापि, अंशदान के हिसाब से चैनलों की पहुंच उपभोक्ताओं की पसंद पर छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि यह वितरण प्रणाली में एट्रेसेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक आधारों में से एक आधार है।
52. चूंकि गुच्छे बनाने की स्वतंत्रता दोनों पणधारियों को दी गई है, इसलिए यह आशा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर गुच्छे तैयार करेंगे। उपभोक्ताओं की पसंद के अलावा, गुच्छे का संघटन तय करने के लिए डीपीओज पर किसी प्रकार का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति को प्रभावित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपभोक्ताओं की पसंद गुच्छों का संघटन निर्धारित करने के लिए केवल एक मार्गदर्शी कारक बना रहे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी प्रसारणकर्ता वितरक के स्तर पर गुच्छा तैयार करने में हस्तक्षेप न करे।
53. चैनलों के अ-लॉ-कार्ट प्रसारण या बुके के रूप में प्रसारण के लिए आवश्यक है कि प्रसारक और वितरक के बीच में आवश्यक अंतःसंयोजन करार हो। यदि एक वितरक किसी प्रसारक के साथ बुके के लिए समझौता करता है परंतु उस बुके के कुछ चैनलों को अपने बुके में शामिल करता है तो दोनों के बीच शुल्क का लेन देन चैनलों के अ-लॉ-कार्ट के आधार पर अंतःसंयोजन करार के आधार पर होगा। इसलिए इन विनियमों में प्रसारक और वितरक के बीच अ-लॉ-कार्ट के आधार पर अंतःसंयोजन करार को आवश्यक किया गया है।
54. वितरकों के प्रसंग जो कि प्रसारकों द्वारा बुके के संबंध में है, प्राधिकरण का मत है कि यदि प्रसारक के द्वारा बनाए गए बुके के सभी चैनल वितरक के नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है तो वितरक को ऐसे बुके ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इन विनियमों में यह उपबंध किया गया है कि प्रसारणकर्ता अंतःसंयोजन करार में किसी पूर्व शर्त या किसी ऐसे खंड का उपबंध नहीं कर सकता, जो किसी गुच्छे में चैनल की पैकेजिंग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो।

**एलसीओज को सिग्नल उपलब्ध कराना**

55. डीएस और एचआईटीएच सेवाओं के मामले में अंतिम मील की संयोजनीयता अधिकांशतः एलसीओज द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। केबल टीवी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, एलसीओज उनके प्रचालन के क्षेत्र के प्रधान डाक घर में पंजीकृत किए जाते हैं। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में अनुरोध करने की तारीख से 60 दिन के अंदर एलसीओज को टीवी चैनल के सिग्नल समय से उपलब्ध कराने से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।
56. इन विनियमों में समय से सिग्नल उपलब्ध कराना और अंतःसंयोजन करार करना सुनिश्चित करने के लिए 60 दिन की समयावधि को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि डीपीओज को अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर अंतःसंयोजन करार कर लेना चाहिए और इसके पश्चात अगले 30 दिनों के अंदर एलसीओज को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने चाहिए।
57. मूल्य शृंखला में उचित राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इनवॉयस समय से जारी किए जाएं और देय भुगतानों का निपटान समय से किया जाए। व्यवसाय संबंधी लेन-देनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, को उत्तरवर्ती इनवॉयसों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अनेक बार पणधारियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के दौरान यह सूचित किया गया था कि या तो नियमित इनवॉयसों के अभाव में या उत्तरवर्ती इनवॉयसों में बकाया धनराशि को सूचित न किए जाने के कारण एलसीओज को अंतिम अनेक महीनों के लिए बकाया धनराशियों के रूप में भारी धनराशियों के भुगतान की मांग का अचानक सामना करना पड़ता है। अनेक बार एलसीओज को इस बात की सूचना नहीं होती कि उनके विरुद्ध इतनी भारी लंबित धनराशियां कैसे दर्शाई गई हैं, विशेष रूप से जब वे नियमित रूप से भुगतान कर रहे थे और बकाया धनराशियों को पिछले आसन्न समय में जारी किए गए इनवॉयसों में दर्शाया नहीं गया था। अक्सर इसके परिणामस्वरूप विवाद होते हैं और नए एमएसओ में स्विचिंग होता है।
58. इस मुद्दे का हल यह सुनिश्चित करके निकाला जा सकता है कि एलसीओज को मासिक आधार पर इनवॉयस जारी किए जाएं, जिनमें स्पष्ट रूप से चालू देय धनराशियां और बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, दर्शाई जाएं। इससे व्यवसाय संबंधी लेन-देनों में पारदर्शिता और मूल्य शृंखला में राजस्व प्रवाह भी सुनिश्चित होगा। इस सेक्टर में अशोध्य ऋणों की प्रथा को समाप्त करना आवश्यक है। यदि कोई एलसीओ किसी नए एमएसओ में स्विच करना चाहता है, तो अंतिम इनवॉयस में स्पष्ट रूप से उस एलसीओ के प्रति बकाया धनराशियों का स्तर दर्शाया जाएगा। एलसीओ को किसी वितरक के प्रति भुगतान के चूककर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यदि वह अपनी देय धनराशियों का भुगतान कर देने के एक प्रमाण के रूप में तदनुरूपी भुगतान रसीदों के तुरंत पहले के छः महीने के इनवॉयसों के प्रति प्रस्तुत कर देता है। यह शर्त एलसीओज पर अचानक थोपी जा रही अप्रत्याशित बकाया राशियों से एलसीओज को संरक्षित भी करेगी। तदनुसार, इस संबंध में उचित उपबंध बनाए गए हैं।

**न्यूनतम गारंटियों का निषेध**

59. न्यूनतम गारंटी भिन्न-भिन्न प्रकारों की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता पर इस बात के लिए दबाव डाल सकता है कि वह अंशदान शुल्क या कैरिज शुल्क के रूप में एक निर्धारित धनराशि का भुगतान करे, चाहे नेटवर्क में उपभोक्ताओं की संख्या या किसी चैनल के प्रति वास्तव में अंशदान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी भी हो। कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता से यह कह सकता है कि वह सिग्नल उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करे या यह शर्त लगाए कि उपभोक्ता आधार की एक निश्चित संख्या रखने वाला सेवा प्रदाता ही सिग्नल प्राप्त कर सकता है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि सेवा प्रदाता टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अपने चैनलों के अंशदान के एक न्यूनतम प्रतिशत के लिए एक गारंटी पर जोर दे सकता है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जहां अपने नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले कोई डीपीओ यह शर्त रख सकता है कि वह केवल अनुरोध किए गए चैनल ही चलाएगा, यदि प्रसारणकर्ता अतिरिक्त चैनल (चैनलों) के चलाने के लिए करार करे या डीपीओ अनुरोध किए गए चैनलों चलाने के लिए कुछ न्यूनतम अवधि विनिर्धारित करे।
60. अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 इस बात का निषेध करती है कि एड्रसेबल प्रणालियों में कोई भी सेवा प्रदाता किसी वितरक के साथ किए गए अंतःसंयोजन करार में कोई ऐसी शर्त नहीं लगाएगा, किसी ऐसे खंड पर जोर नहीं देगा या किसी ऐसे खंड का उपबंध नहीं करेगा, जो उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए अंशदान शुल्क के रूप में एक न्यूनतम गारंटीकृत धनराशि का भुगतान करना उस वितरक के लिए आवश्यक बनाए। इसी प्रकार, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में यह उपबंध किया गया है कि कोई सेवा प्रदाता किसी अन्य सेवा प्रदाता से उस सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के लिए अंशदान शुल्क के रूप में किसी न्यूनतम गारंटीकृत धनराशि धनराशि की मांग नहीं करेगा। प्रतियोगी बाजार किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार की न्यूनतम गारंटी पर जोर देने को प्रवेश संबंधी बाधा के रूप में माना जाता है और यह उपभोक्ताओं की पसंद पर प्रतिबंध लगाता है। न्यूनतम गारंटी के मुद्दे पर परामर्श पत्र में चर्चा की गई थी।
61. परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारणकर्ताओं और डीपीओज ने यह राय व्यक्त की थी कि उपभोक्ताओं की न्यूनतम गारंटीकृत संख्या या अंशदान शुल्क के रूप में कोई निर्धारित धनराशि जैसी शर्तों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रसारणकर्ताओं का यह विचार भी था कि अंशदाता की संख्या और चैनलों की दर, परिकलन के लिए प्रमुख मापदंड होना चाहिए, तथापि, अनुमत सीमा के अंदर नेटवर्क के आकार, एलसीएम (तर्कसंगत चैनल संख्याएं) समतुल्यता आदि के आधार पर छूट को परिकलन हेतु माना जाना चाहिए और एक पूर्व-शर्त के रूप में न्यूनतम गारंटी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डीपीओज ने न्यूनतम अंशदान गारंटी के निषेध का भी समर्थन किया।
62. अंतःसंयोजन पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार की न्यूनतम गारंटी तुल्य रूप युग के अतीत की बात है, जिसमें उपभोक्ताओं की संख्या या तो सत्यापनयोग्य थी या इस बात का पता लगाना कठिन था कि कितने उपभोक्ता चैनलों के प्रति अंशदान कर रहे हैं। इसलिए, उनके राजस्व का संरक्षण करने की दृष्टि से सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता से एक निर्धारित धनराशि वसूल किया करते थे या उपभोक्ताओं की एक न्यूनतम संख्या के लिए बिल दिया करते थे, चाहे अन्य सेवा प्रदाता उतने उपभोक्ता प्राप्त करने में समर्थ था या नहीं। इस सेक्टर में डिजिटलीकरण और एड्रसेबिलिटी के आरंभ होने के साथ एक विशेष चैनल में एक्सेस करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता गिना जा सकता है और इसका सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की निम्न रिपोर्टिंग की व्याकुलता राजस्व संबंधी हानि और इस सेक्टर में विवादों का एक मुख्य कारण था और इसी एड्रसेबल प्रणालियों द्वारा ठीक कर लिया गया है। इसके बावजूद, प्राधिकरण ने अवलोकन किया है कि कुछ और अन्य

रूप में न्यूनतम गारंटी इस सेक्टर में अभी भी जारी है। उपभोक्ताओं की संख्या के लिए किसी न्यूनतम गारंटी की शर्त या किसी निर्धारित शुल्क/ निर्धारित धनराशि की शर्त केवल प्रतियोगिता विरुद्ध ही नहीं है बल्कि यह नए सेवा प्रदाताओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधाएं भी उत्पन्न करती है। यह इस सेक्टर में डिजिटलीकरण और एट्रेसेबिलिटी को कार्यान्वित करने के उद्देश्य को भी विफल बनाती है। यह उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराने और सेवाओं को अधिक किरफायती बनाने के विरुद्ध है। इसलिए, जहां तक न्यूनतम गारंटी की धनराशि या निर्धारित शुल्क जारी करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकरण का विचार है कि सेवा प्रदाता न तो किसी निर्धारित धनराशि के भुगतान के लिए जोर दे सकता है और न ही अंतःसंयोजन करार में ऐसे शुल्क के भुगतान के किसी खंड का उपबंध कर सकता है। तदनुसार, इन विनियमों में आवश्यक उपबंध कर दिए गए हैं। एट्रेसेबिलिटी प्रणालियों की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणालियों (एसएमएस) में प्रसारण एवं केबल सेवा का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या गिनने के लिए एक पारदर्शी तंत्र का उपबंध किया गया है और इसलिए इसमें एक उपबंध किया गया है कि किसी डीपीओ द्वारा भुगतानयोग्य अंशदान शुल्क का प्रसारणकर्ता के हिस्से का परिकलन उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

63. जहां तक उपभोक्ताओं की किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी या उपभोक्ता आधार निर्धारित करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकरण का यह विचार है कि बाजार में प्रतियोगितात्मक सुनिश्चित करने और नए प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधा दूर करने के लिए किसी भी सेवा प्रदाता को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह न्यूनतम उपभोक्ता आधार या अपने चैनल (चैनलों) के न्यूनतम अंशदान प्रतिशत की गारंटी के लिए कोई पूर्व शर्त लगाए। तथापि, प्राधिकरण इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि अनेक सेवा प्रदाता, अपने चैनलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से अपने चैनल (चैनलों) के अंशदान के प्रतिशत या उपभोक्ता आधार के कुछ लक्ष्य पूरा करने पर अन्य सेवा प्रदाताओं को गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से विनिर्धारित सीमाओं के अंदर छूट प्रदान कर सकते हैं। किसी ऐसी स्थिति में इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण का यह विचार है कि ऐसी छूट के प्रस्ताव का निषेध करना अनुचित होगा। तथापि, किसी भी मामले में ऐसी शर्तें निर्धारित करने को, चैनल देने के लिए एक पूर्व-शर्त या सिग्नलों का बंद कर दिया जाना या सिग्नलों से मना कर दिया जाना माना जाना चाहिए।
64. जहां तक किसी डीपीओ द्वारा नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्व-शर्त के रूप में चैनल (चैनलों) की संख्या के लिए न्यूनतम गारंटी या अवधि हेतु न्यूनतम गारंटी निर्धारित करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकरण का यह विचार है कि इस प्रकार की पूर्व-शर्त प्रसारणकर्ताओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधा उत्पन्न करेगी और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई है तथा इस प्रकार की पूर्व-शर्त को अतर्कसंगत शर्त माना गया है। तथापि, डीपीओ लंबी अवधि के करार करने के लिए या अतिरिक्त चैनल चलाने के लिए एक्सेस का प्रस्ताव देने हेतु कैरिज शुल्क पर निर्धारित सीमाओं के अंदर छूट का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

#### **संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ):**

65. सेवा प्रदाताओं द्वारा आरआईओ का प्रकाशन गैर-पक्षपातपूर्ण और समान अवसर की शर्तें पूरी करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तरीका है। यह उनकी व्यवसाय संबंधी योजनाओं के अनुसार अपनी सेवाओं का प्रस्ताव देने के लिए सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त लचीलापन उपलब्ध कराता है। परामर्श पत्र में परस्पर सहमति वाली उन शर्तों के आधार पर अंतःसंयोजन करारों की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था, जो किसी प्रसारणकर्ता या डीपीओ द्वारा प्रकाशित आरआईओ का भाग नहीं है। इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि क्या आरआईओ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने का एकमात्र आधार होना चाहिए और आरआईओ में गैर-पक्षपातपूर्ण और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए दरों और छूटों सहित सभी शर्तें और निबंधन शामिल होने चाहिए।
66. जमीन पर गैर-पक्षपात को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए और परामर्शपत्र के प्रत्युत्तर में पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि या तो टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए या चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए नेटवर्क तक पहुंच के लिए अंतःसंयोजन करार आरआईओ के अनुसार किया जाना चाहिए।
67. अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारणकर्ताओं और एक प्रसारणकर्ता एसोसिएशन ने कहा कि केवल आरआईओ के आधार पर होने वाला अंतःसंयोजन करार व्यापार की शर्तों का मोल-तोल करने की प्रसारणकर्ताओं की योग्यता को छीनता है जबकि कॉपीराइट अधिनियम प्रसारणकर्ता संगठनों द्वारा परस्पर वार्ताओं की अनुमति देता है।
68. किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित किया गया आरआईओ एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसके आधार पर कोई सेवा प्रदाता गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर इच्छुक व्यक्तियों को नेटवर्क तक पहुंच या टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराना चाहता है। तथापि, पिछले समय में परस्पर सहमति वाली शर्तों पर लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में उपबंधित लचीलेपन की, विनियामक ढांचे के बाहर जाने और समान स्थिति वाले इच्छुक व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा अनेक बार गलत व्याख्या की गई थी। यह सेवा प्रदाताओं के बीच अनेक विवाद उत्पन्न कर रहा था। किसी विनियमित सेक्टर में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी सेवा प्रदाता अधिसूचित विनियमों और आदेशों के अनुसार अपने व्यवसाय संबंधी लेन-देन करें।
69. यह दलील कि केवल आरआईओ के आधार पर अंतःसंयोजन करार करना कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत प्रसारणकर्ताओं के अधिकार छीन लेता है, जो उन्हें अपने कार्य की लाइसेंसिंग के लिए परस्पर वार्ता करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान करता है, का गलत अर्थ लगाया गया है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ये विनियम, लागू होने वाले विनियमों का अनुपालन करने की शर्त के अधीन उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार अपने आरआईओज तैयार करने के लिए प्रसारणकर्ताओं को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। इने विनियमों में घोषित मापदंडों के आधार पर परस्पर चर्चाओं के पर्याप्त दायरे का उपबंध किया गया है। इस आरआईओ के ढांचे में नेटवर्क तक पहुंच या सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले सभी करारों के लिए एक सामूहिक और पारदर्शी आधार का उपबंध किया गया है। इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विनियामक ढांचे में सेवा प्रदाताओं के लिए आसान प्रवेश और निर्गमन के विकल्पों का उपबंध हो। इस सेक्टर में किसी नए प्रवेशकर्ता के लिए अपेक्षित निवेश की प्रतिबद्धता से पहले यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संपर्क प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत रूप से आश्वस्त हो। प्रसारण और केबल सेवा सेक्टर के मामले में किसी नए प्रसारणकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास घोषित शर्तों एवं निबंधनों पर नेटवर्क एक्सेस करने का तर्कसंगत आश्वासन हो। इसी प्रकार, किसी नए वितरक के लिए यह

आवश्यक है कि उसके पास घोषित शर्तों और निबंधनों पर टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त करने का तर्कसंगत आश्वासन हो। घोषित आरआईओ के बाहर किए जाने वाले परस्पर करार इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति की इस महत्वपूर्ण शर्त को विफल बनाते हैं।

70. यह इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि प्रवेश करने वाले नए ऑपरेटर ऐसी शर्तें प्राप्त करने के लिए विश्वस्त हो सकते हैं जो अन्य व्यक्तियों पर लागू होने वाली शर्तों की तुलना में कम अनुकूल होंगी। इस आरआईओ में स्वीकार्य शर्तों पर करार करने हेतु मापदंडों की परिभाषा दी जानी चाहिए और यह मापदंड उद्देश्यपरक, मापनयोग्य और परिकलनयोग्य होने चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण का यह विचार है कि सभी अंतःसंयोजन करार आरआईओ के अनुसार किए जाने चाहिए।

### **आरआईओ का परीक्षण**

71. इंटरक्नेक्शन विनियम, 2004 तथा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2012 के अनुसार सेवा प्रदाताओं से अपनी वेबसाइट पर आरआईओ के प्रकाशन की अपेक्षा की गई थी। इसके अलावा, इन विनियमों का निर्माण सेवा प्रदाताओं द्वारा आरआईओ की एक प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता के लिए भी किया गया था। यदि किसी भागीदार को ऐसा महसूस होता है कि आरआईओ की नियम तथा शर्तों से विनियामक फ्रेमवर्क के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है तो भागीदार आरआईओ के प्रदाता प्रकाशक के सम्मुख अथवा उचित न्यायाधिकरण के सम्मुख अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अनेक अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि ऐसी आपत्तियां आरआईओ के प्रकाशन की तिथि से काफी लम्बे समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रदाता द्वारा सुधार कार्रवाई, यदि कोई हो, करने में समय लग जाता है। इसके अलावा, इस आरआईओ के आधार पर अनेक अवेषकों के साथ पहले ही निष्पादित किए जा चुके अनुबंधों में आरआईओ में बाद के स्तर पर किए गए संशोधन के अनुसार संशोधन करने पड़ते हैं। इस मामले पर सीपी में चर्चा की गई थी जिसमें इस मामले के निपटान के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ था। मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2016 के संबंध में सीपी की प्रतिक्रिया में भागीदारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किए जाने के पश्चात यह प्रस्ताव दिया गया कि भागीदारों द्वारा वैल्यू श्रृंखला में की जाने वाली टिप्पणियों पर विचार करने पश्चात ही सेवा प्रदाता द्वारा आरआईओ के प्रकाशन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान किए जाने से अंतिम आरआईओ के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क के अनुपालन का भी सुनिश्चय हो सकेगा तथा विवादों में भी कमी आएगी। इस प्रक्रिया के पश्चात भी कोई भी असंतुष्ट भागीदार आरआईओ से संबंधित अपने विवादों के निपटान के लिए उचित न्यायाधिकरण से सम्पर्क कर सकता है।
72. इसकी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ प्रसारकों द्वारा यह टिप्पणी की गई कि डीपीओ को आपत्ति व्यक्त करने के अवसर देने तथा प्रसारकों के लिए उन पर विचार किए जाने की अनिवार्यता तथा की गई आपत्तियों के अनुसार संशोधन किए जाने से अनेक दुविधाएं उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि अनेक डीपीओ (डीटीएच/एमएसओ) कोई न कोई आपत्ति प्रस्तुत करते रहेंगे और आरआईओ को कभी अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सकेगा। एक प्रसारक द्वारा यह कहा गया कि डीपीओ को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाने चाहिए तथा केवल भादूविप्रा के पास ये अधिकार होने चाहिए और उसे ही प्रसारक द्वारा तैयार किए जा रहे आरआईओ के मसौदे तथा प्रकाशन में दखलंदाजी का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। एक डीपीओ द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रसारक के लिए अपनी आरआईओ अथवा संशोधित आरआईओ विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यापन के लिए भादूविप्रा को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता की जानी चाहिए। एक अन्य प्रसारक द्वारा यह कहा गया कि यदि आरआईओ विनियामक अपेक्षाओं के अनुसरण में नहीं है तो कोई भी भागीदार विनियामक अथवा माननीय टीडीएसएटी के सम्मुख इसके संबंध में सम्पर्क कर सकता है। अधिकांश डीपीओ द्वारा यह कहा गया कि सभी मसौदा आरआईओ की प्रस्तुति भादूविप्रा के सम्मुख किए जाने की अनिवार्यता की जानी चाहिए तथा अनुमोदन प्राप्त किए जाने के पश्चात ही इसका प्रकाशन किया जाना चाहिए। यदि इसमें उल्लंघन पाए जाते हैं तो विनियामक द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई खंड विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो इसके संबंध में चुनौती का अधिकार डीपीओ को भी दिया जाना चाहिए।
73. इस मामले पर विभिन्न भागीदारों द्वारा दी गई टिप्पणियों तथा प्रसारकों एवं वितरकों द्वारा आरआईओ के संबंध में किया जाने वाला अंतिमकरण प्रावधानों के अनुरूप होने पर विचार किए जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा यह प्रेक्षण किया गया कि आरआईओ के अंतिमकरण की प्रस्तावित प्रक्रिया से देरिया तथा कार्यों की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसके अलावा इससे यह निश्चित भी नहीं होता है कि सेवा प्रदाता द्वारा अंतिम आरआईओ का प्रकाशन किए जाने के पश्चात विवाद उत्पन्न होंगे अथवा नहीं। इस अतिरिक्त बाधा को यह सुनिश्चय करते हुए सरलता से दूर किया जा सकता है कि सेवा प्रदाता द्वारा प्रारम्भ से ही अपने आरआईओ का प्रकाशन विनियामक फ्रेमवर्क का अनुसरण करते हुए ही किया जाए। इसके अलावा ऐसे मसौदा इंटरक्नेक्ट प्रस्ताव की अनुमति दिया जाना, जो इंटरक्नेक्ट विनियमों के अनुसरण में नहीं है, प्रसारकों एवं डीपीओ के मध्य इंटरक्नेक्शन विनियमन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकरण का यह विचार है कि प्रसारक तथा डीपीओ आरआईओ के प्रकाशन के समय अत्याधिक सावधानी बरतकर प्रारम्भिक स्तर पर ही अपने चैनलों अथवा नेटवर्क, जैसा भी मामला हो, से संबंधित प्रस्तुतियां प्रस्तुत करें ताकि इसकी प्रस्तुति विनियमों एवं मूल्य सूची आदेश के अनुसार हो सके। सभी नियम तथा शर्तें आरआईओ का भाग होंगी ताकि अन्य पक्षों द्वारा इसपर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात यह पूर्ण इंटरक्नेक्शन अनुबंध का भाग बन सके। इस कारण से इस घटक से संबंधित प्रावधान संशोधित कर दिए गए हैं। इन विनियमों में आरआईओ की एक प्रति प्राधिकरण को रिकार्ड के लिए प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता की गई है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आरआईओ के अनुबंध विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप न होने पर भागीदारों को अपनी आपत्तियां उचित न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

### **वितरण शुल्क और छूट**

74. मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2016 में, प्रसारकों द्वारा अपने पे चैनलों और पे चैनलों के बुके पर दी जाने वाली छूट कैर वितरण शुल्क के लिए निर्धारित मूल्यों/दरों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी। वितरण शुल्क पे चैनल या पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के अधिकतम खुदरा मूल्य की 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर रखने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी प्रस्ताव किया था कि प्रसारक चैनल या बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य पर डीपीओ को उस सीमा तक छूट की पेशकश कर सकते हैं कि वितरण शुल्क और छूट ऐसे चैनल या बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक न हों। इसी प्रकार यह भी प्रस्ताव किया गया था कि डीपीओ उसके द्वारा घोषित कैरिज शुल्क की दर पर 35 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश कर सकते हैं।

- 75 इस मुद्दे पर, एक प्रसारक ने यह टिप्पणी की कि वितरण शुल्क अधिकतम खुदरा मूल्य का 10 प्रतिशत होनी चाहिए और स्थापन शुल्क एवं मार्केटिंग शुल्क प्रसारक के विभिन्न छूट मानदंडों में सम्मिलित किया जाए जिसकी उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत हो और आरआईओ में इसका पारदर्शिता के साथ प्रकटन किया जाए। जबकि एक दूसरे प्रसारक का यह मत था कि वितरण शुल्क को कम करके 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए और अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना चाहिए, वो भी 35 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के कोई बदलाव किए बगैर। दूसरी ओर अधिकांश डीपीओ ने सुझाव दिया कि वितरण शुल्क 20 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि यह सीएस क्षेत्र में था। एक डीटीएच ऑपरेटर ने कहा कि 20 प्रतिशत का वितरण शुल्क वितरकों की राजस्व सृजन क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करेगा और उन्हें अपनी आय के लिए प्रसारकों की मूल्य-निर्धारण नीति पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि डीटीएच ऑपरेटर लगभग 4 से 5 प्रतिशत लागत का व्यय संग्रहण लागत के रूप में करते हैं। संग्रहण लागतें एमएसओ द्वारा वहन नहीं की जाती हैं। तदनुसार, एमएसओ के लिए डीटीएच के लिए वितरण मार्जिन 20 प्रतिशत ही रहेगा, क्योंकि लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व और संग्रहण लागत का 10 प्रतिशत है, 5 से 6 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन डीटीएच ऑपरेटरों को मुहैया कराया जाना चाहिए।
- 76 इस विनियामक ढांचे में चैनलों के वितरण की लागत को चैनलों की लागत से पृथक किया गया है। टैरिफ आदेश के अनुसार, चैनलों, जिसमें उपभोक्ता प्रबंधन शामिल है, के वितरण की लागत वसूल करने के लिए वितरकों को नेटवर्क क्षमता शुल्क प्रभारित करने की अनुमति दी गई है। अतः डीपीओ का यह दावा कि वे अपनी आय के लिए प्रसारकों की मूल्य-निर्धारण नीति पर निर्भर रहेंगे, तर्कसंगत नहीं है। वितरण शुल्क केवल पे टेलीविजन चैनल (चैनलों) या साधारण पे चैनलों के बुके (बुकों) के वितरण के उद्देश्य के लिए है। यह तथ्य कि डीटीएच ऑपरेटरों को सरकार को लाइसेंस शुल्क देना अपेक्षित है, को ध्यान में रखते हुए भुगतानों के संग्रहण एवं लेखा में शामिल वितरकों के व्यय, एमएसओ और एलसीओ आदि के बीच वितरण शुल्क में हिस्सेदारी के संबंध में प्राधिकरण ने अधिकतम खुदरा मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत को वितरण शुल्क के रूप में निर्धारित किया है। डीपीओ का यह सुझाव कि वितरण शुल्क 20 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि यह सीएस क्षेत्र में था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उस समय उपभोक्ताओं द्वारा कोई पृथक नेटवर्क क्षमता शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता था। यह विनियामक ढांचे की तुलना सीधे पूर्ववर्ती विनियामक ढांचे से नहीं की जा सकती, जिसमें वितरण और चैनल की लागत एक साथ थी।
- 77 व्यवसाय में उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट आपूर्तिकर्ता को वैल्यु चेन में कुशलता बढ़ाकर अपनी बिक्री बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है। दूसरी ओर उच्च छूट भेदभाव और उपभोक्ता की पसंद पर रोक लगाने का जरिया बन सकता है। विगत में देखा गया था कि कई बार सेवा प्रदाता अपने आरआईओ में अपने उत्पादों एवं सेवाओं के लिए काफी उच्च दर घोषित कर देते हैं और फिर ऐसी दरों भारी छूट देते हैं। छूट की गैर-तर्कसंगत राशियों के कारण भ्रामक/गलत मूल्य निर्धारण और गैर-बराबरी वाला वातावरण बन सकता है। इसलिए, प्राधिकरण को लगता है कि इस तरह की छूटों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि इसे पारदर्शी, मापयोग्य और अविभेदकारी शर्तों पर मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा, प्राधिकरण ने कुछ प्रसारकों के इस विचार से सहमति जताई है कि आरआईओ में घोषित मूल्यों पर छूट की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा तय की जानी चाहिए। इससे उनकी सेवाओं के लिए इष्टतम मूल्य घोषित करने में मदद मिलेगी अर्थात् वो मूल्य जिस पर सकल राजस्व को अधिकतम किया जा सके। यह एक समान सेवा प्रदाताओं के बीच भेदभाव की संभावना को भी कम करेगा। विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझाई गई छूटों पर उच्चतम सीमा 33 से 50 प्रतिशत के बीच हो सकती है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि वितरण शुल्क और डीपीओ को दी जाने वाली छूट का योग अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। इसी प्रकार, डीपीओ द्वारा प्रसारकों को दिए जाने वाले कैरिज शुल्क की दर पर अधिकतम छूट भी 35 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा, विनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि आरआईओ में दी जाने वाली ऐसी छूट निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अविभेदकारी शर्तों के आधार पर आरआईओ में दी जानी चाहिए और छूट के पैरामीटर मापयोग्य एवं गणनायोग्य होंगे।
- 78 इन विनियमों में एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें प्राधिकरण आदेश के माध्यम से वितरक उन चैनलों पर कैरिज शुल्क पर 35 प्रतिशत से अधिक छूट दे सकती है जो जनता की भलाई के लिए हों।

### कैरिज शुल्क

- 79 डीपीओ के नेटवर्क पर इसके टीवी चैनल (चैनलों) को कैरी करने के लिए प्रसारक द्वारा डीपीओ को अदा किए गए प्रभार को सामान्यतः उद्योग द्वारा कैरिज शुल्क कहा जाता है। कैरिज शुल्क का ट्रेंड एनालॉग के दौर में शुरू हुआ था और इसका कारण शायद टीवी सिस्टम में ट्रांसमिशन मीडियम के बैडविड्थ की कमी था। सामान्यतः एक एनालॉग केबल टीवी सिस्टम लगभग 80-100 टीवी चैनल कैरी कर सकता है जबकि प्रसारक के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या नेटवर्क की क्षमता से अधिक है। हालांकि एड्जेस्टेबल सिस्टम में चैनल कैरी करने की क्षमता बढ़ी है मगर उसी दौरान अनुमति प्राप्त प्राइवेट सेटलाइट टीवी चैनलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। डीपीओ द्वारा संस्थापित हेड-एंड उपस्कर ने भी एमएसओ के नेटवर्क की कैरी करने की क्षमता को कम किया है। नेटवर्क क्षमता को और बढ़ाने के लिए डीपीओ को अपनी नेटवर्क अवसंरचना को अपग्रेड करना होगा जिसके लिए डीपीओ को अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। ऐसी लागतों के कुछ हिस्से की भरपाई के लिए प्रसारक और डीपीओ के बीच कैरिज शुल्क ट्रांजेक्शन होती है।
- 80 टीवी सेवाओं के टैरिफ संबंधी परामर्श पत्र में कैरिज शुल्क संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया था। परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारक कैरिज शुल्क के भुगतान की पद्धति के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि डिजिटल नेटवर्कों में क्षमता संबंधी तंगी अब चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि एड्जेस्टेबिलिटी के साथ सब्सक्रिप्शन राजस्व में स्थिर वृद्धि हुई है और इसलिए कैरिज शुल्क पर डीपीओ की निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। प्रसारकों की ओर एक यह सुझाव आया था कि प्राधिकरण को 50 पैसे से लेकर एक रुपए प्रति चैनल प्रति सेट टॉप बॉक्स पर वार्षिक कैरिज शुल्क की उच्चतम सीमा के साथ डीपीओ द्वारा अवसंरचना लागत पर किए गए व्यय के आधार पर कैरिज शुल्क निर्धारित करना चाहिए।
- 81 इसके विपरीत, डीपीओ ने कैरिज शुल्क के किसी विनियम का समर्थन नहीं किया और प्रस्ताव किया था कि आपस में बातचीत द्वारा कैरिज शुल्क तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वितरण नेटवर्क की क्षमता डिजिटलाइजेशन के बाद भी बाधा बनी हुई है और कैरिज शुल्क डीपीओ को चैनल क्षमता बढ़ाने और अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक डीपीओ ने सुझाव दिया था कि प्रारंभ



में कैरिज शुल्क 2 से 5 रुपये के बीच प्रति चैनल प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह रखा जाए और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ इसे धीरे-धीरे कम किया जाए।

- 82 मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में यह प्रस्ताव किया गया था कि अधिकतम दर, जो एक डीपीओ चैनल कैरी करने की एवज में प्रसारक से वसूल कर सकता है, एसडी चैनल (एचडी चैनल के लिए 0.40 प्रति उपभोक्ता प्रति माह) के लिए 0.20 रुपये प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह होगी और इसकी गणना संबंधित बाजार में सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के आधार पर की जाएगी और चैनल के मासिक सब्सक्रिप्शन में वृद्धि के साथ इसे धीरे-धीरे कम किया जाएगा और यदि चैनल विशेष उक्त बाजार में 20 प्रतिशत पैठ प्राप्त कर लेता है यह शून्य हो जाएगी।
- 83 मसौदा विनियम, 2016 के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि कैरिज शुल्क का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि टैरिफ आदेश के संदर्भ में नेटवर्क क्षमता शुल्क डीपीओ द्वारा उपभोक्ता से लिया जाता है। प्रसारक ने यह कहा था कि कैरिज शुल्क को उक्त चैनल को सब्सक्राइब करने वाले उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या के आलोक में देखना चाहिए न कि उपभोक्ता आधार के। जबकि दूसरे प्रसारक ने सुझाव रखा कि कैरिज शुल्क पर 10 पैसा प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह की उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की कि चैनलों (जैसे अंग्रेजी भाषा, जीईसी, फिल्में, खबरें आदि) के कतिपय सेट के लिए कैरिज शुल्क की गणना करने के लिए राज्यों के संदर्भ में लक्षित बाजार को शहरों में उपविभाजित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- 84 समाचार प्रसारकों और उनकी एसोसिएशनों ने टिप्पणी की है कि समाचार प्रसारकों से कोई कैरिज एवं स्थापन/मार्केटिंग शुल्क प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए। एक और प्रसारक ने टिप्पणी की कि कैरिज शुल्क पर उच्चतम सीमा लगाने के अलावा, स्थापन शुल्क को नियंत्रित किया जाए और इस पर उच्चतम सीमा लगाई जाए। एचडी चैनलों के लिए प्रसारकों ने सुझाव रखा कि एचडी चैनलों के लिए कैरिज शुल्क की गणना करने के लिए केवल प्रसारक द्वारा यथा घोषित लक्षित बाजार में डीपीओ के एचडी चैनल आधार पर विचार किया जाए।
- 85 अधिकांश प्रसारकों ने मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 की अनुसूची-1 में विनिर्धारित कैरिज शुल्क की गणना करने की पद्धति पर अपना असंतोष प्रकट किया है। उनकी आशंका थी कि इस तरह की गणना से डीपीओ अपने कैरिज लाभ के लिए चैनल को 20 प्रतिशत से पार नहीं जाने देगा क्योंकि डीपीओ कभी ऐसे मॉडल को पसंद नहीं करेगा जिसमें चैनल उन्हें कोई कैरिज शुल्क अदा किए बगैर उपभोक्ताओं की 20 प्रतिशत की संख्या के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कुछ समाचार प्रसारकों ने कहा कि फ्री टू एयर चैनलों के लिए सभी कैरिज यथा कैरिज शुल्क/मार्केटिंग शुल्क/स्थापन शुल्क को मिलाकर यह 0.20 रुपए प्रति माह प्रति एसटीबी होना चाहिए। बहरहाल, एक व्यक्ति ने कहा है कि 0.20 रुपये के कैरिज शुल्क की दर से कैरिज शुल्क घटक में अत्यधिक कमी आएगी और प्रसारकों को इससे काफी फायदा होगा।
- 86 अधिकांश डीपीओ ने यह सुझाव दिया कि कैरिज शुल्क की गणना में स्लैब सिस्टम नहीं होना चाहिए, इससे डीपीओ का पैकेज के लिए अधिकार समाप्त हो जाएगा। एक डीपीओ ने कहा है कि कैरिज शुल्क ट्रांजेक्शन बिजनस से बिजनस (बी2बी) प्रकृति का है इसलिए इसे विनियामित करना उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा। अधिकांश डीपीओ ने एसडी और एचडी चैनलों के लिए कैरिज शुल्क की सीमा को क्रमशः 20 से 80 पैसे और 40 से 1.20 पैसे करने का सुझाव दिया है।
- 87 इस विनियामक फ्रेमवर्क में टैरिफ आदेश के अनुसार, चैनलों के वितरण की लागत वसूल करने के लिए वितरकों को नेटवर्क क्षमता शुल्क प्रभारित करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह राशि एकल उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या के अनुसार भिन्न हो सकती है। अतः यह आशा है कि डीपीओ चैनलों के सिग्नल की मांग करेगा, जिनकी बाजार विशेष में अधिक मांग है। ऐसे चैनलों के लिए डीपीओ कैरिज शुल्क की मांग नहीं कर सकता क्योंकि यह उपभोक्ताओं से प्रभारित नेटवर्क क्षमता शुल्क से रिट्रांसमिशन व्यय वसूल करने में समर्थ होगा। बहरहाल, चैनल, जिनके लिए प्रसारक ने अनुरोध किया है, कैरी करने के लिए डीपीओ चैनल को उपभोक्ताओं की पर्याप्त संख्या द्वारा सब्सक्राइब किए जाने तक उपभोक्ताओं से प्रभारित नेटवर्क क्षमता शुल्क से पूरे रिट्रांसमिशन व्यय को वसूल करने में समर्थ नहीं होगा। डीपीओ के प्लेटफार्म पर चैनल विशेष को कैरी करने पर उसके द्वारा किए गए रिट्रांसमिशन शुल्क और उपभोक्ताओं से प्रभारित नेटवर्क क्षमता शुल्क की राशि के बीच को अंतर को पाटने के लिए डीपीओ को उस सीमा तक उक्त चैनल के प्रसारक से कैरिज शुल्क प्रभारित करने की अनुमति देना उचित होगा।
- 88 प्राधिकरण कुछ प्रसारकों के इस मत से सहमत है कि 'मस्ट कैरी' के सिद्धांत को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कैरिज शुल्क दर पर उच्चतम सीमा लगाना जरूरी है। विगत में, कई मौकों पर प्रसारक से कैरिज शुल्क के आंकड़े मांगे गए थे। मगर प्रसारक कैरिज शुल्क के लिए पृथक आंकड़े देने में विफल रहे थे। इसके स्थान पर उन्होंने मिश्रित आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें कैरिज शुल्क, स्थापन, मार्केटिंग शुल्क, तकनीकी शुल्क, बैंडविड्थ सपोर्ट और अन्य शुल्क शामिल थे, जिसकी वजह से डीपीओ के प्लेटफार्म पर चैनलों के रिट्रांसमिशन की लागत को वसूल करने के लिए अदा किए गए कैरिज शुल्क से संबंधित आंकड़ों को पृथक करना नामुमकिन था।
- 89 चूंकि डाटा उपलब्ध नहीं था इसलिए प्राधिकरण ने विभिन्न स्रोतों पर विचार किया जो टीवी चैनल की कैरिज शुल्क निकालने के लिए प्रासंगिक थे। दूरदर्शन द्वारा संचालित फ्री टू व्यू डीटीएच सेवा के मामले में, डीटीएच प्लेटफार्म पर एक चैनल को कैरी करने की क्षमता हासिल करने के लिए, 2016 में प्रकाशित आरएफपी के अनुसार आरक्षित मूल्य 4.30 करोड़ रुपये रखा गया था। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 20 से 30 मिलियन उपभोक्ता डीडी फ्री डिश सेवा का लाभ उठा रहे हैं। जो दर्शाता है कि एक चैनल को कैरी की प्रति चैनल लागत 2.15 रुपये प्रतिवर्ष है, 20 मिलियन उपभोक्ता के आधार पर 0.20 पैसा प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह है।
- 90 इस फ्रेमवर्क में, चैनलों, जिनकी मौजूदगी उपभोक्ताओं को ज्ञात नहीं है, को ध्यान में रखकर 'मस्ट कैरी' के उपबंध को स्थापित किया गया है। इसकी पहुंच का विस्तार करने के लिए कैरिज शुल्क वांछित लक्षित बाजार में प्रसारकों को डीपीओ से जुड़ने में समर्थ बनाएगी। ऐसे 6 प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जिनके पास अपने प्लेटफार्म पर 300-400 चैनलों को कैरी करने की क्षमता है। अधिकांश एमएसओ के पास 250-400 चैनलों की क्षमता है। प्राधिकरण ने टैरिफ फ्रेमवर्क में यह निर्णय लिया गया है कि वितरण व्यय वसूल करने के लिए डीपीओ द्वारा उपभोक्ताओं से नेटवर्क क्षमता राशि प्रभारित की जाएगी। फ्रेमवर्क में डीपीओ को उपभोक्ताओं से 100 चैनल हेतु नेटवर्क क्षमता राशि के लिए आश्वस्त किया गया है। प्रत्येक 25 चैनल के बंडल के लिए डीपीओ उपभोक्ता से अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता शुल्क के रूप में एक राशि, जो 20 रु. से अधिक नहीं होगी, प्रभारित कर सकता है। अतः चैनलों के सब्सक्रिप्शन में वृद्धि के साथ नेटवर्क क्षमता शुल्क भी बढ़ता है।

- 91 यह देखा गया है कि किसी घर द्वारा आमतौर पर सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या 80 से 100 के बीच होती है, जो डीपीओ की औसत प्लेटफॉर्म क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत बैठती है। अतः अगर कोई चैनल उपभोक्ता आधार का 20 प्रतिशत प्राप्त कर लेता है तो यह माना जा सकता है कि उक्त चैनल की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की गई है, जो 'मस्ट प्रोवाइड' के तहत कैरी किए जा रहे एक चैनल के बराबर है, और जिस पर कोई कैरिज शुल्क लागू नहीं होगा। अतः प्राधिकरण का मानना है कि चैनल लोकप्रियता हासिल कर लेता है इसके देखने वालों की तादाद ज्यादा है तो उक्त चैनल के लिए डीपीओ द्वारा सब्सक्रिप्शन से अर्जित अधिक राजस्व को देखते हुए कैरिज शुल्क की मात्रा कम की जानी चाहिए।
- 92 गणना में आसानी के लिए प्राधिकरण ने फैसला किया है कि दिए गए माह में यदि चैनल का मासिक सब्सक्रिप्शन लक्षित बाजार में डीपीओ के मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के 5 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, मगर 10 प्रतिशत से कम है तो उक्त माह में प्रसारक द्वारा देय कैरिज शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी, और यदि चैनल का मासिक सब्सक्रिप्शन मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार 10 प्रतिशत तक पहुंच जाता है मगर 15 प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी और यदि चैनल का मासिक सब्सक्रिप्शन मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार 15 प्रतिशत तक पहुंच जाता है मगर 20 प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क में 75 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यदि चैनल का मासिक सब्सक्रिप्शन दिए गए माह में मासिक औसत उपभोक्ता आधार के 20 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो डीपीओ उक्त माह के लिए कोई कैरिज शुल्क प्रभारित नहीं करेगा।
- 93 अतः प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी भी मामले में कैरिज शुल्क की दर 0.20 रुपये प्रति चैनल प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। चूंकि एचडी चैनलों द्वारा उपयोग की जा रही बैण्डविड्थ एसडी चैनलों के लिए अपेक्षित बैण्डविड्थ से लगभग दो गुना है इसलिए प्राधिकरण ने कैरिज शुल्क पर 0.40 रुपये की सीमा लगाई गई है। डीपीओ अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर अपने आरआईओ में कैरिज शुल्क की दर घोषित कर सकते हैं।
- 94 प्राधिकरण ने पाया कि वितरक के नेटवर्क पर उपलब्ध चैनल उन क्षेत्रों में पहुंचता है जो उस हैड-इंड या अर्थ स्टेशन के द्वारा कवर होता है। इसलिए वितरकों के द्वारा कैरिज फी की गणना उस हैड-इंड या अर्थ स्टेशन के मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्राधिकरण ने यह भी देखा कि एक विशेष हैड-इंड एक से ज्यादा क्षेत्रों को कवर करता है इसलिए टारगेट मार्केट एरिया को प्रदेश तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इसलिए प्राधिकरण ने यह तय किया है कि हर वितरक अपने हैड-इंड या अर्थ स्टेशन के द्वारा कवर एरिया को टारगेट मार्केट घोषित करेगा। हालांकि वितरक के लिए यह छूट होगी कि वह हैड-इंड या अर्थ स्टेशन के द्वारा कवर एरिया से कम एरिया को गैर भेदभाव तरीके से टारगेट मार्केट घोषित कर सकता है।
- 95 एचडी चैनल के मामले में प्राधिकरण ने यह देखा है कि अगर उपभोक्ता का एसटीबी एचडी चैनल के सिग्नल प्राप्त करने में समर्थ है तो एचडी चैनल देखें जा सकते हैं। इसलिए, एचडी चैनलों के कैरिज के लिए एचडी टीवी चैनल प्राप्त करने में समर्थ वितरकों के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार पर विचार किया जाना चाहिए। एचडी चैनलों का उपभोक्ता आधार बढ़ने पर कैरिज शुल्क में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। इससे उपभोक्ताओं के लिए एचडी एसटीबी को बढ़ावा मिलेगा और देखने की क्वालिटी में सुधार होगा। तदनुसार, विनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एचडी चैनल का कैरिज शुल्क निकालने के लिए लक्षित बाजार में उक्त माह में डीपीओ का औसत सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या में वो उपभोक्ता शामिल होंगे जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कुछ प्रसारकों ने अपनी टिप्पणियों में यह आशंका प्रकट की थी कि डीपीओ को उनके अपने लाभ के लिए चैनल को 20 प्रतिशत से पार जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चैनलों को कैरी करने के लिए अधिक सब्सक्रिप्शन शुल्क लेना डीपीओ के हित में है। इसके अलावा, यदि चैनल का कंटेंट आकर्षक है तो उपभोक्ता ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करना पसंद करेगा। डीपीओ उपभोक्ता की पसंद का चैनल देने से इंकार नहीं कर सकते।

### प्लेसमेंट

- 96 एड्रसेबल प्रणालियों में, प्रौद्योगिकी में एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका (ईपीजी) का उपबंध किया गया है, जिसमें किसी डीपीओ के नेटवर्क पर चलाए जा रहे चैनल सरल और समझने में आसान तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि उपभोक्ता इस संदर्शिका को आसानी से पढ़ सकें और सभी चैनलों के जरिए फिलपिंग के बजाय अपनी पसंद का चैनल चुन सकें। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में डीपीओज के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे ईपीजी में प्लेटफॉर्म में उपलब्ध सभी चैनलों का सूचीकरण ऐसे तरीके से करें कि उपभोक्ता आसानी से अपनी पसंद का चैनल चुन सकें। एक ही प्रकार के चैनलों के बीच किसी चैनल का प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में, ईपीजी में टीवी चैनलों के प्रकार और भाषा-वार सूचीकरण का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा, मसौदे में यह भी प्रस्ताव दिया गया था कि प्रसारणकर्ता ईपीजी में किसी स्थान विशेष पर अपने चैनल रखने के लिए डीपीओ को सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु या अपने चैनल को कोई विशेष नंबर देने के लिए कोई पूर्व-शर्त नहीं रख सकता। इसलिए, कार्यान्वित करने के लिए ऐसी शर्त व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दो प्रसारणकर्ता अपने टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने से पहले एक पूर्व-शर्त के रूप में ईपीजी में उसी स्थान पर रखने के लिए जोर देते हैं तो वह पूर्व-शर्त पूरी करना किसी डीपीओ के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
- 97 प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारणकर्ताओं ने यह राय व्यक्त की कि चैनलों का प्लेसमेंट और प्लेसमेंट शुल्क को विनियामक ढांचे के दायरे में लाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, गैर-विनियमित प्लेसमेंट और विपणन शुल्क मॉडल को गैर-पारदर्शी बनाता है और एलसीएन के लिए डीपीओज तथा प्रसारणकर्ताओं के बीच किए गए करारों की अनुमति देकर पिछले दरवाजे से प्रवेश का अवसर देता है।
- 98 प्रशुल्क आदेशों में प्रसारणकर्ताओं को अपने चैनलों का प्रकार घोषित करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इन विनियमों के अनुसार यह बात अनिवार्य बनाई गई है कि कोई डीपीओ प्रसारणकर्ताओं द्वारा घोषित किए गए संबंधित प्रकारों के अंतर्गत ईपीजी में चैनलों को स्थान देगा। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य बनाया गया कि डीपीओ एक ऐसे तरीके से एक ही प्रकार के चैनलों को स्थान देगा कि उसी प्रकार के अंदर उसी भाषा के सभी टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में एकसाथ लगातार दिखाई दें। एलसीएन नंबर में बार-बार परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की दृष्टि से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक बार आबंटित एलसीएन नंबर कम से कम एक वर्ष की

अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा। इसलिए, चैनलों के प्लेसमेंट पर्याप्त रूप से विनियमित कर दिए गए हैं और प्रसारणकर्ता को आवश्यक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है ताकि उनके चैनल ईपीजी में किसी अलाभकारी स्थान पर न रखे जाएं। इसलिए, किसी प्रसारणकर्ता के लिए ईपीजी में किसी विशिष्ट स्थान पर रखने के लिए कहने की कोई शर्त नहीं है।

- 99 संशोधित विनियामक ढांचे में उपभोक्ता की पसंद पर अधिक जोर दिया गया है। इसलिए, जब उपभोक्ता केवल उन्हीं चुनिंदा चैनलों को चुनेंगे, जो वे वास्तव में देखना चाहते हैं तो चैनलों के प्लेसमेंट का महत्त्व पूरी तरह कम हो जाएगा। इसके अलावा, विनियामक ढांचे में कैरिज और प्लेसमेंट के बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। पणधारियों की मांग के अनुसार, कैरिज शुल्क को विनियमित कर दिया गया है और 'अवश्य चलाना चाहिए' वाले उपबंध गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से वितरण नेटवर्क में एक्सेस सुनिश्चित करेंगे। पहले सेवा प्रदाताओं द्वारा इन दोनों प्रकार के शुल्कों को एकसाथ मिला दिया गया था और संयुक्त शुल्क का भुगतान न करने से नेटवर्क तक एक्सेस के लिए किसी चैनल से मना किया जा सकता था। अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। चैनलों के पिलेस्मेंट के लिए 15 प्रतिशत तक के डिस्काउंट की सीमा का निर्धारण उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा क्योंकि यह पे चैनलों के लिए समान अवसर नहीं प्रदान करेगा क्योंकि फ्री - टु - एयर चैनलों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य शून्य होता है। तथापि, यदि कोई प्रसारणकर्ता अभी भी किसी विशेष स्थान पर अपना चैनल रखना चाहता है या अपने चैनल को कोई विशिष्ट नंबर देना चाहता है तो इन विनियमों के उपबंधों की शर्त के अधीन वह प्रसारणकर्ता विनिर्धारित ढांचे के अंदर छूट का प्रस्ताव दे सकता है या अंतःसंयोजन करार करने के पश्चात, चैनल को स्थान देने के लिए किसी वितरक को परस्पर सहमति वाले शुल्क का भुगतान कर सकता है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चैनलों के प्लेसमेंट के लिए किए गए ऐसे अंतःसंयोजन करार भी गैर-पक्षपातपूर्ण होंगे। ऐसे करार, यदि कोई हैं, मुख्य अंतःसंयोजन करार के साथ संलग्न किए जाएंगे और इन्हें समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- 100 यह बात नोट की जाती है कि शेरधारकों से प्राप्त टिप्पणियों में और सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए करारों में, विपणन शुल्क, ब्रांड विड्युथ समर्थन शुल्क, चैनल दृश्यता शुल्क आदि जैसे विविध शब्दों का इस्तेमाल भिन्न-भिन्न उद्देश्यों और प्रसारणकर्ताओं तथा डीपीओज के बीच वाणिज्यिक समझौतों के लिए किया गया है। इस प्रकार का वाणिज्यिक समझौता अंतःसंयोजन करार का एक प्रकार है और इसलिए यह गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर होना चाहिए। इसलिए, विनियामक संबंधी कमियों से बचने के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि यदि टेलीविजन चैनल (चैनलों) या भुगतान चैनलों के गुच्छे (गुच्छों) के संबंध में टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक के साथ एक से अधिक अंतःसंयोजन करार किया गया है, तो उत्तरवर्ती प्रत्येक अंतःसंयोजन करार में उस/ उन चैनल (चैनलों) या गुच्छे (गुच्छों) के लिए उस वितरक के साथ लागू पिछले करारों के ब्योरे दिए जाएंगे।
- 101 यह भी अवलोकन किया गया है कि अनेक बार अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा अन्य सेवा प्रदाता को विपणन के नाम से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कभी - कभी प्रसारक डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने चैनलों को उनके द्वारा बनाए गए बुकों में शामिल करने के लिए मार्केटिंग के नाम पर प्रोत्साहन देता है इन विनियमों में प्राधिकरण में यह साफ - साफ कहा है कि प्रसारक वितरक को अपने चैनलों को उनके बुके में शामिल करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं देगा क्योंकि यह चैनलों को सबकाइबर्स को अवांछित रूप में देने को बाध्य करता है। मार्केटिंग शुल्क का भुगतान किसी सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाताओं को सेवाओं को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए किया जाता है। इसलिए, इस प्रकार के शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट मापदंड नहीं हो सकता। इसलिए, इस चरण में ऐसे शुल्क पर प्राधिकरण द्वारा कोई विनियम निश्चित रूप से एक दोषपूर्ण विनियम होगा। फिर भी प्राधिकरण ने यह छूट दी है कि सेवा प्रदाता दूसरे सेवा प्रदाता को पारदर्शी तरीके से 15 प्रतिशत के अंदर आपसी सहमति से डिस्काउंट दे सकता है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि दो सेवा प्रदाताओं के बीच, किसी चैनल के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क के लिए किया गया कोई करार अंतःसंयोजन करार का भाग बनाया जाना चाहिए और उद्योग की पद्धतियों को मॉनीटर करने में प्राधिकरण को समर्थ बनाने हेतु प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।

#### **सिगनल मुद्देय कराने से पहले एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा**

- 102 प्राधिकरण ने अपने पिछले विनियामक फ्रेमवर्क में सिगनल मुद्देय कराने से पहले तकनीकी लेखा परीक्षा पद्धति निर्धारित की थी। परामर्श पत्र में एड्रेसेबल सिस्टम की तकनीकी लेखा परीक्षा की वर्तमान पद्धति के मुद्दों और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।
- 103 परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में, प्रसारकों ने मत प्रकट किया कि एमआईबी द्वारा कोई लाइसेंस प्रदान करने से पहले एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके प्रचालन के लिए लाइसेंस मांगने वाला कोई आवेदक एड्रेसेबल सिस्टम की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन करता है। एक डीटीएच ऑपरेटर ने टिप्पणी की है कि लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी प्रसारक की है, बहरहाल, ऐसी लेखा परीक्षा वर्ष में एक ही बार की जानी चाहिए और प्रत्येक नए चैनल के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा हर बार नहीं की जानी चाहिए। एक और डीटीएच ऑपरेटर ने कहा कि अगर प्रसारक तकनीकी लेखा परीक्षा करना चाहता है तो यह चैनल मुद्देय कराने के बाद की जानी चाहिए या साथ-साथ की जानी चाहिए और यह मत रखा कि भादूविप्रा या टीडीसैट या उपयुक्त फोरम को चूककर्ता पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ डीपीओ ने यह राय दी कि लेखा परीक्षा कराने का दायित्व प्रसारक का नहीं होना चाहिए और यह सुझाव दिया कि भादूविप्रा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों की सूची प्रकाशित कर सकता है, जिनसे डीपीओ अपने सीएस और एसएमएस की स्वतंत्र लेखा परीक्षा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कुछ डीपीओ ने टिप्पणी की है कि प्रसारकों के लिए 15 दिन के भीतर इंटरकनेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद 15 दिन के अंदर लेखा परीक्षा को पूरा करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए अन्यथा आईआरडी जारी होगा। एक एमएसओ और एक एलसीओ एसोसिएशन ने कहा कि अगर बीईसीआईएल/प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्लेटफार्म की जांच की जाती है तो बहरहाल कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, यदि ऐसी कोई जांच नहीं की जाती है तो प्रसारक 30 दिन के भीतर लेखा परीक्षा कराएगा। हितधारकों के सुझावों और चिंताओं को ध्यान में रखकर मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में कतिपय खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
- 104 मसौदा विनियम, 2016 के प्रत्युत्तर में प्रसारक एसोसिएशन ने कहा है कि प्रसारकों को अपनी तकनीकी टीम के जरिये डीपीओ के तकनीकी सिस्टम की लेखा परीक्षा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और बीईसीआईएल या पैनलबद्ध लेखा परीक्षक केवल पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि डीपीओ इसका फायदा उठा सकता है और सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और बाद

में बहाना बना सकता है कि इन सिस्टमों की लेख परीक्षा बीईसीआइएल द्वारा की जाती है और इसे प्रसारक द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक वर्ष के लिए मान्य है। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि सिस्टम में 0 प्रतिशत विसंगति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा तीन महीने में की जानी चाहिए न कि वर्ष में एक बार। एक और प्रसारक ने कहा कि आईबीएफ या किसी प्रसारक उद्योग निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा फर्म द्वारा पहली लेखा परीक्षा प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

- 105 डीपीओ के सिस्टम की लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि डीपीओ द्वारा कार्यान्वित सिस्टम विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार एड्रसेबल है और डीपीओ का नेटवर्क सिगनल की पाइरेसी के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है। टीवी चैनलों के सिगनल प्राप्त करने की प्रक्रिया में लेखा परीक्षा के कारण विलंब को रोकने के लिए यह वांछनीय है कि डीपीओ सुनिश्चित करें कि इसके द्वारा संस्थापित एड्रसेबल सिस्टम विनियमों में विनिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रसारक खुद यह सुनिश्चित करें कि डीपीओ का सिस्टम एड्रसेबल सिस्टम की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रसारकों और डीपीओ की अपेक्षाओं को संतुलित करने के लिए प्राधिकरण को लगता है कि लेखा परीक्षा कराने का दायित्व प्रसारक का होना चाहिए, बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा परीक्षा के कारण टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने की प्रक्रिया में विलंब न हों, एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, इन विनियमों में यथोचित प्रावधान किए गए हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।
- 106 लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्राधिकरण ने फैसला किया है कि यह लेखा परीक्षकों का एक पैनल बनाए, जिनमें से प्रसारक किसी एक को चुन सकते हैं। पैनलबद्ध लेखा परीक्षक द्वारा वितरण प्रणाली की लेखा परीक्षा और सत्यापन करने के बाद यह तर्कसंगत है कि दूसरे प्रसारकों को भी प्रमाणपत्र जारी होने के समय से कम से कम एक वर्ष के लिए इसे स्वीकार करना होगा। इससे न केवल सेवा प्रदाता के ऊपर लागत का बोझ कम पड़ेगा बल्कि लेखा परीक्षा की संख्या भी कम होगी। बहरहाल, संस्थापित एड्रसेबल सिस्टम के कॉन्फिगरेशन या वर्सन में कोई बदलाव होता है तो इस बात की जांच करनी होगी कि सिस्टम इन विनियमों की अनुसूची 3 में वर्णित अपेक्षाओं के अनुरूप है, टेलीविजन चैनल (चैनलों) के सिगनल मुहैया कराने से पहले इसे प्रसारक के लिए खोला जाएगा, यदि पिछले एक वर्ष के भीतर ऐसे वितरक के एड्रसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा की गई है तो वितरक के लिए एड्रसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा करना।
- 107 यदि प्रसारक किसी कारण, जिसके लिए डीपीओ जिम्मेदार है, से लेखा परीक्षा पूरी कराने में असमर्थ है, जिसके कारण वह टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने के अनुरोध की तारीख से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने में असमर्थ है तो इसकी सूचना निर्धारित अवधि के अंदर डीपीओ की दी जाएगी।
- 108 इसका भी प्रावधान किया गया है कि यदि प्रसारक के मत में वितरक का सिस्टम विनियमों की न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार नहीं है तो प्रसारक वितरक के सिस्टम का अंकेक्षण साल भर में एक बार कर सकता है। परंतु यह साफ किया जाता है कि प्रसारक एड्रसेबल सिस्टम की अनुपालना अथवा सब्सक्रिप्शन की रिपोर्ट के बारे में साल भर में सिर्फ एक बार ही अंकेक्षण कर सकता है। यदि वितरक की प्रणाली एड्रसेबल सिस्टम विनियमों के अनुसार नहीं है तो प्रसारक वितरक को 3 सप्ताह की लिखित सूचना देकर सिगनल को विच्छेदित कर सकता है।

#### **एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन**

- 109 प्राधिकरण ने अपने पिछले ढांचे में एसएमएस, सीएस और एसटीबीज आदि के संबंध में एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन विनिर्धारित किए थे। ये तकनीकी विनिर्देशन प्राथमिकतः एड्रसेबिलिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और नकल की रोकथाम करने में सहायता करते हैं। परामर्श पत्र में, प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगतियों के कारण विनिर्देशनों को अद्यतन बनाने, यदि आवश्यक हों, पर पणधारियों के इनपुट्स मांगे थे। इस मुद्दे पर अधिकांश पणधारियों की राय थी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मौजूदा तकनीकी विनिर्देशनों की वर्तमान बाजार परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में, पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात, वितरकों द्वारा संस्थापित प्रणालियों की गुणवत्ता और मानकों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ संशोधनों और अभिवर्धनों का प्रस्ताव दिया गया था।
- 110 विनियमों के मसौदे में उपभोक्ताओं की न्यूनतम 1 मिलियन की सक्षमता वाले एसएमएस की शर्त समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे अनेक एमएसओ हो सकते हैं जो अपेक्षाकृत कम उपभोक्ता आधार को सेवा प्रदान करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक डीपीओ के पास एक सही आकार की प्रणालियां मौजूद हों, एक उपबंध जोड़ा गया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि तैनात की गई प्रणाली 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता आधार के कम से कम 50 प्रतिशत का सक्रियकरण करने में पर्याप्त रूप से सक्षम होनी चाहिए।
- 111 अधिकांश प्रसारणकर्ताओं ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नकल न की जाए, विनिर्देशनों को और अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। एक डीपीओ ने कहा कि यह शर्त बहुत कठोर है कि तैनात की गई एड्रसेबल प्रणाली 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता आधार के कम से कम 50 प्रतिशत का सक्रियकरण करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होनी चाहिए और यह शर्त घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।
- 112 पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात कुछ उपबंधों को और अधिक सशक्त बना दिया गया है, जो इस प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और नकल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। प्राप्त हुए सुझावों के अनुरूप 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता आधार के कम से कम 50 प्रतिशत का सक्रिय करने की शर्त को संशोधित करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

#### **अंतःसंयोजन करार का क्षेत्र**

- 113 आर्गनिक प्रगति को समर्थ बनाने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में उपबंध किए गए थे, जिनमें इस बात को अनिवार्य बनाया गया था कि किसी प्रसारणकर्ता और किसी डीपीओ के बीच किए गए अंतःसंयोजन करार में, सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस/ अनुमति/ पंजीकरण में यथा उल्लिखित डीपीओज के प्रचालन के लाइसेंस में दिए गए/ अनुमतिप्राप्त/ पंजीकृत क्षेत्र, उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम, जिनके लिए टेलीविजन चैनल (चैनलों) के सिगनलों के वितरण पर अंतःसंयोजन करार करने के समय पर मूलतः सहमति व्यक्त की गई

है और तदनुसूची राज्य (राज्यों)/ संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों), जिनमें ये सहमतिप्राप्त क्षेत्र स्थित हैं, के नाम दिए गए होने चाहिए। यह उपबंध किया गया था कि डीपीओज प्रसारणकर्ता को कम से कम 30 दिन का एक पूर्व-लिखित नोटिस देकर अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों) में किसी प्रसारणकर्ता का/के टेलीविजन चैनल (चैनलों) के सिग्नल पुनःप्रसारित कर सकता है, बशर्ते कि यह/यह क्षेत्र अंतःसंयोजन करार में उल्लिखित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अंदर पड़ता हो।

- 114 प्रत्युत्तर में, कुछ प्रसारणकर्ताओं ने टिप्पणी की कि ऐसे विस्तारण के लिए कम से कम 60 दिन का पूर्व-नोटिस अनिवार्य किया जाना चाहिए और यह लिखित करार की शर्त के अधीन होना चाहिए और केवल डीपीओ द्वारा किसी लिखित नोटिस के आधार पर नहीं। जबकि अन्य प्रसारणकर्ताओं ने राय व्यक्त की कि इस प्रकार के विस्तारण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रसारणकर्ता के हित के विरुद्ध होगा और इसके परिणामस्वरूप अजवाबदेही होगी। इसलिए, नए क्षेत्रों के लिए नया करार निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि डीपीओ के अप्रतिबंधित मूवमेंट के कारण प्रतियोगी डीपीओज के बीच विवाद उत्पन्न होंगे। एक डीपीओ ने नोटिस अवधि को घटाकर 15 दिन करने का सुझाव दिया।
- 115 प्राधिकरण ने नोट किया कि गैर-एड्रसेबल प्रणालियों में किसी क्षेत्र के लिए अंतःसंयोजन करार करने से पहले उपभोक्ताओं की संख्या हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर विशिष्ट मूल्यांकन की शर्त के कारण अलग करारों की आवश्यकता थी। एड्रसेबल प्रणालियों के प्रादुर्भाव और एसएमएस में उपभोक्ता के ब्यारों की रिकार्डिंग के पश्चात ये शर्तें अब मौजूद नहीं हैं। यह प्रसारणकर्ताओं के हित में है कि उनके चैनलों की पहुंच बढ़ाई जाए ताकि उन्हें बेहतर अंशदान राजस्व और विज्ञापन संबंधी राजस्व प्राप्त हो सके। अंतःसंयोजन करार करने के समय ये आवश्यक उपबंध किए जा सकते हैं कि विनियमों के अनुसार क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इस करार के अंतर्गत जारी किया गया सूचना संबंधी नोटिस करार का एक भाग बन जाएगा और करार की सभी शर्तें और निबंधन विस्तारित क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। इसके अलावा, यह एमएसओज के हित में भी है क्योंकि वे अधिक कठिनाइयों के बिना प्रचालन के अपने क्षेत्र की योजना बना सकते हैं। यह दलील धार्य नहीं है कि डीपीओज के अप्रतिबंधित मूवमेंट प्रतियोगी डीपीओज के बीच विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई डीपीओ पंजीकरण के अंतर्गत अनुमतिप्राप्त क्षेत्र के अंदर अपने प्रचालनों का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। यह उपभोक्ताओं के लिए भी अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा। इसलिए यह स्थिति प्रत्येक के लिए लाभ की स्थिति है और यह इस सेक्टर में व्यवसाय करने की आसानी में सुधार करगी। इन विनियमों में लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए 30 दिन की समयावधि का उपबंध किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि सिग्नलों के पुनः प्रसारण का विस्तार करने से पहले सूचना हेतु 30 दिन की अवधि पर्याप्त है।

#### **डीपीओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार:**

- 116 डीएस और एचआईटीएस सेवाओं में स्थानीय केबल ऑपरेटर्स (एलसीओज) द्वारा अधिकांशतः अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा जारी किए गए आईपीटीवी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार एलसीओज आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के लिए अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध करा सकते हैं। उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी डीपीओ और एलसीओ के बीच दक्ष अंतःसंयोजन करार महत्वपूर्ण होते हैं। उपभोक्ताओं के लिए सेवा संबंधी मापदंडों की गुणवत्ता पूरी करने के लिए मूल्य शृंखला में एलसीओज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य शृंखला में किसी अन्य प्रतिष्ठान की तरह एलसीओज पंजीकृत सेवा प्रदाता हैं। केबल टीवी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, एलसीओज अपने प्रचालन के क्षेत्र के प्रधान डाक घर में पंजीकृत किए जाते हैं। गैर-अपवर्जकता, अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए, गैर-पक्षपातपूर्णता, लिखित करार और सिग्नलों के समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाने के मूलभूत सिद्धांत किसी डीपीओ और किसी एलसीओ के बीच किए गए अंतःसंयोजन करार पर भी लागू होते हैं।
- 117 परामर्श पत्र में डीपीओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार से संबंधित मुद्दे पर पणधारियों से कहा गया था कि वे इस बात पर अपनी राय दें कि क्या मॉडल अंतःसंयोजन करार (एमआईए) और मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए) का ढांचा, जैसाकि अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 के अनुसार अनिवार्य बनाया गया था, एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डीपीओज और एलसीओज के बीच अंतःसंयोजन करार के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण के पश्चात, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि एमएसओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार के लिए लागू विनियम एचआईटीएस/आईपीटीवी प्रचालक और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। इसके अलावा, स्थानीय केबल ऑपरेटर और डीपीओ के बीच सेवा प्रभारों का समझौता पारस्परिक करार द्वारा विनियमित होगा, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, जहां डीपीओ और एलसीओ सेवा प्रभारों के समझौते के लिए किसी परस्पर सहमति पर पहुंचने में विफल हो जाते हैं, तो नेटवर्क क्षमता शुल्क की धनराशि और वितरण शुल्क को एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में बांटा जाना था।
- 118 राजस्व हिस्सेदारी के मुद्दे पर एक एलसीओ ने कहा कि नेटवर्क क्षमता शुल्क की पूरी धनराशि एलसीओज द्वारा वसूल की जानी चाहिए क्योंकि एलसीओज ही ऐसे हैं, जो कॉक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर के अपने नेटवर्क के जरिए अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध करा रहे हैं। एलसीओज के पास अंशदान राजस्व के अलावा आय कर कोई अन्य साधन नहीं है, जबकि डीपीओज के पास राजस्व के अन्य स्रोत हैं जैसे स्थानीय वीडियो चैनलों पर विज्ञापन, फ्री टू एयर चैनलों का प्लेसमेंट और कैरिज शुल्क। उन्होंने आगे यह भी कहा कि एलसीओज को सेवा की अच्छी गुणवत्ता के लिए अपने नेटवर्क का अनुरक्षण करना होता है और अपने वर्करों को वेतन देना होता है तथा अपने उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए बिजली के बिलों का भुगतान करना होता है। तदनुसार, संग्रहण की इस लागत की प्रतिपूर्ति करने और नेटवर्क के प्रेषण और अनुरक्षण की दृष्टि से प्राधिकरण को यह निर्णय लेना चाहिए कि प्रसारणकर्ता भुगतान चैनल राजस्व के संग्रहण और प्रेषण के लिए वितरण शुल्क का 20 प्रतिशत एलसीओज को उपलब्ध कराएगा और डीपीओज को नहीं।
- 119 एमआईए और एसआईए के ढांचे में पर्याप्त लचीलापन और अपना व्यवसाय करने के लिए करार के पक्षकारों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वे सेवा प्रभारों और बिडिंग के संबंधित निर्धारण, जिम्मेदारियों के वितरण पर परस्पर सहमति व्यक्त करके उपभोक्ताओं को टीवी प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अंतःसंयोजन करार कर सकते हैं। इसके अलावा, यह उपबंध भी किया गया है कि परस्पर चर्चाओं की विफलता की स्थिति में एक फाल बैक विकल्प के रूप में एसआईए के अनुसार अंतःसंयोजन करार किया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण ने जिम्मेदारियों का सीमांकन कर दिया है और डीपीओ तथा एलसीओ के बीच सेवा प्रभारों का तदनुसूची निर्धारण निश्चित कर दिया है। एसआईए में एलसीओज

को उपभोक्ता केंद्रित जिम्मेदारियां दी गई हैं जबकि एमएसओ को ऐसी जिम्मेदारियां दी गई हैं जो प्रत्यक्ष रूप से एसएमएस से संबद्ध हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग शामिल है।

- 120 एड्रसेबल प्रणालियों में, एसएमएस में प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा अंशदानकृत चैनलों/गुच्छों तथा उपभोक्ता आधार के संबंध में आंकड़ा आधार दिए गए हैं। यह आंकड़ा आधार सत्यापनयोग्य और लेखापरीक्षा योग्य है। एमआईए और एसआईए के उपबंधों के अंतर्गत तदनुरूपी एसएमएस आंकड़ा आधार के एक्सेस को एलसीओ के साथ संबद्ध करने के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इन व्योरो के साथ अंशदान के सही-सही व्योरे डीपीओ और डीपीओ के साथ जुड़े एलसीओज को ज्ञात होते हैं। सेवा प्रभागों का निर्धारण, किए गए कार्य के सिद्धांत पर किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, जिम्मेदारियों का वितरण और डीपीओज तथा एलसीओज के वितरण नेटवर्क के अनुरक्षण की लागत मामला-दर-मामला आधार पर भिन्न-भिन्न है। डीपीओज के राजस्व के स्रोत और संबद्ध खर्च भी मामला-दर-मामला आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। एड्रसेबल प्रणालियों में अंतर्निहित इन असमानताओं और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का विचार है कि डीपीओ और एलसीओ परस्पर चर्चाओं के आधार पर सेवा संबंधी प्रभार निर्धारित करें। सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद के कारण सिग्नल बाधित न हों, प्राधिकरण ने केवल ऐसे मामलों के लिए डीपीओ और एलसीओ के बीच एक फाल बैक समझौता विनिर्धारित किया है, जहां डीपीओ और एलसीओ के बीच परस्पर चर्चाएं विफल हो जाती हैं और फिर भी वे अपने संबंध जारी रखना चाहते हैं।
- 121 मूल्य शृंखला में एलसीओ उपभोक्ताओं को अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध कराते हैं और उसे किए गए खर्च वसूल करने और लाभ की एक उचित राशि अर्जित करने में समर्थ होना चाहिए। एक एलसीओ का यह तर्क धार्य नहीं है कि नेटवर्क क्षमता शुल्क की पूरी धनराशि एलसीओ द्वारा वसूल की जानी चाहिए क्योंकि एलसीओ ही ऐसा व्यक्ति है, जो कॉन्सिडर केबल और ऑप्टिकल फाइबर के अपने नेटवर्क के जरिए अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि टीवी चैनलों के वितरण में डीपीओ के नेटवर्क और प्रणालियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, एलसीओ की यह दलील भी धार्य नहीं है कि संग्रहण और प्रेषण तथा नेटवर्क के अनुरक्षण की उनकी लागत की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से प्राधिकरण को यह निर्णय लेना चाहिए कि प्रसारणकर्ता भुगतान चैनल राजस्व के संग्रहण और प्रेषण के लिए वितरण शुल्क का 20 प्रतिशत एलसीओज को उपलब्ध कराएंगे और डीपीओज को नहीं क्योंकि भुगतान टीवी चैनलों के वितरण में डीपीओ तथा लिंक एलसीओ की सेवाएं शामिल होती हैं और एलसीओज का प्रसारणकर्ताओं के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। इस ढांचे में नेटवर्क की क्षमता केवल तथाकथित विनियामक ढांचे के अंशदान के एफटीए के समान हैं और इन दोनों के लिए उपभोक्ताओं को सेवाओं की प्रदायगी हेतु एक ही प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 के अनुसार किसी फाल बैक समझौते में सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे केवल एफटीए अंशदानों के संबंध में अंशदान संबंधी राजस्व को 55:45 के अनुपात में एमएसओ:एलसीओ के अनुपात में बांटें। इसलिए, प्राधिकरण ने नेटवर्क क्षमता शुल्क की धनराशि के बंटवारे के लिए वही अनुपात विनिर्धारित करने का निर्णय लिया है। भुगतान चैनलों के संबंध में भी चूंकि इस विनियामक ढांचे में भुगतान चैनल के वितरण में शामिल सेवा के लिए प्रभागों को भुगतान चैनल के मूल्य से अलग कर दिया गया है। इसलिए, भुगतान चैनलों के वितरण में शामिल वितरण शुल्क, जो डीपीओ और लिंक एलसीओ दोनों की सेवाओं के लिए प्रभागों के अनुरूप है, को उसी अनुपात में वितरित कर दिया गया है।

#### **सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट:**

- 122 एड्रसेबल प्रणालियों में किसी चैनल या भुगतान चैनलों के किसी गुच्छे के उपभोक्ताओं की संख्या लेखापरीक्षा योग्य और सत्यापन योग्य है। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में एड्रसेबल प्रणालियों के लिए अंशदान रिपोर्टों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।
- 123 अनेक अवसरों पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि डीपीओज प्रसारणकर्ताओं को समय से अंशदान रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराते। दूसरी ओर, डीपीओज ने अक्सर यह शिकायत की है कि प्रसारणकर्ताओं के पास अंशदान रिपोर्ट के लिए कोई संयुक्त फार्मेट नहीं है और अलग-अलग प्रसारणकर्ता के लिए हर बार ग्राहकोनुकूल रिपोर्टें तैयार करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है।
- 124 डीपीओज ने यह भी सूचना दी कि अक्सर प्रसारणकर्ता अंशदान संबंधी ऐसी सूचना मांगते हैं जो उस विशेष प्रसारणकर्ता के चैनल से संबंधित नहीं होती। दूसरी ओर, मासिक अंशदान की संख्याओं के परिकलन के तरीके पर प्रसारणकर्ताओं ने अनेक बार अपनी चिंता व्यक्त की है कि तत्कालीन विनियामक ढांचे के अनुसार तैयार की गई अंशदान रिपोर्ट में संभवतः उन उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया, जो किसी कैलेंडर मास में 30 या 31 दिन, जैसा भी मामला हो, से कम अवधि के लिए सक्रिय रहे हैं। यह उन्हें वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी स्थिति में रख सकता है। इन मुद्दों पर परामर्श पत्र में विस्तार से चर्चा की गई थी।
- 125 प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि सही अंशदान रिपोर्टों की समय से उपलब्धता इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति और मूल्य शृंखला में शेरधारकों का राजस्व सुनिश्चित करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। अंशदान रिपोर्ट में होने वाला कोई विलंब मूल्य शृंखला में बिलिंग चक्र और नकदी प्रवाह को प्रभावित करता है। पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें अंशदान रिपोर्ट का फार्मेट और अंशदान की संख्याओं के परिकलन के लिए पद्धति विनिर्धारित की गई थी। अंशदान रिपोर्ट की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विनियमावली के मसौदे में एक उपबंध किया गया था, जिसमें डीपीओज के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति से 15 दिन के अंदर अंशदान रिपोर्टें उपलब्ध कराएं। किसी भी कारण से डीपीओ से अंशदान रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारणकर्ता को यह अधिकार दिया गया था कि वह ठीक पिछले महीने के लिए वितरक द्वारा भुगतानयोग्य प्रसारणकर्ता अंशदान शुल्क की 10 प्रतिशत बढ़ाई गई धनराशि के लिए एक अनंतिम इनवॉयस जारी कर सके और वितरक पर यह दायित्व डाला गया था कि वह उस अनंतिम इनवॉयस के आधार पर भुगतान करे। इसके अलावा, बिल संबंधी आघात से बचने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया था कि किसी प्रसारणकर्ता द्वारा जारी किए गए इनवॉयस में स्पष्ट रूप से चालू भुगतान की देय धनराशियां और बकाया, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट किया जाएगा। निवारण के लिए एक यह उपबंध किया गया था कि प्रसारणकर्ता का किसी ऐसी बकाया धनराशि पर कोई दावा नहीं होगा, जो उस इनवॉयस जिससे बकाया धनराशि संबंधित है, के लिए नियत तारीख के पश्चात जारी किए गए तुरंत अगले तीन लगातार इनवॉयसों में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

- 126 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच अंशदान काउंट प्राप्त करने के लिए समयावधि के पहलू पर कुछ प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि प्राधिकरण को अपराह्न 07:00 बजे से प्रातः 09:30 बजे के बीच सूचना प्राप्त करने के लिए समयावधि में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। कुछ प्रसारणकर्ताओं ने यह राय व्यक्त की कि अंशदान रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपबंधित 15 दिन का समय घटाकर 7 दिन कर दिया जाना चाहिए। एक प्रसारणकर्ता एसोसिएशन ने इनवॉयसों में बकाया धनराशियों से संबंधित उपबंध समाप्त करने और किसी भी समय अपनी बकाया धनराशियों का दावा करने के अपने कानूनी अधिकार को पुनःस्थापित करने की बात कही। प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि प्रतिभूति जमा का उपबंध होना चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के मामले में, एक प्रसारणकर्ता ने सुझाव दिया कि पहले महीने के पश्चात विसंयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 127 दूसरी ओर, कुछ एमएसओ और उनकी एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि एक महीने में चार बार अंशदान काउंट प्राप्त करना एक कठिन कार्य है और यह ऐसे एसएमएस तथा सीएसएस को क्षति पहुंचाएगा जिससे प्रणाली का कार्य-निष्पादन प्रभावित होगा। उनके अनुसार, महीने के आरंभ और अंत में अंशदान काउंट प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया सही है।
- 128 सूचना प्राप्त करने की समयावधि में परिवर्तन करने के संबंध में कुछ पणधारियों के सुझाव पर यह नोट किया गया कि उपभोक्ता काउंट किसी उपभोक्ता द्वारा देखे जा रहे चैनल पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि किसी उपभोक्ता को देखने के लिए कौन सा चैनल प्राधिकृत किया गया है। इसलिए, रिपोर्ट प्राप्त करने के समय में परिवर्तन उपभोक्ताओं की संख्या में कोई अंतर नहीं लाएगा। यह प्रस्ताव प्राइम टाइम के लिए है। इसलिए, प्रस्तावित समयावधि में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक एक महीने में चार बार सीएसएस और एसएमएस से आंकड़े प्राप्त करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सीएसएस और एसएमएस को स्वतः आंकड़ा प्राप्त करने के लिए पूर्व कार्यक्रमबद्ध बनाया जा सकता है और इसके लिए किसी मैनुअल प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एक महीने में चार बार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आंकड़े और रिपोर्टिंग प्राप्त करने के लिए बड़ी हुई आवश्यकता को अनिवार्य करना वास्तविक उपभोक्ताओं के निकट उनके उत्पादों के मौद्रिकीकरण के लिए सेवा प्रदाताओं की सहायता करेगा। उपभोक्ता रिपोर्ट भेजने के लिए समय कम करने के मुद्दे पर प्राधिकरण, पणधारियों के विचार से सहमत है और इसलिए इसे प्रत्येक कैलेंडर मास के अंत से घटा कर 7 दिन कर दिया गया है।

### अंकेक्षण

- 129 मसौदा अंतर संयोजन विनियम 2016 में प्राधिकरण ने अंकेक्षण का एक तरीका प्रस्तावित किया था जिसका उद्देश्य सब्सक्रिप्शन सूचनाओं में निहित सूचनाओं को अंकेक्षित करना था, वितरक को अपने अंकेक्षण करा करके उसकी सूचना प्रसारक को देनी थी। इसका भी प्रावधान किया गया था कि प्रसारक को लगता है कि उसके द्वारा अंकेक्षण उसके अपने हित में आवश्यक है तो वह एक वर्ष में एक बार वितरक के एसएमएस, कैस और अन्य सिस्टमों का अंकेक्षण करा सकता है। सब्सक्रिप्शन सूचनाओं में किसी प्रकार की छेड़-छाड़ को रोकने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया था कि अंकेक्षण का व्यय वितरक वहन करेगा यदि अंकेक्षित और रिपोर्टिड सब्सक्रिप्शन शुल्क में 2 प्रतिशत से ज्यादा अंतर होता है अन्यथा प्रसारक ही अपने अंकेक्षण का व्यय वहन करेगा। लेकिन इसका भी प्रावधान किया गया था कि यदि अंतर 0.5 प्रतिशत से कम है तो उसके लिए पुनः इन्वॉइस को देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 130 प्रतिउत्तर में एक प्रसारक ने कहा कि 0.5 प्रतिशत के अंतर को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एमएसओ और उनकी संस्था ने कहा कि कैस एवं एसएमएस के बीच में पूरी तरह से तारतम्य संभव नहीं है क्योंकि कई ऐसे कारण हैं जो सही सूचना प्रदान करने से रोक सकते हैं और इसलिए इनके अंतर को 2.5 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत बढ़ा कर 0.5 प्रतिशत कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया। एक एमएसओ ने सलाह दी कि अंकेक्षण का व्यय सिर्फ प्रसारक को ही हर हालत में वहन करना चाहिए न कि वितरक को। कुछ प्रसारकों ने यह सलाह दी कि विसंगति की अवस्था में मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क का 20 प्रतिशत दंड के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 131 उचित और सही सब्सक्रिप्शन सूचना सेवा प्रदाताओं के मध्य प्रशुल्कों के लेन-देन के लिए अति आवश्यक है। सिस्टमों का अंकेक्षण एक ऐसी विधि है जिससे सही डाटा और सिस्टमों का विनिर्देश विनियमों के हिसाब से सत्यापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एट्रिसेबिल सिस्टमों का वेल्यु चेन में एक दूसरे के उपर भरोसा स्थापित करता है इसलिए ऐसे एट्रिसेबिल सिस्टमों के अंकेक्षण के लिए एक विधि का निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण का मत है कि यदि वितरक अपने सब्सक्रिप्शन सूचनाओं के सत्यापन के लिए अपने सिस्टमों का अंकेक्षण कराके उसकी सूचना सभी प्रसारकों को भेज देता है तो विभिन्न अंकेक्षणों की आवश्यकता नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था प्रसारकों एवं वितरकों के खर्चे को भी कम करेगा। कुछ प्रसारकों की चिंता है कि सिग्नल उपलब्ध कराने के बाद वितरक का सिस्टम विनियमों के अनुसार नहीं रहता है इसलिए प्रसारकों को इसके अंकेक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि प्रसारक अंकेक्षण सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या यदि प्रसारक के अनुसार वितरक द्वारा प्रयोग में एट्रिसेबिल सिस्टम विनियमों के अनुसार नहीं है तब प्रसारक कारण बताते हुए वितरक के एसएमएस, कैस और अन्य सिस्टमों का अंकेक्षण कर सकता है, इन विनियमों के प्रावधान सभी पणधारकों को समान अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि इनके मध्य झगड़े और खर्च कम हो सकें जहां तक 0.5 प्रतिशत के अंतर का प्रश्न है, यह पाया गया कि इस प्रकार का अंतर सिस्टमों की सीमा की वजह से कभी-कभी हो सकती है। इसलिए पुनः इन्वॉइस देने से लेन-देन में देरी हो सकती है। पणधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी विसंगति बार-बार न आए। प्रसारक की सलाह जिसमें कि उनके द्वारा दंड देने के लिए कहा गया था, इसका प्रावधान किया गया है कि यदि ब्याज मिलाकर विसंगति 2 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो अंकेक्षण का व्यय वितरक वहन करेगा। प्राधिकरण ने इस समय कोई दंड निर्धारित नहीं किया है क्योंकि विसंगति आने पर इसकी जांच उचित स्तर पर की जानी चाहिए क्योंकि इसके लिए मामले की परीक्षा और साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

### टीवी चैनलों के सिग्नलों का विसंयोजन:

- 132 टीवी चैनलों के सिग्नलों का विसंयोजन ऐसे मुद्दों में से एक मुद्दा है, जहां प्रसारणकर्ताओं और डीपीओज के हित के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित की रक्षा किया जाना भी आवश्यक है। पिछले दृष्टांतों में यह अवलोकन किया गया कि जहां सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद के कारण किसी प्रसारणकर्ता या डीपीओ द्वारा सिग्नल काट दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ता अधर में लटका दिए गए हैं, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004

और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में एक उपबंध था कि जहां सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे टीवी चैनलों के सिग्नलों के विसंयोजन से पहले संबंधित सेवा प्रदाता को तीन सप्ताह का पूर्व-लिखित नोटिस दें। इसके अलावा, इन विनियमों में एक ऐसा उपबंध भी उपलब्ध था, जिसमें सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे समाचारपत्रों के जरिए टीवी चैनलों के विसंयोजन के संबंध में सूचना प्रकाशित करें। समाचारपत्रों में विसंयोजन से संबंधित सूचना के प्रकाशन की शर्त को विनियमावली, 2016 के मसौदे में समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, उनकी सीमित पहुंच के कारण लक्षित उपभोक्ताओं द्वारा स्थानीय/क्षेत्रीय समाचारपत्र में दी गई अधिसूचनाएं अक्सर अनदेखी रह जाती थीं। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं के लिए 21 दिन की नोटिस अवधि बनाए रखते हुए, इसलिए उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए संबंधित चैनल पर स्करोलों के जरिए प्रकाशन की शर्त का प्रस्ताव दिया गया है।

- 133 प्रत्युत्तर में एक एमएसओ ने राय व्यक्त की कि समाचारपत्रों में नोटिस के प्रकाशन के अनिवार्य उपबंध को जारी रखा जाना चाहिए, जैसाकि पिछली विनियमावली में अनिवार्य किया गया था। उसने तर्क दिया कि प्रस्तावित विसंयोजन की स्थिति में प्रसारणकर्ता/एमएसओ क्रमशः एमएसओज/एलसीओ एक सामान्य संसूचन भेज सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप चैनल का अचानक विसंयोजन हो सकता है। एक प्रसारणकर्ता ने यह टिप्पणी दी कि प्लेटफॉर्म पर चैनलों की अनुपलब्धता के संबंध में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए डीपीओज को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे प्रसारणकर्ता के चैनलों पर स्करोल चलाएं बल्कि केवल डीपीओज के होम चैनलों पर ही स्करोल चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 134 प्रसारण उद्योग एक उपभोक्ता-केंद्रिक उद्योग है। किसी भी मामले में ऐसा उपभोक्ता, जिसने चूक नहीं की है, को प्रचालकों के बीच करार न करने या विवादों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। प्राधिकरण ने अवलोकन किया कि किसी भी कारण से टीवी चैनलों के सिग्नलों के विसंयोजन की स्थिति में उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करना आवश्यक है। इसलिए, तत्कालीन विनियमों में उपबंधित तीन सप्ताह का समय बनाए रखा गया है। यह अवधि प्रभावित पक्षकारों को यह अवसर देगी कि वे विसंयोजन रोकने के लिए संभावित हल खोजने की संभावना तलाश सकें। विसंयोजन से संबंधित सूचना के समाचारपत्रों के जरिए प्रकाशन को जारी रखने के सुझाव पर प्राधिकरण का विचार है कि समाचारपत्र में नोटिस के प्रकाशन की अनिवार्यता उपभोक्ताओं पर किसी अधिक प्रभाव के बिना सेवा प्रदाताओं पर लागत संबंधी भार को बढ़ाती है क्योंकि स्थानीय/क्षेत्रीय समाचारपत्र में दी गई ये अधिसूचनाएं उनकी सीमित पहुंच के कारण लक्षित उपभोक्ताओं द्वारा अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। चैनलों के विसंयोजन के बारे में स्करोल चलाने के पहलू पर यह उल्लेख किया जाता है कि इसे जारी रखना उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए अधिक प्रभावी है। इसलिए, प्राधिकरण का यह विचार है कि संबंधित चैनल (चैनलों) पर स्करोलों के जरिए, विसंयोजन की तारीख से 15 दिन पहले उपभोक्ता को सूचित करना डीपीओ की जिम्मेदारी होगी। इसे रोकने के लिए ऐसे स्करोल या सूचना उपभोक्ता की देखने की अनुभूति में बाधा नहीं पहुंचाती या विषय-वस्तु को सामान्य रूप से देखने में बाधा नहीं पहुंचाती। इसलिए, टेलीविजन स्क्रीन पर स्थिर चित्रों के रूप में डाले गए सूचना के किसी प्रदर्शन का निषेध कर दिया गया है।

#### **इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों का सूचीकरण**

- 135 एट्रेसेबल प्रणालियों में, प्रौद्योगिकी में एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका (ईपीजी) दी गई है, जिसमें डीपीओ के नेटवर्क पर चलाए जा रहे चैनल एक सरल, समझने में आसान तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि उपभोक्ता आसानी से इस संदर्शिका को पढ़ सकें और सभी चैनलों के जरिए पिलपिंग के बजाए अपनी पसंद के चैनल चुन सकें। ईपीजी में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रत्येक टीवी चैनल को एक चैनल नंबर भी दिया गया है। अंतः संयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि प्रत्येक डीपीओ द्वारा उसके द्वारा वितरित प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक ऐसे तरीके से एक चैनल नंबर दिया जाना चाहिए कि उसी प्रकार के टीवी चैनल निरंतर एकसाथ रखे जाएं और एक स्थान पर केवल एक ही चैनल दिखाई दे। इसके अलावा, यह प्रस्ताव दिया गया था कि टेलीविजन चैनल को दिया गया नंबर, वह नंबर दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वितरक द्वारा नहीं बदला जाएगा।
- 136 प्रत्युत्तर में, अधिकांश प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि चैनल को प्रसारण दर्शकगण अनुसंधान परिषद् (बीएआरसी) की रेटिंग के पिछले 12 महीने के औसत के अनुसार ईपीजी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि उच्चतर रेटिंग वाले चैनल, चैनलों के एक विशेष प्रकार को आबंटित एलसीएन (तर्कसंगल चैनल नंबर) के शीर्ष पर रखे जाने चाहिए और यह कार्य हर वर्ष दोहराया जा सकता है। एक नए प्रसारणकर्ता ने सुझाव दिया कि हिंदी, अंग्रेजी, व्यवसाय चैनल, क्षेत्रीय चैनल आदि जैसे प्रकार के अंदर उप-श्रेणीकरण होना चाहिए। जबकि अन्य समाचार प्रसारणकर्ता ने टिप्पणी दी कि नई विनियमावली लागू होने के पश्चात एलएनसी आबंटित चैनलों के लिए यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और डीपीओज को एलसीएन बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक उस प्रकार की समग्र श्रृंखला ही बदल न दी गई हो और फिर भी चैनल की क्रम संबंधी स्थिति उस प्रकार में वही बनी रहनी चाहिए, जबकि कोई नया अभिवर्धन उस प्रकार में तैथिक क्रम में होना चाहिए।
- 137 कुछ डीपीओज ने बताया कि किसी भी कारण से टीवी चैनलों के विसंयोजन के मामलों में, डीपीओ पर यह दायित्व नहीं डाला जाना चाहिए कि वह प्रसारणकर्ता को पुनः वही चैनल नंबर उपलब्ध कराए, यदि प्लेटफॉर्म पर वह चैनल दोबारा वापस आता है। एक डीपीओ ने कहा कि चैनल नंबर देने के लिए अनिवार्य की गई अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 महीने कर दी जानी चाहिए।
- 138 टेलीविजन सेवाओं से संबंधित मूल्य सूची मामले में शीर्षक के परामर्श पत्र में शैली वर्गीकरण के मुद्दे पर सुस्पष्ट अभिव्यक्ति की जा चुकी है। मूल्य सूची आदेश के मसौदे में सात शैलियां प्रस्तावित की गई थी तथा प्रसारकों को किसी भी प्रस्तावित शैली के लिए अपने चैनलों का वर्गीकरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। विनियम के उपबंधों के अनुसार डीपीओ के लिए प्रसारकों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चैनलों को स्थापित करने की अनिवार्यता की गई है। देश में लगभग 800 टेलीविजन चैनल हैं। यदि सभी प्रसारकों को अपनी शैली तैयार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए तो शैलियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा जिससे उपभोक्ताओं के सम्मुख अत्यधिक कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएंगी और उनके लिए अपने टेलीविजन सेट में से ईपीजी के प्रयोग से शैलियों के ढेर में से स्करोल करना एक दुष्कर कार्य बन जाएगा। इस प्रकार प्रसारकों को अपनी शैलियां तैयार करने की अनुमति प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आठ शैलियों में से प्रसारकों के लिए अपने चैनलों की शैली की घोषणा किए जाने की अनिवार्यता की गई है। लोचकता के उद्देश्य से प्रसारकों के लिए विविध प्रकार की शैलियां भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।



- 139 ईपीजी में चैनलों का उचित सूचीकरण, देखने के उद्देश्य के लिए चैनल का चयन करने में उपभोक्ताओं की सहायता करता है। यदि चैनल, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) के आधार पर सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो इसके कारण टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के आधार पर समय-समय पर चैनलों का स्थान बदला जा सकता है, जो उन उपभोक्ताओं में नाराजगी उत्पन्न करेगा, जो किसी प्रकार के अंतर्गत ईपीजी में आमतौर पर चैनल का स्थान याद रखते हैं। इसलिए टी-आर-पी के आधार पर चैनलों की लिस्टिंग को निर्धारित नहीं किया गया है और इसे वितरकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। प्राधिकरण कुछ पणधारियों के इन विचारों से सहमत है कि उप-श्रेणीकरण, देखने के लिए अपनी पसंद का चैनल चुनने में उपभोक्ता की सहायता करेगा और इसलिए प्राधिकरण ने डीपीओ के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों को इस तरीके से स्थान दें कि प्रसारणकर्ता द्वारा घोषित उसी प्रकार के टीवी चैनल तैथिक क्रम में एकसाथ रखे गए हों और उसी प्रकार के अंदर उसी भाषा के सभी टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में लगातार साथ-साथ दिखाई दें।
- 140 उपभोक्ता आमतौर पर चैनल नंबर याद रखते हैं और अपनी पसंद का चैनल देखने के लिए अपने रिमोट पर चैनल नंबर दबाते हैं। किसी चैनल विशेष को दिए गए चैनल नंबर में बार-बार किए गए परिवर्तन से उपभोक्ताओं को असुविधा होती है। यह भी अवलोकन किया गया है कि अनेक प्रसारणकर्ता, किसी विशेष डीपीओ के नेटवर्क पर, उसे दिए गए नंबर के साथ, उपभोक्ताओं के लिए अपने टीवी चैनल का विज्ञापन करते हैं। प्रसारणकर्ता तब भी कठिनाई का सामना करता है, यदि चैनल नंबर बार-बार बदल दिया जाता है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि 6 महीने का समय कम है और इसलिए डीपीओज के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे नंबर दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक चैनल नंबर न बदलें। तथापि, प्राधिकरण कुछ पणधारियों के इस विचार से सहमत है कि यदि किसी कारण से चैनल अनुपलब्ध होता है या किसी प्रसारणकर्ता द्वारा चैनल के प्रकार में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, तो किसी विशेष टेलीविजन चैनल को दिया गया चैनल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में नए प्रकार के चैनलों के साथ रखने के लिए बदला जा सकता है। तदनुसार, इन विनियमों में उचित उपबंध कर दिए गए हैं।
- 141 नए विनियम लागू होने के पश्चात आबंटित किए गए एलसीएन के लिए यथास्थिति बनाए रखना, डीपीओज के लिए अनिवार्य बनाने के पणधारियों के सुझाव के संबंध में उल्लेख किया जाता है कि यह सुझाव धार्य नहीं है, क्योंकि डीपीओज के प्लेटफॉर्म पर चैनल की उपलब्धता और इसका स्वरूप, नए ढांचे, सेवा प्रदाताओं के ब्योरे की रिपोर्टिंग के आलोक में भिन्न हो सकता है।

### सेवाप्रदाता के विवरण की रिपोर्ट

- 142 प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर में, सेवा प्रदाताओं, नामतः प्रसारणकर्ताओं, एमएसओज, एलसीओज, डीटीएच प्रचालकों, एचआईटीएस प्रचालकों और आईपीटीवी प्रचालकों, की संख्या बहुत अधिक है। आईसीटी के इस्तेमाल द्वारा किसी एकल स्थान पर सूचना की उपलब्धता, एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सेवा प्रदाताओं का पता लगाने में सेवा प्रदाताओं की सहायता करेगी और अंतःसंयोजन करार करने के हिसाब से व्यवसाय करने को आसान बनाएगी। यह, बाज़ार में अत्यधिक आवश्यक अनुशासन लाते हुए विनियम का अनुपालन मॉनिटर करने में प्राधिकरण की सहायता भी करेगी, जो इस सेक्टर को एक स्थायी प्रगति के पथ पर लाएगी।
- 143 तदनुसार, इन विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने ब्योरे जैसे नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल का पता और वेब साइट सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रस्तुत करें। इसके अलावा, सेवा प्रदाता वेबसाइट से यह सत्यापन करेंगे कि टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए या नेटवर्क तक पहुंच के लिए, जैसा भी मामला हो, विसंयोजन चाहने वाले अन्य सेवा प्रदाता ने वेबसाइट पर अपने ब्योरे दर्ज करा दिए हैं। तथापि, कोई संदेह समाप्त करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराना सेवा प्रदाताओं को यह अधिकार नहीं देगा कि वे इस प्रकार का व्यवसाय करें, जब तक सुसंगत नीति/दिशानिर्देशों के अंतर्गत सरकार से अनुमति/अनुमोदन/लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त न कर लिया गया हो।

### अनुपालन अधिकारी को नामजद करना

- 144 विनियामक ढांचे का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से यह बात महत्वपूर्ण है कि विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग शर्तों का सही भावना से सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन किया गया है। इसलिए, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि प्रत्येक प्रसारणकर्ता और डीपीओ इस शर्त के साथ अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा कि तुरंत पिछली कैलेंडर तिमाही में 2,00,000 से कम के औसत उपभोक्ता आधार वाले किसी डीपीओ के लिए यह अनिवार्य नहीं था। प्रत्युत्तर में एक प्रसारणकर्ता ने कहा कि उपभोक्ता आधार की सीमा 2,00,000 से घटाकर 50,000 कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक लक्ष्य बाज़ार में अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। एमएसओ की एसोसिएशन ने कहा कि अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए दी गई समयावधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी जानी चाहिए और किसी परिवर्तन की स्थिति में विनियम के मसौदे में यथाउपबंधित 10 दिन की समयावधि कम है क्योंकि व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति में समय लगता है।
- 145 विनियामक ढांचे का उद्देश्य केवल तभी पूरा किया जा सकता है, यदि सभी सेवा प्रदाताओं का अनुपालन स्तर अच्छा हो। इसलिए, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन विनियमों के उपबंध और विनियमों तथा प्रशुल्क आदेशों में विनिर्धारित अपेक्षित रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएं। इसलिए, इन विनियमों में ये उपबंध किए गए हैं कि प्रत्येक प्रसारणकर्ता और डीपीओ एक अनुपालन अधिकारी नामजद करेगा। यदि प्रसारणकर्ता या डीपीओ कोई कंपनी है, तो अनुपालन अधिकारी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामजद किया जाना चाहिए। यदि भुगतान प्रसारणकर्ता या डीपीओ कोई व्यक्ति या कोई साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का कोई संघ है तो प्रसारणकर्ता या डीपीओ को सभी साझेदारों या संघ के प्रमुख, जैसा भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया हो। किसी अनुपालन अधिकारी को नामजद करने के लिए समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में कुछ पणधारियों के सुझाव पर प्राधिकरण द्वारा यह विचार करते हुए सहमति व्यक्त की गई कि किसी कंपनी के मामले में अनुपालन अधिकारी का पदनाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अनुमोदन प्राप्त कर सकें और प्राधिकरण को

सूचित कर सकें। तदनुसार, इन विनियमों में यह उपबंध किया गया है कि अनुपालन अधिकारी को नामजद करने का काम विनियमों के प्रारंभण के 30 दिन के अंदर किया जाएगा और इस नामजदगी के पश्चात अनुपालन अधिकारी के ब्योरे 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को संसूचित किए जाएंगे। इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी के नाम में होने वाला कोई परिवर्तन, उस परिवर्तन के होने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को संसूचित किया जाएगा।

#### **निरसन:**

- 146 दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियाँ) विनियमावली, 2016, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) (आठवीं) (एड्रसेबल प्रणालियाँ) प्रशुल्क आदेश, 2016 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) सेवा के गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रसेबल प्रणालियाँ) विनियमावली, 2016 की सरकारी अधिसूचना के साथ प्राधिकरण ने सभी प्रकार की एड्रसेबल प्रणालियों के लिए व्यापक और सामान्य विनियामक ढांचा लागू कर दिया है। इसलिए, इसके सभी संशोधनों और इसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के साथ डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू दूरसंचार विनियमावली, 2012 का निरसन कर दिया गया है। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004, जो डीएस को छोड़कर, आईपीटीवी, डीटीएच और एचआईटीएस जैसी एड्रसेबल प्रणालियों और गैर-एड्रसेबल प्रणालियों के लिए लागू थी, एड्रसेबल प्रणालियों के लिए लागू उपबंधों की सीमा तक निरसित कर दी गई है। ऐनालॉग प्रणालियों से संबंधित उपबंध, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 द्वारा विनियमित होती रहेंगी। एड्रसेबल प्रणालियों के जरिए सेवा उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा सभी अंतःसंयोजन करार या तो आवश्यक रूप से संशोधित करने होंगे या दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणालियाँ) विनियमावली, 2016 के उपबंधों के अनुपालन में एक नया करार करना होगा।

#### **विनियमावली और नए अंतःसंयोजन करारों का प्रारंभण:**

- 147 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को तुरंत लागू हो जाएंगे। प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि इन विनियमों के लागू होने की तारीख को यथास्थिति बड़ी संख्या में मौजूदा अंतःसंयोजन करार होंगे, जो पिछले अंतःसंयोजन विनियमों के ढांचे के आधार पर सेवा प्रदाताओं द्वारा पहले ही कर लिए गए हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और पुराने विनियामक ढांचे से नए ढांचे में निर्बाध पारगमन को समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण ने विनियमों और प्रशुल्क आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में सभी मौजूदा अंतःसंयोजन करारों का या तो नवीकरण करने या उन्हें संशोधित करने के लिए 150 दिन के समय का उपबंध किया है। सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 150 दिन से पहले ही अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करारों को संशोधित कर लें ताकि सिग्नलों के अचानक विसंयोजन से बचा जा सके या विनियमों के उल्लंघन के जोखिम से बचा जा सके। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि कुछ मौजूदा करार निर्धारित समय सीमा से पहले समाप्त हो रहे हों, हालांकि वे इन विनियमों के प्रारंभण की तारीख को यथास्थिति वैध थे। इसलिए, सेवा प्रदाताओं को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे मौजूदा करारों का नवीकरण निर्धारित समय तक कर लें ताकि ऐसे करारों की वैधता विस्तारित की जा सके। यह बात स्पष्ट की जाती है कि कोई भी नया अंतःसंयोजन करार ऐसे अपवादों के दायरे में नहीं आएगा। सभी नए अंतःसंयोजन करार इन विनियमों के आधार पर करने होंगे।

## **TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2017

**F. No. 21-4/2016-B&CS.**—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, —

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and

(b) published under notification No. S.O. 44(E) and 45(E), dated the 9<sup>th</sup> January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:—

### **THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES**

#### **INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) REGULATIONS, 2017**

(No. 1 of 2017)

#### **CHAPTER – I**

#### **PRELIMINARY**

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017.

(2) These regulations shall cover commercial and technical arrangements, among service providers for interconnection, for broadcasting services relating to television provided through addressable systems throughout the territory of India.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (b) “active subscriber” for the purpose of these regulations, means a subscriber who has been authorized to receive signals of television channels as per the subscriber management system and whose set top box has not been denied signals;
- (c) “addressable system” means an electronic device (which includes hardware and its associated software) or more than one electronic device put in an integrated system through which transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels can be done in encrypted form, which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within the limits of the authorization made, on the choice and request of such subscriber, by the distributor of television channels;
- (d) “a-la-carte” or “a-la-carte channel” with reference to offering of a television channel means offering the channel individually on a standalone basis;
- (e) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (f) “average active subscriber base” means the number arrived by averaging the active subscriber base count in the manner specified in the Schedule VII;
- (g) “bouquet” or “bouquet of channels” means an assortment of distinct channels offered together as a group or as a bundle and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (h) “broadcaster” means a person or a group of persons, or body corporate, or any organization or body who, after having obtained, in its name, downlinking permission for its channels, from the Central Government, is providing programming services;
- (i) “broadcaster’s share of maximum retail price” with reference to a pay channel or a bouquet of pay channels means any fee payable by a distributor of television channels to a broadcaster for signals of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be, and for which due authorization has been obtained by such distributor from that broadcaster;
- (j) “broadcasting services” means the dissemination of any form of communication like signs, signals, writing, pictures, images and sounds of all kinds by transmission of electro-magnetic waves through space or through cables intended to be received by the general public either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (k) “cable service” or “cable TV service” means the transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels through cables;
- (l) “cable television network” or “cable TV network” means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;
- (m) “carriage fee” means any fee payable by a broadcaster to a distributor of television channels only for the purpose of carrying its channels through the distributor’s network, without, specifying the placement of such channels onto a specific position in the electronic programme guide or, seeking assignment of a particular number to such channels;
- (n) “compliance officer” means any person designated so, who is capable of appreciating requirements for regulatory compliance under these regulations, by a service provider;
- (o) “direct to home operator” or “DTH operator” means any person who has been granted licence by the Central Government to provide direct to home (DTH) service;
- (p) “direct to home service” or “DTH service” means re-transmission of signals of television channels, by using a satellite system, directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary such as local cable operator or any other distributor of television channels;
- (q) “distribution fee” means any fee payable by a broadcaster to a distributor of television channels for the purpose of distribution of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be, to subscribers and it does not include carriage fee;

- (r) “distribution platform” means distribution network of a DTH operator, multi- system operator, HITS operator or IPTV operator;
- (s) “distributor of television channels” or “distributor” means any DTH operator, multi-system operator, HITS operator or IPTV operator;
- (t) “electronic programme guide” or “EPG” means a program guide maintained by the distributors of television channels that lists television channels and programmes, and scheduling and programming information therein and includes any enhanced guide that allows subscribers to navigate and select such available channels and programmes;
- (u) “free-to-air channel” or “free-to-air television channel” means a channel which is declared as such by the broadcaster and for which no fee is to be paid by the distributor of television channels to the broadcaster for signals of such channel;
- (v) “head end in the sky operator” or “HITS operator” means any person permitted by the Central Government to provide head end in the sky (HITS) service;
- (w) “head end in the sky service” or “HITS service” means transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels—
  - (i) to intermediaries like local cable operators or multi-system operators by using a satellite system and not directly to subscribers; and
  - (ii) to the subscribers by using satellite system and its own cable networks;
- (x) “interconnection” means commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipments and networks to provide broadcasting services to the subscribers;
- (y) “interconnection agreement” with all its grammatical variations and cognate expressions means agreements on interconnection providing technical and commercial terms and conditions for distribution of signals of television channel;
- (z) “internet protocol television operator” or “IPTV operator” means a person permitted by the Central Government to provide IPTV service;
- (aa) “internet protocol television service” or “IPTV service” means delivery of multi channel television programmes in addressable mode by using Internet Protocol over a closed network of one or more service providers;
- (bb) “local cable operator” or “LCO” means a person registered under rule 5 of the Cable Television Networks Rules, 1994;
- (cc) “maximum retail price” or “MRP” for the purpose of these regulations, means the maximum price, excluding taxes, payable by a subscriber for a-la-carte pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be;
- (dd) “multi-system operator” or “MSO” means a cable operator who has been granted registration under rule 11 of the Cable Television Networks Rules, 1994 and who receives a programming service from a broadcaster and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators;
- (ee) “network capacity fee” means the amount, excluding taxes, payable by a subscriber to the distributor of television channels for distribution network capacity subscribed by that subscriber to receive the signals of subscribed television channels and it does not include subscription fee for pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be;
- (ff) “pay broadcaster” means a broadcaster which has declared its one or more channels as pay channel to the Authority under the provisions of applicable regulations or tariff order, as the case may be;
- (gg) “pay channel” means a channel which is declared as such by the broadcaster and for which a share of maximum retail price is to be paid to the broadcaster by the distributor of television channels and for which due authorization needs to be obtained from the broadcaster for distribution of such channel to subscribers;
- (hh) “programme” means any television broadcast and includes—
  - (i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials;
  - (ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation,and the expression “programming service” shall be construed accordingly;

- (ii) “QoS Regulations” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (jj) “reference interconnection offer” or “RIO” means a document published by a service provider specifying terms and conditions on which the other service provider may seek interconnection with such service provider;
- (kk) “service provider” means the Government as a service provider and includes a licensee as well as any broadcaster, distributor of television channels or local cable operator;
- (ll) “set top box” or “STB” means a device, which is connected to or is part of a television receiver and which enables a subscriber to view subscribed channels;
- (mm) “subscriber” for the purpose of these regulations, means a person who receives broadcasting services, from a distributor of television channels, at a place indicated by such person without further transmitting it to any other person and who does not cause the signals of television channels to be heard or seen by any person for a specific sum of money to be paid by such person, and each set top box located at such place, for receiving the subscribed broadcasting services, shall constitute one subscriber;
- (nn) “subscriber management system” means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber’s record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;
- (oo) “tariff order” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017;
- (pp) “television channel” means a channel, which has been granted permission for downlinking by the Central Government under the policy guidelines issued or amended by it from time to time and reference to the term ‘channel’ shall be construed as a reference to “television channel”.

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made thereunder or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) and the rules and regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

## CHAPTER II

### INTERCONNECTION

**3. General obligations of broadcasters.**— (1) No broadcaster shall engage in any practice or activity or enter into any understanding or arrangement including exclusive contracts with any distributor of television channels that prevents any other distributor of television channels from obtaining signals of television channel of such broadcaster for distribution.

(2) Every broadcaster shall, within sixty days of receipt of written request from a distributor of television channels for obtaining signals of television channel or within thirty days of signing of interconnection agreement with the distributor, as the case may be, provide, on non-discriminatory basis, the signals of television channel to the distributor or convey the reasons in writing for rejection of the request if the signals of television channel are denied to such distributor:

Provided that imposition of any term or condition by the broadcaster, which is unreasonable, shall be deemed to constitute a denial of request:

Provided further that this sub-regulation shall not apply to a distributor of television channels, who requests signals of a particular television channel from a broadcaster while at the same time demands carriage fee for distribution of that television channel or who is in default of payment to the broadcaster and continues to be in such default.

(3) If a broadcaster, proposes or stipulates for, directly or indirectly, placing the channel in any specified position in the electronic programme guide or assigning a particular channel number, as a pre-condition for providing signals, such pre-condition shall also amount to imposition of unreasonable condition.

*Explanation:* For removal of doubt, it is clarified that if a pay broadcaster offers discount, in non-discriminatory manner, through its reference interconnect offer on the maximum retail price of pay channel, within the limit as specified in sub-regulation (4) of regulation 7, to distributors of television channels for placing the channel in any specified position in the electronic programme guide or assigning particular channel number, such offer of discount shall not be considered a pre-condition.

(4) No broadcaster shall propose, stipulate or demand for, directly or indirectly, packaging of the channel in any particular bouquet offered by the distributor of television channels to subscribers.

(5) No broadcaster shall propose, stipulate or demand for, directly or indirectly, guarantee of a minimum subscriber base or a minimum subscription percentage for its channel or bouquet.

*Explanation:* For removal of doubt, it is clarified that the subscription percentage of a channel or bouquet refers to the percentage of subscribers subscribing to a specific channel or bouquet out of average active subscriber base of a distributor.

**4. General obligations of distributors of television channels.**— (1) No distributor of television channels shall engage in any practice or activity or enter into any understanding or arrangement including exclusive contracts with any broadcaster that prevents any other broadcaster from obtaining access to the network of such distributor for distribution of its channel.

(2) No distributor of television channels shall engage in any practice or activity or enter into any understanding or arrangement including exclusive contracts with any local cable operator that prevents any other local cable operator from obtaining signals of television channels from such distributor for further distribution.

(3) Every distributor of television channels shall declare coverage area of each distribution network as a target market:

Provided that it shall be permissible for a distributor to declare, in non-discriminatory manner, any area within the coverage area of distribution network as a target market.

*Explanation:* For the purpose of this regulation, each Head-end or Earth Station, as the case may be, and its associated network used for distribution of signals of television channels shall constitute one distribution network.

(4) Every distributor of television channels shall, within thirty days from the commencement of these regulations or within thirty days from the commencement of its operations, as the case may be, on its website, publish—

- (a) target markets as declared under sub-regulation (3) of this regulation;
- (b) the total channel carrying capacity of its distribution network in terms of number of standard definition channels;
- (c) list of channels available on the network;
- (d) number of channels for which signals of television channels have been requested by the distributor from broadcasters and the interconnection agreements signed;
- (e) spare channel capacity available on the network for the purpose of carrying signals of television channels; and
- (f) list of channels, in chronological order, for which requests have been received from broadcasters for distribution of their channels, the interconnection agreements have been signed and are pending for distribution due to non-availability of the spare channel capacity:

Provided that the list of channels in chronological order, under clause (f), shall be prepared on the basis of date and time of receipt of the written request from the broadcaster:

Provided further that for the purpose of calculating spare channel capacity of the distribution network, one high definition channel shall be equal to two standard definition channels:

Provided further that spare channel capacity available on the network under clause (e) shall be the difference between the total channel carrying capacity of the distribution network and numbers of channels available on the distribution network in terms of standard definition channels:

Provided further that any subsequent change, due to addition or reduction in total channel carrying capacity of the distribution network or due to addition of channels on the distribution network or due to discontinuation of existing channels available on distribution the network, shall be reflected in the spare channel capacity:

Provided also that any change in the information, published under this sub-regulation, shall be updated on the website within seven calendar days from the date of occurrence of such change.

(5) Every distributor shall allocate every alternate spare channel capacity on its network to the channels, in sequential manner, listed under clause (f) of sub-regulation (4), for distribution of the television channels.

(6) Nothing contained in the sub-regulation (5) shall apply if no request for distribution of a television channel is pending under clause (f) of sub-regulation (4).

(7) Subject to the availability of spare channel capacity on the distribution network, under sub-regulation (4), every distributor of television channels shall, within sixty days of receipt of written request from a broadcaster for distribution of television channel or within thirty days of signing of written interconnection agreement with the broadcaster, as the case may be, carry, on non-discriminatory basis, the signals of such television channel or convey the reasons in writing for rejection of request if the distribution of such television channel is denied to the broadcaster:

Provided that imposition of any term or condition by the distributor of television channels, which is unreasonable, shall be deemed to constitute a denial of request:

Provided further that nothing contained in this sub-regulation shall apply to a broadcaster who refuses to pay the carriage fee to the distributor of television channels or who is in default of payment to the distributor and continues to be in such default.

(8) It shall be permissible to the distributor of television channels to discontinue carrying of a television channel in case the monthly subscription percentage for that channel is less than five percent of the monthly average active subscriber base of that distributor in the target market specified in the interconnection agreement, in each of the immediately preceding six consecutive months:

Provided that for the purpose of calculation of monthly subscription percentage for high definition television channel, the monthly average active subscriber base shall be of subscribers capable of receiving high definition television channels.

(9) A distributor of television channels shall not be under obligation to carry a channel which has been discontinued as per sub-regulation (8), for a period of one year from the date of such discontinuation.

(10) If a distributor of television channels, before providing access to the network for distribution of television channels requested by a broadcaster, directly or indirectly, proposes, stipulates or demands for a minimum guarantee for period or number of channels, as a pre-condition for providing access to the network, such pre-condition shall also amount to imposition of unreasonable condition.

(11) Every distributor of television channels shall, within sixty days of receipt of written request from a local cable operator or within thirty days of signing of written interconnection agreement with the local cable operator, as the case may be, provide, on non-discriminatory basis, signals of television channels to such local cable operator or convey the reasons in writing for rejection of request if the signals are denied to such local cable operator:

Provided that imposition of any term or condition by the distributor of television channels, which is unreasonable, shall be deemed to constitute a denial of request:

Provided further that in case, it is not feasible to provide signals of television channels at a location where the signals have been requested by the local cable operator, the distributor of television channels shall inform the local cable operator within thirty days from the date of receipt of request the reasons for such non-feasibility:

Provided further that this sub-regulation shall not apply in case of a local cable operator who is in default of payment of a distributor of television channels and continues to be in such default:

Provided also that a local cable operator shall not be treated as being in default of payment to a distributor if it has made payment of all bills of preceding six months.

(12) No distributor of television channels shall, for providing signals of television channels to a local cable operator, propose, stipulate or demand for, directly or indirectly, guarantee of a minimum subscriber base.

(13) Nothing contained in the sub-regulation (11) and sub-regulation (12) of this regulation shall apply to a DTH operator.

**5. General obligations of service providers.**— (1) No service provider shall, directly or indirectly, prohibit another service provider from providing its services to any subscriber or in any geographical area, as the case may be.

(2) No service provider shall, propose, stipulate or demand for, directly or indirectly, payment of a minimum guarantee amount by other service provider for providing signals of television channels or access to the network, as the case may be.

(3) Every service provider shall issue monthly invoice, to the other service provider with whom interconnection agreements have been entered into, for collection of payment and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date for payment.

(4) Any claim for arrears by the service provider under these regulations, shall be accompanied by proof of service of invoices for the periods to which the arrears pertain.

### CHAPTER III

#### REFERENCE INTERCONNECTION OFFER

**6. Compulsory offering of channels on a-la-carte basis.**—(1) Every broadcaster shall offer all its television channels on a-la-carte basis to the distributors of television channels:

Provided that the broadcaster may also offer its pay channels, in addition to offering of pay channels on a-la-carte basis, in form of bouquet:

Provided further that such bouquet shall not contain--

(a) any 'free-to-air channel'; and

(b) High definition (HD) and Standard Definition (SD) variants of the same channel.

**7. Publication of reference interconnection offer by broadcaster for pay channels.**—(1) Every broadcaster shall publish, on its website, reference interconnection offer, in conformance with the regulations and the tariff orders notified by the Authority, for providing signals of all its pay channels to the distributor of television channels—

(a) within sixty days of commencement of these regulations; and

(b) before launching of a pay channel.

and simultaneously submit, for the purpose of record, a copy of the same to the Authority.

(2) The reference interconnection offer, referred to in sub-regulation (1), shall contain the technical and commercial terms and conditions relating to, including but not limited to, maximum retail price per month of pay channel, maximum retail price per month of bouquet of pay channels, discounts, if any, offered on the maximum retail price to distributors, distribution fee, manner of calculation of 'broadcaster's share of maximum retail price', genre of pay channel and other necessary conditions:

Provided that a broadcaster may include in its reference interconnection offer, television channel or bouquet of pay channels of its subsidiary company or holding company or subsidiary company of the holding company, which has obtained, in its name, the downlinking permission for its television channels from the Central Government, after written authorization by them.

*Explanation:* For the purpose of these regulations, the definition of "subsidiary company" and "holding company" shall be the same as assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(3) Every broadcaster shall declare a minimum twenty percent of the maximum retail price of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be, as the distribution fee:

Provided that the distribution fee declared by the broadcaster shall be uniform across all the distribution platforms.

(4) It shall be permissible to a broadcaster to offer discounts, on the maximum retail price of pay channel or bouquet of pay channels, to distributors of television channels, not exceeding fifteen percent of the maximum retail price:

Provided that the sum of distribution fee declared by a broadcaster under sub-regulation (3) and discounts offered under this sub-regulation in no case shall exceed thirty five percent of the maximum retail price of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be:

Provided further that offer of discounts, if any, to distributors of television channels, shall be on the basis of fair, transparent and non-discriminatory terms:

Provided also that the parameters of discounts shall be measurable and computable.

(5) Every broadcaster of pay channel shall mention in its reference interconnection offer the names of persons, telephone numbers, and e-mail addresses designated to receive request for receiving interconnection from distributors of television channels and grievance redressal thereof.

(6) The terms and conditions mentioned in the reference interconnection offer shall include all necessary and sufficient provisions, which make it a complete interconnection agreement on signing by other party, for distribution of television channels.

(7) The Authority, *suo-motu* or otherwise, may examine the reference interconnection offer submitted by a broadcaster and on examination if the Authority is of the opinion that the reference interconnection offer is not in conformance with the provisions of the regulations and the tariff orders notified by the Authority, it may, after giving an opportunity of being heard to such broadcaster, direct such broadcaster to modify the said reference interconnection offer and such broadcaster shall amend reference interconnection offer accordingly and publish the same within fifteen days of receipt of the direction.

(8) Any amendment to the reference interconnection offer shall be published in the same manner as provided under the sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) of this regulation.



(9) In the event of any amendment to the reference interconnection offer by a broadcaster under sub-regulation (8), the broadcaster shall give an option to all distributors, with whom it has written interconnection agreements in place, within thirty days from the date of such amendment and it shall be permissible to such distributors to enter into fresh interconnection agreement in accordance with the amended reference interconnection offer, within thirty days from the date of receipt of such option, or continue with the existing interconnection agreement.

**8. Publication of reference interconnection offer by distributor of television channels.**—(1) Every distributor of television channels shall publish, on its website, reference interconnection offer, in conformance with the regulations and the tariff orders notified by the Authority, for carrying channels—

- (a) within sixty days of commencement of these regulations; and
- (b) before starting a new distribution network:

and simultaneously submit, for the purpose of record, a copy of the same to the Authority.

Provided that such reference interconnection offer shall be applicable only in the cases where a broadcaster requests a distributor of television channels to carry the broadcaster's channels on the distribution network.

(2) The reference interconnection offer, referred to in sub-regulation (1), shall contain the technical and commercial terms and conditions relating to, including but not limited to, target market, rate of carriage fee per month, average active subscriber base of standard definition set top boxes and high definition set top boxes at the time of publication of the reference interconnection offer, discounts, if any, offered on the rate of carriage fee, manner of calculation of carriage fee payable to the distributor and other necessary conditions:

Provided that the rate of carriage fee per standard definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed twenty paisa:

Provided further that the rate of carriage fee per high definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed forty paisa:

Provided also that a distributor of television channels shall calculate the carriage fee amount for television channels as per the provisions specified in the Schedule I, which shall change with the changes in monthly subscription percentage of such television channels.

(3) It shall be permissible to a distributor of television channels to offer discounts to broadcasters on the rate of carriage fee which shall not exceed thirty five percent of the rate of carriage fee declared under sub-regulation (2):

Provided that offer of discounts, if any, to broadcaster on the carriage fee, shall be on the basis of fair, transparent and non-discriminatory terms:

Provided further that the parameters of discounts shall be measurable and computable:

Provided also that it shall be permissible for a distributor of television channels to offer discounts exceeding thirty five percent of the rate of carriage fee declared under sub-regulation (2) for the channel specified by the Authority, through a direction, in the public interest.

(4) Every distributor of television channels shall, in its reference interconnection offer, mention the names of persons, telephone numbers, and e-mail addresses, designated for receiving interconnection requests from broadcasters and grievance redressal thereof.

(5) The terms and conditions mentioned in the reference interconnection offer shall include all necessary and sufficient provisions, which make it a complete interconnection agreement for signing by other party, for carrying television channels.

(6) The Authority, *suo-motu* or otherwise, may examine the reference interconnection offer submitted by a distributor of television channels and on examination if the Authority is of the opinion that the reference interconnection offer has not been prepared in conformance with the provisions of the regulations and the tariff orders notified by the Authority, it may, after giving an opportunity of being heard to such distributor, direct such distributor to modify the said reference interconnection offer and such distributor shall amend reference interconnection offer accordingly and publish the same within fifteen days of receipt of the direction.

(7) Any amendment to the reference interconnection offer shall be published in the same manner as provided under the sub-regulation (1), (2), (3), (4) and (5) of this regulation.

(8) In the event of any amendment in the reference interconnection offer by a distributor of television channels under sub-regulation (7), the distributor shall give an option to all broadcasters, with whom it has written interconnection agreements in place, within thirty days from the date of such amendment and it shall be permissible to such broadcasters to enter into fresh interconnection agreements in accordance with the amended reference interconnection offer within thirty days from the date of receipt of such option or continue with the existing interconnection agreements.

## CHAPTER IV

## INTERCONNECTION AGREEMENT

**9. General provisions relating to interconnection agreements.**—(1) It shall be mandatory for service providers to reduce the terms and conditions of all their interconnection agreements to writing.

(2) A service provider shall not incorporate any provision in the interconnection agreement with the other service provider which would require, directly or indirectly, the latter to pay a minimum guaranteed amount and any agreement to contrary shall be void.

(3) It shall be mandatory for service providers to either renew or amend all their existing interconnection agreements in compliance with the provisions of the regulations and the tariff orders notified by the Authority, within one hundred and fifty days of commencement of these regulations.

**10. Interconnection agreement between broadcaster and distributor of television channels.**—(1) No broadcaster shall provide signals of pay channels to a distributor of television channels without entering into a written interconnection agreement with such distributor of television channels.

(2) No distributor of television channels shall distribute pay channels of any broadcaster without entering into a written interconnection agreement with such broadcaster.

(3) It shall be mandatory for a broadcaster and a distributor of television channels to enter into written interconnection agreement on a-la-carte basis for distribution of pay channels.

(4) Every broadcaster shall devise an application form for request of signals of television channel by distributors of television channels in accordance with the Schedule II.

(5) A distributor of television channels desirous of obtaining signals of television channels shall make a written request in the application form devised by the broadcaster.

(6) Every distributor of television channels before requesting signals of television channels from a broadcaster shall ensure that the addressable systems to be used for distribution of television channels meet the requirements as specified in the Schedule III.

(7) If a broadcaster, before providing signals of television channels, is of the opinion that the addressable system, being used by the distributor for distribution of television channels, does not meet the requirements specified in the Schedule III, it may, without prejudice to the time limit specified in sub-regulation (2) of the regulation 3, cause audit of the addressable system of the distributor by M/s. Broadcast Engineering Consultants India Limited, or any other auditor empanelled by the Authority for conducting such audit and provide a copy of the report prepared by the auditor to the distributor:

Provided that unless the configuration or the version of the addressable system of the distributor has been changed after issuance of the report by the auditor, the broadcaster, before providing signals of television channel shall not cause audit of the addressable system of the distributor if the addressable system of such distributor has been audited during the last one year by M/s. Broadcast Engineering Consultants India Limited, or any other auditor empanelled by the Authority and the distributor produces a copy of such report as a proof of conformance to the requirements specified in the Schedule III.

(8) Every broadcaster of pay channel, within thirty days of receipt of written request from a distributor of television channels, shall enter into a written interconnection agreement with the distributor of television channels for providing signals of its pay channel in accordance with the terms and conditions of the reference interconnection offer published by the broadcaster:

Provided that the 'broadcaster's share of maximum retail price' payable by a distributor of television channels under the interconnection agreement shall be calculated on the basis of the maximum retail price of pay channel or bouquet, the distribution fee and the discounts agreed in the interconnection agreement:

Provided further that the period of the interconnection agreement in no case shall be less than one year from the date of commencement of the agreement:

Provided also that in case more than one interconnection agreement are entered into with a distributor in respect of television channel or bouquet of pay channels, each subsequent interconnection agreement shall contain the details of the earlier agreements in force with that distributor for such channel or bouquet, as the case may be.

*Explanation:* For the removal of doubt, it is clarified that on receipt of a written request from a distributor by a broadcaster for obtaining signals of pay channels, the written interconnection agreement, between the broadcaster and the distributor, shall be entered into within thirty days of receipt of such request, and, the broadcaster shall provide signals of its pay channels, within thirty days from the date of signing of written interconnection agreement, to the distributor of television channels.

(9) It shall be permissible to a broadcaster to sign the interconnection agreement with distributors of television channels for a-la-carte pay channel or bouquet of pay channels of its subsidiary company or holding company or subsidiary company of the holding company, which has obtained, in its name, the downlinking permission for its television channels from the Central Government, after written authorization from such companies.

(10) It shall be permissible to a distributor of television channels to sign the reference interconnection offer published by a broadcaster under sub-regulation (1) of regulation 7, as an interconnection agreement, for obtaining signals of television channels and send the said agreement to the broadcaster for providing signals.

(11) A broadcaster shall not incorporate any provision, directly or indirectly, in its interconnection agreement with a distributor of television channels which require such distributor of television channels to include the channel or bouquet of pay channels offered by the broadcaster in any particular bouquet of channels offered by such distributor to the subscribers and any agreement to contrary shall be void.

(12) A broadcaster shall not incorporate any provision, directly or indirectly in its interconnection agreement with a distributor of television channels which requires such distributor of television channels to give a guarantee for a minimum subscriber base or a minimum subscription percentage for the channels offered by the broadcaster and any agreement to contrary shall be void.

*Explanation:* For removal of doubt, it is clarified that any discount, offered as an incentive by a broadcaster on the maximum retail price of the pay channel or the bouquet of pay channels, based on actual number of subscribers or actual subscription percentage, recorded in a month shall not amount to guarantee for a minimum subscriber base or a minimum subscription percentage for its channel.

(13) It shall be the responsibility of every broadcaster who enters into an interconnection agreement with a distributor of television channels to hand over a copy of such interconnection agreement to that distributor of television channels within a period of fifteen days from the date of execution of the interconnection agreement and retain a copy of an acknowledgement so obtained from the distributor.

(14) Every broadcaster shall enter into a new written interconnection agreement with distributor of television channels before the expiry of the existing interconnection agreement:

Provided that the broadcaster shall, at least sixty days prior to the date of expiry of the existing interconnection agreement, give notice to the distributor of television channels to enter into new written interconnection agreement:

Provided further that in case the parties fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the broadcaster shall not make the signals of television channels available to the distributor of television channels on expiry of the existing interconnection agreement:

Provided also that the distributor of television channels shall, fifteen days prior to the date of expiry of its existing interconnection agreement, inform the subscribers through scrolls on the channels included in the said agreement—

(a) the date of expiry of its existing interconnection agreement; and

(b) the date of disconnection of signals of television channels in the event of its failure to enter into new interconnection agreement.

(15) No distributor of television channels shall carry television channels, for which a request has been received from a broadcaster for distribution of television channels, without entering into a written interconnection agreement with such broadcaster.

(16) Every distributor of television channels shall devise an application form, for seeking access to its distribution network for distribution of television channels by broadcasters, in accordance with the Schedule IV.

(17) A broadcaster desirous of distribution of its television channel shall make a written request in the application form devised by the distributor of television channels.

(18) Every distributor of television channels, within thirty days of receipt of written request from a broadcaster for distribution of television channels, shall enter into a written interconnection agreement with the broadcaster for carrying television channels in accordance with the terms and conditions of the reference interconnection offer published by the distributor:

Provided that the carriage fee payable by a broadcaster to the distributor of television channels under the interconnection agreement shall be calculated on the basis of the rate of carriage fee and the discounts agreed in the interconnection agreement:

Provided further that the period of the interconnection agreement in no case shall be less than one year from the date of commencement of the agreement:

Provided also that in case more than one interconnection agreement are entered with a broadcaster in respect of a television channel, each subsequent interconnection agreement shall contain the details of the earlier agreements in force with that broadcaster for such channel.

*Explanation:* For the removal of doubt, it is clarified that on receipt of a written request from a broadcaster by a distributor for carrying television channels, the written interconnection agreement, between the distributor and the broadcaster, shall be entered into within thirty days of receipt of such request and, the distributor shall distribute television channels of such broadcaster's within thirty days, from the date of signing of written interconnection agreement or from the date of availability of spare channel capacity on the distribution network, whichever is later, through the distribution network.

(19) It shall be permissible to a broadcaster to sign the reference interconnection offer published by a distributor of television channels under sub-regulation (1) of regulation 8, as an interconnection agreement, for carrying television channels and send the said agreement to such distributor for providing access to the distribution networks.

(20) It shall be the responsibility of every distributor of television channels who enters into an interconnection agreement with a broadcaster to hand over a copy of written interconnection agreement to that broadcaster within a period of fifteen days from the date of execution of the interconnection agreement and retain a copy of an acknowledgement so obtained from the broadcaster.

(21) Every distributor of television channels shall enter into a new written interconnection agreement, for carrying television channels requested by a broadcaster, before the expiry of the existing interconnection agreement:

Provided that the distributor of television channels shall, at least sixty days prior to the date of expiry of the existing interconnection agreement, give notice to the broadcaster to enter into new written interconnection agreement:

Provided further that in case the parties fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the distributor of television channels may not carry such television channels on expiry of the existing interconnection agreement:

Provided further that a distributor of television channels shall not discontinue carrying a television channel if the signals of such television channel remain available for distribution and monthly subscription percentage for that particular television channel is more than twenty percent of the monthly average active subscriber base in the target market:

Provided also that if the distributor of television channels decides to discontinue carrying a television channel due to expiry of the existing interconnection agreement, it shall, fifteen days prior to the date of expiry of its existing interconnection agreement, inform the subscribers through scrolls on the channels included in the said agreement—

(a) the date of expiry of its existing interconnection agreement; and

(b) the date of disconnection of signals of television channels in the event of its failure to enter into new interconnection agreement.

**11. Territory of interconnection agreement.**—(1) The interconnection agreement signed between a broadcaster and a multi-system operator shall include the following details for describing the territory for the purpose of distribution of signals of television channels --

(a) the registered area of operation of the multi-system operator as mentioned in the registration granted by the Central Government;

(b) the names of specific areas for which distribution of signals of television channels has been agreed, initially, at the time of signing of the interconnection agreement; and

(c) the names of the corresponding states/ union territories in which such agreed areas as referred in clause (b) of this sub-regulation are located.

(2) It shall be permissible to the multi-system operator to distribute the channels beyond the areas agreed under sub-regulation (1), by giving a written notice to the broadcaster, after thirty days from the date of receipt of such written notice by the broadcaster and the said notice shall deemed to be an addendum to the existing interconnection agreement:

Provided that such areas fall within--

(a) the registered area of operation of the multi-system operator; and

(b) the states or union territories in which the multi-system operator has been permitted to distribute the signals of television channels under the interconnection agreement.

(3) Nothing contained in sub-regulation (2) shall apply if written objections with reasons from the broadcaster have been received by the multi-system operator during the said thirty days notice period:

Provided that any objection by the broadcaster, which is unreasonable, shall be deemed to constitute a denial of provisioning of signals beyond the areas agreed under the clause (b) of sub-regulation (1).

**12. Interconnection agreement between distributor of television channels and local cable operator.**—(1) No distributor of television channels shall provide signals of television channels to a local cable operator without entering into a written interconnection agreement with such local cable operator.

(2) No local cable operator shall distribution television channels of any broadcaster to any subscriber without entering into a written interconnection agreement with a distributor of such television channels.

(3) Every multi-system operator shall, within thirty days of receipt of written request from a local cable operator, enter into a written interconnection agreement with such local cable operator for providing signals of television channels, on lines of the model interconnection agreement as set out in the Schedule V by mutually agreeing on the clauses 10, 11 and 12 of the said agreement:

Provided that the multi-system operator and the local cable operator, without altering or deleting any clause of the model interconnection agreement, may add, through mutual agreement, clauses to the model interconnection agreement however such addition shall not have the effect of diluting any of the clauses as laid down in the model interconnection agreement:

Provided further that in case the multi-system operator and the local cable operator fail to enter into interconnection agreement, the multi-system operator and the local cable operator shall enter into the standard interconnection agreement as specified in the Schedule VI.

*Explanation:* For removal of doubt, it is clarified that in the event of any conflict between the terms and conditions of the model interconnection agreement and new terms and conditions added through mutual agreement by the parties, the terms and conditions of the prescribed model interconnection agreement shall prevail.

(4) Every multi-system operator, upon entering into a written interconnection agreement with a local cable operator, shall provide signals of television channels, within thirty days of entering into the written interconnection agreement, to such local cable operator.

(5) It shall be the responsibility of every multi-system operator who enters into an interconnection agreement with a local cable operator to handover a copy of such agreement to that local cable operator within a period of fifteen days from the date of execution of the agreement and retain a copy of an acknowledgement so received from the local cable operator.

(6) Every multi-system operator shall enter into a new written interconnection agreement with local cable operator before the expiry of the existing interconnection agreement:

Provided that the multi-system operator shall, at least sixty days prior to the date of expiry of the existing interconnection agreement, give notice to the local cable operator to enter into new written interconnection agreement:

Provided further that in case, the parties fail to enter into new written interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the distributor shall not make available the signals of television channels to the local cable operator on expiry of the existing interconnection agreement:

Provided also that the multi-system operator shall, fifteen days prior to the date of expiry of its existing interconnection agreement, inform the subscribers through scrolls on the channels included in the said agreement—

(a) the date of expiry of its existing interconnection agreement; and

(b) the date of disconnection of signals of television channels in the event of its failure to enter into new interconnection agreement.

(7) The settlement of service charges between local cable operator and multi-system operator shall be governed by mutual agreement:

Provided that in cases the multi-system operator and the local cable operator fail to arrive at a mutual agreement for settlement of service charges, then the network capacity fee amount and the distribution fee amount shall be shared in the ratio of 55:45 between multi-system operator and local cable operator.

(8) The provisions of sub-regulations (3), (4), (5), (6) and (7) of this regulation shall, with necessary adaptations and modifications, apply to HITS operator and IPTV operator.

**13. Non-Applicability to DTH operator.**— Nothing contained in the regulations 11 and 12 shall apply to a DTH operator.

## CHAPTER V

## SUBSCRIPTION REPORT AND AUDIT

**14. Subscription report and monthly fee.**—(1) Every distributor of television channels shall, within seven days from the end of each calendar month, provide, in the format specified in the Schedule VII, complete and accurate monthly subscription report of channels and bouquets of pay channels, to the broadcasters, with whom the written interconnection agreements have been entered into for distribution of channels:

Provided that it shall be permissible to a broadcaster to disconnect the signals of its television channel after giving written notice of three weeks to the distributor if the distributor fails to provide the monthly subscription report under this regulation.

(2) On the basis of monthly subscription report, the broadcaster shall issue monthly invoice to the distributor for 'broadcaster's share of maximum retail price' payable by such distributor to the broadcaster and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date for payment:

Provided that the broadcaster shall allow a time period of at least fifteen days to the distributor of television channels for making payment from the date of receipt of invoice by the distributor:

Provided further that in case the distributor fails to provide the monthly subscription report within the period of seven days from the end of the calendar month, the broadcaster shall have the right to raise a provisional invoice, for an amount increased by ten percent of the 'broadcaster's share of maximum retail price' payable by the distributor to the broadcaster for the immediate preceding month, and the distributor shall be under obligation to make the payment on the basis of such provisional invoice:

Provided also that it shall be mandatory for the broadcaster and the distributor to carryout reconciliation, between the provisional invoice and the final invoice raised by the broadcaster on the basis of the monthly subscription report sent by the distributor, within three months from the date of issue of such provisional invoice.

(3) Every distributor of television channels shall issue monthly invoice to the broadcasters, with whom the written interconnection agreements have been entered into for carrying channels, for payment of the carriage fee payable by such broadcaster along with the average active subscriber base in the target market in the month and the monthly subscription report for the channel of the broadcaster carried by the distributor of television channels in the format specified in the Schedule VII and such invoices shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date for payment:

Provided that the distributor shall allow a time period of at least fifteen days to the broadcaster for making payment from the date of receipt of invoice by the broadcaster.

**15. Audit.**—(1) Every distributor of television channels shall, once in a calendar year, cause audit of its subscriber management system, conditional access system and other related systems by an auditor to verify that the monthly subscription reports made available by the distributor to the broadcasters are complete, true and correct, and issue an audit report to this effect to each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement:

Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every distributor of television channels to cause audit, under this sub-regulation, from anyone of such empanelled auditors:

Provided further that any variation, due to audit, resulting in less than zero point five percent of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid.

(2) In cases, where a broadcaster is not satisfied with the audit report received under sub-regulation (1) or, if in the opinion of a broadcaster the addressable system being used by the distributor does not meet requirements specified in the Schedule III, it shall be permissible to the broadcaster, after communicating the reasons in writing to the distributor, to audit the subscriber management system, conditional access system and other related systems of the distributor of television channels, not more than once in a calendar year:

Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every broadcaster to cause audit, under this sub-regulation, from anyone of such empanelled auditors:

Provided further that if such audit reveals that additional amount is payable to the broadcaster, the distributor shall pay such amount, along with the interest at the rate specified by the broadcaster in the interconnection agreement, within ten days and if such amount including interest due for any period exceed the amount reported by the distributor to be due for such period by two percent or more, the distributor shall bear the audit expenses, and take necessary actions to avoid occurrence of such errors in the future:

Provided also that it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor, if such audit reveals that the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the Schedule III.

(3) Every distributor of television channels shall offer necessary assistance to auditors so that audits can be completed in a time bound manner.

## CHAPTER VI

### MISCELLANEOUS

**16. Change in the maximum retail price and the nature of a channel.**—Every broadcaster, before making any change, in the maximum retail price of the pay channel or the bouquet of pay channels, or in the nature of the channel, as the case may be, declared under the tariff order notified by the Authority, shall follow the provisions of these regulations including but not limited to the provisions pertaining to publication of reference interconnection offer by broadcasters of pay channels.

**17. Disconnection of signals of television channels.**—No service provider shall disconnect the signals of television channels without giving at least three weeks' notice in writing to other service provider, clearly specifying the reasons for the proposed disconnection:

Provided that the period of three weeks' notice shall start from the date of receiving the notice by the other service provider:

Provided further that the distributor of television channels shall, fifteen days prior to the date of disconnection, inform the subscriber, through scrolls on the channels proposed to be disconnected, the date of disconnection of signals of such television channels:

Provided also that no service provider shall display notice for disconnection of signals of television channels in form of static images overlaid on the television screen, obstructing normal viewing of the subscribers.

**18. Listing of channels in electronic programme guide.**—(1) Every broadcaster shall declare the genre of its channels and such genre shall be either 'Devotional' or 'General Entertainment' or 'Infotainment' or 'Kids' or 'Movies' or 'Music' or 'News and Current Affairs' or 'Sports' or 'Miscellaneous'.

(2) It shall be mandatory for the distributor to place channels in the electronic programme guide, in such a way that the television channels of same genre, as declared by the broadcasters, are placed together consecutively and one channel shall appear at one place only:

Provided that all television channels of same language within the same genre shall appear together consecutively in the electronic programme guide:

Provided further that it shall be permissible to the distributor to place a channel under sub-genre within the genre declared for the channel by the broadcaster.

(3) Every distributor of television channels shall assign a unique channel number for each television channel available on the distribution network.

(4) The channel number once assigned to a particular television channel shall not be altered by the distributor for a period of at least one year from the date of such assignment:

Provided that this sub-regulation shall not apply in case the channel becomes unavailable on the distribution network:

Provided further that if a broadcaster changes the genre of a channel then the channel number assigned to that particular television channel shall be changed to place such channel together with the channels of new genre in the electronic program guide.

**19. Details of service providers.**—(1) The Authority may, in order to protect the interest of the consumer or service provider or to promote and ensure orderly growth of the broadcasting and cable television sector or for monitoring and ensuring compliance of these regulations, by order or direction, specify website for the purpose of reporting of the details by service providers.

(2) Every service provider shall report, its name, address, contact number, e-mail address and license/ permission/ registration details issued by the Central Government on the website specified by the Authority, within thirty days from the date of commencement of these regulations or within thirty days from the specification of website for the purpose, whichever is later.

(3) Any service provider, who commences its operations after coming into effect of these regulations shall report, its name, address, contact number, e-mail address and license/ permission/ registration details issued by the Central Government on the website specified by the Authority, within thirty days from the date of commencement of its operations or within thirty days from the specification of website for the purpose, whichever is later.

(4) It shall be mandatory for a service provider to verify, from the website specified by the Authority, that the service provider seeking interconnection for providing signals of television channels or access to the network, as the case may be, has reported its details under sub-regulation (2) and sub-regulation (3):

Provided that this sub-regulation shall be applicable in the event of the Authority specifying such website.

**20. Designation of compliance officer and his obligations.**—(1) Every broadcaster and distributor of television channels shall, within thirty days from the date of commencement of these regulations, designate a compliance officer.

(2) Every broadcaster and distributor of television channels, who commences its operations after coming into effect of these regulations, shall, within thirty days from the date of commencement of its operations, designate a compliance officer.

(3) Every broadcaster or distributor of television channels, as the case may be, shall, within thirty days from the date of designation of the compliance officer under the provisions of this regulation, furnish to the Authority the name, complete address, contact number and e-mail address of the compliance officer along with authenticated copy of the board's resolution authorizing the designation of such compliance officer:

Provided that the distributor of television channels, which is not a company, shall, within thirty days from the date of designation of the compliance officer under the provisions of this regulation, furnish to the Authority the name, full address, contact number and e-mail address of the compliance officer along with authenticated copy of the authorization letter authorizing the designation of such compliance officer.

(4) In the event of any change in the name of the compliance officer so designated under provisions of this regulation, the same shall be reported to the Authority by the service provider within thirty days from the date of occurrence of such change along with authenticated copy of the board's resolution or authorization letter, as the case may be.

(5) In the event of any change in the address or contact number or email address of the compliance officer, the same shall be reported to the Authority by the service provider within ten days from the date of occurrence of such change.

(6) The compliance officer shall be responsible for—

- (a) generating awareness for ensuring compliance with the provisions of these regulations;
- (b) reporting to the Authority, with respect to compliance with these regulations and directions of the Authority issued under these regulations; and
- (c) ensuring that proper procedures have been established and are being followed for compliance of these regulations.

(7) The provisions contained in the sub-regulation (6) shall be in addition to the liability of the service provider to comply with the requirements laid down under these regulations.

**21. Intervention by the Authority.**—The Authority may, in order to protect the interest of the consumer or service provider or to promote and ensure orderly growth of the broadcasting and cable television sector or for monitoring and ensuring compliance of these regulations, by order or direction, intervene, from time to time.

**22. Repeal and saving.**—(1) The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 are hereby repealed.

(2) The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004, to the extent they are applicable to addressable systems, are hereby repealed.

(3) Notwithstanding the repeal of regulations mentioned, under sub-regulation (1) and sub-regulation (2) of this regulation, anything done or any action taken or proposed to have been done under the said regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./456/16]

**Note.**—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017.



**Schedule I***(Refer sub-regulation (2) of the regulation 8)***Calculation of the carriage fee amount**

The carriage fee amount, for each month or part thereof, during the term of the interconnection agreement shall be calculated as given below:-

Sl.	Calculation of the carriage fee amount
1	If monthly subscription for a channel in the target market is less than five percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market.
2	If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to five percent but less than ten percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by 0.75 times of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market.
3	If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to ten percent but less than fifteen percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by 0.5 times of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market.
4	If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to fifteen percent but less than twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by 0.25 times of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market.
5	If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to 'Nil'.

**Note:-** (1) For the purpose of calculation of carriage fee amount for a high definition channel, the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market shall be of subscribers capable of receiving high definition television channels.

(2) The average active subscriber base of the distributor in a month shall be calculated in the manner as prescribed in the Schedule VII.

(3) The monthly subscription for a channel shall be calculated in the manner as prescribed in the Schedule VII.

(4) The Illustration-I (for standard definition channel) and Illustration-II (for high definition channels) given below explains the calculation of carriage fee amount:-

**ILLUSTRATION-I**

Suppose a distributor of television channels has an agreement with a broadcaster for carriage of a standard definition channel called 'X' at the rate of Rs. 0.20 per subscriber per month. The carriage fee amount payable by the broadcaster to the distributor would be calculated as follows:-

Month	Average Active Subscriber Base over the month	Monthly subscription percentage of the standard definition Channel 'X'	Rate of Carriage Fee (in Paisa)	Multiplier	Carriage Fee Amount in (Rs.)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(B)x(D)x(E)
January	1000	4%	20	1	200.00
February	800	8%	20	0.75	120.00

March	1500	12%	20	0.50	150.00
April	2000	19%	20	0.25	100.00
May	3000	20%	20	0	0.00
June	4000	22%	20	0	0.00
July	10000	17%	20	0.25	500.00
August	20000	25%	20	0	0.00

### **ILLUSTRATION-II**

Suppose a distributor of television channels has an agreement with a broadcaster for carriage of a high definition channel called 'Y' at a rate of Rs. 0.40 per subscriber per month then the carriage fee amount payable by the broadcaster to the distributor would be calculated as follows:-

Month	Average Active Subscriber Base, of high definition STBs, over the month	Monthly subscription percentage of the high definition Channel 'Y'	Rate of Carriage Fee (in paisa)	Multiplier	Carriage Fee Amount in (Rs.)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(B)x(D)x(E)
January	100	2%	40	1	40.00
February	80	5%	40	0.75	24.00
March	150	11%	40	0.50	30.00
April	160	16%	40	0.25	16.00
May	180	20%	40	0	0.00
June	200	22%	40	0	0.00
July	190	17%	40	0.25	19.00
August	170	25%	40	0	0.00

**Schedule II***(Refer sub-regulation (4) of the regulation 10)***Application form for request of signals of television channels**

1. Name of the distributor of television channels:
2. The names of Owners/Directors/Partners of the distributor:
3. Registered Office address:
4. Address for communication:
5. Name of the contact person/ Authorized Representative:
6. Telephone:
7. Email address:
8. Copy of certificate of registration/ permission/ license (Attach a Copy):
9. Details of Head-end, Conditional Access Systems (CAS) and Subscriber Management Systems (SMS) deployed by the distributor:
10. Details of the areas, corresponding States/ UTs and details of the Head-end from which the signals of television channels shall be distributed in such areas:
11. Area wise present subscriber base of the distributor:
12. List of channels and bouquets for which signals of television channels are requested:
13. Service Tax registration number:
14. Entertainment Tax Number:
15. PAN No. (Attach a copy):
16. Are the CAS/ SMS in compliance with the regulations: YES / NO
17. Copy of the report of the Auditor in compliance of the Schedule III of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable System) Regulations 2017, if available:

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Date and Place

**DECLARATION**

I \_\_\_\_\_ s/o, d/o \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Owner/Proprietor/Partner /Director/ Authorized Signatory), of \_\_\_\_\_ (Name of Distributor of television channels), do hereby declare that the details provided above are true and correct. I state that the addressable systems installed for distribution of television channels meet the technical and other requirements specified in the Schedule III of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable System) Regulations 2017. The configuration and the version of the addressable system have not been changed after issuance of the report by the Auditor.

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Date and Place

**Schedule III***(Refer sub-regulation (6) of the regulation 10)***Addressable Systems Requirements****A) Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS):**

1. The distributor of television channels shall ensure that the current version of the CAS, in use, do not have any history of hacking.

*Explanation:* A written declaration available with the distributor from the CAS vendor, in this regard, shall be construed as compliance of this requirement.

2. The SMS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the SMS including but not limited to activation and deactivation commands.
3. It shall not be possible to alter the data and logs recorded in the CAS and the SMS.
4. The distributor of television channels shall validate that the CAS, in use, do not have facility to activate and deactivate a Set Top Box (STB) directly from the CAS terminal. All activation and deactivation of STBs shall be done with the commands of the SMS.
5. The SMS and the CAS should be integrated in such a manner that activation and deactivation of STB happen simultaneously in both the systems.

*Explanation:* Necessary and sufficient methods shall be put in place so that each activation and deactivation of STBs is reflected in the reports generated from the SMS and the CAS terminals.

6. The distributor of television channels shall validate that the CAS has the capability of upgrading STBs over-the-air (OTA), so that the connected STBs can be upgraded.
7. The fingerprinting should not get invalidated by use of any device or software.
8. The CAS and the SMS should be able to activate or deactivate services or STBs of at least 10% of the subscriber base of the distributor within 24 hours.
9. The STB and Viewing Card (VC) shall be paired from the SMS to ensure security of the channel.
10. The CAS and SMS should be capable of individually addressing subscribers, for the purpose of generating the reports, on channel by channel and STB by STB basis.
11. The SMS should be computerized and capable of recording the vital information and data concerning the subscribers such as:
  - a. Unique customer identification (ID)
  - b. Subscription contract number
  - c. Name of the subscriber
  - d. Billing address
  - e. Installation address
  - f. Landline telephone number
  - g. Mobile telephone number
  - h. E-mail address
  - i. Channels, bouquets and services subscribed
  - j. Unique STB number
  - k. Unique VC number.

12. The SMS should be capable of:

- a. Viewing and printing of historical data in terms of the activations and the deactivations of STBs.
  - b. Locating each and every STB and VC installed.
  - c. Generating historical data of changes in the subscriptions for each subscriber and the corresponding source of requests made by the subscriber.
13. The SMS should be capable of generating reports, at any desired time about:
- i. The total number of registered subscribers.
  - ii. The total number of active subscribers.
  - iii. The total number of temporary suspended subscribers.
  - iv. The total number of deactivated subscribers.
  - v. List of blacklisted STBs in the system.
  - vi. Channel and bouquet wise monthly subscription report in the prescribed format.
  - vii. The names of the channels forming part of each bouquet.
  - viii. The total number of active subscribers subscribing to a particular channel or bouquet at a given time.
  - ix. The name of a-la carte channel and bouquet subscribed by a subscriber.
  - x. The ageing report for subscription of a particular channel or bouquet.
14. The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.
15. The CAS shall be able to tag and blacklist VC numbers and STB numbers that have been involved in piracy in the past to ensure that such VC or the STB cannot be re-deployed.
16. It shall be possible to generate the following reports from the logs of the CAS:
- a. STB-VC Pairing / De-Pairing
  - b. STB Activation / De-activation
  - c. Channels Assignment to STB
  - d. Report of the activations or the deactivations of a particular channel for a given period.
17. The SMS shall be capable of generating bills for each subscriber with itemized details such as the number of channels subscribed, the network capacity fee for the channels subscribed, the rental amount for the customer premises equipment, charges for pay channel and bouquet of pay channels along with the list and retail price of corresponding pay channels and bouquet of pay channels, taxes etc.
18. The distributor shall ensure that the CAS and SMS vendors have the technical capability in India to maintain the systems on 24x7 basis throughout the year.
19. The distributor of television channels shall declare the details of the CAS and the SMS deployed for distribution of channels. In case of deployment of any additional CAS/ SMS, the same should be notified to the broadcasters by the distributor.
20. Upon deactivation of any subscriber from the SMS, all programme/ services shall be denied to that subscriber.

21. The distributor of television channels shall preserve unedited data of the CAS and the SMS for at least two years.

**(B) Fingerprinting:**

1. The distributor of television channels shall ensure that it has systems, processes and controls in place to run finger printing at regular intervals.
2. The STB should support both visible and covert types of finger printing.
3. The finger printing should not be removable by pressing any key on the remote of STB.
4. The finger printing should be on the top most layer of the video.
5. The finger printing should be such that it can identify the unique STB number or the unique VC number.
6. The finger printing should appear on the screens in all scenarios, such as menu, Electronic Programme Guide (EPG), Settings, blank screen, and games etc.
7. The location, font colour and background colour of fingerprint should be changeable from head end and should be random on the viewing device.
8. The finger printing should be able to give the numbers of characters as to identify the unique STB and/or the VC.
9. The finger printing should be possible on global as well as on the individual STB basis.
10. The overt finger printing should be displayed by the distributor of television channels without any alteration with regard to the time, location, duration and frequency.
11. Scroll messaging should be only available in the lower part of the screen.
12. The STB should have a provision that finger printing is never disabled.
13. The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.

**(C) Set Top Box (STB):**

1. All STBs should have a Conditional Access System.
2. The STB should be capable of decrypting the Conditional Access messages inserted by the Head-end.
3. The STB should be capable of doing finger printing. The STB should support both Entitlement Control Message (ECM) and Entitlement Management Message (EMM) based fingerprinting.
4. The STB should be individually addressable from the Head-end.
5. The STB should be able to receive messages from the Head-end.
6. The messaging character length should be minimal 120 characters.
7. There should be provision for global messaging, group messaging and the individual STB messaging.
8. The STB should have forced messaging capability including forced finger printing display.
9. The STB must be compliant to the applicable Bureau of Indian Standards.
10. The STBs should be addressable over the air to facilitate OTA software upgrade.
11. The STBs with facilities for recording the programs shall have a copy protection system.

**Schedule IV***(Refer sub-regulation (16) of the regulation 10)***Application form for access to the network for distribution of a television channel**

- a. Name of the broadcaster:
- b. The names of CEO/MD of the broadcaster:
- c. Registered Office address:
4. Address for communication:
5. Name of the contact person/ Authorized Representative:
6. Telephone:
7. Email address:
8. Name of channel for which request for distribution has been made:
9. Copy of permission letter issued by the ministry of information and broadcasting for downlinking of the channels mentioned above in India:
10. Nature of channel (pay or free- to- air)
11. Genre of channel:
12. Language(s) of channel:
13. Downlinking parameters of the channel:
  - a. Name of satellite:
  - b. Orbital location:
  - c. Polarisation:
  - d. Downlinking frequency:
14. Modulation/coding and compression standard of channel:
15. Encryption of channel: encrypted/unencrypted

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Date and Place:

**DECLARATION**

I \_\_\_\_\_ s/o, d/o \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Authorized Signatory), of \_\_\_\_\_ (Name of the broadcaster), do hereby declare that the details provided above are true and correct.

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Date and Place:

**Schedule V***[Refer sub-regulation (3) of the regulation 12]*

**MODEL INTERCONNECTION AGREEMENT BETWEEN MULTI SYSTEM OPERATOR AND LOCAL CABLE OPERATOR FOR PROVISIONING OF CABLE TV SERVICES THROUGH DIGITAL ADDRESSABLE SYSTEMS (DAS).**

*[1. Each page of this Agreement shall be signed by the authorised signatory of Multi System Operator and Local Cable Operator;*

*2. The numbers allotted to the clauses in this format shall not be altered and additions (if any) may either be carried out at the end of relevant clause or after the last clause of this format].*

This Technical and Commercial Interconnection Agreement along with its Schedules and Annexures is executed on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 201\_ by and between:

\_\_\_\_\_, having its office at \_\_\_\_\_, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the “**MSO**” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors of the **ONE PART**.

MSO's Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals (strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)

#### AND

\_\_\_\_\_, having its office at \_\_\_\_\_, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the “**LCO**” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors, of the **OTHER PART**

LCO's Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals (strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)

The **MSO** and the **LCO** are hereinafter individually referred to as ‘Party’ and collectively referred to as “**Parties**”.

#### WHEREAS,

A. The MSO is a cable operator, who has been granted registration No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ under the Cable Television Networks Rules, 1994, by the Ministry of Information and Broadcasting, for providing cable TV services through digital addressable systems in the areas of \_\_\_\_\_ notified by the Central Government under Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

B. The LCO is a cable operator, who has been granted registration under the Cable Television Networks Rules, 1994, having postal registration No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, in the head post office \_\_\_\_\_, [Name of the head post office] for providing Cable TV Services in \_\_\_\_\_ [Mention the area].

C. The LCO has requested the MSO vide its letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ for making available signals of TV channels and the MSO has agreed vide its letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ to provide signals of TV channels to such LCO.

D. **TERRITORY:** Territory, in the context of this Agreement is \_\_\_\_\_ [mention the name of area(s)/ city(ies)/ district(s)/ state(s) for which this agreement is being signed.]

E. The Parties have mutually agreed to execute this Agreement - on principal to principal and non-exclusive basis - between them to govern the roles, responsibilities, rights, obligations, technical and commercial arrangement in regard to the distribution of TV channels in the Territory.

F. The Parties also mutually agree that each and every transaction including transaction of any properties/ assets between the Parties shall be carried out in writing or in any other verifiable means.

**NOW, THEREFORE**, in consideration of the foregoing and the mutual covenants contained herein, the Parties agree as follows: -

#### 1. DEFINITIONS

The words and expressions used in this Agreement shall have meanings as assigned to them in the Schedule to this Agreement. All other words and expressions used in this Agreement, but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made there under or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

#### 2. TERM OF THE AGREEMENT

2.1 The Agreement shall commence on \_\_\_\_\_ [dd/mm/yyyy] and remain in force till \_\_\_\_\_ [dd/mm/yyyy] or the date of expiry of registration of the MSO or the LCO, as the case may be, whichever is earlier, unless terminated by either Party as per the terms and conditions of this Agreement.

2.2 The duration of the Agreement may be extended on terms and conditions to be mutually agreed between the Parties and recorded in writing provided that the extended term does not go beyond the last date of validity of registration of the MSO or the LCO, whichever is earlier.



### 3. TERMINATION OF THE AGREEMENT

3.1 Either Party has a right to terminate the Agreement by serving an advance notice of 21 days in writing to the other Party in the event of:-

- (i) material breach of the Agreement by the other Party which has not been cured within 15 days of being required in writing to do so; or
- (ii) the bankruptcy, insolvency or appointment of receiver over the assets of other Party; or
- (iii) the other Party indulging in, or allowing or inducing any person to indulge in piracy or carrying programming service provided on the channel which is in violation of the Programme and Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

3.2 The LCO has a right to terminate the Agreement in the event of the MSO discontinuing the business of distribution of TV channels in the Territory.

3.3 The MSO has a right to terminate the agreement in the event of the LCO discontinuing its cable TV business in the Territory.

3.4 If the MSO decides to discontinue the business of distribution of TV channels in the Territory for any reason, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the LCO at least 90 days prior to such discontinuation.

3.5 If the LCO decides to discontinue its business of providing signals of TV channels to the subscriber in the territory, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the MSO at least 90 days prior to such discontinuation.

### 4. EFFECT OF TERMINATION AND EXPIRY

4.1 In the event of termination or expiry of the term of the Agreement, as the case may be, at the instance of either Party, each Party shall pay all amounts due and payable up to the date of termination or expiry to the other Party.

4.2 The LCO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the MSO all properties and assets belonging to the MSO, which are in the custody of the LCO. The LCO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the MSO, in custody of the LCO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the MSO and in the event of inability of LCO to repair such properties/assets, the LCO shall pay to the MSO the depreciated value of such properties/ assets.

4.3 The MSO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the LCO all properties and assets belonging to the LCO, which are in the custody of the MSO. The MSO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the LCO, in custody of the MSO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the LCO and in the event of inability of MSO to repair such properties/assets, the MSO shall pay to the LCO the depreciated value of such properties/ assets.

Explanation:- The clause 4.2 and 4.3 above shall not have any application in respect of Hardware or any other equipment belonging to the MSO or the LCO, as the case may be, which are installed at the premises of the subscribers.

4.4 If the LCO or the MSO, as the case may be, fails to hand over the assets or make good losses or damages caused to such properties and assets within the above stipulated period, the defaulting Party shall be liable to make payment for the depreciated value of the same together with simple interest calculated at the rate 2% over and above the base rate of interest of the State Bank of India.

### 5. PROVISIONING OF SERVICES

5.1 The MSO shall make available signals of TV channels to the LCO, on non-exclusive basis, in order to distribute the same to the subscribers in the Territory, in terms of this agreement and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

5.2 The LCO shall carry signals of TV channels received from the MSO, on non-exclusive basis, for distribution to the subscribers in the Territory.

5.3 The Parties shall compulsorily transmit, re-transmit or otherwise carry any channel or programme only in encrypted mode through a digital addressable system strictly in terms of and in accordance with the applicable laws and regulations.

5.4 The roles and responsibilities of the Parties to the Agreement for provisioning of services are contained in **clause 10** of this Agreement.

5.5 In consideration of the roles and responsibilities mentioned in **clause 10** of the Agreement, the revenue settlement between the LCO and the MSO have been mentioned in the **clause 12** of the Agreement.

## **6. RIGHTS OF THE MSO**

6.1 The MSO shall continue to have a right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it may expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service provided to the subscribers.

6.2 The MSO shall sign the interconnection agreement with broadcasters for distribution of TV Channels as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

6.3 The MSO shall have the right to finalise the maximum retail price of each channel, as payable by the subscriber in compliance with the provisions of applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.4 The MSO shall have the right to package the channels/ services offered on the network, as per its business plan and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.5 The MSO shall have the right to finalise the rate of Basic Service Tier (BST) in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority from time to time.

6.6 The MSO shall have the right to finalise the rates of bouquets of channels, if offered by the MSO, in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority.

6.7 The MSO shall have the right to get all requisite information from the LCO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

## **7. RIGHTS OF THE LCO**

7.1 The LCO shall continue to have its right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it can expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service offered to the subscriber on its network.

7.2 The LCO shall have right to get all the requisite information from the MSO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

## **8. OBLIGATIONS OF THE MSO**

8.1 MSO shall set up and operationalise the Head-end, Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) for ensuring efficient and error-free services to the subscribers by recording and providing individualized preferences for channels, billing cycles or refunds.

8.2 The MSO shall make available to the LCO, the necessary and sufficient information relating to the details of channels, bouquets of channels, and services offered to the subscribers including their prices.

8.3 The MSO shall provide web based grievance redressal mechanism for addressing the complaints of LCOs in relation to the provision of services, roles and responsibilities, revenue settlements, quality of services etc.

8.4 The MSO shall not issue pre-activated STBs and the STBs shall be activated only after the details of the Customer Application Form (CAF) have been entered into the SMS.

8.5 The MSO shall generate bills for subscribers on regular basis, for charges due and payable for each month or as per the billing cycle applicable for that subscriber, within 3 days from the end of the billing cycle.

8.6 The MSO shall provide access to the relevant part of the SMS under its control to the LCO for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

8.7 The MSO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the LCO or person associated with such transmission.

8.8 The MSO shall comply with all the applicable statutes or laws for the time being in force, or any rules, codes, regulations, notifications, circulars, guidelines, orders, directions etc. issued, published or circulated under any law for the time being in force.

8.9 The MSO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the LCO in respect of cable TV signals under this Agreement or any property of the LCO may be infringed or prejudiced.

8.10 The MSO shall be responsible for encryption of the complete signal, up to the STB installed at the premises of the subscriber.

8.11 The MSO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' advance notice to the LCO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

8.12. The MSO shall make available consumer friendly electronic payment options in the subscriber management system for the electronic payment of bills by the subscribers, prepaid system for subscribers and facility for acknowledgments/receipts to the subscribers for the payments made by them.

8.13 The MSO shall provide to the LCO at least 2% of the total STBs active in the network of the LCO with an upper cap of 30 STBs as maintenance spare, which are not pre-activated, to ensure speedy restoration of services affected due to any fault in STB. This quantity of maintenance spare STBs shall be maintained during the term of the agreement.

8.14 The MSO shall intimate to the LCO, at least 15 days in advance, in respect of any proposed changes in the package composition or the retail tariff being offered to the subscriber.

8.15 The MSO shall have no right, without the prior written intimation to the LCO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

## **9. OBLIGATIONS OF THE LCO**

9.1 The LCO shall handover a copy of CAF received from subscribers within 15 days to the MSO.

9.2 The LCO shall be responsible for entering the details of the bill amount paid by the individual subscriber to the LCO for the Cable TV services in the SMS.

9.3 The LCO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the MSO, or any other person associated with such retransmission.

9.4 The LCO shall have no right, without the prior written intimation to the MSO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

9.5 The LCO shall not replace the STBs of the MSO with the STBs of any other MSO without receiving the requests from the subscribers through application forms for returning the STB of the existing connections and for providing new connections through Customer Application Form. The new Set Top Box shall be activated only after entry of the details, as provided in new Customer Application Form, into the Subscriber Management System of the new MSO.

9.6 The LCO shall –

(i) not transmit or retransmit, interpolate or mix any signals which are not transmitted or generated by the MSO without the prior written consent of the MSO;

(ii) not insert any commercial or advertisement or information on any signal transmitted by the MSO. Any such tampering of signals or interpolating of signals shall be deemed to be a violation of this Agreement and shall constitute sufficient cause for termination of this Agreement by the MSO by giving such notice as prescribed under the law or under this agreement;

(iii) not interfere in any way with the signals provided by the MSO and also not use any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box or Smart card and any other like equipments;

(iv) not alter or tamper the Hardware including the seal (seal to prevent opening of set top box), misuse, replace, remove and shift the Smart card or STB without the written consent of MSO from their respective original addresses;

(v) not use, either before or after the installation of STB, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es), smart card(s) other than the STB(s), Smart cards and any other equipments supplied/ approved by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

(vi) intimate the MSO promptly about any alteration, tampering with the Hardware including the seal, misuse, replacement, removal and shifting of Smart cards and STBs, without the written consent of MSO, from their respective original addresses and also about the use, either before or after the STBs, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es) and smart card(s) other than the STB(s), Smart card(s) and any other items of Hardware supplied by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

9.7 The LCO shall not provide connection to any entity for further retransmission of the Cable TV signals.

9.8 The LCO shall not record and then retransmit Cable TV signals or otherwise to block or add or substitute or otherwise tamper with the signal being transmitted by the MSO or with the trunk line nor shall allow any other person to do so.

9.9 The LCO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the MSO in respect of the Cable TV signals under this Agreement or any property of the MSO may be infringed or prejudiced.

9.10 The LCO shall permit access to the systems under its control to the MSO, on non-exclusive basis, for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

9.11 The LCO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' notice to the MSO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

#### 10. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE MSO AND THE LCO:

Sl. No.	Role	Responsibility of the MSO or the LCO as mutually agreed by the Parties - fill the cell accordingly	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Devising of Consumer Application Form, either in electronic format or print format or both, for initial subscription to broadcasting services containing the information as provided in the Schedule I of the QoS regulations.		
2	a. Provide information to consumers about the details of services at the time of every new connection as per the QoS regulations. b. Providing information to the subscriber about the details of STB schemes offered and the warranty/ repairing policy applicable thereof.		
3	Provisioning of broadcasting services to the consumer upon obtaining duly filled Consumer Application Form and providing a copy of the same to the consumer as per the QoS regulations.		The Party who has been assigned this responsibility shall update the information in the Subscriber Management System (SMS) in each case within 24 hours from the receipt of the application.
4	Assigning a unique identification number (UIN) to every subscriber and communicating the same to the consumer as per the provisions of the QoS regulations.		The UIN shall be generated from the SMS. In case the responsibility is assigned to the LCO then the relevant access of the SMS should be provided by the MSO to the LCO.
5	Activation of broadcasting services to the subscribers.		(1) Activation shall be done only after only after the details of Consumer Application Form have been entered into the SMS.  (2) In case the responsibility is assigned to the LCO then the MSO should provide relevant access to SMS for activation of broadcasting services.
6	Activation of requested channel(s) or bouquet(s) available on the platform, upon receiving a verifiable request from a subscriber as per the provisions of the QoS regulations.		
7	Deactivation of requested channel(s) and bouquet(s) from the subscription package of subscriber upon receiving a verifiable request from the subscriber, as per the provisions of the QoS regulations.		
8	Temporary suspension of the broadcasting services of a subscriber upon receiving a request from the subscriber as per the provisions of the QoS regulations.		

9	Restoration of services of a subscriber, upon request from the subscriber as per the provisions of the QoS regulations.		
10	Relocation of connection of a subscriber from one location to another location, upon the request for the same as per the provisions of QoS regulations.		
11	Providing notice to the subscribers regarding interruption of signals for preventive maintenance as specified in QoS Regulations.		
12	Disconnection of broadcasting services to a subscriber upon request from the subscriber and refunding of deposits subject to fulfilment of the terms and conditions provided in the QoS regulations.		
13	Offering broadcasting services to the subscribers either on pre-paid basis or post-paid basis or both as provided in the QoS regulations.		
14	Changing payment mechanism from pre-paid to post-paid or vice-versa, as the case may be, on the request made by the subscriber.		
15	Generation of post-paid bills for subscribers as per the QoS regulations.		
16	Delivery of post-paid bills to subscribers as per the QoS regulations.		
17	Issuance and delivery of receipts to post-paid subscribers for manual payments made by them and entering the details of the receipts in the subscriber management system as per the QoS regulations.		
18	Acknowledging pre-paid payments to the subscriber and updating the subscriber management system accordingly.		
19	Providing set top boxes to the subscribers conforming to the standards prescribed in the QoS regulations.		
20	Offering different schemes for the STB as per the QoS regulations.		
21	Offering annual maintenance scheme for the Customer Premises Equipment provided under outright purchase scheme after the expiry of guarantee/warranty period as per the QoS regulations		
22	Repairing of a malfunctioning set top box as per the QoS regulations.		
23	Publicizing toll free consumer care number and address of the web based complaint management system to the subscribers through customer care channel and website, as provided in the QoS Regulations.		
24	Providing copies of Manual of Practice (MoP) to subscribers as specified in QoS regulations.		The MSO shall finalize the contents of MOP. Copies of such MoP shall be shared with the LCO.
25	Payment of taxes to the Government.	<b>MSO and/ or LCO</b>	The specific details of tax payment responsibilities need to be filled in the adjoining cells at the time of signing of the agreement as per the rules and

			regulations of the respective Tax authorities.
--	--	--	--

*Note:- The responsibilities for various roles mentioned in the column (2) above can be mutually agreed by the Parties and accordingly the cells of the column (3) to be filled.*

## 11. BILLING

11.1 The billing for subscriber shall be in the name of \_\_\_\_\_. However, each Party shall ensure that the applicable laws, rules and regulations relating to taxes are complied with.

11.2 The Party, in whose name the billing for subscribers have been agreed in the clause 11.1 above, shall receive the payment of the subscription fee paid by the subscribers. The revenue share as per clause 12.1 of this Agreement shall be paid by this Party to the other Party on receipt of the invoice from the other Party.

## 12. REVENUE SETTLEMENT BETWEEN THE LCO AND THE MSO AND RELATED RIGHTS AND OBLIGATIONS

12.1 The settlement of charges between the LCO and the distributor shall be in the following manner:-

- (a) network capacity fee amount shall be shared in the ratio of \_\_: \_\_ between multi system operator and local cable operator respectively.
- (b) the distribution fee amount shall be shared in the ratio of \_\_: \_\_ between multi system operator and local cable operator respectively.

### Note:-

- (1) *For mutual agreement cases where the roles and responsibilities of the MSO and the LCO have been agreed as per column (3) of clause (10), this clause can be suitably amended based on mutual agreement.*
- (2) *Network capacity fee amount and the distribution fee shall have the same meaning as defined in the Interconnection Regulations and Tariff Order.*

12.2\*

### (When the billing for subscribers is in the name of the LCO and the LCO receives the payment of subscription fee paid by the subscribers)

The MSO shall issue monthly invoice to the LCO towards dues payable by the LCO for revenue settlement and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment which shall not be less than seven days. Any demand of arrears shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain. The amounts raised in the invoice shall be payable on or before the due date as mentioned therein.

## OR

12.2\*

### (When the billing for subscribers is in the name of the MSO and the MSO receive the payment of subscription fee paid by the subscribers)

The MSO shall share the complete information relating to the subscribers billing and receipt of the payments with the LCO. The LCO shall issue monthly invoice to the MSO towards dues payable by the MSO for revenue settlement and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment which shall not be less than seven days. Any demand of arrears shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain. The amounts raised in the invoice shall be payable on or before the due dates as mentioned therein.

*(\*Strike out whichever is not applicable at the time of signing individual agreement)*

12.3 The Party shall update the details of the subscription amount realised from the subscriber, in the SMS within 7 days from the due date.

## 13. DEFAULTS

13.1 Without prejudice to such rights and remedies that the Parties may have in law or under the provisions of this Agreement, in the event of any delay or failure by the MSO or the LCO, as the case may be, to make payments of dues on or before the respective due dates, the LCO or the MSO, as the case may be, shall have the right:-

- (i) to disconnect the services subject to the compliance of the applicable rules, regulations, directions or orders of the Authority;

(ii) to terminate this Agreement, subject to compliance of the applicable laws in force;

(iii) to charge a simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India from the date such amounts became due until those are fully and finally paid;

13.2 In cases where any of the Parties has failed to make payment on or before due date for three consecutive months in the past, the other Party shall have right to demand the interest free security deposit which shall not exceed average of immediately preceding 6 months billing amounts and the same shall be maintained for the remaining term of the agreement.

13.3 Upon disconnection of the service as mentioned in clause 13.1 above, whether accompanied by termination of this Agreement or not, the defaulting Party shall be liable to deposit forthwith all sums payable by it. In the case of termination, accounts shall be settled within thirty days and for delayed payments, either Party shall be liable to pay simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India.

#### 14. UNDERTAKINGS

14.1 Each Party shall recognize the exclusive ownership of the property owned and installed by the other Party and shall not have or claim any right, title or interest or lien of whatsoever nature.

14.2 Nothing contained herein shall constitute either Party as the agent or partner or the representative of the other for any purpose and neither Party shall have the right or authority to assume, create or incur any liability or obligation of any kind, express or implied, in the name of or on behalf of the other Party and the relationship between the MSO and the LCO shall remain on "Principal to Principal" basis.

14.3 It is expressly understood by the Parties that "\_\_\_\_\_ " logo(s) is a Registered Trade Mark of the MSO, and the LCO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the MSO. Consent of the MSO is hereby given to the LCO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the MSO.

14.4 It is expressly understood by the Parties that "\_\_\_\_\_ " logo(s) is a Registered Trade Mark of the LCO, and the MSO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the LCO. Consent of the LCO is hereby given to the MSO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the LCO.

14.5 It is clearly understood and accepted by each Party that it shall have no right to use any intellectual property of the other on its Cable TV service or otherwise on or after the withdrawal by the other Party of its consent for such uses.

14.6 In case the LCO or the MSO, as the case may be, decides to transfer its interest in respect of its business of providing Cable TV Service to any other party / person (third party), in whole or in part, the LCO or the MSO, as the case may be, shall give prior notice to the MSO or the LCO. One Party shall not have any objection to such transfer if the other Party has complied with its obligations under this contract and has paid all its dues.

Provided, however, that such third party shall sign and execute a deed of adherence to the terms and conditions of this Agreement and other undertaking/ bonds to the satisfaction of the MSO or the LCO, as the case may be, in order to give effect to the provisions of this Agreement.

14.7 The LCO shall maintain and continue to maintain its Postal Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration certificate issued by the Postal Authority.

14.8 The MSO shall maintain and continue to maintain its Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration.

14.9 Both the Parties shall comply with the Programme Codes and Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

14.10 Both the Parties shall comply with the laws for the time being in force in India, as applicable to them.

#### 15. PREVENTION OF PIRACY

15.1 The Parties shall not indulge or allow any person to indulge in Piracy or in reverse engineering of any technology used in the Hardware or any component thereof nor shall they use the Hardware to be connected to any equipment for setting up a mini head-end for retransmission of the signals generated from the same.

15.2 Signal to any subscriber shall be disconnected by the MSO or the LCO, as the case may be, after giving due notice as required under applicable regulations, if found to be indulged in or abetting any Piracy.

**16. DISCLAIMER AND INDEMNITY**

16.1 In no event, the MSO shall be liable to the LCO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprival of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the MSO.

16.2 In no event, the LCO shall be liable to the MSO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprival of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the LCO.

16.3 LCO shall indemnify the MSO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the LCO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to LCO's breach.

16.4 MSO shall indemnify the LCO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the MSO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to MSO's breach.

**17. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION**

17.1 As mandated by the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Parties shall not institute any suit or seek injunction or interim orders in any court or judicial tribunal/ authority in India with respect to any claims, dispute or differences between the Parties arising out of this Agreement save and except before the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, New Delhi ("TDSAT"). The Parties agree that all disputes between the Parties shall be resolved solely through proceedings instituted before the TDSAT.

**18. FORCE MAJEURE**

18.1 Failure on the part of the MSO or the LCO to perform any of its obligations, shall not entitle either Party to raise any claim against the other or constitute a breach of this Agreement to the extent that such failure arises from an event of Force Majeure. If through Force Majeure the fulfilment by either Party of any obligation set forth in this Agreement is delayed, the period of such delay shall not be taken into account in computing periods prescribed by this Agreement. Force Majeure will include act of god, earthquake, tides, storm, flood, lightening, explosion, fire, sabotage, quarantine, epidemic, arson, civil disturbance, terrorist attack, war like situation, or enactment of any law or rules and regulation made by the Authorities or revocation of registration of the Parties any circumstances beyond the reasonable control of the Parties herein that directly or indirectly hinders or prevents either of the Parties from commencing or proceeding with the consummation of the transactions contemplated hereby. The Party affected by such Force Majeure event shall promptly notify the other Party of the occurrence of such event. It is agreed between the Parties that lack of funds shall not in any event constitute or be considered an event of Force Majeure. If the conditions of Force Majeure to continue for a period exceeding one month, the Parties shall meet to decide upon the future performance of the Agreement. If the Parties are unable to agree upon a plan for future performance, then the Agreement shall be terminated upon notice of either Party to the other, on expiry of one month from the date of such notice.

18.2 Any accrued payment obligation of a Party prior to the commencement of Force Majeure shall survive the termination of this Agreement pursuant to such Force Majeure.

**19. NOTICES**

19.1 Any notice to be served on any Party by the other shall be deemed to have been validly sent if sent by Registered Post Acknowledgement Due (RPAD) or speed post service of Department of Post, Government of India or by hand delivery duly acknowledged at the address mentioned in the beginning or at such other changed address as the Party may inform and the date of receipt of such notice shall be the date of receipt by the other Party or 7 days from the date of dispatch of the notice by RPAD, whichever is earlier.

**20. RESTRICTION ON TRANSFER**

20.1 The either Party shall not remove, sell, assign, mortgage, transfer/sublet and encumber all or any part of the network which belongs to the other Party. If the Party indulges in any of the above-mentioned acts, the said acts shall be illegal and void ab-initio and the Party shall also be liable for any action under the applicable law.

**21. CONFIDENTIALITY**

21.1 The Parties shall keep in strict confidence, any information received by one from the other while participating in the affairs/business of each other and shall not disclose the same to any person not being a party to this Agreement.

21.2 The Parties shall also bind their employees, officers, advisors, associates, contractors, agents, authorized persons and other similar persons to whom the above mentioned information may be disclosed, to the obligations of confidentiality.

21.3 The Parties hereby agrees that the confidential information can be disclosed to the statutory authority on demand by such authorities.



**22. MODIFICATIONS**

22.1 The Agreement cannot be modified, varied or terminated except in writing. Any variation of the Agreement, including Addendum Agreements, Annexures, Schedules or any other document, called by whatever name, but executed in relation to this Agreement, shall be mutually agreed to in writing and executed by or on behalf of the Parties.

**23. BINDING EFFECT**

23.1 This Agreement modifies all prior understanding of the Parties as to the subject matter thereof and shall not be amended except in writing by both the Parties. Any other understanding between the Parties (if any) with regard to any other matter or any accrued rights and obligation of the Parties not covered under this agreement, if any, shall continue to be in full force and effect.

**IN WITNESS WHEREOF** the Parties have set and subscribed their respective hands to this Agreement on the date and year appearing hereinabove.

Signed on behalf of the MSO

( \_\_\_\_\_ )

In the presence of

1. ....

2. ....

Signed on behalf of the LCO

( \_\_\_\_\_ )

In the presence of

1. ....

2. ....

*Note : The self attested copies of power of attorney/authorization letter, whereby the signatories of this agreement have been authorised to sign and execute this agreement by the Parties, shall be attached with this agreement.*

**Schedule**

**DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS****A. DEFINITIONS**

In the Agreement unless the context requires otherwise, the following words and expressions shall have the meanings set out herein below:

- (a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (b) "addressable system" shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (c) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under subsection (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (d) "basic service tier" means a bouquet of free to air channels as referred to in the Tariff Order;
- (e) "bouquet" or "bouquet of channels" means an assortment of distinct channels offered together as a group or as a bundle and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (f) "broadcaster" means a person or a group of persons, or body corporate, or any organization or body who, after having obtained, in its name, downlinking permission for its channels, from the Central Government, is providing programming services;
- (g) "cable service" or "cable TV service" means the transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels through cables;
- (h) "cable television network" or "cable TV network" means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;
- (i) "customer care centre" means a department or a section or a facility established under QoS regulations;
- (j) "CTN Act" means the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995);

- (k) “encryption or encrypted” in respect of a signal of cable television network, means the changing of such signal in a systematic way so that the signal would be unintelligible without use of an addressable system and the expression “unencrypted” shall be construed accordingly;
- (l) “free-to-air channel” shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order;
- (m) “hardware” means a multi-system operator approved set top box to enable the decryption of signals of Channels transmitted in encrypted form, the remote and other associated components and accessories;
- (n) “head-end” means a facility that contains satellite receivers, modulator, compression equipment, multiplexes, and conditional access facilities, other transmission equipments and has antennas which receive signals from Satellite and/or from local studio for retransmission to subscribers directly or through linked LCOs;
- (o) “Interconnection Regulation” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (p) “Manual of Practice (MoP)” means the Manual of Practice as referred to in the QoS Regulation;
- (q) “pay channel” shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order;
- (r) “piracy” means unauthorized reception, retransmission or redistribution of Cable TV Signal by any person by any means and modes including but not limited to any alteration, tampering of the seal or any component or accessory thereof or misuse, replacement, removal and/or shifting of Hardware or any use, either before or after the set top box, any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit or unauthorized devices or any activity, which has the effect of, or which may result into, infringement and violation of trade mark and copyright of the MSO or the LCO as the case may be;
- (s) “programme” means any television broadcast and includes-
  - (i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials,
  - (ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation,and the expression “programming service” shall be construed accordingly;
- (t) “QoS Regulation” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (u) “set top box” means a device, which is connected to or is part of a television receiver and which enables a subscriber to view subscribed channels;
- (v) “smart card” means the card duly approved by the multi system operator as part of the Hardware, which enables the subscriber to gain access to the Cable TV signals of Channels.
- (w) “subscriber” for the purpose of these regulations, means a person who receives broadcasting services, from a distributor of television channels, at a place indicated by such person without further transmitting it to any other person and who does not cause the signals of television channels to be heard or seen by any person for a specific sum of money to be paid by such person, and each set top box located at such place, for receiving the subscribed broadcasting services, shall constitute one subscriber;
- (x) “subscriber management system” means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber’s record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;
- (y) “Tariff Order” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017;
- (z) “trunk line” means the coaxial/optic fibre cable network and other allied equipment such as receiver nodes, amplifiers, splitters etc. owned and installed by the multi-system operator or its associate companies for the purpose of transmitting Cable TV Signal to various LCOs till the receiving end of various LCOs, including the LCO, to enable them to re-transmit the Cable TV Signal to respective subscribers;

All other words and expressions used in this interconnection agreement but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made there under or the CTN Act and the rules and regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

**B. INTERPRETATION**

In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) Any reference to the singular in the Agreement shall include a reference to the plural and vice versa and words importing one gender only shall include all other genders unless the context otherwise requires;
- (b) The word “person” shall include individuals, corporations, partnerships, association of persons and any other entities;
- (c) Any references to article, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules are references to Articles, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules to the Agreement unless the context otherwise expressly provides;
- (d) References to a “month” are to a calendar month;
- (e) Headings and titles are for ease of reference only and shall not affect the interpretation of this agreement and in no way be read to give a construction not harmonious with the interpretation of various clauses of this agreement done otherwise independent of the title.
- (f) Any reference to law, regulation, statutory provision, order, guideline, policy, etc, includes references to such law or regulation or provision, order, guideline, policy, etc., as modified, codified, amended or re-enacted from time to time.

**Schedule VI**

*(Refer second proviso to sub-regulation (3) of regulation 12)*

**STANDRAD INTERCONNECTION AGREEMENT BETWEEN MULTI SYSTEM OPERATOR AND LOCAL CABLE OPERATOR FOR PROVISIONING OF CABLE TV SERVICES THROUGH DIGITAL ADDRESSABLE SYSTEMS (DAS).**

*[Each page of the Agreement shall be signed by the authorised signatory of the Multi System Operator and the Local Cable Operator]*

This Technical and Commercial Interconnection Agreement along with its Schedules and Annexures is executed on this \_\_\_\_ day of \_\_\_\_ 201\_ by and between:

\_\_\_\_\_, having its office at \_\_\_\_\_, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the “**MSO**” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors of the **ONE PART**.

MSO’s Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals *(strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)*

**AND**

\_\_\_\_\_, having its office at \_\_\_\_\_, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the “**LCO**” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors, of the **OTHER PART**

LCO’s Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals *(strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)*

The **MSO** and the **LCO** are hereinafter individually referred to as ‘Party’ and collectively referred to as “**Parties**”.

**WHEREAS,**

A. The MSO is a cable operator, who has been granted registration No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ under the Cable Television Networks Rules, 1994, by the Ministry of Information and Broadcasting, for providing cable TV services through digital addressable systems in the areas of \_\_\_\_\_ notified by the Central Government under Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

B. The LCO is a cable operator, who has been granted registration under the Cable Television Networks Rules, 1994, having postal registration No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, in the head post office \_\_\_\_\_, [Name of the head post office] for providing Cable TV Services in \_\_\_\_\_ [Mention the area].

C. The LCO has requested the MSO vide its letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ for making available signals of TV channels and the MSO has agreed vide its letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ to provide signals of TV channels to such LCO.

D. TERRITORY: Territory, in the context of this Agreement is \_\_\_\_\_ [mention the name of area(s)/ city(ies)/ district(s)/ state(s) for which this agreement is being signed.]

E. The Parties have mutually agreed to execute this Agreement - on principal to principal and non-exclusive basis - between them to govern the roles, responsibilities, rights, obligations, technical and commercial arrangement in regard to the distribution of TV channels in the Territory.

F. The Parties also mutually agree that each and every transaction including transaction of any properties/ assets between the Parties shall be carried out in writing or in any other verifiable means.

**NOW, THEREFORE**, in consideration of the foregoing and the mutual covenants contained herein, the Parties agree as follows: -

## 1. DEFINITIONS

The words and expressions used in this Agreement shall have meanings as assigned to them in the Schedule to this Agreement. All other words and expressions used in this Agreement, but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made there under or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

## 2. TERM OF THE AGREEMENT

2.1 The Agreement shall commence on \_\_\_\_\_ [dd/mm/yyyy] and remain in force till \_\_\_\_\_ [dd/mm/yyyy] or the date of expiry of registration of the MSO or the LCO, as the case may be, whichever is earlier, unless terminated by either Party as per the terms and conditions of this Agreement.

2.2 The duration of the Agreement may be extended on terms and conditions to be mutually agreed between the Parties and recorded in writing provided that the extended term does not go beyond the last date of validity of registration of the MSO or the LCO, whichever is earlier.

## 3. TERMINATION OF THE AGREEMENT

3.1 Either Party has a right to terminate the Agreement by serving an advance notice of 21 days in writing to the other Party in the event of:-

- (i) material breach of the Agreement by the other Party which has not been cured within 15 days of being required in writing to do so; or
- (ii) the bankruptcy, insolvency or appointment of receiver over the assets of other Party; or
- (iii) the other Party indulging in, or allowing or inducing any person to indulge in piracy or carrying programming service provided on the channel which is in violation of the Programme and Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

3.2 The LCO has a right to terminate the Agreement in the event of the MSO discontinuing the business of distribution of TV channels in the Territory.

3.3 The MSO has a right to terminate the agreement in the event of the LCO discontinuing its cable TV business in the Territory.

3.4 If the MSO decides to discontinue the business of distribution of TV channels in the Territory for any reason, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the LCO at least 90 days prior to such discontinuation.

3.5 If the LCO decides to discontinue its business of providing signals of TV channels to the subscriber in the territory, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the MSO at least 90 days prior to such discontinuation.

## 4. EFFECT OF TERMINATION AND EXPIRY

4.1 In the event of termination or expiry of the term of the Agreement, as the case may be, at the instance of either Party, each Party shall pay all amounts due and payable up to the date of termination or expiry to the other Party.

4.2 The LCO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the MSO all properties and assets belonging to the MSO, which are in the custody of the LCO. The LCO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the MSO, in custody of the LCO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the MSO and in the event of inability of LCO to repair such properties/assets, the LCO shall pay to the MSO the depreciated value of such properties/ assets.

4.3 The MSO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the LCO all properties and assets belonging to the LCO, which

are in the custody of the MSO. The MSO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the LCO, in custody of the MSO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the LCO and in the event of inability of MSO to repair such properties/assets, the MSO shall pay to the LCO the depreciated value of such properties/ assets.

Explanation:- The clause 4.2 and 4.3 above shall not have any application in respect of Hardware or any other equipment belonging to the MSO or the LCO, as the case may be, which are installed at the premises of the subscribers.

4.4 If the LCO or the MSO, as the case may be, fails to hand over the assets or make good losses or damages caused to such properties and assets within the above stipulated period, the defaulting Party shall be liable to make payment for the depreciated value of the same together with simple interest calculated at the rate 2% over and above the base rate of interest of the State Bank of India.

## 5. PROVISIONING OF SERVICES

5.1 The MSO shall make available signals of TV channels to the LCO, on non-exclusive basis, in order to distribute the same to the subscribers in the Territory, in terms of this agreement and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

5.2 The LCO shall carry signals of TV channels received from the MSO, on non-exclusive basis, for distribution to the subscribers in the Territory.

5.3 The Parties shall compulsorily transmit, re-transmit or otherwise carry any channel or programme only in encrypted mode through a digital addressable system strictly in terms of and in accordance with the applicable laws and regulations.

5.4 The roles and responsibilities of the Parties to the Agreement for provisioning of services are contained in clause 10 of this Agreement.

5.5 In consideration of the roles and responsibilities mentioned in clause 10 of the Agreement, the revenue settlement between the LCO and the MSO have been mentioned in the clause 12 of the Agreement.

## 6. RIGHTS OF THE MSO

6.1 The MSO shall continue to have a right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it may expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service provided to the subscribers.

6.2 The MSO shall sign the interconnection agreement with broadcasters for distribution of signals of TV Channels as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

6.3 The MSO shall have the right to finalise the maximum retail price of each channel, as payable by the subscriber in compliance with the provisions of applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.4 The MSO shall have the right to package the channels/ services offered on the network, as per its business plan and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.5 The MSO shall have the right to finalise the rate of Basic Service Tier (BST) in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority from time to time.

6.6 The MSO shall have the right to finalise the rates of bouquets of channels, if offered by the MSO, in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority.

6.7 The MSO shall have the right to get all requisite information from the LCO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

## 7. RIGHTS OF THE LCO

7.1 The LCO shall continue to have its right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it can expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service offered to the subscriber on its network.

7.2 The LCO shall have right to get all the requisite information from the MSO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

## 8. OBLIGATIONS OF THE MSO

8.1 MSO shall set up and operationalise the Head-end, Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) for ensuring efficient and error-free services to the subscribers by recording and providing individualized preferences for channels, billing cycles or refunds.

8.2 The MSO shall make available to the LCO, the necessary and sufficient information relating to the details of channels, bouquets of channels, and services offered to the subscribers including their prices.

8.3 The MSO shall provide web based grievance redressal mechanism for addressing the complaints of LCOs in relation to the provision of services, roles and responsibilities, revenue settlements, quality of services etc.

8.4 The MSO shall not issue pre-activated STBs and the STBs shall be activated only after the details of the Customer Application Form (CAF) have been entered into the SMS.

8.5 The MSO shall generate bills for subscribers on regular basis, for charges due and payable for each month or as per the billing cycle applicable for that subscriber, within 3 days from the end of the billing cycle.

8.6 The MSO shall provide access to the relevant part of the SMS under its control to the LCO for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

8.7 The MSO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the LCO or person associated with such transmission.

8.8 The MSO shall comply with all the applicable statutes or laws for the time being in force, or any rules, codes, regulations, notifications, circulars, guidelines, orders, directions etc. issued, published or circulated under any law for the time being in force.

8.9 The MSO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the LCO in respect of cable TV signals under this Agreement or any property of the LCO may be infringed or prejudiced.

8.10 The MSO shall be responsible for encryption of the complete signal, up to the STB installed at the premises of the subscriber.

8.11 The MSO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' advance notice to the LCO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

8.12. The MSO shall make available consumer friendly electronic payment options in the subscriber management system for the electronic payment of bills by the subscribers, prepaid system for subscribers and facility for acknowledgments/receipts to the subscribers for the payments made by them.

8.13 The MSO shall provide to the LCO at least 2% of the total STBs active in the network of the LCO with an upper cap of 30 STBs as maintenance spare, which are not pre-activated, to ensure speedy restoration of services affected due to any fault in STB. This quantity of maintenance spare STBs shall be maintained during the term of the agreement.

8.14 The MSO shall intimate to the LCO, at least 15 days in advance, in respect of any proposed changes in the package composition or the retail tariff being offered to the subscriber.

8.15 The MSO shall have no right, without the prior written intimation to the LCO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

## **9. OBLIGATIONS OF THE LCO**

9.1 The LCO shall handover a copy of CAF received from subscribers within 15 days to the MSO.

9.2 The LCO shall be responsible for entering the details of the bill amount paid by the individual subscriber to the LCO for the Cable TV services in the SMS.

9.3 The LCO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the MSO, or any other person associated with such retransmission.

9.4 The LCO shall have no right, without the prior written intimation to the MSO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

9.5 The LCO shall not replace the STBs of the MSO with the STBs of any other MSO without receiving the requests from the subscribers through application forms for returning the STB of the existing connections and for providing new connections through Customer Application Form. The new Set Top Box shall be activated only after entry of the details, as provided in new Customer Application Form, into the Subscriber Management System of the new MSO.

9.6 The LCO shall –

(i) not transmit or retransmit, interpolate or mix any signals which are not transmitted or generated by the MSO without the prior written consent of the MSO;

(ii) not insert any commercial or advertisement or information on any signal transmitted by the MSO. Any such tampering of signals or interpolating of signals shall be deemed to be a violation of this Agreement and shall

constitute sufficient cause for termination of this Agreement by the MSO by giving such notice as prescribed under the law or under this agreement;

(iii) not interfere in any way with the signals provided by the MSO and also not use any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box or Smart card and any other like equipments;

(iv) not alter or tamper the Hardware including the seal (seal to prevent opening of set top box), misuse, replace, remove and shift the Smart card or STB without the written consent of MSO from their respective original addresses;

(v) not use, either before or after the installation of STB, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es), smart card(s) other than the STB(s), Smart cards and any other equipments supplied/ approved by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

(vi) intimate the MSO promptly about any alteration, tampering with the Hardware including the seal, misuse, replacement, removal and shifting of Smart cards and STBs, without the written consent of MSO, from their respective original addresses and also about the use, either before or after the STBs, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es) and smart card(s) other than the STB(s), Smart card(s) and any other items of Hardware supplied by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

9.7 The LCO shall not provide connection to any entity for further distribution of the Cable TV signals.

9.8 The LCO shall not record and then retransmit Cable TV signals or otherwise to block or add or substitute or otherwise tamper with the signal being transmitted by the MSO or with the trunk line nor shall allow any other person to do so.

9.9 The LCO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the MSO in respect of the Cable TV signals under this Agreement or any property of the MSO may be infringed or prejudiced.

9.10 The LCO shall permit access to the systems under its control to the MSO, on non-exclusive basis, for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

9.11 The LCO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' notice to the MSO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

#### 10. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE MSO AND THE LCO:

Sl. No.	Role	Responsibility of the MSO or the LCO	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Devising of Consumer Application Form, either in electronic format or print format or both, for initial subscription to broadcasting services containing the information as provided in the Schedule I of the QoS regulations.	MSO	
2	a. Provide information to consumers about the details of services at the time of every new connection as per the QoS regulations. b. Providing information to the subscriber about the details of offered STB schemes and the warranty/ repairing policy applicable thereof.	LCO	The MSO shall communicate to the LCO the details of services and STB Schemes along with repairing/ warrantee policy for onward communication to subscribers.
3	Provisioning of broadcasting services to the consumer upon obtaining duly filled Consumer Application Form and providing a copy of the same to the consumer as per the QoS regulations.	LCO	The LCO shall update the information in the subscriber management systems in each case within 24 hours from receipt of the application
4	Assigning a unique identification number (UIN) to every subscriber and communicating	LCO	The UIN shall be generated from the SMS. The relevant access of the SMS

	the same to the consumer as per the provisions of the QoS regulations.		should be provided by the MSO to the LCO.
<b>5</b>	Activation of broadcasting services to the subscribers.	<b>LCO</b>	(1) Activation shall be done only after only after the details of Consumer Application Form have been entered into the SMS.  (2) The MSO should provide relevant access to SMS for activation of broadcasting services.
<b>6</b>	Activation of requested channel(s) or bouquet(s) available on the platform, upon receiving a verifiable request from a subscriber as per the provisions of the QoS regulations.	<b>LCO</b>	Activation shall be done only through SMS.
<b>7</b>	Deactivation of requested channel(s) and bouquet(s) from the subscription package of subscriber upon receiving a verifiable request from the subscriber, subscriber as per the provisions of the QoS regulations.	<b>LCO</b>	Deactivation shall be done only through SMS.
<b>8</b>	Temporary suspension of broadcasting services of a subscriber upon receiving a request from the subscriber as per the provisions of the QoS regulations.	<b>LCO</b>	Temporary suspension shall be done only through SMS.
<b>9</b>	Restoration of services of a subscriber, upon request from the subscriber as per the provisions of the QoS regulations.	<b>LCO</b>	Restoration of services shall be done only through SMS.
<b>10</b>	Relocation of connection of a subscriber from one location to another location, upon the request for the same as per the provisions of QoS regulations.	<b>LCO</b>	The LCO shall update the information in the subscriber management system immediately
<b>11</b>	Providing notice to the subscribers regarding interruption of signals for preventive maintenance as specified in QoS Regulations.	<b>MSO</b>	If preventive maintenance is to be carried out by the LCO then he shall inform the MSO to enable him to give notice to the subscribers
<b>12</b>	Disconnection of broadcasting services to a subscriber upon request from the subscriber and refunding of deposits subject to fulfilment of the terms and conditions provided in the QoS regulations.	<b>MSO</b>	
<b>13</b>	Offering broadcasting services to the subscribers either on pre-paid basis or post-paid basis or both as provided in the QoS regulations.	<b>MSO</b>	
<b>14</b>	Changing payment mechanism from pre-paid to post-paid or vice-versa, as the case may be, on the request made by the subscriber.	<b>MSO</b>	
<b>15</b>	Generation of post-paid bills for subscribers as per the QoS norms.	<b>MSO</b>	
<b>16</b>	Delivery of post-paid bills to subscribers as per the QoS regulations.	<b>MSO</b>	
<b>17</b>	Issuance and delivery of receipts to post-paid subscribers for manual payments made by them and entering the details of the receipts in the subscriber management system as per the QoS regulations.	<b>MSO</b>	



18	Acknowledging pre-paid payments to the subscriber and updating the subscriber management system accordingly.	MSO	
19	Providing set top boxes to the subscribers conforming to the standards prescribed in the QoS regulations.	MSO	
20	Offering different schemes for the STB as per the QoS regulations.	MSO	
21	Offering annual maintenance scheme for the Customer Premises Equipment provided under outright purchase scheme after the expiry of guarantee/warranty period as per the QoS regulations	MSO	
22	Repairing of a malfunctioning set top box as per the QoS regulations.	MSO	
23	Publicizing toll free consumer care number and address of the web based complaint management system to the subscribers through customer care channel and website, as provided in the QoS Regulations.	MSO	
24	Providing copies of Manual of Practice (MoP) to subscribers as specified in QoS regulations.	LCO	The MSO shall finalize the contents of MOP. Copies of such MoP shall be shared with the LCO.
25	Payment of taxes to the Government.	MSO and/ or LCO	The specific details of tax payment responsibilities need to be filled in the adjoining cells at the time of signing of the agreement as per the rules and regulations of the respective Tax authorities.

## 11. BILLING

11.1 The billing for subscribers shall be in the name of the MSO. However, each party shall ensure that the applicable laws, rules and regulations relating to taxes are complied with.

11.2 The MSO shall receive the payment of the subscription fee paid by the subscribers. The revenue share as per clause 12.1 of this Agreement shall be paid by the MSO to the LCO on receipt of the invoice from the LCO.

## 12. REVENUE SETTLEMENT BETWEEN THE LCO AND THE MSO AND RELATED RIGHTS AND OBLIGATIONS

12.1 The network capacity amount and distribution fee amount shall be shared in the ratio of 55:45 between multi system operator and local cable operator respectively.

**Note:-**Network capacity fee amount and the distribution fee shall have the same meaning as defined in the Interconnection Regulations and Tariff Order.

12.2 The MSO shall share the complete information relating to the subscribers billing and receipt of the payments with the LCO. The LCO shall issue monthly invoice to the MSO towards dues payable by the MSO for revenue settlement and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment which shall not be less than seven days. Any demand of arrears shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain. The amounts raised in the invoice shall be payable on or before the due dates as mentioned therein.

12.3 The Party shall update the details of the subscription amount realised from the subscriber, in the SMS within 7 days from the due date.

### 13. DEFAULTS

13.1 Without prejudice to such rights and remedies that the Parties may have in law or under the provisions of this Agreement, in the event of any delay or failure by the MSO or the LCO, as the case may be, to make payments of dues on or before the respective due dates, the LCO or the MSO, as the case may be, shall have the right:-

- (i) to disconnect the services subject to the compliance of the applicable rules, regulations, directions or orders of the Authority;
- (ii) to terminate this Agreement, subject to compliance of the applicable laws in force;
- (iii) to charge a simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India from the date such amounts became due until those are fully and finally paid;

13.2 In cases where any of the Parties has failed to make payment on or before due date for three consecutive months in the past, the other Party shall have right to demand the interest free security deposit which shall not exceed average of immediately preceding 6 months billing amounts and the same shall be maintained for the remaining term of the agreement.

13.3 Upon disconnection of the service as mentioned in clause 13.1 above, whether accompanied by termination of this Agreement or not, the defaulting Party shall be liable to deposit forthwith all sums payable by it. In the case of termination, accounts shall be settled within thirty days and for delayed payments, either Party shall be liable to pay simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India.

### 14. UNDERTAKINGS

14.1 Each Party shall recognize the exclusive ownership of the property owned and installed by the other Party and shall not have or claim any right, title or interest or lien of whatsoever nature.

14.2 Nothing contained herein shall constitute either Party as the agent or partner or the representative of the other for any purpose and neither Party shall have the right or authority to assume, create or incur any liability or obligation of any kind, express or implied, in the name of or on behalf of the other Party and the relationship between the MSO and the LCO shall remain on "Principal to Principal" basis.

14.3 It is expressly understood by the Parties that "\_\_\_\_\_ " logo(s) is a Registered Trade Mark of the MSO, and the LCO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the MSO. Consent of the MSO is hereby given to the LCO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the MSO.

14.4 It is expressly understood by the Parties that "\_\_\_\_\_ " logo(s) is a Registered Trade Mark of the LCO, and the MSO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the LCO. Consent of the LCO is hereby given to the MSO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the LCO.

14.5 It is clearly understood and accepted by each Party that it shall have no right to use any intellectual property of the other on its Cable TV service or otherwise on or after the withdrawal by the other Party of its consent for such uses.

14.6 In case the LCO or the MSO, as the case may be, decides to transfer its interest in respect of its business of providing Cable TV Service to any other party / person (third party), in whole or in part, the LCO or the MSO, as the case may be, shall give prior notice to the MSO or the LCO. One Party shall not have any objection to such transfer if the other Party has complied with its obligations under this contract and has paid all its dues.

Provided, however, that such third party shall sign and execute a deed of adherence to the terms and conditions of this Agreement and other undertaking/ bonds to the satisfaction of the MSO or the LCO, as the case may be, in order to give effect to the provisions of this Agreement.

14.7 The LCO shall maintain and continue to maintain its Postal Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration certificate issued by the Postal Authority.

14.8 The MSO shall maintain and continue to maintain its Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration.

14.9 Both the Parties shall comply with the Programme Codes and Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

14.10 Both the Parties shall comply with the laws for the time being in force in India, as applicable to them.

**15. PREVENTION OF PIRACY**

15.1 The Parties shall not indulge or allow any person to indulge in Piracy or in reverse engineering of any technology used in the Hardware or any component thereof nor shall they use the Hardware to be connected to any equipment for setting up a mini head-end for retransmission of the signals generated from the same.

15.2 Signal to any subscriber shall be disconnected by the MSO or the LCO, as the case may be, after giving due notice as required under applicable regulations, if found to be indulged in or abetting any Piracy.

**16. DISCLAIMER AND INDEMNITY**

16.1 In no event, the MSO shall be liable to the LCO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprivation of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the MSO.

16.2 In no event, the LCO shall be liable to the MSO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprivation of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the LCO.

16.3 LCO shall indemnify the MSO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the LCO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to LCO's breach.

16.4 MSO shall indemnify the LCO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the MSO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to MSO's breach.

**17. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION**

17.1 As mandated by the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Parties shall not institute any suit or seek injunction or interim orders in any court or judicial tribunal/ authority in India with respect to any claims, dispute or differences between the Parties arising out of this Agreement save and except before the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, New Delhi ("TDSAT"). The Parties agree that all disputes between the Parties shall be resolved solely through proceedings instituted before the TDSAT.

**18. FORCE MAJEURE**

18.1 Failure on the part of the MSO or the LCO to perform any of its obligations, shall not entitle either Party to raise any claim against the other or constitute a breach of this Agreement to the extent that such failure arises from an event of Force Majeure. If through Force Majeure the fulfilment by either Party of any obligation set forth in this Agreement is delayed, the period of such delay shall not be taken into account in computing periods prescribed by this Agreement. Force Majeure will include act of god, earthquake, tides, storm, flood, lightening, explosion, fire, sabotage, quarantine, epidemic, arson, civil disturbance, terrorist attack, war like situation, or enactment of any law or rules and regulation made by the Authorities or revocation of registration of the Parties any circumstances beyond the reasonable control of the Parties herein that directly or indirectly hinders or prevents either of the Parties from commencing or proceeding with the consummation of the transactions contemplated hereby. The Party affected by such Force Majeure event shall promptly notify the other Party of the occurrence of such event. It is agreed between the Parties that lack of funds shall not in any event constitute or be considered an event of Force Majeure. If the conditions of Force Majeure to continue for a period exceeding one month, the Parties shall meet to decide upon the future performance of the Agreement. If the Parties are unable to agree upon a plan for future performance, then the Agreement shall be terminated upon notice of either Party to the other, on expiry of one month from the date of such notice.

18.2 Any accrued payment obligation of a Party prior to the commencement of Force Majeure shall survive the termination of this Agreement pursuant to such Force Majeure.

**19. NOTICES**

19.1 Any notice to be served on any Party by the other shall be deemed to have been validly sent if sent by Registered Post Acknowledgement Due (RPAD) or speed post service of Department of Post, Government of India or by hand delivery duly acknowledged at the address mentioned in the beginning or at such other changed address as the Party may inform and the date of receipt of such notice shall be the date of receipt by the other Party or 7 days from the date of dispatch of the notice by RPAD, whichever is earlier.

**20. RESTRICTION ON TRANSFER**

20.1 The either Party shall not remove, sell, assign, mortgage, transfer/sublet and encumber all or any part of the network which belongs to the other Party. If the Party indulges in any of the above-mentioned acts, the said acts shall be illegal and void ab-initio and the Party shall also be liable for any action under the applicable law.

**21. CONFIDENTIALITY**

21.1 The Parties shall keep in strict confidence, any information received by one from the other while participating in the affairs/business of each other and shall not disclose the same to any person not being a party to this Agreement.

21.2 The Parties shall also bind their employees, officers, advisors, associates, contractors, agents, authorized persons and other similar persons to whom the above mentioned information may be disclosed, to the obligations of confidentiality.

21.3 The Parties hereby agrees that the confidential information can be disclosed to the statutory authority on demand by such authorities.

**22. MODIFICATIONS**

22.1 The Agreement cannot be modified, varied or terminated except in writing. Any variation of the Agreement, including Addendum Agreements, Annexures, Schedules or any other document, called by whatever name, but executed in relation to this Agreement, shall be mutually agreed to in writing and executed by or on behalf of the Parties.

**23. BINDING EFFECT**

23.1 This Agreement modifies all prior understanding of the Parties as to the subject matter thereof and shall not be amended except in writing by both the Parties. Any other understanding between the Parties (if any) with regard to any other matter or any accrued rights and obligation of the Parties not covered under this agreement, if any, shall continue to be in full force and effect.

**IN WITNESS WHEREOF** the Parties have set and subscribed their respective hands to this Agreement on the date and year appearing hereinabove.

Signed on behalf of the MSO

( \_\_\_\_\_ )

In the presence of

1. ....

2. ....

Signed on behalf of the LCO

( \_\_\_\_\_ )

In the presence of

1. ....

2. ....

*Note: The self attested copies of power of attorney/authorization letter, whereby the signatories of this agreement have been authorised to sign and execute this agreement by the Parties, shall be attached with this agreement.*

**Schedule**

**DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS****A. DEFINITIONS**

In the Agreement unless the context requires otherwise, the following words and expressions shall have the meanings set out herein below:

- (a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (b) “addressable system” shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (c) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under subsection (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (d) “basic service tier” means a bouquet of free to air channels as referred to in the Tariff Order;
- (e) “bouquet” or “bouquet of channels” means an assortment of distinct channels offered together as a group or as a bundle and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (f) “broadcaster” means a person or a group of persons, or body corporate, or any organization or body who, after having obtained, in its name, downlinking permission for its channels, from the Central Government, is providing programming services;

- (g) “cable service” or “cable TV service” means the transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels through cables;
- (h) “cable television network” or “cable TV network” means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;
- (i) “customer care centre” means a department or a section or a facility established under QoS regulations;
- (j) “CTN Act” means the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995);
- (k) “encryption or encrypted” in respect of a signal of cable television network, means the changing of such signal in a systematic way so that the signal would be unintelligible without use of an addressable system and the expression “unencrypted” shall be construed accordingly;
- (l) “free-to-air channel” shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order;
- (m) “hardware” means a multi-system operator approved set top box to enable the decryption of signals of Channels transmitted in encrypted form, the remote and other associated components and accessories;
- (n) “head-end” means a facility that contains satellite receivers, modulator, compression equipment, multiplexes, and conditional access facilities, other transmission equipments and has antennas which receive signals from Satellite and/or from local studio for retransmission to subscribers directly or through linked LCOs;
- (o) “Interconnection Regulation” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (p) “Manual of Practice (MoP)” means the Manual of Practice as referred to in the QoS Regulation;
- (q) “pay channel” shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order;
- (r) “piracy” means unauthorized reception, retransmission or redistribution of Cable TV Signal by any person by any means and modes including but not limited to any alteration, tampering of the seal or any component or accessory thereof or misuse, replacement, removal and/or shifting of Hardware or any use, either before or after the set top box, any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit or unauthorized devices or any activity, which has the effect of, or which may result into, infringement and violation of trade mark and copyright of the MSO or the LCO as the case may be;
- (s) “programme” means any television broadcast and includes-
  - (iii) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials,
  - (iv) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation,
 and the expression “programming service” shall be construed accordingly;
- (t) “QoS Regulation” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017;
- (u) “set top box” means a device, which is connected to or is part of a television receiver and which enables a subscriber to view subscribed channels;
- (v) “smart card” means the card duly approved by the multi system operator as part of the Hardware, which enables the subscriber to gain access to the Cable TV signals of Channels.
- (w) “subscriber” for the purpose of these regulations, means a person who receives broadcasting services, from a distributor of television channels, at a place indicated by such person without further transmitting it to any other person and who does not cause the signals of television channels to be heard or seen by any person for a specific sum of money to be paid by such person, and each set top box located at such place, for receiving the subscribed broadcasting services, shall constitute one subscriber;
- (x) “subscriber management system” means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber’s record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;
- (y) “Tariff Order” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017;

- (z) “trunk line” means the coaxial/optic fibre cable network and other allied equipment such as receiver nodes, amplifiers, splitters etc. owned and installed by the multi-system operator or its associate companies for the purpose of transmitting Cable TV Signal to various LCOs till the receiving end of various LCOs, including the LCO, to enable them to re-transmit the Cable TV Signal to respective subscribers;

All other words and expressions used in this interconnection agreement but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made there under or the CTN Act and the rules and regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

## B. INTERPRETATION

In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) Any reference to the singular in the Agreement shall include a reference to the plural and vice versa and words importing one gender only shall include all other genders unless the context otherwise requires;
- (b) The word “person” shall include individuals, corporations, partnerships, association of persons and any other entities;
- (c) Any references to article, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules are references to Articles, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules to the Agreement unless the context otherwise expressly provides;
- (d) References to a “month” are to a calendar month;
- (e) Headings and titles are for ease of reference only and shall not affect the interpretation of this agreement and in no way be read to give a construction not harmonious with the interpretation of various clauses of this agreement done otherwise independent of the title.
- (f) Any reference to law, regulation, statutory provision, order, guideline, policy, etc, includes references to such law or regulation or provision, order, guideline, policy, etc., as modified, codified, amended or re-enacted from time to time.

## Schedule VII

*(Refer sub-regulations (1) and (3) of the regulation 14)*

### Subscription Reports

**A: Monthly subscription reports of channels or bouquets to be provided by a distributor of television channels to a broadcaster.**

**Reported Month:**\_\_\_\_\_

**Year:**\_\_\_\_\_

A.1 Monthly subscription of a channel or bouquet shall be arrived at, by averaging the number of subscribers subscribing that channel or bouquet, as the case may be, recorded four times in a month, as provided in table-1 and table-2 respectively. The number of subscribers shall be recorded at any point of time between 19:00 HRS to 23:00 HRS of the day.

Table 1- Monthly subscription for a-la-carte channels

Sl.	Name of the channel	Number of subscribers of the channel on 7 <sup>th</sup> day of the month	Number of subscribers of the channel on 14 <sup>th</sup> day of the month	Number of subscribers of the channel on 21 <sup>st</sup> day of the month	Number of subscribers of the channel on 28 <sup>th</sup> day of the month	Monthly subscription of the channel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=[(3)+(4)+(5)+(6)]/4
1.						
2.						

**Table 2- Monthly subscription for bouquets of pay channels**

Sl.	Name of the bouquet of pay channels	Name of constituent channels of bouquet of the broadcaster	Number of subscribers of the bouquet on 7 <sup>th</sup> day of the month	Number of subscribers of the bouquet on 14 <sup>th</sup> day of the month	Number of subscribers of the bouquet on 21 <sup>st</sup> day of the month	Number of subscribers of the bouquet on 28 <sup>th</sup> day of the month	Monthly subscription of the bouquet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=[(4)+(5)+(6)+(7)]/4
1.							
2.							

**B: Subscription reports in cases where the transaction of carriage fee is involved.****Reported Month:** \_\_\_\_\_**Year:** \_\_\_\_\_**Target Market:** \_\_\_\_\_

B1: Monthly subscription for the channel and bouquet of the broadcaster carried by the distributor of television channels shall be calculated in the manner specified above in the table-1 and table -2 of this schedule, respectively.

B2: Average active subscriber base in the target market in the month shall be arrived at, by averaging the active subscriber base count recorded four times in a month, in the manner as provided in the table-3. The active subscribers base count of the network shall be captured from the subscriber management system at any point of time between 19:00 HRS to 23:00 HRS of the day.

**Table 3 –Average active subscriber base in a month in the target market**

Type of STB	active subscriber base count on 7 <sup>th</sup> day of the month	active subscriber base count on 14 <sup>th</sup> day of the month	active subscriber base count on 21 <sup>st</sup> day of the month	active subscriber base count on 28 <sup>th</sup> day of the month	Average active subscriber base in the month
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)=[(2)+(3)+(4)+(5)]/4
Standard Definition STB					
High Definition STB					

B3: For the purpose of calculation of carriage fee for standard definition channel, the average active subscriber base of standard definition STBs as well as high definition STBs deployed in target market shall be taken into account.

B4: For the purpose of calculation of carriage fee for high definition television channel, the average active subscriber base of high definition STBs deployed in target market shall be taken into account.

**Note:**

- Each set top box, located at a place indicated by the subscriber for receiving the subscribed broadcasting services from the distributor of television channels, shall constitute one subscriber.
- The reports shall be generated in non-editable PDF format, with read only permissions.

**Explanatory Memorandum to the Telecommunication (Broadcasting and cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (No 1 of 2017)**

**Background**

1. The TRAI Act entrusts Telecom Regulatory Authority of India, amongst others, with the functions to ensure technical compatibility and effective interconnection between different service providers, fix the terms and conditions of interconnectivity between the service providers, and regulate arrangement amongst service providers for sharing their revenue derived from providing telecommunication services. In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (k) of sub-section (1) of section (2) of the Act, in the year 2004, the Central Government notified the broadcasting services and cable services to be telecommunication services. The interconnection between broadcasting service providers is a techno-commercial arrangement by which service providers connect their equipments and networks to deliver broadcasting services to subscribers.
2. To discharge the above mentioned functions, the Authority, from time to time, notifies regulatory framework for interconnection between service providers for broadcasting services. Under the notified framework service providers finalize their commercial and technical terms to arrive at an agreement and share revenues as per the agreement.
3. The first interconnection regulations for broadcasting services, namely the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), were notified by the Authority on 10.12.2004 (hereinafter referred to as the Interconnection Regulations, 2004). These were initially notified to regulate interconnection arrangements between service providers for distribution of TV channels in analog mode, in vogue at that point of time. From time to time, need arose to clarify, as well as to expand the scope of the Interconnection Regulations, 2004 to include addressable systems such as Direct to Home (DTH), Head-end In the Sky (HITS), and Internet Protocol Television (IPTV). The basic features of the Interconnection Regulations, 2004, inter alia, encompass the provisions for providing signals of a TV channel on non-discriminatory terms to distributors of TV channels, publishing Reference Interconnection Offer (RIO) for interconnection to ensure level playing field, entering in to written interconnection agreement, disconnection of signals of TV channel, and ascertaining the subscriber base.
4. The evolution of technology paved the way for digitization and addressability of the cable services. For implementation of digitization with addressability in the cable TV sector, the Parliament amended the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 on 30th December, 2011. Subsequently, the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012 were notified by the Central Government on 28th April, 2012. The Authority notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012) on 30th April, 2012 (hereinafter referred as the Interconnection Regulations, 2012). These regulations were specifically applicable for cable services provided through Digital Addressable Cable Television Systems (DAS). The Interconnection Regulations, 2004, continued for non-addressable cable TV systems and also for other addressable systems such as DTH, HITS and IPTV. The basic features of the Interconnection Regulations, 2012 were similar to the basic features of the Interconnection Regulations, 2004, mentioned in Para 3 above.
5. As per the roadmap notified by the Central Government, after 31st March, 2017, the provisioning of cable services shall be permitted through Digital Addressable Systems only. Till now, digitization of the cable services has been completed in most of the urban areas. With the implementation of digitization and addressability in the cable TV sector, majority of subscribers receive broadcasting services through addressable systems.
6. Broadcasting services provided through addressable systems have numerous advantages over those provided through analog non-addressable systems. The digital addressable systems are efficient in provisioning of services and enable choice to the subscribers. The subscribers gets better signal quality, enhanced viewing experience, choice of more channels and can pay only for those channels/ services which they subscribes. For service providers, the addressable systems enable transparent business transactions based on verifiable parameters and improve transparency. It allows the collection of tax revenue, by the Government, commensurate to the actual market size.
7. The full benefits of digitisation can be accrued to various stakeholders in the value chain only when the business transactions are transparent and based on objective, measurable and computable parameters. The effective competition and level playing field in the market place is possible when the interconnection is based on transparent and non-discriminatory principles. TRAI is conscious of the fact that, while the interconnection regulatory framework should uphold necessary discipline in the sector to ensure transparent and non-discriminatory practices, it should also provide required freedom to service providers in the value chain to innovate. It should be able to provide a level playing field to all the service providers, effective choice to consumers, and orderly growth of the sector.
8. The regulatory framework ought to evolve with the time to keep pace with the developments in the sector. Accordingly, the Authority decided to review, in a complete and holistic manner, the regulatory framework for broadcasting services delivered through addressable systems which include Tariff orders, and Interconnection and Quality of Service (QoS) Regulations.



9. In line with the established practice, for reviewing the regulatory framework for broadcasting services, the Authority issued series of consultation papers on Tariff, Interconnection and QoS issues. The consultation paper on “Tariff Issues related to TV services” was issued on 29th January, 2016, “Interconnection framework for Broadcasting TV Services distributed through Addressable Systems” was issued on 4th May, 2016, and “Issues related to Quality of Services in Digital Addressable Systems and Consumer Protection” was issued on 18th May, 2016.
10. For consultation on “Interconnection framework for Broadcasting TV Services distributed through Addressable Systems” (the CP), initially one month time was given to the stakeholders to submit their comments. On requests of the stakeholders, the last date for submission of comments was extended by a week time i.e. up to 10th June, 2016. The last date for submitting counter comments was 17th June, 2016. In response to this consultation paper, a total of 28 comments and 1 counter comment were received from stakeholders. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) program to discuss issues relating to interconnection with stakeholders was held on 13th July, 2016 at Delhi, which was attended by a large number of stakeholders.
11. After detailed analysis of the comments, counter-comments, and the views expressed by the stakeholders during the OHD, and internal examination of the issues relating to interconnection based on the information available with the Authority, draft Interconnection Regulations, 2016 namely the draft Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2016 were framed and the same were uploaded on TRAI website along with explanatory memorandum detailing objects and reasons of the draft Interconnection Regulations, 2016 for consultation with the stakeholders. The stakeholders were requested to provide their comments/ views on the draft, specifically on specific values suggested in the draft. A time up to 28th October, 2016 was provided to the stakeholders for comments, which was, on the request of the stakeholders, extended up to 15th November, 2016, by the Authority. The stakeholders were also requested to provide their inputs on completeness and consistency of the regulations within and with other draft regulations/ tariff orders. To better understand the views/ comments, the stakeholders were requested to provide their inputs with adequate justification. In response, a total 45 comments were received and these written comments were uploaded on TRAI website. After taking into consideration the comments received from the stakeholders and in-house analysis, the Authority finalized the Telecommunication (Broadcasting and cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017. The subsequent paragraphs explain the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulation, 2017.

#### **Copyright Issues**

12. In response to the draft Interconnection Regulations 2016, some of the broadcasters stated that provisions of ‘non-exclusivity’, and ‘must provide’ are in conflict with certain provisions of the Copyright Act 1957. They have argued that the Copyright Act 1957 allows content owners and broadcasting organisations to exclusively license or assign their works and grant broadcast reproduction rights, whereas, the provisions of the draft regulations require the broadcasters to compulsorily provide their channels to distributors of television channels on non-exclusive basis. They have further stated that the draft Interconnection Regulations 2016, denies the broadcaster the right to negotiate with the distributors.
13. The Authority is of the view that a TV channel is a distinct and different ‘product’ and is comprised of a collection of different individual programmes such as movies, sports, dramas, soap operas, music, etc. Some of these programmes are either created by the broadcasters themselves or they are acquired through license/ assignment from various content producers or production houses. Therefore, a TV channel is a mixture of different individual copyrightable works either owned or acquired through license/ assignment from different copyright owners/ authors by a broadcaster. The provisions of Interconnection Regulations, 2017 do not in any manner regulate as to how or at what price/royalty a broadcaster can acquire content form the content owners. These regulations do not in any manner regulate the process of acquiring the license by the broadcasters from the content owners for its TV channel and they also do not regulate copyrighted work underlying the TV channels. These regulations however govern the manner of offering of TV channels to the DPOs for further re-transmission to the subscribers on non-discriminatory basis. Therefore the contention of the broadcaster that the provisions of regulations are in conflict with the Copyright Act is not tenable.
14. The argument of the broadcasters that compulsory providing of TV signals to DPOs on non-exclusive basis and mandating agreement on the basis of RIO conflict with the provisions of Copyright Act is not in conformance with the well-settled position of law. This issue has been settled by Hon’ble TDSAT in the case of M/s Noida Software Technology Park Ltd. Vs. M/s Media Pro Enterprise India Pvt. Ltd. & Ors., in Petition No. 295 (C) of 2014, judgement dated 07.12.2015. A Statutory Appeal carried from the Hon’ble TDSAT judgment in Noida Software Technology Park vs. Media Pro Enterprises India Pvt. Ltd. was dismissed by the Hon’ble Supreme Court vide order dated 26.02.2016 in Civil Appeal No. 1446 of 2016.
15. The arguments of the broadcasters that signing of interconnection agreement on the basis of RIO takes away their right of mutual negotiation for licensing their BRR under Copyright Act is also not tenable. On this issue, it is

important to note that the rule 9 read with rule 10 of the Cable Television Networks Rules, 1994 mandates TRAI to specify Standard Interconnection Agreements (SIA) to be entered for interconnection between broadcaster and MSOs. However, in terms of these regulations, TRAI has in fact refrained from prescribing any specific RIO or SIA for broadcasters giving them full freedom to innovate and market their offerings. These Regulations give freedom to broadcasters to devise and design their RIOs as per their own choice subject to compliance with the provisions of the regulations/ Tariff Order. The Hon'ble TDSAT in the case of Star Sports India Pvt. Ltd. Vs. Hathway Cable & Datacom Ltd. in Petition No. 47(C) of 2014, judgement dated 25.09.2014 has given its approval to the concept of RIO as a measure of ensuring a level playing field. If anything in these Regulations, the TRAI has reduced the extent of regulatory intervention.

16. In the above referred judgements, Hon'ble TDSAT has exhaustively dealt with the issues of copyright and interconnection regulations and conclusively determined that the provisions relating to non-exclusivity, non-discrimination, reference interconnection offer etc. do no conflict with the provisions of Copyright Act.

#### **Non-exclusivity and Non-discrimination**

17. The Interconnection Regulations, 2004 and the Interconnection Regulations, 2012 prohibited exclusive arrangements, which prevent other service providers to get signals of TV channels or access to distribution networks, between service providers. They also made it obligatory on part of broadcasters to provide signals of TV channels to DPOs, on receipt of request for the same, on non-discriminatory basis which is commonly referred as 'must provide' principle and which in essence mandate a broadcaster to must make available its TV channels to DPOs and through them to viewers on an equal basis within a given territory. The principle of non-exclusivity and must provisioning of signals have to be examined primarily from the consumer's perspective. While at this juncture, although large number of broadcasters are present across popular genres, the competition is far from fair due to monopolistic nature of TV channels. TV channels within the same genre are differentiated from one another by their branding and composition of programs. They are not substitutes in the perception of consumers. As in a monopoly, firms in monopolistic competition are price setters, rather than price takers. If a TV channel, in demand in a particular market, is not available on any one TV distribution network and another popular channel in that market is not available on a competing distribution network then in such market the consumers may have to subscribe for services of more than one operator to view their favourite channels. Moreover, it is impractical for a consumer to obtain broadcasting/ cable services from multiple DPOs. In broadcasting and cable TV sector, to some extent, vertical integration still exists between broadcasters and DPOs. Any kind of exclusive agreements, whereby signals of popular TV channels can be denied to a competitor so as to promote the broadcaster's integrated distribution network will affect fair competition and choice to the consumers. Similarly, entering into any understanding or arrangement by a DPO with a broadcaster or LCO which prevents other broadcasters or other LCOs to access the network of the DPO for re-transmission or to obtain signals of TV channels may be prejudicial to the competition.
18. TRAI, being a sectoral regulator of broadcasting services and cable services, has been entrusted with the task of ensuring a level playing field and fair competition in the sector and also ensuring that the interests of consumers and service providers are protected. Therefore, TRAI has power to look at all issues affecting competition in the market and to craft remedies for the same on ex-ante basis. The Authority is of the view that any kind of exclusivity in distribution of TV channels is prejudicial for competition and hence should not be permitted and mandatory provisioning of signal is a meaningful step towards achieving the goal of fair competition and the interest of consumer. Accordingly in the draft Interconnection Regulations, 2016, necessary provisions for non-exclusivity and must provide were made. After analysis of the comments received in response to the draft Interconnection Regulations, 2016, it appears that these principles have been widely accepted and therefore these principles have been retained in these regulations.

#### **Must Carry**

19. The provisions relating to 'must carry' existed in the Interconnection Regulations, 2012, which was applicable for cable TV services provided through DAS. The 'must carry' provisions in the Interconnection Regulations, 2012, enabled broadcasters of Hindi, English and Regional channels to access the network of an MSO for re-transmission to the subscribers. However, in the Interconnection Regulations, 2004, which regulated non-addressable cable TV systems and the other addressable systems like DTH, HITS and IPTV, there was no 'must carry' provision. In the CP, it was proposed to make a uniform "must carry" provision for all addressable systems.
20. A service provider in the value chain may act as a seeker or as a provider. For example, when a distributor seeks signals of TV channels from a broadcaster, it acts as a seeker and the broadcaster in such case becomes a provider of the signals of TV channel. Whereas, when a broadcaster approaches a distributor for accessing its network for re-transmission of its channel(s) then it acts as a seeker and the distributor becomes the provider. The 'must provide' provision helps DPOs in making available TV channels to its subscribers on the basis of demand in a market. Similarly, 'must carry' provision removes entry barrier for a television channel to enter into a target market, as a broadcaster can distribute its channel(s) through the DPOs available in that target market.

21. In response to the CP, majority of the broadcasters stated that 'must carry' provision should be applicable for all types of networks. Whereas, one broadcaster and some DPOs stated that 'must carry' provision should not be made applicable to DTH and HITS networks as there are transponder capacity constraints. After analysis of the comments received in response to the CP, 'must carry' provision, wherein spare capacity of a DPO to be allocated on first come first served basis, was proposed in the draft Interconnection Regulations, 2016 for all types of addressable systems.
22. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, a broadcaster suggested that to ensure proper implementation of this clause, a real time monitoring of requests is required. It was suggested that the requests from broadcasters for re-transmission of their channels should be received by DPOs through websites only. Another broadcaster opined that DPOs should publish and update complete details of their network's channel carrying capacity and pending channel list in chronological order, within 7 days of any change in place of 30 days as proposed in the draft Interconnection Regulations 2016. Some broadcasters and an association stated that non stipulation of minimum channel carrying capacity for DPOs and the proposed provision of must carry on first come first serve basis may dilute the 'must carry' principle as deserving channels may be deprived access merely due to timing of request. They further commented that regional channels should be carried by regional MSOs. Many broadcasters also suggested that DPOs should continue to carry all the channels/ bouquets, which are available on their platform during the last calendar quarter from the effective date of the proposed regulation, for at least next 60 days to provide level playing field to all broadcasters.
23. DTH operators commented that satellite bandwidth is a scarce resource, which makes it not only cost prohibitive for DTH operators to add requisite transponders but is also difficult to obtain because of the long waiting time involved (usually 1-2 years) for various clearances. Therefore, they opined that flexibility be given to them to use this bandwidth economically and efficiently to meet the demands and preferences of their retail customers.
24. DTH operators also commented that 'first come first served' should not be implemented in situations where there is a gap between demand and supply and/or the resource to be provided is scarce. The principle of 'first come first served' might end up creating disputes between broadcasters and DPOs since it would be hard to determine the priority level of broadcasters' requests for the carriage of a channel. It would also lead to administrative issues (documentation, etc.) which would be difficult for private entities to manage. DTH operators further commented that due to these challenges the capacity of this media can never match that of the cable operators therefore it is their right as business entity to be able to sell the satellite space at the best possible business proposition.
25. Some DTH operators stated that the obligation of must carry will force DTH to carry even those channels which have very less demand or no demand which will be highly detrimental to the DTH platforms as well as to the customer. This will impact the customer base of DTH operators who would tend to move to other Digital platforms. Unlike a DAS operator which may have region based offerings, DTH operation is a PAN India operation where a DTH operator has to be selective in the choice of the channels to be placed on its platform.
26. One of the MSOs have suggested to have a proviso to regulation dealing with the 'must carry issue' that in case the number of channels in genre be filled to the extent of 10% of available capacity, then the distributor should be at liberty to deny carriage of a channel on the "first come first serve basis".
27. As per the downlinking guidelines of the Ministry of Information and Broadcasting (MIB), a broadcaster can distribute its TV channel through distributors of TV channels only. Therefore, it becomes essential that a broadcaster desirous of re-transmission of its TV channels to subscribers in a market should be able to access the network of distributors of TV channels in that market. The 'must carry' principle removes the entry barrier for channels and ensures that the network is accessible for distribution of channel. Denial of access to that particular market by a DPO may cause jeopardy to that broadcaster as it cannot reach end consumers in that particular market through any other alternate means.
28. On the other hand, a DPO plans the capacity of its distribution networks on the basis of demand in the market and availability of network resources. There is a distinct possibility that at a given time when a broadcaster approaches a distributor for re-transmission of its channels, spare capacity in the distribution network may not be available. To address the issues relating to capacity constraints and requirement of non-discriminatory access to distribution networks, a balanced approach need to be adopted. Accordingly, the following provisions have been made in these regulations:-
  - i. DPOs have been mandated to declare its target market and publish total channel carrying capacity and spare channel capacity along with other details specified in the regulation on its website, as the capacity varies from network to network,
  - ii. Any change in the information published by the DPOs on its website is required to be updated within seven days from the date of occurrence of such change so that the broadcasters can take informed decision before making request for carrying the channels,

- iii. An interconnection agreement has to be in place for getting access to the network,
  - iv. DPOs are also required to maintain and publish on its website the list of channels, in chronological order, for which requests have been received from broadcasters for re-transmission of their channels, the interconnection agreements have been signed and are pending for re-transmission due to non-availability of the spare channel capacity. This will not only improve the transparency but also act as a deterrent for non-serious players seeking access.
  - v. DPO is required to allocate every alternate spare channel capacity on its network, in sequential manner, from the list for re-transmission of the television channels. This will address the issue of non-discrimination and would also enable carry those TV channels which are in demand in the market and requests have been made by the DPO for distribution after entering into interconnection agreement.
29. Thus, the Authority has decided that 'must carry' provision should be uniformly applicable to all types of DPOs subject to availability of spare capacity. In this way, while the DPOs have the freedom to plan their networks, the broadcasters would be able to get access to the distribution networks on non-discriminatory basis.
30. In deference to the long standing demand of broadcasters to mandate 'must carry' obligation on the DPO as a reciprocal obligation to the 'must provide' mandate on the broadcasters, in these regulations the TRAI has made applicable such provisions for all category of DPOs. The provisions relating to 'must carry' make it obligatory on part of DPOs to carry signals of TV channels of broadcasters, on receipt of written request for the same, on non-discriminatory basis.
31. On the suggestion of some stakeholders regarding setting up of a minimum channel carrying capacity by DPO, the Authority noted that India is a pluralistic country with diverse requirements therefore; the choice of the customer may be varied depending on different demographics. The DPOs create network capacities depending upon the requirement of that market in which they are operating. Therefore, mandating a minimum capacity for networks may serve purpose for one region but that may not be suitable for other region. On the contrary mandating minimum channel carrying capacity for a distribution network may increase the cost to the consumers. The market forces would play an important and significant role in the matter of carrying capacity of the DPO. Therefore, the Authority is of the view that the channel carrying capacity of a DPO should be left to market forces and therefore, the same has not been regulated.
32. The Authority noted that, generally, the channels available on a distribution platform are a mix of channels obtained through 'must provide', 'must carry' and free to air channels distributed by a DPO as per demand in the market. So it is necessary that the available capacity of a distribution network is best utilised to meet the demand of the consumers in a particular market. Therefore, these regulations provide full right to the DPO on the used capacity of its network. However, on spare channel capacity, it has been made obligatory to allocate every alternate channel capacity in sequential manner from the pending list. For such channels the DPOs will get the carriage fee till the average channel subscriber base reaches 20%. Thus the above mechanism in no way restricts the business plans of DPOs and protects its right on its capacity to carry channels while addressing broadcasters concern also.
33. The MSOs suggestion that a proviso in the regulation dealing with the 'must carry' that in case the number of channels in genre be filled to the extent of 10% of available capacity, then the distributor should be at liberty to deny carriage of a channel on the "first come first serve basis" cannot be accepted as DPOs are allocating only the alternate spare capacity that too with carriage fee. Further, the subscriber demand will play a role in continuance of such channel and a provision has already been made for discontinuation of channel if it fails to acquire a minimum percentage of subscriber base during predefined time period.
34. In order to protect DPOs from carrying a non-popular channel under 'must carry' it was proposed in the draft Interconnection regulations, 2016, that DPO can discontinue carrying of a television channel in case the monthly subscription, for that particular television channel is less than 5% of the monthly average active subscriber base of that distributor in the target market specified in the interconnection agreement, in each of the immediately preceding six consecutive months. On this issue, most of the broadcasters opined that such provision may give unilateral power to DPOs to discriminate and will be against the principle of network neutrality and will enable operator to act as gate keepers for channels. A broadcaster suggested that a provision may be made for DTH and HITS operators to discontinue a channel if the subscription, in the preceding six months is less than or equal to a given minimum of 10 % of the total active subscriber base of that operator averaged over that period. Many broadcasters stated that, since HD penetration is very low, it is likely that HD Channels in many case would not qualify the criterion of 5% and will be liable to be disconnected by DPO. Therefore, they demanded protection for HD channels in this regard. Some other broadcaster said that, similar is the case for English genre channels as there is very less population demanding for English language channels. On the contrary, some DPOs quoted that it should be permitted to discontinue the channel if subscription percentage remains below 5% on the average subscriber base of the past 3 months instead of 6 months, and after such disconnection the permissible period of denial to carry the same channel again should be increased from 1 year to 3 years.

35. The Authority noted that such provision existed in the Interconnections, 2012 which was applicable for DAS. The Authority is of the view that such provision would ensure that non-popular channels do not occupy the space on a distribution network. Therefore the provision has been retained with slight modification. In case of failure to maintain the required subscription levels, a DPO, in its discretion, could refuse to grant further access to the network for a period of further one year.
36. One of the unique features of digital networks is that it supports re-transmission of High Definition (HD) Channels. The picture quality and viewing experience in HD channels are far better than those of SD channels prevalent in the market. Generally, the bit-rate of HD channel is approximately two times of the bit rate of corresponding SD channels. Therefore, the Authority has mandated that in case one HD channel is discontinued or added by DPO then for the purpose of calculation of spare capacity, one HD channels shall be counted equivalent to two SD channels.
37. The Authority noted that at present there are only 17% of DTH subscribers are having HD set-top boxes and in case of MSO's subscribers, this figure is very low. Therefore, in such a situation, the likelihood of subscription of HD channels falling below 5% of total subscriber base of a DPO is very high. Therefore, the Authority is of the view that such channels needs different treatment and it has been decided that for the purpose of calculation of monthly subscription for HD TV channels, only the subscribers capable of receiving HD TV channels shall be considered.
38. However, the Authority has not agreed with the suggestion of some stakeholder regarding the protection to English language channels as it would be unfair to grant protection to channels on the language or genre basis and also it would be impossible to segregate the subscribers on the basis of their choice of language of channels.
39. On the suggestion of stakeholders in response to the CP regarding setting up of web-based interconnection request management systems, the Authority has constituted a task force to deliberate the issue of developing such a system.

#### **Time Limit for Provisioning of Signals/ Access to Network**

40. The Interconnection Regulations, 2004 contained provisions relating to provisioning of signals of TV channels to seeker in a time bound manner. It was provided that a service provider should either provide the signals in the stipulated time of 60 days from the date of the request and, in case the service provider turns down the request, the reasons for such a refusal must be recorded in writing and conveyed to the seeker within 60 days from the date of the request so that the affected party can take corrective actions or agitate before appropriate forum, as the case may be. Time bound interconnection between service providers is essential for fair competition in the market and meeting the demand of the consumers in time. However, in the past, on many occasions, the Authority noted that even though providers (broadcasters or DPOs) did respond to the requests within the stipulated time, the negotiations to enter into mutually agreed written interconnection agreement were prolonged defeating the very purpose of the regulations. In many cases, due to prolonged negotiations, the time period of 60 days was not adhered to by either party. In the CP the issues relating to timely provisioning of signals / access to distribution network were discussed. To ensure the compliance of these regulations in letter and spirit, it was proposed in the CP that the 60 days period may be further sub-divided into sub-activities and RIO may contain necessary and sufficient conditions, so that a seeker can sign the same and send that to the provider for further necessary action, in case of any delay.
41. In response to the CP, most of the broadcasters and some DPOs supported the existing time line of 60 days for providing signals of TV channels/ access to the network, without any sub-division and suggested that financial disincentives may be levied on service provider in case of any default. Another broadcaster commented that 60 days period is not sufficient for a broadcaster to complete all the procedures for providing signals of TV channels and therefore it should be increased. Some DPOs stated that 60 days may be sub-divided into 2 periods i.e. 30 days each, the first for raising objections, technical audit etc. and the second for curing the defects. A cable operator commented that only 30 days are sufficient for providing signal of TV channels.
42. The Authority noted that the service providers are required to carry out certain activities before providing signals of TV channels/ access to the network such as commercial discussions for entering into written interconnection agreements, assessment of addressable systems, provisioning of Integrated Receiver Decoders (IRDs) and other technical infrastructure. To ensure timely provisioning of signals/ access to the network, it is necessary that discussions for signing of interconnection agreements are completed in time bound manner. Delays in signing of interconnection agreements results in delay in providing signals of TV channels/ access to the network. Many times it has been observed that either for want of certain additional information, or on some technical or commercial grounds, the refusal to enter into agreement was conveyed by provider to seeker at the far end of the permissible period. Therefore, the permitted 60 days time cannot be used for signing or refusal of interconnection

agreement only. The time period for signing of agreement and remaining other activities to be carried out for providing signals of TV channels/ access to the network need to be divided so that the delays are eliminated. Therefore, the Authority was of the view that the seeker and provider should conclude all the commercial discussions by entering into the written interconnection agreement within 30 days from the date of receipt of request from a service provider and make necessary arrangements for provisioning of signals of TV channels/ access to the network within next 30 days from the date of signing of the interconnection agreement. Accordingly in the draft Interconnection Regulations, 2016, necessary provisions for dividing the 60 days period into two separate periods of 30 days each, for signing of agreement and provisioning of signals/ access to the network, were made. After analysis of the comments received in response to the draft Interconnection Regulations, 2016, it appears that the stakeholders do not have any specific comment other than what were already articulated in response to the CP and therefore, the provisions relating to time limit for provisioning of signals/ access to network as proposed in the draft Interconnection Regulations, 2016 have been retained in these regulations.

43. On the aspect of levy of financial disincentives on the service providers for delay, the Authority noted that generally the delays in providing signals / access to distribution networks were either due to delay in signing of agreements or disputes of varied nature between the service providers. Now separation of time periods for signing of interconnection agreements and remaining technical activities, and the requirement for signing of agreements on the basis of reference interconnect offer should be able to address the issue relating to delays in signing of interconnection agreement to a large extent. Disputes can be appropriately resolved by the service providers either through mutual discussions or the same can be decided by the dispute resolution forums. Therefore, the Authority is of the view that prescription of financial disincentives at this stage is not necessary.

#### **Reasons for denial of Signals / Access to Network**

44. In the Interconnection Regulations, 2004 and the Interconnection Regulations, 2012, one of the parameters permitted for denial of signals/ access to the network was default in payment. In the draft Interconnection Regulations, 2016 also, after detailed analysis of the comments received in response to the CP, the Authority proposed to continue with such provision which makes the principles of “must provide” and “must carry” non-applicable in cases where the seeker is in default of payment and continues to be in default.
45. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, some broadcasters stated that while considering default by a DPO (seeker), as a reasonable parameter for denial of interconnection request, default by the DPO with that broadcaster along with all other broadcasters operating in the sector should be taken into account. Another broadcaster commented that reasons for denial should also include previous outstanding with any broadcaster/ proven track record of non-payment, criminal record of DPO/ criminal proceedings pending against DPOs and DPOs not complying with technical specifications.
46. For any industry, the revenue flow across the value chain is of utmost necessity for the growth of the industry. It is right that a habitual defaulter service provider should face some additional conditions before provisioning of signals/ access to distribution networks. However, for doing so in non-discriminatory manner, the industry needs to evolve an index to measure the level of default of a service provider, which does not exist today. Whenever, such mechanism is evolved by the industry, this could be another reason for imposing some additional conditions. The existing provisions relating to the default are inclusive and not exhaustive. The service providers are free to impose any other reasonable condition in non-discriminatory manner and seekers are free to respond to them. Therefore, the Authority, has retained the provision which makes principles of “must provide” and “must carry” non applicable to the cases where the seeker is in default of payment and continues to be in default.

#### **Packaging of a Channel in DPO's Bouquet**

47. For ease of subscription and management, in addition to offering the channels on a-la-carte basis, distributors offer bouquets of channels as per the demand of subscribers. However, in the past, it was noted that, there has been direct or indirect influence by broadcasters on distributors for packaging of their channels in specific bouquets offered by them. Generally the price difference between a-la-carte and bouquet offerings was kept very high. Such practices led to offering of some non-popular channels along with few popular channels as part of bouquets. This practice led to compromise of consumer choice as the subscribers were swayed to subscribe such bouquets in place of a-la-carte channels due to wide difference between the bouquet price and the sum of a-la-carte prices of constituent channels. In order to address the issue, in the draft Interconnection Regulations 2016, it was proposed that the broadcaster shall not include any clause in the interconnection agreement which, directly or indirectly, affects the decisions of a DPO to package channels in a bouquet offered to the subscribers.
48. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, some broadcasters opined that complete restriction on broadcasters to ask for specific packaging should not be permitted as this affects the revenue stream of a broadcaster. Broadcasters also stated that niche channels would suffer due to this and it would affect the reach of channels in terms of geographic distribution and therefore it may limit the production of good quality content in the industry. A news broadcaster commented that DPOs should be encouraged to create “genre wise packs” rather

than a mix/ match of channels. Further, for packages covering wide genres, DPOs should not be allowed to disadvantage a channel with other channels in the competing genre.

49. Some DPOs have suggested that a provision should be added in the regulations which prevent broadcaster to impose any condition on a distributor to mandatorily offer all bouquets formed by such broadcasters. They have argued that if no such provision is added then the broadcasters would try and push their bouquets instead of subscribers choosing bouquets as per their wishes and tastes.
50. In order to address the issue, the Authority, in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 has brought in a new framework, wherein a broadcaster has freedom to offer its pay channels in form of bouquet(s). Similarly, a distributor has also been given freedom to form its own bouquet(s) by including a-la-carte pay channels or bouquet(s) of pay channels of different broadcasters.
51. The arguments of the stakeholders that the proposed restrictions on packaging may limit the production of good quality content and affects the revenue stream of a broadcaster are untenable as subscription of channels/ bouquets by consumers as per their choice should encourage the broadcasters to offer good quality channels to meet their demand. For improving the reach of channels in terms of geographical distribution, the Authority has already increased the scope of "must carry" provisions in these regulations. However, the reach of channels in terms of subscription must be left to choice of consumers as this is one of the primary reasons for implementation of addressability in the distribution system.
52. Since the freedom for forming the bouquets has been given to both the stakeholders, therefore, it is expected that they will form the bouquets on the basis of consumers demand. Any kind of direct or indirect influence on DPOs for deciding composition of bouquet, other than the choice of consumers, affect the orderly growth of the sector. In order to ensure that choice of the consumers remain only guiding factor for determining the composition of bouquets, it is necessary to ensure that no broadcaster interferes with bouquet formation at the level of distributor.
53. For distribution of pay channels by DPOs on a-la-carte basis or for distribution of bouquets of pay channels, formed by broadcasters, it necessary that the interconnection agreement is in place. If a DPO enters into an interconnection agreement with the broadcaster for offering of broadcaster's bouquet and it forms its own bouquet(s) by including only some pay channels of the broadcaster's bouquet then the revenue settlement between the broadcaster and DPO should be according to the interconnection agreement signed for those particular channels on a-la-carte basis. Further to ensure that choice of a-la-carte selection remain available to customers in all circumstances, in these regulations the broadcasters and DPOs have been mandated to enter into interconnection agreement on a-la-carte basis for all pay channels before distribution.
54. On the concerns of DPOs regarding imposition of any condition to mandatorily offer all bouquets formed by such broadcasters, the Authority is the view that if all the constituent channels of the bouquet formed by the broadcaster are not available on the platform of the DPO then by default, the DPO will not be under obligation to carry such bouquet of broadcaster. Accordingly, necessary provisions have been made in these regulations that a broadcaster cannot provide any pre-condition as well as any clause in the interconnection agreement which directly or indirectly affect the packaging of the channels in a bouquet.

#### **Provisioning of Signal to LCOs**

55. In case of DAS and HITS services, the last mile connectivity is mostly provided by LCOs. As per Cable TV Act and rules made there under, LCOs are registered in the head post offices of the areas of their operation. The Interconnection regulations, 2004 and the Interconnection regulations, 2012 contained provisions relating to time bound provisioning of signals of TV channel to LCOs within 60 days from the date of request.
56. In these regulations, to ensure the timely signing of interconnection agreement and provisioning of signals, the time period of 60 days has been divided in two parts. It has been mandated that the DPOs should enter into an interconnection agreement within 30 days from the date of receipt of request and thereafter provide the signals of TV channels to the LCO within next 30 days.
57. To ensure the proper revenue flow in the value chain, it is essential that the invoices are raised in time and due payments are also settled in time. Arrears, if any, need to be reflected in the subsequent invoices to ensure transparency in the business transactions. Many times, during the interactions with the stakeholders, it was reported that either in the absence of regular invoices or due to non-intimation of arrears in the subsequent invoices, the LCOs are suddenly confronted with demand for payment of huge amounts as arrears for last many months. Many a time LCOs have no information as to how such huge pending dues have been shown against them, especially when they were making regular payments and the arrears were not reflected in the invoices issued in the immediate past. Often it leads to disputes.
58. The issue can be tackled by ensuring that the invoices are issued on a monthly basis clearly showing the current dues as well as the arrears, if any. This will also ensure the transparency in the business transactions and revenue flow in the value chain. It is necessary to curb the practice of bad debts in the sector as it ultimately affects the

price to subscribers. The latest invoices should clearly show the level of arrears outstanding against the LCO. The LCO should not be considered in default of payment to a distributor of TV channels if it produces the copy of immediately preceding six consecutive month's invoices with corresponding payment receipts, as a proof of having paid its dues. Such stipulation will protect the LCOs from unexpected and unforeseen arrears being suddenly thrust upon them. Accordingly, suitable provisions have been made in this regard.

### **Prohibition of Minimum Guarantees**

59. There may be different types of minimum guarantee. For example, a service provider may insist on other service provider to pay a fixed amount irrespective of number of subscribers actually subscribing a channel or number of subscribers in the network. There may be a situation, where a service provider might ask the other service provider to ensure a minimum number of subscribers before providing signals or stipulate a condition that only the service provider having a stipulated number of subscriber base can seek signals. There may be another possibility that the service provider might insist for a guarantee for a minimum percentage of subscription of its channels for providing signals of TV channels. A situation may also arise where a DPO before providing access to its network may put a condition that it will carry the requested channel only if the broadcaster enters into agreement for carriage of additional channel(s) or the DPO prescribes a certain minimum period for carriage of the requested channels.
60. The Interconnection Regulations, 2004 provide that in addressable systems, no service provider shall stipulate, insist or provide for any clause in an interconnection agreement with a distributor which would require such distributor to pay a minimum guarantee amount as subscription fee for the services provided. Similarly, the Interconnection Regulations 2012 provided that no service provider shall demand from any other service provider a minimum guarantee amount as subscription fee for the channels provided by such service provider. In a competitive market, insistence on any kind of minimum guarantee by either party is considered as an entry barrier and restricts the choice of consumers. The issue of minimum guarantee was discussed in the CP.
61. In response to the CP, most of the broadcasters and DPOs opined that conditions such as minimum guaranteed number of subscribers or any fixed amount as a subscription fee should not be allowed. Broadcasters were also of the view that subscriber numbers and the rate of channels should be the core parameter for calculation however, discounts based on network size, LCN (logical channel numbers), parity etc. within the allowed caps should be considered for calculation, and minimum guarantee as a pre-condition should not be allowed. DPOs also favoured the prohibition of a minimum subscription guarantee.
62. Any kind of minimum guarantee between the interconnecting parties is reminiscent of the analogue era, in which the numbers of subscribers were either not verifiable or it was difficult to ascertain as to how many subscribers are subscribing the channels. Therefore, in order to protect their revenue, service providers used to charge a fixed amount from the other service provider or used to bill for a minimum number of subscribers irrespective of whether the other service provider has been able to get that many subscribers or not. With the advent of digitisation and addressability in the sector, every subscriber accessing a particular channel can be counted and the same can be easily verified. The malaise of under-reporting of subscribers was a main cause of revenue loss and disputes in the sector and the same has been cured by addressable systems. Despite that, the Authority has observed that the minimum guarantees in some or other form are still continuing in the sector. Stipulation of any minimum guarantee for number of subscribers or stipulation of any fixed fee/ fixed amount is not only anti-competitive but it also creates entry barriers for new service providers. It also defeats the purpose of implementing digitisation and addressability in the sector. This is against the objective of providing choice to the consumers and making services more affordable. Therefore, as far as the issue of minimum guarantee amount or fixed fee is concerned, the Authority is of the view that service provider neither can insist for payment of a fixed amount nor can provide such clause for payment of such fee in the interconnection agreement. Accordingly the necessary provisions have been made in these regulations. The Subscriber Management Systems (SMS) of addressable systems provides for a transparent mechanism to count the number of subscribers availing broadcasting services and therefore a provision has been made that the 'broadcaster's share of maximum retail price' payable by a DPO shall be calculated on the basis of number of subscribers.
63. As far as the issue of prescription of guarantee of a minimum number of subscribers or subscriber base is concerned, the Authority is of the view that for ensuring competitiveness in the market and to remove entry barrier for new entrants, no service provider should be allowed to stipulate a pre condition for guarantee of minimum subscriber base or minimum subscription percentage of its channel(s). However, the Authority is also conscious of the fact that many service providers, in order to promote their channels, may like to provide discounts, within the prescribed limits in non-discriminatory manner, to other service providers on their fulfilling of certain target of the subscriber base or subscription percentage of its channel(s). In such a situation, to ensure the orderly growth of the sector, the Authority is of the view that it would be unfair to prohibit offering of such discounts. However in no case, such prescription should transcend to the denial of signals or discontinuation of signals or a pre-condition for giving the channel.



64. As far as, the issue of prescribing of minimum guarantee for period or minimum guarantee for number of channel(s), as a pre-condition for providing access to the network, by a DPO, is concerned, the Authority is of the view that such pre-condition would create an entry barrier for broadcasters and therefore the same has also not been allowed and such pre-condition has been qualified as unreasonable term. However, the DPO would be free to offer discounts, within prescribed limits, on the carriage fee for offering access for carrying of additional channels or for entering into longer duration agreements.

#### **Reference Interconnection Offer (RIO)**

65. Publication of RIO by service providers is one of the most effective ways of meeting non-discrimination and level playing field requirements. It also provides enough flexibility to service providers for offering their services as per their business plans. In the CP, the issue of allowing interconnection agreements based on mutually agreed terms, which do not form part of RIO published by a broadcaster or a DPO, was deliberated. It was also discussed whether the RIO should be the only basis for signing of interconnection agreement and the RIO should include all the terms and conditions including rates and discounts, to ensure non-discrimination and level playing field.
66. After considering the comments of the stakeholders in response to the CP, to effectively ensure the non-discrimination on ground, in the draft Interconnection Regulations, 2016, it was proposed that an interconnection agreement, either for providing signals of TV channels or for access to the network for re-transmission of channels, should be entered into in accordance with the RIO.
67. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, some broadcasters and one broadcasters association stated that interconnection agreement to be based only on RIO takes away broadcasters' ability to negotiate the terms of trade while the Copyright Act permits mutual negotiations by Broadcast Organisations.
68. The RIO published by a service provider is an offer on the basis of which a service provider wants to provide the signals of TV channels or access to the network to the seeker on non-discriminatory basis. However, in the past, the flexibility provided in the Interconnection Regulations, 2004 and the Interconnection Regulations, 2012, for signing of written interconnection agreement on mutual agreed terms, was many times misinterpreted by service providers to transcend beyond the regulatory framework and discriminate among similarly placed seekers. This was giving rise to number of disputes between service providers. In a regulated sector, to ensure level playing field, it is essential that all service providers conduct their business transactions as per the notified regulations and orders.
69. The argument, that the signing of interconnection agreement only on the basis of RIO, takes away the rights of broadcasters under the Copyright Act which gives them freedom for mutual negotiation for licensing their work, is misplaced. Here it is important to note that these regulations in no way regulate the licensing or assignment of copyright 'work' as defined in the Copyright Act. These regulations regulate the distribution of channels to the subscribers and signing of interconnection agreements for that purpose. It is further important to note that these regulations give complete freedom to broadcasters to devise and design their RIOs as per their own choice subject to compliance with applicable regulations. The regulations provide enough scope for mutual discussions on the basis of declared parameters. The RIO framework provides a common and transparent basis for all agreements to be entered for provisions of signals or access to the network. For ensuring the orderly growth of the sector, it is essential that the regulatory framework provides for an easy entry as well as exit options for service providers. For a new entrant in the sector, before committing the requisite investments, it is of paramount importance that he is reasonably assured of getting forward and backward linkages. In case of broadcasting and cable TV sector, for a new broadcaster it is essential to have reasonable assurance of accessing the networks at declared terms and conditions. Similarly, for a new distributor it is essential to have reasonable assurance of getting signals of TV channels at declared terms and conditions. Mutual agreements, beyond the declared RIO defeat this vital requirement for orderly growth of the sector.
70. It also helps to ensure that new entrant operators can be confident of getting terms which will not be less favourable to those applied to others. The RIO must define the parameters for arriving at an agreement on acceptable terms and such parameters should be objective, measurable and computable. Therefore, the Authority is of the view that all the interconnection agreements should be signed in accordance with RIO.

#### **Examination of RIO**

71. As per the Interconnection Regulations, 2004 and the Interconnection Regulations, 2012, the service providers were required to publish their RIOs on their websites. Further, these regulations also created an obligation on the service provider to file a copy of RIO with the Authority. If any stakeholder felt that the terms and conditions of an RIO contravene the provisions of the regulatory framework then that stakeholder was at liberty to raise his objection with the provider publishing the RIO or at an appropriate forum. On many occasions it was observed that such objections were often raised after long time from the date of publication of RIO. This resulted in delay in initiation of corrective action, if any, by the provider. Further, an amendment to the RIO at a belated stage necessitated amendments in agreements with multiple seekers already executed on the basis of that RIO. The

issue was deliberated in the CP wherein a consultative approach was suggested to address these issues. After considering the comments of the stakeholders in response to the CP, in the draft Interconnection Regulations, 2016, it was proposed that the service provider shall publish finalise its RIO after considering the comments of stakeholders in the value chain. Such provision would ensure that the final RIO is compliant to the regulatory framework and lead to reduction in disputes. Even after this exercise, an aggrieved stakeholder can approach an appropriate forum for settling their disputes on RIO.

72. In response some broadcasters commented that enabling DPO to raise objection and making it obligatory on the part of broadcaster to consider and amend RIO as per those objections would introduce lot of complications in the process as multiple DPOs (DTH/MSOs) keep on raising one objection or the other and the RIO will never attain finality. One broadcaster stated that such a right should not be given to DPOs and only TRAI should hold the right and solely be responsible to intervene in the RIO being drafted and published by the broadcaster. One DPO suggested that the broadcaster should be made to mandatorily report its RIO or amended RIO to TRAI to verify the compliance of the same with the regulatory requirement. Another broadcaster stated that if the RIO is not in compliance with the regulations then any stakeholders can approach regulator or Hon'ble TDSAT. Majority of DPOs stated that it should be mandated that all draft RIOs be first submitted to TRAI to go through them and published after its approval. If the same are non-compliant, the Regulator can take appropriate action. Further they stated that the DPOs should also be allowed to challenge the same, if some clauses are contrary to the Regulatory Framework.
73. After considering the comments of various stakeholders on this issue and on giving cautious consideration to the provisions in relation to finalization of the RIO by broadcasters and distributors, the Authority observed that the proposed process for finalisation of RIO may lead to delays and repetitive work. Also, it was not able to guarantee the non-occurrence of the disputes after publication of final RIO by a service provider. This extra burden can be easily avoided by ensuring that the service provider publishes its RIO in compliance of the regulatory framework at the initial stage itself. Further, permitting a draft Reference Interconnect Offer which is not in conformity with the Interconnect Regulations would be antithetic to the very purpose of regulating interconnection between broadcasters and DPOs. Therefore the Authority is of the view that the broadcaster and the DPO shall take utmost care at the time of publication of RIO at initial stage itself for offering of their channels or networks, as the case may be, so that it fully conforms to the provisions of the regulations and Tariff Order. All the necessary terms and conditions shall form part of the RIO so that the RIO when signed by the other party becomes a complete interconnection agreement. For this reason provisions relating to this aspect have been modified. In these regulations, it has been mandated that copy of RIO shall be submitted to the Authority for record. Needless to mention that, the stakeholders would have freedom to raise their objections on the RIO terms which are not in conformance with the regulatory framework at appropriate forum.

#### **Distribution Fee and Discounts**

74. In the draft Interconnection Regulations, 2016, comments were solicited from the stakeholders on the values/ rates specified for distribution fee and discounts offered by broadcasters on their pay channels and bouquet of pay channels. The distribution fee was proposed at the minimum rate of 20% of the MRP of a pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be. Further, the Authority proposed that a broadcaster may offer discounts on the MRP of a channel or bouquet to a DPO, to the extent that the sum of distribution fee and discounts do not exceed 35% of the MRP of such channel or bouquet. Similarly it was also proposed that a DPO may offer up to 35% discounts on the rate of carriage fee declared by such DPO. It is important to note that the proposed limit of 35% on the sum of distribution fee and discounts as aforesaid is only in relation to commercial terms between the broadcaster and the DPO and does not apply to the discounts that maybe provided by the DPO to the subscriber. Basic purpose of putting a cap on discounts on business to business transactions is to persuade service providers to declare realistic prices for their products/ services and ensure level playing field.
75. On this issue, a broadcaster commented that distribution fee should be 10% of the MRP and placement fee and marketing fee to be subsumed in the various discount parameters of broadcasters, with a capping of 15% and transparently disclosed in the RIO. While another broadcaster opined that the distribution fee should be reduced to 15% and discount on MRP be increased to 20% without altering the cap of 35%. On the other hand, most of the DPOs have suggested that instead of 20%, the distribution fee should be 55% as it was in CAS regime. One of the DTH operators has stated that the distribution fee of 20% will substantially squeeze the revenue generation capacity of the distributors and they will have to depend on the pricing strategy of broadcasters for their income. Further, they have also stated that the DTH operators incur a cost of around 4 to 5 % as collection cost. According to DTH operators, the collection costs are not borne by the MSOs. Accordingly, the distribution margin for the MSO would continue to be 20% however for DTH owing to the licence fee @ of 10% of gross revenue and collection cost, additional margin in the range of 5 to 6% should be provided.
76. In this regulatory framework, the price of network capacity has been separated from the price of channels. As per the Tariff Order, for recovering the cost of distribution of channels which includes subscriber management, the distributors are permitted to charge the network capacity fee. Therefore the contention of DPOs that they would

depend on pricing strategy of broadcasters for their income is not tenable. The distribution fee is for the purpose of managing the distribution of pay channel(s) or bouquet(s) of pay channels only. Keeping in view the facts that the DTH operators are required to pay the license fee to the Government, the expenses of the distributors involved in the collection and accounting of the payments, sharing of the distribution fee amount between MSOs and LCOs etc., the Authority has provided for minimum 20% of the MRP as distribution fee. The DPOs suggestion that instead of 20%, the distribution fee should be 55% as it was in CAS regime, is not tenable because at that point of time there was no separate network capacity fee payable by subscribers. This regulatory framework is not directly comparable to the earlier regulatory frameworks wherein the price of distribution and channel was combined.

77. In a business, the discounts on MRP of a product/ service provide flexibility to the suppliers to increase its sales by improving efficiency in the value chain. On the other hand very high level of discounts may become a source for discrimination and source of exploiting consumers. It was observed in the past that many times service providers, in their RIOs, declare very high rates for their products or services and then they offer deep discounts on such rates. Unreasonable amounts of discounts lead to illusionary/ perverse pricing and non-level playing field. The Authority felt it necessary to put a reasonable cap on discounts as absence of such prescription would hamper the commercial interests of various stakeholders and would be detrimental to choice of the subscribers. Therefore, there is a need to regulate such discounts so as to provide the same on transparent, measurable and non-discriminatory terms. Further, the Authority has agreed with the views of some broadcasters that maximum amount of discounts on prices declared in the RIO should be capped. This will help in declaring the optimum price for their services i.e. the price at which their gross revenues are maximised. This will also reduce the possibility of discrimination between the similarly placed service providers. The cap on discounts suggested by various stakeholders varies from 33% to 50%. Therefore, the Authority is of the view that the sum of distribution fee and discounts offered to DPO shall be restricted to 35% of the MRP. Similarly maximum discount on the rate of carriage fee offered by DPOs to broadcasters shall also be limited to 35%. Further, in the regulations, it has provided that any such discounts must be offered in the RIO on the basis of fair, transparent and non-discriminatory terms and the parameters of discounts shall be measurable and computable.
78. In the interest of public good, a provision has been made in these regulations which allow DPOs to offer discounts exceeding 35% of the rate of carriage fee to certain TV channels specified by the Authority through directions.

### **Carriage fee**

79. Charges paid by a broadcaster to a DPO for carrying its TV channel(s) over the DPO's network are commonly termed, by industry, as Carriage fee. The trend of carriage fee, started in analog era, was perhaps due to bandwidth constraints of transmission medium in cable TV systems. An analog cable TV system can generally carry around 80-100 channels while the number of channels available for broadcast are more than the network capacity. Though, in the addressable system, the channel carrying capacity has increased but at the same time, the number of permitted private satellite TV channels has also sharply increased. In order to increase the network capacity further, a DPO is required to upgrade its network infrastructure which entails additional cost for the DPO. In order to meet a part of such costs, carriage fee transactions took place between the broadcasters and DPOs.
80. The issue relating to carriage fee was deliberated in the consultation paper on tariff for TV services. In response to the consultation paper, majority of broadcasters were against the practice of carriage fee payments stating that capacity constraints in digitised networks are no longer a concern. They argued that with addressability there has been a steady increase in the subscription revenues and therefore the dependence of the DPOs on carriage fee should diminish. Another suggestion from the broadcasters was that the Authority must fix the carriage fee of a DPO based on the infrastructure cost incurred by that DPO with a cap on the annual carriage fee at 50 paisa to one rupee per channel per set-top-box.
81. On the contrary, the DPOs did not favour any regulation of the carriage fee and had proposed that carriage fee be decided based on mutual negotiations. They had stated that capacity of the distribution networks remains constrained even after the digitisation process and that carriage fee incentivise a DPO to add channel capacity and upgrade its network. One DPO has suggested that carriage fee be initially limited between Rs. 2 to Rs. 5 per channel per subscriber per month and be gradually reduced with an increase in the number of subscribers.
82. In the draft Interconnection Regulations, 2016, it was proposed that a maximum rate which a DPO may charge from a broadcaster for carrying of channel would be Rs. 0.20 per subscriber per month for SD channel (Re. 0.40 per subscriber per month for HD channel) calculated on the average active subscriber base of the target market and it would gradually reduce with the increase in the monthly subscription of the channel and it would become nil, if that particular channel achieves 20% penetration in that market and continues so.
83. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, most of the broadcasters have commented that there is no rationale for carriage fee, as in terms of Tariff order, network capacity fee is charged from consumers by DPOs. It was stated by a broadcaster that carriage fee must be co-related with the actual number of subscribers subscribing that channel and not on the subscriber base. While another broadcaster suggested that the carriage fee should be capped at 10 Paisa per subscriber per month. Some broadcasters commented that for calculating

carriage fee for certain sets of channels (e.g., English language GEC, Movies, News etc.), the target markets in terms of states should be allowed to be further subdivided into cities.

84. News broadcasters and their association commented that no carriage and placement/ marketing fee should be charged from the news broadcasters. Another news broadcaster also commented that in addition to capping of carriage fee, Placement Fee shall also be regulated and capped. A broadcaster suggested that to calculate carriage fee for HD channels, only HD subscriber base of a DPO in the target markets as declared by a broadcaster should be considered.
85. Most of the broadcasters have expressed their concern with the manner of calculation of carriage fee prescribed in the Schedule-I of the draft Interconnection Regulations 2016. Their apprehension was that with such type of calculations, the DPOs will not allow channels to reach beyond 20% subscriber base for their own carriage benefits as DPOs would never prefer a model where channels reach to a target of 20 % subscriber base in return of no carriage fees paid to them. Some news broadcasters stated that for free to air News Channels, all charges i.e. Carriage Fee/Marketing Fee/Placement Fee put together should be capped at Rs. 0.20/- per month per STB. However, an individual stated that the rate of carriage fee at Rs. 0.20 will effectively reduce the carriage fee component drastically, bringing great relief to the broadcasters.
86. Most of the DPOs have suggested that there should not be a slab system in the calculation of carriage fee; this takes away the right of DPOs to package. One DPO has stated that carriage fee transaction is of Business to Business (B2B) nature therefore regulating it is not in the interest of subscribers. Most of the DPOs have suggested increasing the carriage fee cap from 20 paisa to 80 paisa and from 40 paisa to Rs.1.20 paisa for SD and HD channels respectively.
87. In this regulatory framework, as per the Tariff Order, for recovering the cost of distribution of channels the distributors are permitted to charge the network capacity fee. This amount would vary based on the number of channels subscribed by individual subscriber. Therefore, it is expected that a DPO would seek signals of channels which are in demand in a particular market. For such channels, a DPO cannot demand for a carriage fee as it would be able to recover retransmission expenses from the network capacity fee charged from the subscribers. However, for carrying channels, which have been requested by a broadcaster, a DPO may not be able to recover fully the retransmission expenses from the network capacity fee charged from the subscribers till the channel is subscribed by sufficiently large number of subscribers. In order to fill the gap between the retransmission expenses incurred by a DPO on carrying a particular channel on its platform and network capacity fee amount charged from subscribers it would be reasonable to permit a DPO to charge carriage fee to that extent from the broadcaster of that channel.
88. The Authority agrees with the views of some broadcasters that a cap on carriage fee rate is necessary to effectively implement the principles of 'must carry'. In the past, on many occasions, the carriage fee data was sought from broadcasters. But the broadcasters have failed to give segregated data for carriage fee. Instead they had provided a mixed data which included carriage fee, placement, marketing fee, technical fee, bandwidth support and other fee making it impossible to clearly distinguish the data pertains to carriage fee paid to cover the cost of re-transmission of channels on the platform of DPOs.
89. Since the segregated data for carriage fee alone was not available, the Authority has taken into account various sources, which are relevant, to arrive at a cap for carriage fee. In case of free to view DTH service operated by Doordarshan, for acquiring capacity for carrying one channel on the DTH platform, the reserve price was kept at Rs. 4.30 Crores, as per the RFP published in 2016. As per the industry estimates, there are 20 to 30 million consumers availing DD free dish service. Which indicates that the per channel cost of carrying a channel is Rs. 2.15 per year, considering 20 million subscribers, equating to around Rs. 0.18 paisa per subscriber per month. Further, the mixed data relating to carriage fee and others available with the Authority and in public domain have also been analysed. This analysis also supports the proposed cap for carriage fee. The Authority is conscious of the fact that the rate of carriage fee varies with the changes in the input cost incurred for erection, operation and maintenance of the distribution networks and number of subscribers. Therefore the cap on carriage fee should be reviewed on periodic basis say in every 2 to 3 years period. In case of some material changes in the input costs, the review can be initiated early also.
90. Thus, the Authority came to a conclusion that the carriage fee rate shall in no case exceed Rs. 0.20 per channel per subscriber per month. Since the bandwidth consumed by HD channels is approximately double the bandwidth required for SD channels therefore the Authority has kept the ceiling of carriage fee as Rs. 0.40 for HD channels. The DPOs may declare the rate of carriage fee in their RIOs within the prescribed cap for this purpose to optimise their revenues.
91. In this framework, the provision 'must carry' has been enshrined keeping in view the channels whose presence is not known by the subscribers. In order to expand its reach, the carriage fee will enable broadcasters to interconnect with DPOs in a desired target market. There are six private DTH operators which are having capacity of carrying around 400-600 channels on their platforms. The majority of MSOs are having capacity ranging from

300-600 channels. The Authority in the tariff framework has decided that the network capacity amount to be charged by the DPOs from the subscribers, to recover the distribution expenses. In the framework, a DPO has been assured for a network capacity amount for 100 channels from the subscribers. Further, the network capacity fee increases with the increase in subscription of channels.

92. When the real choice will become available to subscribers, the number of channels subscribed by a household may vary in the range of 80 to 120 channels which come out to be approximately 20% of the average platform capacity of a DPO. Therefore if a channel attains 20% of the subscriber base it can be reasonably assumed that the said channel is demanded by the subscribers which is equivalent to a channel being carried under 'must provide' which do not attract any carriage fee. Therefore the Authority is of the view that, in case a channel gathers popularity and wider viewership, the quantum of carriage fee should diminish owing to the increased revenues accruing from subscriptions by the DPO for that channel. Further, the carriage fee payment must decrease with the increase in the subscription level of a channel even before reaching 20% penetration level as the network capacity fee paid by subscribers also contributes towards recovering the retransmission expenses.
93. For ease of computation, the Authority has decided that in a given month, if the monthly subscription of the channel reaches 5% or more but below 10%, of the monthly average active subscriber base of the DPO in target market, there should be, a reduction of 25% in carriage fee amount payable by the broadcaster in that month and, a reduction of 50% in carriage fee amount in case the monthly subscription of the channel reaches 10% or more but below 15% of the monthly average active subscriber base and, a reduction of 75% in carriage fee amount in case the monthly subscription of the channel reaches 15% or more but below 20%, of the monthly average active subscriber base. If the monthly subscription of channel reaches 20% of monthly average subscriber base in a given month, then the DPO shall not charge any carriage fee for that month.
94. The Authority observed that, a channel reaches to all the subscribers in the geographical area covered by a particular head end or the earth station installed by a DPO. Therefore, it is legitimate expectation on the part of DPOs to calculate the carriage fee amount by considering the monthly average active subscriber base of the head end or the earth station. The Authority also observed that a particular head end covers more than one state and therefore restricting the target market area to the boundaries of state will not be reasonable. Therefore, the Authority has decided that every DPO shall declare coverage area of each distribution network head end wise or Earth station wise as a target market. However, to meet the specific needs, it shall be permissible for a distributor to declare, in non-discriminatory manner, any area within the coverage area of distribution network(s) as a target market(s).
95. In respect of HD channel, the Authority observed that the HD channels can be seen only if a subscriber's STB is capable of receiving HD signals. Therefore, for carriage of HD channels the average active subscriber base of the distributor, capable of receiving HD TV channels should be considered. Accordingly provision has been made in the regulation that for arriving the carriage fee of HD channels, the average active subscriber base of the DPO in that month in the target market shall be of subscribers capable of receiving high definition television channels. The apprehension expressed by some broadcasters in their comments that the DPOs will not allow channel reach beyond 20% for their own carriage benefits is not tenable as it is in the interest of DPOs to get more network capacity fee and subscription fee from distribution of channels. Moreover, if the channel is attractive, the subscriber would like to subscribe such channels. The DPOs cannot deny subscriber choice.

### **Placement**

96. In addressable systems, the technology provides for an Electronic Program Guide (EPG) wherein the channels being carried on a DPO's network can be arranged in a simple and easy to understand manner so that the subscriber can easily go through this guide and select the channel of choice instead of flipping through all the channels. In the draft Interconnection Regulations, 2016, the DPOs were mandated to list all the channels available on the platform in the EPG, in such a manner that a consumer can easily select the channel of its choice. The genre and language wise listing of TV channels in the EPG was proposed in the draft Interconnection Regulations, 2016 to ensure placement of a channel among similar channels. Further, in the draft, it was proposed that the broadcaster cannot put any pre-condition for providing signals to the DPOs to place his channels at a particular position in the EPG or to assign a particular number to his channel as such stipulation may not be practically possible to implement. For example, if any two broadcasters insist for same position in the EPG as a pre-condition before providing signals of their TV channels then it is not practically possible for a DPO to meet the pre-condition.
97. In response, most of the broadcasters opined that the placement of channels and placement fee should be brought under the ambit of regulatory framework. As per them, non regulated placement and marketing fee makes the model non-transparent and create a back door entry by allowing negotiated agreements between DPOs and broadcasters for LCN.

98. In these regulations the broadcasters have been given a complete freedom to declare the genre of their channels and in terms of the regulations, it has been mandated that a DPO shall place the channels in the EPG under the respective genres so declared by the broadcasters. Further it has also been mandated that DPOs shall place the channels of the same genre in such a manner that all TV channels of same language within the same genre shall appear together consecutively in the EPG. In order to curb the practice to frequently change LCN number, it has been mandated that LCN number once allocated will not be changed for duration of at least one year. Therefore, the placements of channels have been adequately regulated and necessary protection has been granted to the broadcaster so that their channels are not placed at any disadvantageous position in the EPG. Hence as such there is no requirement for a broadcaster for asking for a specific position in the EPG.
99. In the new regulatory framework, emphasis has been increased on consumer choice. Therefore, when consumers will choose only selected channels which they actually want to view, the importance of placement of channel reduces drastically. Further, in the regulatory framework, the carriage and placement have been clearly distinguished. The carriage fee as per demand of the stakeholders has been regulated and must carry provisions would ensure the access to the distribution networks in non-discriminatory manner. Earlier, these two kinds of fees were clubbed together by service providers and non payment of combined fee could have denied a channel the access to the network. Now the same will not be possible. Mandating provision for discount within ceiling of 15% for allocation of placement or LCN as some percentage of channel price (MRP) may not serve the purpose as it will create a non level playing field for pay channels vis-a-vis FTA channels as in case of FTA channels the MRP is nil. However, in case, a broadcaster still wishes to place its channel at a particular position or a specific number assigned to its channel, subject to the provisions of these regulations, the broadcaster may offer discount within the prescribed framework or pay the mutually agreed fee, after signing the interconnection agreement, to a distributor for placing the channel. It is important to note here that such interconnection agreements, signed for placement of channels, shall also be non-discriminatory. Such agreements, if any, shall be appended with the main interconnection agreement and would be filed with the Authority as per the regulations notified by the Authority from time to time. It will ensure the transparency.
100. It is noted that in the comments received from the stakeholders and the agreements entered by service providers, varied terms like marketing fee, bandwidth support fee, channel visibility fee etc. are used for different purposes and commercial arrangements between broadcasters and DPOs. Any such commercial arrangement is a type of interconnection agreement and therefore it has to be on non-discriminatory basis. Therefore, to avoid the regulatory gaps, it has been mandated that in case more than one interconnection agreement are entered with a distributor of television channels in respect of television channel(s) or bouquet(s) of pay channels, each subsequent interconnection agreement shall contain the details of the earlier agreements in force with that distributor for such channel(s) or bouquet(s).
101. It is also observed that many times a fee in the name of marketing is paid by a service provider to other service provider for the promotion and advertisement of its services. Sometimes broadcasters provide incentives to the distributors for inclusion of channels in the bouquets offered by the DPO in the name of marketing. In these regulations, the Authority has clearly mandated that no incentive, in whatsoever name, can be given by the broadcaster to the DPO for inclusion of its channels in the DPO's bouquet because it results in pushing of channels to the subscribers. The marketing fee towards promotion and advertisement of services contributes towards increase in business which is due to the effort of the two parties. Therefore, there cannot be a specific parameter for regulating such fee. Hence, at this stage, any regulation by Authority on such fee is bound to be a porous regulation. Still the Authority has permitted that a service provider may offer transparent discount to the other service provider out of the limit of 15% if it is mutually agreed. However it has been decided that any agreement, for any kind of fee for a channel, between two service providers should be made part of interconnection agreement and reported to the Authority to enable the Authority to monitor the industry practices.

#### **Audit of Addressable System before Provisioning of Signals**

102. The Authority in its earlier regulatory framework had prescribed technical audit methodology before provisioning of signals. In the CP, the issues in the current methodology of technical audit of addressable systems and need to review them were discussed.
103. In response to CP, broadcasters opined that before any license is granted by MIB a mechanism should be introduced to ensure that any applicant seeking license to operate is completely compliant of addressable system requirements. A DTH operator commented that the responsibility of audit lies with the broadcaster however such audit should be restricted to once a year and added that technical audit for each new channel should not be conducted every time. Another DTH operator stated that if the broadcaster intends to do the technical audit, it should be done either after providing the channel or simultaneously, and opined that TRAI or TDSAT or appropriate forum should take action against erroneous parties. Some DPOs opined that onus of audit should not lie with broadcasters and suggested that TRAI can publish a list of authorized auditors who can be approached by DPOs to get its CAS and SMS independently verified. Some DPOs commented that broadcaster should be mandated to complete audit within 15 days else issue IRDs after signing the interconnect agreement within next 15 days. An MSO and an LCO association stated that if a platform is inspected by BECIL/authorized agency, then

no objections should be raised however, if no such inspection is done, broadcasters should audit in 30 days. Taking into account of the suggestions and concerns of the stakeholders certain clauses were proposed in the draft Interconnection Regulations, 2016.

104. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, broadcaster association stated that the broadcaster should be given the right to conduct the audit of the technical systems of DPOs through its own technical team; BECIL or empanelled auditor may be appointed only in case of dispute between the parties. They have argued that DPOs can take advantage and tamper with the systems later on the pretext that there systems are audited by BECIL and in terms of draft regulations the same cannot be challenged by broadcaster since it is valid for a period of one year. Some broadcasters commented that Audits should be conducted quarterly and not limited to once a year, to bring in 0% discrepancy and transparency in the system. While another broadcaster submitted that 1st Audit should be conducted in presence of broadcaster representative by an Audit firm decided by IBF or any broadcaster industry body.
105. The Audit of the systems of DPO is necessary to ensure that the systems deployed by a DPO are addressable as per the regulatory requirement. To ensure that the audit does not delay the process of getting signals of TV channels, it is desirable that the DPO ensures that the addressable system installed by it meets the requirements specified in regulations. It is also important that the broadcaster assure itself that the addressable systems of the DPO meet the minimum requirement as specified in the regulatory framework. In order to balance the requirements of broadcasters and DPOs, the Authority is of the view that the onus of carrying out audit should lie with the broadcaster, however, to ensure that the audit should not delay the process of providing of signals of TV channels, a mechanism needs to be devised. Accordingly, suitable provisions have been brought in these regulations. These are explained in the following paragraph.
106. To speed up the process of auditing, the Authority has decided that it may specify a panel of auditors from which broadcasters may choose any one. Once a distribution system is audited and certified by an empanelled auditor, it is only logical that other broadcasters will also have to accept the same for at least one year period from the time of issue of certification. This will not only reduce burden on the service providers but also reduce number of audits. However, in the event of any change in configuration or version of the addressable systems installed, to check that the system remained in conformance with the requirements specified in Schedule III of these regulations, it would be permissible to the broadcaster, before providing signals of television channel(s), to cause audit of the addressable systems of the distributor even if the addressable systems of such distributor have been audited during the last one year.
107. In case a broadcaster is unable to complete the audit in time for reasons attributable to DPO, due to which it is unable to provide signals of TV channels within the prescribed period of 60 days from the date of the request for providing signals of TV channels, the same should be communicated to the DPO within such prescribed time period.
108. It has also been provided that if in the opinion of a broadcaster the addressable system of a DPO does not meet the requirement of the regulations then the broadcaster may audit the system of DPO not more than once in a calendar year. However, it is clarified that the broadcaster can carry out the audit only once a year after provisioning of signals of TV channels to the DPO for the purpose of checking the conformance of the addressable systems and/or to verify the subscription reports submitted by the DPOs. Accordingly provisions have been made in these regulations. Further, it has also been provided that if a DPO's system does not meet the requirements for addressable systems, the broadcaster may disconnect its signals to such DPO after giving a 3 weeks written notice for the same to the DPO.

#### **Minimum Technical Specification for Addressable Systems**

109. The Authority in its earlier framework had prescribed minimum technical specifications for addressable systems in respect of SMS, CAS, and STBs etc. These technical specifications primarily ensure the addressability and transparency, and help in preventing piracy. In the CP, the Authority sought the inputs of the stakeholders on updating the specifications, if required, due to the progress in technologies. On the issue, most of the stakeholders were of the opinion that existing technical specifications by TRAI need a review in line with the current market scenario. In the draft Interconnection Regulations, 2016, after considering the comments of the stakeholders and internal analysis, some amendments and additions were proposed to further strengthen the quality and standards of systems installed by the distributors.
110. In the draft regulations, the requirement of SMS with capability of minimum 1 million subscribers was dropped as there could be many MSOs who will serve smaller subscriber base. To ensure that each DPO have right sized systems in place, a provision was added which mandated that the system deployed should be capable enough to carry out activation of at least 50% of the subscriber base within 24 hours.
111. Most of the broadcasters have stated that the specification needs to be further strengthened to ensure that piracy does not happen. One DPO has stated that the condition that the addressable system deployed should be capable

enough to carry out activation of at least 50% of the subscriber base within 24 hours is very stringent and the requirement should be reduced to 10%.

112. After considering the comments received from the stakeholders, some of the provisions have been further strengthened which are required for increasing transparency in the system and controlling piracy. In line of the suggestions received, the requirement of carrying out activation of at least 50% of the subscriber base within 24 hours has been revised to 10%.

#### **Territory of Interconnection Agreement**

113. To enable organic growth, provisions were made in the draft Interconnection Regulations, 2016, wherein it was mandated that the interconnection agreement signed between a broadcaster and a DPO should contain the licensed/ permitted / registered area of operation of the DPOs as mentioned in the license/ permission / registration granted by the Government; the names of specific areas for which distribution of signals of television channel(s) has been agreed, initially, at the time of signing of the interconnection agreement and the names of the corresponding state(s)/ union territory (ies) in which such agreed areas are located. It was provide that the DPOs could re-transmit signals of television channel(s) of a broadcaster in other area(s) by giving a prior written notice of at least thirty days to the broadcaster, provided that such area(s) falls within the state/UT mentioned in the interconnection agreement.
114. In response, some broadcasters commented that for such expansion, a prior notice of at least 60 days should be mandated and it must be subject to written agreement and not merely on the basis of a written notice by the DPO. While another opined that such expansion should not be allowed as it would be detrimental to the broadcaster, and would lead to unaccountability, therefore fresh agreement needs to be executed for the new areas. It was also stated that unrestricted movements of DPOs may cause disputes between competing DPOs. One of DPO has suggested reducing the notice period to 15 days.
115. The Authority noted that in non-addressable systems, due to the requirement of specific assessment on the basis of a ground survey for number of subscribers before entering into interconnection agreement for a territory, separate agreements were required. These requirements no more exist after the emergence of the addressable systems and recording of subscriber details in the SMS. It is in the interest of broadcasters that reach of their channels is increased so that they get better subscription revenue as well as the advertisement revenue. Necessary provisions can be made at the time of signing in the interconnection agreement that intimation notice issued under the agreement for expanding territory, as per the regulations, would become part of the agreement; and all terms and conditions of the agreement would apply for expanded territories also. Further, it is in the interest of MSOs also as they can plan their area of operations without much difficulties. The argument that the unrestricted movements of DPOs may cause disputes between competing DPOs is not tenable as any DPO is free to expand its operations within the permitted area under registration. This would provide more options for the consumers also. Therefore it is win - win for everyone and it would improve the ease of doing business in the sector. In these regulations, a time period of 30 days have been provided for the entering into written interconnection agreement, therefore, the Authority is of the view that, DPO may expand distribution of signals of TV channels after completion of 30 days period from the date of receipt of such notice by broadcaster. The broadcaster will have liberty to raise written objection on such expansion during the said 30 days notice period. The notice of expansion shall deem to be an addendum to the existing interconnection agreement. Any unreasonable objection by the broadcaster shall be deemed as denial of request form the DPO.

#### **Interconnection Agreement between DPO and LCO**

116. In DAS and HITS services, the last mile connectivity is mostly provided by Local Cable Operators (LCOs). In terms of the IPTV licensing guidelines issued by the Government, the LCOs can also provide last mile connectivity for IPTV service providers. Efficient interconnection arrangements between a DPO and an LCO are vital for delivering services to the subscribers. LCOs play a very important role in the value chain for meeting the quality of service norms for the subscribers. LCOs, like any other entity in the value chain, are registered service providers. As per the Cable TV Act and Rules made there under, LCOs are registered in the head post office of the area of their operation. The fundamental principles of non-exclusivity, must provide, non-discrimination, written agreement, and time bound provisioning of signals applies to interconnection arrangement between a DPO and an LCO as well.
117. In the CP, on the issue relating to interconnection between DPO and LCO, stakeholders were asked to provide their opinion as to whether framework of Model Interconnection Agreement (MIA) and Standard Interconnection Agreement (SIA) as it was mandated in terms of Interconnection Regulations, 2012 should be made applicable for interconnection between DPOs and LCOs providing broadcasting services through addressable systems. After considering the comments of the stakeholders and internal analysis, in the draft Interconnection Regulations, 2016, it was proposed that the regulations applicable for interconnection agreement between MSO and LCO shall also apply mutatis-mutandis for interconnection agreement between HITS / IPTV operator and LCO. Further, the settlement of service charges between LCO and DPO shall be governed by mutual agreement. Provided that in



cases where the DPO and the LCO fails to arrive at a mutual agreement for settlement of service charges, then the network capacity fee amount for subscribed channels and the distribution fee was to be shared in the ratio of 55:45 between MSO and LCO respectively.

118. On the issue of revenue sharing, one LCO stated that the complete network capacity fee amount should be charged by LCOs as LCOs are the one who are providing last mile connectivity through their network of coaxial cable and optical fibre. LCOs have no other source of income apart from subscription revenue, where as DPOs have other revenue sources such as advertisement on local video channels, placement of free to air channels and carriage fee. They further stated that LCOs have to maintain their network for good quality of service and give salaries to its workers and pay electricity bills to give uninterrupted service to its subscribers. Accordingly, in order to compensate this cost of collection and remittance and maintenance of network, the Authority should decide that broadcasters will provide twenty percent (20%) distribution fee to LCOs for collection and remittance of pay channel revenue and not to DPOs.
119. The framework of MIA and SIA which provide enough flexibility and ample freedom to the parties to the agreement to carry out their business. They may enter into an interconnection agreement, for provision of broadcasting services to subscribers, by mutually agreeing on distribution of responsibilities, respective settlement of service charges and billing. Further it has been provided that in case of failure of mutual discussions, as a fall back option, the interconnection agreement will be signed in terms of SIA wherein the Authority has demarcated the responsibilities and fixed the corresponding settlement of service charges between DPO and LCO. In the SIA, LCOs have been given the consumer centric responsibilities whereas the MSOs have been given the responsibilities which are directly linked with the SMS including billing for the subscribers.
120. In the addressable systems, the SMS contains database regarding the subscriber base and the channels/ bouquets subscribed by each subscriber. This database is verifiable and auditable. Under the provisions of MIA and SIA, the access of the corresponding SMS database has been extended to link LCOs. With these details, the exact subscription details are known to the DPO as well as to the LCOs connected to the DPO. The service charges need to be settled on work done principle. However, the distribution of responsibilities and costs of maintaining the distribution networks, of DPOs as well as LCOs, vary on case to case basis. The sources of revenue and associated expenses of DPOs also vary on case to case basis. Keeping in view these dissimilarities and the transparency inbuilt into the addressable systems, the Authority is of the view that DPO and LCO settle the service charges, based on mutual discussions. To protect the interest of service providers and to ensure that signals are not disrupted due to dispute between the service providers, the Authority has prescribed a fall back arrangement between DPO and LCO, only for cases where the mutual discussions fail between DPO and LCO; and still they want to continue their relationship.
121. The LCO in the value chain provides last mile connectivity to subscribers and he should be able to recover the expenses incurred and earn a reasonable amount of profit. The argument of an LCO that the complete network capacity fee amount should be charged by LCOs as LCOs are the one who are providing last mile connectivity through their network of coaxial cable and optical fibre is not tenable as the distribution of TV channels involves the systems and networks of DPO also. Further, the argument of LCO that in order to compensate their cost of collection and remittance and maintenance of network, the Authority should decide that broadcasters will provide twenty percent (20%) distribution fee to LCOs for collection and remittance of pay channel revenue and not to DPOs is also not tenable as distribution of pay TV channels involves the services of DPO as well as link LCO and LCOs do not have any direct relationship with broadcasters. In this framework network capacity resembles the FTA only subscriptions of erstwhile regulatory framework and these two requires the similar kind of resources for delivery of services to subscribers. Keeping in view the fact that in terms of the Interconnection Regulations, 2012, in a fall back arrangement, the service providers were required to share the subscription revenue in respect of FTA only subscriptions in the ratio MSO::LCO as 55::45, the Authority has decided to prescribe the same ratio for sharing of network capacity fee amount. In respect of pay channels also since in this regulatory framework, the charges for services involved in the distribution of pay channel has been separated from the pay channel price, the distribution fee, which corresponds to the charges for services, of DPO and link LCO together, involved in the distribution of pay channels, has been distributed in the same ratio.

### **Subscription Reports**

122. In addressable systems, the number of subscribers of a channel or a bouquet of pay channels is auditable and verifiable. The Interconnection Regulations, 2004 and the Interconnection Regulations, 2012 contained provisions relating to subscription reports for addressable systems.
123. On many occasions, complaints were received that DPOs do not provide subscription reports in time to broadcasters. On the other hand, DPOs often complained that broadcasters do not have a common format for subscription report and it becomes practically difficult for them to generate customized reports each time for individual broadcaster.

124. DPOs also informed that quite often broadcasters seek subscription information that do not relate with the channel of that particular broadcaster. On the manner of calculation of monthly subscription numbers, broadcasters had many times expressed their concerns that the subscription report prepared as per erstwhile regulatory framework may not include those subscribers who remained active for less than 30 or 31 days, as the case may be, in a calendar month. This can put them at a commercially disadvantageous position. These issues were discussed in detail in the CP.
125. The Authority is aware of the fact that the timely availability of correct subscription reports is fundamental to ensure revenue of the stakeholders in the value chain and orderly growth of the sector. Any delay in subscription report affects the billing cycle and cash flow in the value chain. After considering the comments of the stakeholders and internal analysis, in the draft Interconnection Regulations, 2016, a schedule was inserted which prescribed the format of subscription report and the methodology for calculation of subscription numbers. For ensuring the timely availability of subscription report, a provision was made in the draft regulations wherein the DPOs were mandated to provide subscription report within 15 days from end of each calendar month. In the event of non- receipt of subscription report from DPO due to any reason, a right was given to the broadcaster to issue a provisional invoice, for an amount increased by 10% of the 'broadcaster's share of maximum retail price' payable by the distributor for the immediate preceding month, and the distributor was put under obligation to make the payment on the basis of such provisional invoice. Further, to avoid bill shocks, it was proposed that invoice raised by a broadcaster shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any. For deterrence, a provision was made that the broadcaster shall have no claim on any arrear amount which has not been specified by him in the immediate next three consecutive invoices issued after the due date for the invoice to which arrears pertain.
126. In response to the draft Interconnection Regulations, 2016, on the aspect of time period for capturing subscription count between 19:00 HRS to 23:00 HRS of the day, some broadcasters stated that the Authority should consider revising the time period for capturing information between 7 PM to 9.30 PM. Some broadcasters opined that the time of 15 days provided for generation of subscription report should be reduced to 7 days. A broadcaster association stated to remove the provision relating to arrears in the invoices and restore their legal right to claim their arrears at any time. The broadcasters have stated that there should be a provision of security deposit. In case of non-submission of reports, a broadcaster suggested that disconnection should be allowed after 1<sup>st</sup> month itself.
127. On the other hand, some MSOs and its association have suggested that capturing of subscription count 4 times in a month is cumbersome and it will also put strain on SMS and CAS impacting the performance of the system. As per them, the current procedure of capturing of subscription count at the beginning and end of the month is fine.
128. On the suggestion of some of the stakeholders regarding changing of time period for capturing of information, it is noted that the subscriber count is not dependent on the channel being viewed by a subscriber but it depends on the fact that which channels which have been authorised for viewing to a subscriber. Therefore, change in timing of the capturing of the report would not make any difference in the subscriber numbers. The proposal is for prime time. Therefore no change is required in the proposed time period. As far as capturing of the data from CAS and SMS 4 times in a month is concerned, it is noted that the CAS and SMS can be pre-programmed to capture the data automatically and no manual effort is required. Therefore mandating increased periodicity for capturing data and reporting on the basis of captured data 4 times a month would help the service providers to monetise their products on closer to actual subscribers. On the issue of reducing time for sending subscriber reports, the Authority is in agreement with the view of stakeholders and therefore it has been reduced to 7 days from the end of each calendar month. If the DPO fails to provide the monthly subscription report then the broadcaster may disconnect the signals of TV channels after giving prior notice of 3 weeks to the DPO. This provision would help in ensuring the timely availability of the subscription report to the broadcaster. The broadcaster may also issue a provisional invoice for an amount increased by 10% of the 'broadcaster's share of maximum retail price' for the immediate preceding months, in case the DPO fails to issue the subscription report on time. It has also been mandated to the service provider to carryout reconciliation with 2 months. This is expected to bring in the discipline in the sector.

### **Audit**

129. In the draft interconnection regulation, 2016, the Authority proposed a methodology for audit for the purpose of verifying the information contained in the subscription reports. The DPO was required to conduct subscription audit of its systems by any one empanelled auditor and send the report to the broadcaster. It was provided that in case the broadcaster feels that the conduction of audit is necessary to protect its business interests then the broadcaster may, not more than once in a calendar year, audit the SMS, CAS and other related systems of the DPOs. In order to deter and discourage any kind of discrepancies and manipulation in the subscription reports provided to the broadcasters, Authority had proposed that the cost of audit would to be borne by the DPO if the difference in audited and reported subscription figures is more than 2%, otherwise the broadcaster seeking audit of subscription report shall be liable for audit fee payment. However, it was provisioned that any variation, due to audit, resulting in less than 0.5% of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid.

130. In response, one broadcaster stated that the discrepancy of 0.5% in the subscriber report should not be neglected. On the other hand, MSOs and its association have stated that it is impossible to maintain perfect harmony between CAS and SMS as there are many factors which can hamper the accuracy, and suggested to increase the discrepancy percentage to 2.5-3% from 0.5 %. However they have not given any justification for the same. One MSO has suggested that the cost of audit shall be borne by the broadcaster only and not by DPO under any circumstances. Some broadcasters suggested that in case of any discrepancy there should be a provision of penalty of at least 20% of monthly 'broadcaster's share of maximum retail price'.
131. Proper and accurate subscription report is very important as the settlement of charges between the service providers is based on such reports. Audit of systems is a tool to verify the correctness of data and systems specification as per the requirements under the regulations. Moreover allowing audit of addressable systems will help in confidence building measure in the value chain. Therefore, a mechanism is required to be put in place for audit of such addressable systems. The Authority is of the view that if a DPO gets its system audited from an auditor for the purpose of verifying subscription reports and sends these reports to the broadcasters then the problem of multiple audits can be solved significantly. This will also reduce the burden on the broadcasters and DPOs. The concerns of some broadcasters that after initial audit, a DPO's system may not remain compliant with the technical specification and therefore, the right of audit should be given to the broadcaster has been considered by the authority. It has been provided that if a broadcaster is not satisfied with the audit report received or, if in the opinion of a broadcaster the addressable system being used by the distributor does not meet technical requirements specified in **Schedule III** then the broadcaster may, after communicating the reasons of dissatisfaction in writing to the DPO not more than once in a calendar year, audit the SMS, CAS and other related system of the DPOs. The provisions of this regulation provide a level playing field to all the stakeholders and also help in reducing burden and litigations. As far as, allowing discrepancies of 0.5% is concerned, it is noted that such variation may happen due to system limitations resulting in a difference between the actual number of subscribers and reported subscriptions on some occasions. Therefore, revising invoice would delay the payment settlements. However, the stakeholders should undertake utmost care that such discrepancies should not occur on regular basis. On the suggestion of the broadcaster regarding penalty, it has been provided that a broadcaster may levy interest on the payable amount and if such amount including interest exceeds by 2 % then the DPO shall bear the broadcaster's audit expenses. The Authority has at this stage not specified any further penalty as such discrepancy needs case to case examination and proof of evidence in the appropriate forum.

#### **Disconnection of Signals of TV Channels**

132. Disconnection of signals of TV channels is one of the issues, where the interest of consumers also needs to be safeguarded along with that of the broadcasters and DPOs. In the past instances have been observed where, due to dispute between the service providers, signals by a broadcaster or DPO are cut off, leaving consumers in the lurch. The Interconnection Regulations 2004, as well as the Interconnection Regulation 2012, had a provision where the service providers were mandated to give a prior written notice of 3 weeks to the concerned service provider before disconnection of signals of TV channels. Further in these regulations a provision was also available which mandates service providers to publish information regarding disconnection of TV channels through News papers. The requirement of publication of information regarding disconnection in the News papers was removed in the draft regulations 2016, as such notifications in local/regional newspaper often go unnoticed by the targeted subscribers due to their limited reach. Further, while retaining the notice period of 21 days to the service providers, the requirement of publication through scrolls on the concern channel was proposed to protect the interest of consumers
133. In response, an MSO opined that the compulsory provision of publication of notice in the news papers should be continued as was mandated in the past regulations. He argued that in event of proposed disconnection, the broadcasters/MSOs may send a normal communication to the MSOs/LCOs respectively which may result in surprise disconnection of channel. A broadcaster commented that for intimating subscribers regarding non-availability of channels on the platform, DPOs should not be allowed to run scrolls on broadcaster's channels; but the scrolls should be allowed to run only on DPO's home channels.
134. Broadcasting industry is a consumer centric industry. In no case, a consumer, who has not defaulted, should bear the brunt of the disputes or non-agreements between the service providers. The Authority observed that it is necessary to protect the interests of consumers as well as service providers in the event of disconnection of signals of TV channels due to any reason. Therefore, the time of three weeks provided in the erstwhile regulation has been retained in these regulations. This period will allow the affected parties to look for possible solutions to prevent disconnection. On the suggestion of continuance of the publication of information regarding disconnection through news papers, the Authority is of the view that the mandate of publication of news paper notice increases burden on the service providers without much impact on the consumers as such notifications in local/regional newspaper often go unnoticed by the targeted subscribers due to their limited reach. On the aspect of running scrolls about the disconnection of channel it is mentioned that such communication is more effective to protect the interest of consumers. Therefore the Authority is of the view that it would be the responsibility of DPO

to inform the subscriber 15 days prior to the date of disconnection through scrolls on concerned channels. To ensure that such scrolls or information do not hamper the viewing experience of the subscriber or obstruct normal viewing of the channel, any display of information in form of static images overlaid on the television screen has been prohibited.

#### **Listing of Channels in Electronic Programme Guide**

135. In addressable systems, the technology provides for a Electronic Program Guide (EPG) wherein the channels being carried on the DPO's network can be arranged in a simple easy to understand manner so that the subscriber can easily go through this guide and select the channel of choice instead of flipping through all the channels. The EPG also assigns a channel number to each TV channel available on the platform. In the draft Interconnection Regulations, 2016, it was proposed that every DPO should assign a channel number for each television channel distributed by him in such a way that the TV channels of same genre are placed together consecutively and one channel appear at one place only. Further, it was proposed that the number assigned to a television channel shall not be altered by the distributor for a period of at least one year from the date of such assignment.
136. In response, most of the broadcasters stated that channels should be listed in the EPG as per the last 12 months average of Broadcast Audience Research Council (BARC) rating. They opined that channels with higher ratings should be placed at the top of LCNs (Logical Channel Number) allocated to a particular genre of channels and this exercise can be repeated annually. A news broadcaster suggested that there should be sub-categorization within genre like Hindi, English, Business channel, Regional etc. While another news broadcasters commented that after new Regulations come into effect *status quo* should be maintained for LCNs allotted channels and DPOs should not be allowed to change LCNs, unless the overall genre series is changed, and even then, the sequential position of the channel should remain the same in that genre while any new additions should be in the chronological order in that genre.
137. Some DPOs stated that in the cases of disconnection of TV channels for any reason, DPO should not be obligated to provide the same channel number again to the broadcaster if the channel comes back again on the platform. One DPO stated that the period mandated for assignment of channel number should be reduced from 1 year to 6 months.
138. The issue of genre classification was well articulated in the consultation paper titled as "Tariff Issues related to TV Services". In the draft Tariff Order, seven genres were proposed and complete freedom was given to the broadcaster to classify their channels in any of the proposed genre. In terms of these regulations, the DPOs have been mandated to place the channels in the genre so declared by the broadcasters. There are around 800 TV channels in the country. If every broadcaster is allowed to create its own genre then there would be an unmanageably large number of genres which would cause great hardship and inconvenience to the consumers as it would be next to impossible for a consumer to scroll through EPG having lot of genres on their TV sets. Thus the proposal to allow broadcasters to create their own genres will be impracticable. Therefore the Authority has mandated that the broadcasters should declare the genre of its channel in any of the specified eight genres. To provide the flexibility to the broadcasters, miscellaneous genre has also been specified.
139. Proper listing of channels in the EPG helps the subscribers in selecting the channel for the purpose of viewing. If the channels are listed on the basis of Television Rating Point (TRP) then it may cause change in the position of the channels from time to time based on the television rating point which will create annoyance to the subscribers who generally remembers the position of the channel in the EPG under a genre. Therefore, the listing of channel on the basis of TRP is not being mandated and it is left open to the distributor to decide listing of channels within the prescribed framework. The Authority is in agreement with the views of some of the stakeholders that sub-categorisation will help the consumer in selecting the channel of its choice for viewing and therefore the Authority has mandated the DPO to place channels in the EPG, in such a way that the TV channels of same genre, as declared by the broadcaster, are placed together consecutively and all TV channels of same language within the same genre shall appear together consecutively in the electronic programme guide.
140. The consumer generally remembers the channel number and enters the channel number on his remote for viewing that channel. Frequent changes in the channel number assigned to a particular channel causes inconvenience to the subscribers. It has also been observed that many broadcasters advertise their TV channel to consumers along with the number assigned to it on the network of a particular DPO. The broadcaster also faces difficulty if the channel number is changed frequently. Therefore the Authority is of the view that the 6 months time may not be sufficient and therefore the DPOs have been mandated not to alter the channel numbers for at least one year from the date of such assignment. However, the Authority is in agreement of the view of some stakeholders that if the channel becomes unavailable due to any reason or there is a change in the genre of the channel by a broadcaster then the channel number assigned to a particular television channel can be changed to place such channel with the channels of new genre in the EPG. Accordingly, suitable provisions have been made in these regulations.

141. Regarding the stakeholder's suggestion to mandate DPOs to maintain *status quo* for LCN allotted after coming into effect of new regulations. The suggestion is not tenable as availability and its nature of channel in the DPOs platform may vary in the light of new framework.

#### **Reporting of Details of Service Providers**

142. In broadcasting and cable TV sector, the number of service providers namely broadcasters, MSOs, LCOs, DTH operators, HITS operators and IPTV operators are very large. The information availability at a single place by use of ICT would help service providers to know the available service providers in a particular area and would provide ease of doing business in terms of entering into interconnection agreement. This would also help the Authority to monitor the compliance of the regulation bringing much needed discipline in the market which may take the sector on a sustainable growth path. In the draft Interconnection Regulations 2016, a provision was made regarding reporting of details by the service providers. The stakeholders, in their response, have largely supported this requirement.
143. Accordingly, in these regulations the service providers have been mandated to report their details such as name, address, contact number, e-mail address and license/ permission/ registration issued by the Central Government on the website to be specified by the Authority. Further, it has been provided that the service providers shall verify, from the website that the other service provider seeking interconnection for providing signals of TV channels or access to the network, as the case may be, has reported its details on the website. However, for removal of any doubt it is clarified that mere providing the information on the website would not give any service providers the right to carry out such business unless such permission/approval/licence/registration has been obtained from the Government under relevant policy/guidelines.

#### **Designating a Compliance Officer**

144. In order to fulfil the objective of regulatory framework, it is important that the reporting requirements specified under the regulations are complied by the service provider in letter and spirit. Therefore, in the draft Interconnection Regulation, 2016 it was proposed that every pay broadcaster and DPO shall appoint a compliance officer however, it was not mandatory for the DPOs having average subscriber base over preceding calendar quarter less than 2 lakh. In response, one broadcaster stated that the limit of subscriber base should be reduced from 2 lakh to 50 thousand and compliance officer should be appointed in every target market. The MSO's association stated that the time period given for appointment of compliance officer should be increased from 30 days to 60 days and in event of any change the time period of 10 days as provided in the draft regulation is less because re-appointment of persons takes time.
145. The objective of regulatory framework can be fulfilled only if the compliance level of all the service providers is good. It is therefore very important that the provisions of these regulations and requisite reports prescribed in the regulations and tariff orders are provided to the Authority. Therefore, the provisions have been made in these regulations that every broadcaster and DPO shall designate a compliance officer irrespective of nature of their offerings and size of their operations. Further, if the broadcaster or DPO is a company then it has been prescribed that the compliance officer should be designated by the board of directors of the company. Whereas, if the DPO is an individual or a partnership firm or an association of individuals then the broadcaster or DPO should furnish the authorisation letter signed by all the partners or the head of the association, as the case may be, authorising such compliance officer. On the suggestion of some of the stakeholders regarding increase in time period for designating a compliance officer the Authority agrees that sufficient time should be given to the service providers so that they can take approval for designation of compliance officer and report the details to the Authority. Accordingly, it has been provided in these regulations that the designation of compliance officer shall be done within 30 days of commencement of the regulations and after such designation the details of the compliance officer shall be communicated to the Authority within 30 days. Further, any change in the name of the compliance officer shall be communicated to the Authority within 10 days from the date of occurrence of such change.

#### **Repeal**

146. With the Gazette notification of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017, the Authority has made a comprehensive and common regulatory framework applicable for all types of addressable systems. Therefore, the Interconnection Regulation, 2012, applicable for Digital Addressable Cable TV Systems, along with all its amendments and directions issued there under has been repealed. The Interconnection Regulations, 2004 which were applicable for non addressable systems as well as addressable systems such as IPTV, DTH and HITS except DAS has been repealed to the extent they are applicable to addressable systems. The provisions relating to analog systems shall continue to be governed by the Interconnection Regulations, 2004. All the existing interconnection agreements for providing services through addressable systems have to be either necessarily

modified or entered as a fresh agreement in compliance with the provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017.

**Commencement of the Regulations and New Interconnection Agreements**

147. These regulations shall come into effect immediately on the date of their publication in the Official Gazette. The Authority is aware that, as on the date of coming in to effect of these regulations, there would be large numbers of existing interconnection agreements in place, which have already been entered into by the service providers based upon the framework of earlier interconnection regulations. Therefore to protect the interests of consumers as well as service providers and to enable a smooth transition from the earlier regulatory framework to the new one, the Authority has provided a time of 150 days from the date of commencement of these regulations to either renew or amend all the existing interconnection agreements in compliance with the provisions of the regulations and the tariff orders notified by the Authority. The service providers are advised to modify their existing interconnection agreements well in advance before the time period of 150 days allowed, so as to avoid the sudden disconnection of signals or to avoid the risk of violating the regulations. Situation may also arise that some existing agreements may be expiring before the said cut-off date, though they were valid as on the date of commencement of these regulations. Therefore, the service providers have been permitted to renew such existing agreements so as to extend the validity of such agreement till the cut-off date. It is clarified that no new interconnection agreement shall come within the purview of such savings. All the new interconnection agreements have to be signed on the basis of these regulations.